रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 30, 1985/अग्रहायण 9, 1907
No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 30, 1985/AGRAHAYANA 9, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1985

का. आ. 5303.—केन्द्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 615(अ), तारीख 21 अगस्त, 1985, का, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3(ii), तारीख 21 अगस्त, 1985 में प्रकाशित हुई है, आंशिक रूप से उपान्तरण करते हुए, श्री आर. के. शास्त्री को, श्री बी. सी. माथुर के स्थान पर, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में जांच करने के लिए एकमात्र सदस्य नियुक्त करती है ।

[सं. 11012/187/85-एन ई-IV]

एस. एस. शर्मा, विशेष कार्य अधिकारी (असम)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 11th November, 1985

S.O. 5303.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), and in partial modification of the Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 615 (E), dated the 21st August, 1985 published in the Gazetted of India, Extraordinary, Part II, Section 3 (ii), dated the 21st August, 1985, the Central Government hereby appoints Shri R. K. Shastri as sole Member of the Commission of Inquiry in place of Shri B. C. Mathur to inquire into the matters specified in the said Notification.

[No. 11012/187/85-NE-IV]

S. S. SHARMA, Officer on Special Duty

कार्मिक और प्रशिक्षण; प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण)

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1985

का. आ. 5304.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के साथ पठित, अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारतीय संपरीक्षा तथा लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) (तीसरा संशोधन) नियम, 1985 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में,—

(क) नियम 54 में, उप-नियम (13क) के पश्चात्, निम्नलिखित उप: नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(13ख) इस नियम के अधीन अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन, ऐसे किसी व्यक्ति को मंजूर नहीं की जाएगी जो पहले ही कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करता है या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के और/या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम/स्वशासी निकाय/स्थानीय निधि के अन्य किसी नियम के अधीन उसका पात्र है :

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस नियम के अधीन कुटुम्ब पेंशन के लिए अन्यथा पात्र है, इस नियम के अधीन कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने के विकल्प का निश्चय कर सकता है यदि वह किसी अन्य स्रोत से अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन को छोड़ देता है ।";

(ख) प्ररूप 5 में, क्रम संख्या 9 के पश्चात्, निम्नलिखित और क्रम संख्यांक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"10. उल्लेख करें कि क्या अन्य किसी स्रोत जैसे सेना, किसी राज्य सरकार और/या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम/स्वशासी निकाय/स्थानीय निधि, से कुटुम्ब पेंशन अनुज्ञेय है ।"

[सं. 1/2/85-पेंशन एकक]
एस. वी. सिंह, उप सचिव

टिप्पण : केन्द्रीय सिवल सेवा (पेंशन) नियम, 1972, का. आ. 934 तारीख 1-4-72 के रूप मे प्रकाशित किए गए थे। नियमों का तृतीय संस्करण (दिसम्बर, 1981 तक संशोधित) 1982 में मुद्रित किया गया ।

पश्चात्वर्ती संशोधन इस विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा किए गए :—

1. 32/4/83-पी. यू.	26-8-83
2. 29/4/83/पी. यू.	15-11-84
3. 7/3/84-पी. यू.	17-11-84
4. 38/15/85-पी. यू.	1-7-85
5. 7/4/85-पी. यू.	29-10-85

MINISTRY OF PERSONNEL, AND TRAINING ADMINISTRATIVE REFORMS & PUBLIC GRIEVANCES & PENSION

(Department of Pension & Pensioners Welfare)

New Delhi, the 4th November, 1985.

S.O. 5304.—In exercise of the powers conferred by the provise to article 309, read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the president hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, namely —

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) (Third Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

(a) in rule 54, after sub-rule (13A), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(13-B) Family Pension admissible under this rule shall not be granted to a person who is already in receipt of family pension or is eligible therefor under any other rules of the Central Government or a State Government and/or a public sector undertaking/autonomous body/Local Fund under the Central or a State Government :—

Provided that a person who is otherwise eligible for family pension under this rule may opt to receive family pension admissible from any other source." family pension admisible from any other source."

(b) in Form 5, after Serial No.9, the following shall be inserted, namely:—

"10. Indicate whether family pension is admissible from any other source—Military or State Government and/or a public sector undertaking/autonomous body/Local Fund under the Central or a State Government."

[No. 1/2/85-Pension Unit]
S. V. SINGH, Dy. Secy.

NOTE:— The Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 were published as S.O. 934 dated 1-4-1972. The Third Edition (corrected upto December, 1981) of the Rules was printed in 1982.

Subsequently amended vide this Department's notification.

1. 32/4/83-PU Dated 26-8-83.
2. 29/483-PU Dated 15-11-84.
3. 7/3/84-PU Dated 17-11-84.
4. 38/15/85-PU Dated 1-7-85.
5. 7/4/85-PU Dated 29-10-85.

(कार्मिक और प्रशिक्षण, विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1985

का. आ. 5305.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित, धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जी आर पी, जम्मू में 11-6-84 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 20/84 के अंतर्गत रजिस्टर किए गए जम्मू में रेल पटरी को विस्फोटक पदार्थों से अभिध्वंस करने की बाबत, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम,

1908 (1908 का 6) की धारा 3 और धारा 4 और भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 126 के अधीन दण्डनीय अपराधों, और उक्त अपराधों, और उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न होने वाली वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए किन्हीं अन्य अपराधों, के संबंध में या उनसे संसक्त प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षडयंत्रों के अन्वेषण के लिए, जम्मू-कश्मीर सरकार की सहमति से, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्य की शक्तियां और अधिकारिता का विस्तारण सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य पर करती है ।

[सं. 228/27/85-ए. वी. डी.-II]

(Deptt. of Personnel & Training)

ORDER

New Delhi, the 13th November, 1985

S.O. 5305.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5, read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the Government of Jammu and Kashmir, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Jammu and Kashmir for the investigation of offences punishable under sections 3 and 4 of the Explosive Substances, Act, 1008 (6 of 1908) under section 126 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890) and attempts and abetments and conspiracies in relation to or in connection with the said offences and any other arising out of the same facts, in regard to the sabotage by Explosive Substances of the Railway Track at Jammu as registered vide FIR No. 20|84, dated 11-6-84 at G.R.P., Jammu.

[No. 228|27|85-ADV. II-II]

आदेश

का. आ. 5306.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित, धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गांधी नगर पुलिस स्टेशन, जम्मू, केस सं. 411/85, तारीख 17 सितम्बर, 1985 की बाबत, आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985 (1985 का 31) की धारा 3, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 (1920 का 34) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 के नियम 6, भारतीय आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 25 और संवत् 2005 के जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा जारी किए गए एनिमी एजेन्ट्स आर्डिनेन्स की धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराधों और उक्त अपराधों तथा उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए किन्हीं अन्य अपराधों के संबंध में या उनसे संसक्त प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षडयंत्रों के अन्वेषण के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार की सहमति से, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियां और अधिकारिता का विस्तारण सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य पर करती है ।

[सं. 228/27/85-ए. वी. डी.-II-I]

के. जी. गोयल, उप सचिव

ORDER

S.O. 5306.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5, read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the Government of Jammu and Kashmir hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Jammu and Kashmir for the investigation of offences punishable under section 3 of the Terrorists and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1985 (31 of 1985), rule 6 of the Passport (Entry into India) Rules, 1950, read with sub-section (3) of section 3 of the Passport (Entry into India), Act, 1920, section 25 of the Indian Arms Act, 1959 (54 of 1959) and section 3 of the Enemy Agents Ordinance of 2005 Samvat issued by the Government of Jammu and Kashmir and attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with the said offences and any other offences committed during the course of the same transaction, arising out of the same facts in regard to the case No. 411|85, dated the 17th September, 1985 of Police Station, Gandhi Nagar, Jammu.

[No. 228|27|85-AVD. II-I]

K. G. GOEL, Dy. Secy.

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1985

का. आ. 5307.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1811 तारीख 11-4-85 द्वारा केन्द्रीय केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

जी. जी. एस II से सी टी एफ सोभासन

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाना

गांव	ब्लाक न.	है.	आर.	से.
1	2	3	4	5
जगुदन	463	0	00	75
	467	0	01	50
	466	0	03	65
	465	0	07	25
	472	0	01	25
	कार्ट ट्रेक	0	00	50
	637	0	04	00
	611	0	06	00
	615	0	03	75
	610	0	02	10
	607	0	05	75
	535	0	04	90
	534	0	03	75
	526	0	00	10
	533	0	01	50
	532	0	01	50
	537	0	01	75
	कार्ट ट्रेक	0	00	25
	531	0	00	60
	544	0	02	50
	549	0	02	00
	कार्ट ट्रेक	0	00	20
	559	0	08	00
	560	0	00	60
	561	0	02	40
	562	0	02	90
	कार्ट ट्रेक	0	00	15
	565	0	04	00
	567	0	03	75
	1013	0	04	60
	1016	0	03	00
	1017	0	03	00
	कार्ट ट्रेक	0	00	25
	1050/1/ए	0	06	05
	1051	0	05	00
	1045	0	03	55
	1046	0	00	80
	1044/2	0	02	85
	1058	0	03	90
	कार्ट ट्रेक	0	00	25
	1061	0	05	00
	1059	0	00	25
	1062	0	07	25
	1079	0	00	15
	1080	0	03	25
	1078	0	03	05
	1077	0	01	10

[सं. 12016/37/85ओ एन जी-डी 4]

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 13th November, 1985

S.O. 5307.—Whereas by Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1811 date 11-4-85 under subu-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that Notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this Notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this Notification hereby acquires for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the rigt of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GGS II to C.T.E. Sobhasan

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Jagudan	463	0	00	75
	467	0	01	50
	466	0	03	65
	465	0	07	25
	472	0	01	25
	Cart track	0	00	50
	637	0	04	00
	611	0	06	00
	615	0	03	75
	610	0	02	10
	607	0	05	75
	535	0	04	90
	534	0	03	75
	526	0	00	10
	533	0	01	50
	532	0	01	50
	537	0	01	75
	Cart track	0	00	25
	531	0	00	60
	544	0	02	50

1	2	3	4	5
	549	0	02	00
	Cart track	0	00	20
	559	0	08	00
	560	0	00	60
	561	0	02	40
	562	0	02	90
	Cart track	0	00	15
	565	0	04	00
	567	0	03	75
	1013	0	04	60
	1016	0	03	00
	1017	0	03	00
	Cart Track	0	00	25
	1050/1/A	0	06	05
	1051	0	05	00
	1045	0	03	55
	1046	0	00	80
	1044/2	0	02	85
	1058	0	03	90
	Cart Track	0	00	25
	1061	0	05	00
	1059	0	00	25
	1062	0	07	25
	1079	0	00	15
	1080	0	03	25
	1078	0	03	05
	1077	0	01	10

[No. O-12016/37/85-ONG-D 4]

का. आ. 5308—यत : पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2139 तारीख 8-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईपलाईनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एन. के. एफ जे. से एन. के.—141

राज्य—गुजरात जिला—अहमदाबाद तालुका—विरमगाम

गांव	सर्वे न.	हे.	आर.	सें
तेलवा	20/1	0	08	52
	23/1	0	08	88
	25	0	13	68
	31	0	04	56
	32/2	0	02	28
	32/1	0	07	44
	32/3	0	07	92

[सं. O-12016/50/85-ओ एन जी-डी. 4]

S.O. 5308.—Whereas by notfication of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2139 dated 8-5-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pippeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from No. NKFJ to NK-141

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hectare	Are	Hectare
1	2	3	4	5
Telavl	20/1	0	08	52
	23/1	0	08	88
	25	0	13	68
	31	0	04	56
	32/2	0	02	28
	32/1	0	07	44
	32/3	0	07	92

[No. O-12016/50/85-ONG-D4]

का. आ. 3509—यत : पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2141 तारीख 8-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईपलाईनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे इस धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एन. के. जी. एल. से एन. के. ई एल.

राज्य गुजरात जिला : मेहसान तालुक कडी

गांव	सर्वे नं.	हे.	आर.	सें.
सुरज	650	0	06	36
	653/1	0	09	12
	653/2			
	654	0	18	48
	654	0	08	16

[सं. 12016/52/85-ओ. एन. जी-डी-4]

S.O. 5309.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2141 dated 8-5-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pippeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From NKGL to NKEL

State : Gujarat District : Mahsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Suraj	650	0	06	36
	653/1 653/2	0	09	12
	654	0	18	48
	654	0	08	16

[No. O-12016/52/85 ONG-D4]

का. आ. 5310 :—यत : पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 2146 तारीख 8-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईपलाईनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

मेवड —4 से सोमासन —68 से सोभासन—54

राज्य गुजरात जिला : व तालुका : मेहसाना —				
गांव	सर्वे नं.	हे.	आर.	सें.
1	2	3	4	5
मेवड	403	0	04	80

[सं. O-12016/55/85-ओ. एन. जी.—डी-4]

S.O. 5310.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2146 dated 8-5-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline·

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pippeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from MEVAD-4 to SOB-68 to SOB-54.

State : Gujarat	District & Taluka : Mehsana			
Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
Mevad	403	0	04	80

[No. O 12016/55/85-ONG-D 4]

का. आ. 5311.—यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 2445 तारीख 8-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईपलाईनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत : अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एन. के. ई. जी. से एन. के. ओ.

राज्य गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका विरमगाम				
गांव	सर्वे न.	हे.	आर	सें.
भटारीया	12	0	01	08
	13	0	09	16
	11	0	05	04
	10	0	06	66

[सं. O-12016/56/85-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 5311.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2445 dated 8-5-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline·

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government,

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 5 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pippeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in

Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From NKEG to NKO

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Bhatariya	12	0	01	08
	13	0	09	16
	11	0	05	04
	10	0	06	66

[No. O 12016/76/85-ONG-D 4]

का. आ. 5312:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का आ. सं. 2144 तारीख 8-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की [इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एन. के. ई. जी० से एन. के. ओ.

राज्य गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : विरमगाम

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर	सेन्टीयर
मेहमदपुरा	44	0	07	08
	46	0	05	72

[सं. O-12016/57/85-ओ एन जी.-डी. 4]

S.O. 5312.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2144 dated 8-5-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. NKEG to NKO

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Mehmadpura	44	0	07	08
	46	0	05	72

[No. O-12016/57/85-ONG-D 4]

का. आ. 5313:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2389 तारीख 18-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एन. के. ई. वी. से एन. के. ई. यू. 67

राज्य :— गुजरात जिला:— अहमदाबाद तालुका :— विरमगाम

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
सजपुरा	76/पी	0	09	60
	82/1	0	03	84

[सं. —12016/60/85— ओ एन जी—डी 4]

S.O. 5313.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2389 dated 18-5-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pippeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from NKEV to NKEU

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Sujpura	76/P	0	09	60
	8/21	0	03	84

[No. O-12016/60/85-ONG D4]

का. आ. 5314.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2908 तारीख 11-6-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एस. एन. ए. यू. से एस. एस. सी. टी. एफ.

राज्य :— गुजरात जिला व तालुका : मेहसाना

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
संथाल	588	0	14	40
	586	0	16	45

[सं. O—12016/73/85— ओ एन जी— डी 4]

S.O. 5314.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2908 dated 11-6-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pippeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in

Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from SNAU to S.S. CTF.

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Santhal	588	0	14	40
	586	0	16	45

[No. O—12016/73/85—ONG-D 4]

का. आ. 5315:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2914 तारीख 14-6-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों के बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जे. एन. एन. से जे. एन. ए. जी.

राज्य :— गुजरात जिला व तालुका :— मेहसाना

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
मांकणज	822	0	01	44
	820	0	07	92
	820	0	03	84
	962	0	06	60
	962	0	05	16
	899	0	00	72
	964	0	08	04
	960	0	09	84

[सं. O- 12016/78/85- अ। एन जी- डी 4]

S.O. 5315.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2914 dated 14-6-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall insted of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from JNN to JNAG

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Maknaj	822	0	01	44
	820	0	07	92
	820	0	03	84
	962	0	06	60
	962	0	05	16
	899	0	00	72
	964	0	08	04
	960	0	09	84

[No. O—12016/78/85—ONG-D 4]

का. आ. 5316:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 3095 तारीख 14-6-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में

विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एस. एन. ए. ए. से एस. एस. सी. टी. एफ. हीडर

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाना

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
कसलपुरा	858	0	03	60
	857	0	08	90
	809	0	15	70
	808	0	16	60
	805	0	12	70

[सं. O- 12016/79/85- ओ एन जी-डी 4]

S.O. 5316.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3095 dated 14-6-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall insted of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from SNAA to S.S. CTF Header

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Kasalpura	858	0	03	60
	857	0	08	90
	809	0	15	70
	808	0	16	60
	805	0	12	70

[No. O—12016/79/85-ONG-GD 4]

का. आ. 5317: यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3494 तारीख 17-7-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एस. एन. एच. से संथाल जी. जी. एस.

राज्य :– गुजरात जिला व तालुका :– मेहसाना

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
संथाल	867	0	04	92
	872	0	06	72
	873	0	03	80
	878	0	12	36
	821	0	05	16
	820	0	12	96
	881	0	07	68
	882	0	18	48

[सं. O–12016/ 83/85– ओ एन जी–डी 4]

S.O. 5317.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3494 dated 17-7-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from SNH to Santhal GGS

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
Santhal	867	0	04	92
	872	0	06	72
	873	0	03	80
	878	0	12	36
	821	0	05	16
	820	0	12	96
	881	0	07	68
	882	0	18	48

[No. O–12016/83/85–ONG-D 4]

का. आ. 5318:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3495 तारीख 17–7–85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एन. के. एफ. आई. से एन के. जी. जी. एस– 1

राज्य :– गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : विरमगांम

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
तेलाबी	139/2	0	03	00
	139/1	0	02	40
	139/1/पी	0	01	68
	139/4	0	01	56
	140/3	0	02	76
	कार्टट्रेक	0	06	30
	140/4	0	10	20
	कार्टट्रेक	0	01	08
	55	0	02	40

[सं. O–12016/ 84/85– ओ एन जी–डी 4]

S.O. 5318.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3495 dated 17-7-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall insted of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from NRFI to NK. GGS I.

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka :Viramgam

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Telavi	139/2	0	03	00
	139/1	0	02	40
	139/1/P	0	01	68
	139/4	0	01	56
	140/3	0	02	76
	Cart/track	0	06	30
	140/4	0	10	20
	Cart track	0	01	08
	55	0	02	40

[No. O—12016/84/85-ONG-D4]

का.आ. 5319:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3484 तारीख 16-7-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और, यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एस. एन. ए. पी. से एस. एन. ए. जे.

राज्य :— गुजरात जिला व तालुका :— मेहसाना

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
संथाल	423	0	09	40
	420	0	06	50

[सं. O—12016/88/85—ओ एन जी—डी 4]

S.O. 5319.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3484 dated 16-7-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall insted of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from SNAP to SANAJ

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Santhal	423	0	09	40
	420	0	06	50

[No. O—12016/88/85-ONG-D 4]

का.आ. 5320:—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3486 तारीख 16-7-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और, यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे, उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एन. के. एफ. एक्स से एन. के. एफ. वाई से एन. के. एफ. ई.

राज्य :—गुजरात जिला :—व तालुका :—मेहसाना

गांव	ब्लोक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
मेहमदपुरा	7	0	07	20
	6	0	04	44
	6	0	04	68
	358	0	11	04
	354	0	05	76
	353	0	08	54
	350	0	02	40
	349	0	07	44
	348	0	06	00

[सं. O-12016/90/85-ओ. एन. जी-डी-4]

S.O. 5320.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3486 dated 16-7-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall insted of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from NKFX to NKFY to NKFE

State : Gujarat District & Taluka : Mehsan

Village	Block No.	Hectare	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Memadpura	7	0	07	20
	6	0	04	44
	6	0	04	68
	358	0	11	04
	354	0	05	76
	353	0	08	64
	350	0	02	40
	349	0	07	44
	348	0	06	00

[No. O—12016/90/85-ONG-D 4]

का.आ. 5321:—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3487 तारीख 16-7-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और, यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे, उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा

अनुसूची

कूप नं. 26 से जी सी एस

राज्य : गुजरात जिला : खेड़ा तालुका : खम्भात

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेंन्टीयर
लुनज	252	0	06	65
	251	0	07	78
	249	0	07	74

[सं. O-12016/91/85-ओ एनजी-डी-4]

S.O. 5321.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3487 dated 16-7-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall insted of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. 26 to G.C.S.

State : Guiarat District : Kheda Taluka : Cambay

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Lunaj	252	0	06	65
	251	0	07	78
	249	0	07	74

[No. O-12016/91/85-ONG-D 4]

का.आ. 5322:—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3489 तारीख 16-7-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और, यत:, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और, आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एन. के. ई. एन. से एन. के. ई. पी.

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : विरमगाम

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेन्टीयर
बाल सासन	373 1	0	06	96
	374 4	0	02	88
	374 1	0	03	00
	372 1	0	11	52
	371 1	0	05	88
	371 1	0	02	16
	371 2	0	04	56

[सं. O-12016/93/85-ओ. एन. जी-डी-4]

S.O. 5322.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3489 dated 16-7-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from NKEN to NKEP

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Balsasan	373/1	0	06	96
	374/4	0	02	88
	374/1	0	03	00
	372/3	0	11	52
	371/1	0	05	88
	371/1	0	02	16
	371/2	0	04	56

[No. O—12016/93/85-ONG-D 4]

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1985

का.आ. 5323:—यतः, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4284 तारीख 30-8-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और, यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

जंक्शन पोइन्ट से जी. जी. एस 4 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कलोल

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
कलोल	252/228	0	04	00
	252/225	0	01	40
	252/224	0	18	15
	252/223/16	0	01	45
	252/223/8	0	01	50
	252/223/6	0	04	00
	252/223/3	0	04	65
	252/223/9	0	00	10
	252/223/11	0	00	35
	252/223/12	0	00	60
	214	0	07	50
	215	0	01	80
	कार्टट्रेक	0	01	44
	252/76	0	01	12
	252/68	0	08	40
	252/69	0	08	73
	252/66	0	02	52
	252/65/1	0	01	00
	252/30	0	05	50
	252/61	0	07	00
	252/22	0	02	80
	252/23	0	03	68
	252/25	0	09	36
	252/27	0	00	10
	Kans	0	01	12
	252/1/2	0	01	00
	251/12	0	05	25
	251/13	0	01	53
	251/11	0	03	87
	251/10	0	00	50
	251/32	0	07	40
	251/33	0	01	75

1	2	3	4	6
	251/34	0	06	00
	251/35	0	01	05
	251/36	0	02	34
	251/39	0	00	95
	251/40	0	01	20
	251/41	0	02	72

[सं. O-12016/99/85-ओ. एन. जी. डी-4]

New Delhi, the 14th November, 1985

S.O. 5323.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4284 dated 30-8-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Junction Point to GGS IV

State :Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-tare
1	2	3	4	5
Kalol	252/228	0	04	00
	252/225	0	01	40
	252/224	0	18	15
	252/223/16	0	01	45
	252/223/8	0	01	50
	252/223/6	0	04	00
	252/223/3	0	04	65
	252/223/9	0	00	10
	252/223/11	0	00	35
	252/223/12	0	00	60
	214	0	07	50
	215	0	01	80
	Cart track	0	01	44
	252/76	0	01	12
	252/68	0	03	40
	252/69	0	03	73
Kalol—(Contd.)	252/66	0	02	52
	252/65/1	0	01	00
	252/30	0	05	50
	252/61	0	07	00
	252/22	0	02	80
	252/23	0	03	68
	252/25	0	09	36
	252/27	0	00	10
	Kans	0	01	12
	252/1/2	0	01	00
	251/12	0	05	25
	251/13	0	01	53
	251/11	0	03	87
	251/10	0	00	50
	251/32	0	07	40
	251/33	0	01	75
	251/34	0	06	00
	251/35	0	01	05
	251/36	0	02	34
	251/39	0	00	95
	251/40	0	01	20
	251/41	0	02	72

[No. O-12016/99/85-ONG-D 4]

का. आ. 5324.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि असम राज्य में दिब्रो जंक्शन पाईंट से लकुवा जी.टी.एफ. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप उपयुक्त, शिवसागर/असम के कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

लकूवा सि.टि.एफ. से दिखौ जंकसन पाईण्ट तक

राज्य–असम; जिला –शिवसागर; तालुक –शिलाकुटि

ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टयर	एरे	सेन्टीयरे
1	2	3	4	5
भजनी गांव	13/ख	0	2	41
	12/ख	0	3	08
	7/ख	0	2	14
	11/ख	0	2	01
	50/ख	0	2	01
	51/ख	0	2	54
	52/ख	0	3	08
	66/ख	0	3	21
	63/ख	0	3	21
	64/ख	0	2	14
	113/ख	0	2	14
	121/ख	0	5	75
भाजनी गांव	122/ख	0	2	01
	123/ख	0	5	89
	125/ख	0	1	34
	190/ख	0	2	81
	189/ख	0	6	02
	187/ख	0	7	36
	193/ख	0	3	75
	195/ख	0	4	82

[सं. O–12016/104/85-ओ. एन. जी–डी-4]

S.O .5324.—Whereas it apepars to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Dikhow Junction Point to Lakwa C.T.F. in Sibsagar Dist., Assam, pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Govt. hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, viz. the Deputy Commissioner, Sibsagar, Assam.

And every person making such objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

LAND SCHEDULE

Dikhow Junction Point to Lakwa C.T.F.

State : Assam Distt. : Sibsagar Taluk : Silakuti

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Bhajani Gaon	13/Kha	0	2	41
	12/Kha	0	3	08
	7Kha	0	2	14
	11/Kha	0	2	01
	50/Kha	0	2	01
	51/Kha	0	2	54
	52/Kha	0	3	08
	66/Kha	0	3	21
	63/Kha	0	3	21
	64/Kha	0	2	14
	113/Kha	0	2	14
	121/Kha	0	5	75
	122/Kha	0	2	01
	123/Kha	0	5	89
	125 Kha	0	1	34
	190 Kha	0	2	81
	189/Kha	0	6	02
	187/Kha	0	7	36
	193/Kha	0	3	75
	195/Kha	0	4	82

[No. O—12016/104/85-CNG-D-4]

का. आ. 5325:—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि असम राज्य में लाकूवा जि. जि. एस. 5 से लाकूवा जि. जि. एस. 4 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप उपायुक्त, शिवसागर/असम के कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

आर. ओ. यू. लाकूवा जि. जि. एस-5 से जि. जि. एस 4 तक

राज्य—असम; जिला—शिवसागर; तालुक—बकवा

ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टेयर	ऐरे	सेन्ट यरे
1	2	3	4	5
जालूकनी बिल	72/ख	0	5	35
	73/ख	0	9	36
	75/ख	0	6	69
	76/ख	0	2	68
	77/ख	0	6	02

[सं. O-12016/105/85-ओ. एन. जी.-डी-4]

S.O. 5325.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Lakwa G.G.S. 5 to G.G.S. 4 in Sibsagar District, Assam, pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And, whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the se tion 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Govt. hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, viz., the Deputy Commissioner, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

R.O.U. from Lakwa GGS-5 to GGS-4.

State : Assam, District : Sibsagar, Taluk Bokotha

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Jalukani Bill	72/Kha	0	5	35
	73/Kha	0	9	36
	75/Kha	0	6	69
	76/Kha	0	2	68
	77/Kha	0	6	02

[No. O—12016/105/85-ONG-D-4]

का. आ. 5326.—यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि असम राज्य में दिखौ जंकसन पईण्ट से लाकूवा सि.टि.एफ. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसा लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप उपायुक्त शिवसागर/असम के कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी को मार्फत ।

अनुसूची

लकूवा सि. टि. एफ. से दिखौ जंकसन पाईण्ट तक

राज्य—असम; जिला—शिवसागर; तालूक-शिलाकूटि

ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टर	ऐरे	सेन्ट यरे
1	2	3	4	5
शिलाकूटि				
भकत गांव	226/ख	0	11	37
	225/ख	0	0	54
	228/ख	0	2	41
	224/ख	0	0	27
	229/ख	0	2	01
	230/ख	0	2	41
	231/क	0	4	15
	232/ख	0	2	68
	233/ख	0	4	68
	234/ख	0	1	74
	236/ख	0	0	54
	236/ग	0	1	61
	235/ख	0	3	34
	241/ख	0	1	07
	241/ग	0	0	54
	242/ख	0	4	68
	242/ग	0	3	21
	243/ख	0	3	48
	285/ख	0	6	02
	286/ख	0	11	37
	287/ख	0	4	01

1	2	3	4	5
भकत गांव	288/ख	0	1	07
—(जारी)	291/ख	0	0	54
	370/ख	0	6	02
	369/ख	0	8	70
	375/ख	0	1	07
	378/ख	0	7	36
	380/ख	0	2	41
	382/ख	0	7	22
	385/ख	0	3	61
	383/ख	0	3	61
	424/ग	0	3	34
	424/घ	0	5	35
	384/घ	0	3	34
	433/ख	0	0	40
	425/ख	0	3	61
	428/ख	0	2	81
	432/ख	0	0	40
	116/ख	0	2	01
	115/ख	0	2	41
	473/ख	0	0	54
	476/ख	0	4	01
	479/ख	0	3	61
	479/ग	0	2	81
	478/ख	0	2	81
	558/ख	0	7	22
	560/ख	0	4	82
	561/ख	0	3	48
	565/ख	0	6	69
	569/ख	0	3	61
	570/ख	0	1	61
	548/ख	0	0	67
	549/ख	0	4	41
	555/ख	0	5	35
	253/ख	0	0	54
	254/ख	0	1	87

[सं. O-12016/106/85—ओ. एन. जी.—डी-4]
पी०के० राजगोपालन डेस्क अधिकारी

S.O. 5326.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Dikhow Junction Point to Lakwa C.T.F. in Sibsagar Dist., Assam, pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annxed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 1962), the Central Govt., hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, viz. the Deputy Commissioner, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Dikhow Junction Point to Lakwa C.T.F.

State : Assam Dist. : Sibsagar Taluk : Silakuti

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Silakuti Bhakat Gaon	226/Kha	0	11	37
	225/Kha	0	0	54
	228/Kha	0	2	41
	224/Kha	0	0	27
	229/Kha	0	2	01
	230/Kha	0	2	41
	231/Kha	0	4	15
	232/Kha	0	2	68
	233/Kha	0	4	68
	234/Kha	0	1	74
	236/Kha	0	0	54
	236/Ga	0	1	61
	235/Kha	0	3	34
	241/Kha	0	1	07
	241/Ga	0	0	54
	242/Kha	0	4	68
	242/Ga	0	3	21
	243/Kha	0	3	48
	285/Kha	0	6	02
	286/Kha	0	11	37
	287/Kha	0	4	01
	288/Kha	0	1	07
	291/Kha	0	0	54
	370/Kha	0	6	02
	369/Kha	0	8	70
	375/Kha	0	1	07
	378/Kha	0	7	36
	380/Kha	0	2	41
	382/Kha	0	7	22
	385/Kha	0	3	61
	383/Kha	0	3	61
	424/Ga	0	3	34
	424/Kha	0	5	35
	384/Kha	0	3	34
	433/Kha	0	0	40
	425/Kha	0	3	61
	428/Kha	0	2	81
	432/Kha	0	0	40
	116/Kha	0	2	01
	115/Kha	0	2	61
	473/Kha	0	0	54
	476/Kha	0	4	01
	479/Ga	0	3	61
	479/Kha	0	2	81
	478/Kha	0	2	81
	558/Kha	0	7	22
	560/Kha	0	2	82
	561/Kha	0	3	48
	565/Kha	0	6	69
	569/Kha	0	3	61
	570/Kha	0	1	61

1	2	3	4	5
	548/Kha	0	0	67
	549/Kha	0	4	41
	555/Kha	0	5	35
	253/Kha	0	0	54
	254/Kha	0	1	87

[No. O-12016/106/85-ONG-D 4]

P. K. Rajag palan, Desk Officer

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1985

का.आ.सं. 5357:--यत: भारत सरकार को अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है गुजरात राज्य में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में उभराट से हजीरा तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपयोग के अधिकार अर्जित किये गये हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड-7 के उपखण्ड (1) की धारा (i) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 15-7-85 से समाप्त कर दिया गया है।

अत: अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के नियम-4 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं।

[सं. ओ.-12016/120/83-प्रोड/जीपी]

ह./-

(गुजरात के सूरत और वलसाड जिला के लिए नियमान्तर्गत सक्षम प्राधिकारी)

अनुसूची

उभराट से हजीरा तक पाइप लाइन कार्य समिति

मंत्रालय का नाम	गांव	का.आ. सं.	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम मंत्रालय	भाटपरि ता. चोरासी जि: सूरत	433	11-2-84	15-7-85

New Delhi, the 18th November, 1985

S.O. 5327.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from Ubhrat to Hazira in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 15-7-85.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

[No. O-12016/120/83-PROD/GP]

Sd/-

Competent Authority under the Act for Surat & Valsad Districts in Gujarat State

SCHEDULE

Termination of Pipeline from D.S. Ubhrat to Hazira

Name of Ministry	Village	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Energy, Deptt. of Petroleum	Bhatpore Tal : Chorasi Dist. : Surat	433	11-2-84	15-7-85

का.आ. 5328:—यत: भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में उभराट से हजीरा तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपयोग के अधिकार अर्जित किये गये हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड-7 के उपखण्ड (1) की धारा (i) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 15-7-85 से समाप्त कर दिया गया है।

अत: अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के नियम-4 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं।

[सं. ओ-12016/101/83-प्रोड/जी.पी]

ह./-

गुजरात के सूरत और वलसाड जिला के लिए नियमान्तर्गत सक्षम प्राधिकारी

अनुसूची

उभराट से हजीरा तक पाइप लाइन कार्य समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का.आ. सं.	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम मंत्रालय	दांता ता: नवसारी जि: वलसाड	434	11-2-84	15-7-85

S.O. 5328.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from Ubhrat to Hazira in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 15-7-85.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipeline (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

[No. O-12016/101/83-PROD/GP]

Sd/-

Competent Authority under the Act for Surat & Valsad District in Gujarat State

SCHEDULE

Termination of Pipeline from Ubhrat to Hazira

Name of Ministry	Village	S.O. No.	Date of publication in Gazette of India	Date of Termination of operation
Ministry of Petroleum	Danti Tal : Navsari Dist. : Valsad	434	11-2-84	15-7-85

का.आ. 5329 :—यतः भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में उभराट से हजीरा तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपयोग के अधिकार अर्जित किये गये हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड-7 के उपखण्ड (1) की धारा (i) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 15-7-85 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के नियम-4 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं।

[सं. ओ-12016/102/83-प्रोड/जी.पी.]

ह./-

गुजरात के सूरत और वलसाड जिला के लिए नियमान्तर्गत सक्षम प्राधिकारी

अनुसूची

उभराट से हजीरा तक पाइप लाइन कार्य समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का. आ. सं.	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम मंत्रालय	भाटपोर ता: चोरासी जि: सूरत	436	11-2-84	15-7-85

S.O. 5329.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from Ubhrat to Hazira in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 15-7-85.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

[No. O-12016/102/83-PROD/G.P.]

Sd/-

Competent Authority under the Act for Surat & Valsad Districts in Gujarat State

SCHEDULE

Termination of Pipeline from Ubhrat to Hazira

Name of Ministry	Village	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Ministry of Petroleum	Bhatpore Tal : Chorasi Dist. : Surat	436	11-2-84	15-7-85

का.आ. 5330 :—यतः भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में उभराट से हजीरा तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपयोग के अधिकार अर्जित किये गये हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड-7 के उपखण्ड (1) की धारा (i) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 15-7-85 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के नियम-4 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं।

[सं. ओ–12016/114/83–प्रोड/जी.पी.]

ह./-

गुजरात के सूरत और वलसाड जिला के लिए नियमान्तर्गत सक्षम प्राधिकारी

अनुसूची

उभराट से हजीरा तक पाइप लाइन कार्य समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का.आ. सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम मंत्रालय	पांटा ता: चोरासी जि : सूरत	440	11-2-84	15-7-85

S.G. 5330.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from Ubhrat to Hazira in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 15-7-85.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1962, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

[No. O-12016/114/83-PROD/G.P.]

Sd/-

Competent Authority under the Act for Surat & Valsad Districts in Gujarat State

SCHEDULE

Termination of Pipeline from Ubhrat to Hazira

Name of Ministry	Village	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Ministry of Petroleum	Panta Tal : Chorasi Dist. : Surat	440	11-2-84	15-7-85

का. आ. 5331 :—यतः भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में उभराट से हजीरा तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपयोग के अधिकार अर्जित किये गये हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड-7 के उपखण्ड (1) की धारा (i) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 15-7-85 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोगके अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के नियम-4 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं।

[सं. ओ–12016/115/83–प्रोड/जी.पी.]

ह./-

गुजरात के सूरत और वलसाड जिला के लिए नियमान्तर्गत सक्षम प्राधिकारी

अनुसूची

उभराट से हजीरा तक पाइप लाइन कार्य समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का. आ. सं.	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम मन्त्रालय	हुमस ता: चोरासी जि: सूरत	943	24-4-84	15-7-85

S. O. 5331. Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962, the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from Ubhrat to Hazira in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 15-7-85.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

[No. O-12016/115/83-PROD/G.P.]

Sd/-

Competent Authority under the Act for Surat & Valsad Districts in Gujarat State

SCHEDULE

Termination of Pipeline from Ubhrat to Hazira

Name of Ministry	Village	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Ministry of Petroleum	Dumas Tal : Chorasi Dist. : Surat	943	24-4-84	15-7-85

का.आ. 5332 :—यतः भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में उभराट से हजीरा तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपयोग के अधिकार अर्जित किये गये हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड-7 के उपखण्ड (1) की धारा (j) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 15-7-85 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के नियम-4 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं।

[सं. ओ-12016/117/83-प्रोड/जी.पी.]

ह./-

गुजरात के सूरत और वलसाड जिला के लिए नियमान्तर्गत सक्षम प्राधिकारी

अनुसूची

उभराट से हजीरा तक पाइप लाइन कार्य समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का.आ. सं.	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम मंत्रालय	उभराट ता: नवसारी जि: वलसाड	442	11-2-84	15-7-85

S.O. 5332. .—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (i) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from Ubhrat to Hazira in Gujarat State.

And Whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 15-7-85.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

[N.O-12016/117/83-PROD/G.P.]

Sd/-

Competent Authority under the Act for Surat & Valsad Districts in Gujarat State

SCHEDULE

Termination of Pipeline from Ubhrat to Hazira

Name of Ministry	Village	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Ministry of Petroleum	Ubhrat Tal : Navsari Dist. : Valsad	442	11-2-84	15-7-85

का.आ. 5333 :—यतः भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में उभराट से हजीरा तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपयोग के अधिकार अर्जित किये गये हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड-7 के उपखण्ड (1) की धारा (i) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 15-7-85 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के नियम-4 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते है।

[सं. ओ-12016/118/83-प्रोड/जी.पी.]

ह./-

गुजरात के सूरत और वलसाड जिला के लिए नियमान्तर्गत सक्षम प्राधिकारी

अनुसूची

उभराट से हजीरा तक पाइप लाइन कार्य समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का.आ. सं.	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम मन्त्रालय	गवीयर ता: चोरासी जि: सूरत	441	11-2-84	15-7-85

S.O. No. 5333. —Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from Ubhrat to Hazira in Gujarat State.

And whereas Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 15-7-85.

Now, therefore, under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

[No. 12016/118/83-PROD/G.P.]

Sd/-

Competent Authority under the Act for Surat & Valsad Districts in Gujarat State

SCHEDULE

Termination of Pipeline from Ubhrat to Hazira

Name of Ministry	Village	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Ministry of Petroleum	Gaviyar Tal : Chorasi Dist. : Surat	441	11-2-84	15-7-85

का.आ. 5334 :—यतः भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है गुजरात राज्य में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में उभ'राट से हजीरा तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपयोग के अधिकार अर्जित किये गये हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड-7 के उपखण्ड (1) की धारा (i) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 15-7-85 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के नियम-4 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं।

[सं 12016/119/83 प्रोड/जी.पी.]

ह./-

गुजरात के सूरत और वलसाड जिला के लिए नियमान्तर्गत सक्षम प्राधिकारी

अनुसूची

उभ्राट से हजीरा तक पाइप लाइन कार्य समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का.आ. सं.	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम मंत्रालय	कवास ता: चोरासी जि: सूरत	432	11-2-84	15-7-85

S.O. No. 5334.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from Ubhrat to Hazira in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 15-7-85.

Now, therefore, under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

[No. 12016/119/83-PROD/G.P.]

Sd/-

Competent Authority under the Act for Surat & Valsad Districts in Gujarat State

SCHEDULE

Termination of Pipeline from Ubhrat to Hazira

Name of Ministry	Village	S.O. No.	Date of publication in Gazette of India	Date of termination of operation
Ministry of Petroleum	Kawas Tal : Chorasi Dist. : Surat	432	11-2-84	15-7-85

का. आ. 5335 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं० 2036 ता० 11-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन को इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम:पहाड़ा खुर्द तहसील:पिछोर जिला:शिवपुरी राज्य (मध्यप्रदेश)

अनु क्र./	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	831	0.143
2.	844	0.470
3.	832	0.042
4.	841	0.136
5.	842	0.010
6.	843	0.386
7.	839	0.052
8.	439/890	0.188
9.	811	0.031
10.	853	0.073
11.	854	0.324
12.	855	0.251
13.	856	0.491
14.	700	0.073
15.	701	0.157
16.	702	0.240
17.	747	0.240
18.	748	0.073
19.	659	0.188
20.	660	0.157
21.	666	0.021
22.	667	0.470
23.	668	0.052
24.	677	0.188
25.	679	0.293
26.	680	0.084
27.	840	0.021
28.	676	0.010
योग :—कुल क्षेत्रफल		4.864

[सं. O—14016/314/85—जी.पी.]

S.O. 5335.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2036 dated 4-5-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Pahara Khurd Tehsil : Pichhore Distt. : Shivpuri

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hector
1	2	3
1.	831	0.143
2.	844	0.470
3.	832	0.042
4.	841	0.136
5.	842	0.010
6.	843	0.386
7.	839	0.052
8.	439/890	0.188
9.	811	0.031
10.	853	0.073
11.	854	0.324
12.	855	0.251
13.	856	0.491

1	2	3
14.	700	0.073
15.	701	0.157
16.	702	0.240
17.	747	0 240
18.	748	0.073
19.	659	0.188
20.	660	0.157
21.	666	0.021
22.	667	0.470
23.	668	0.052
24.	677	0.188
25.	679	0 293
26.	680	0 084
27.	840	0.021
28.	676	0.010
	Total Area	4 864

[No. O-14016/314/85- G.P.]

का. आ. 5336 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन **(भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962** (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत **सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना** का. आ. सं. 2036, तारीख 11-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम:घपौरा तहसील:पिछौर जिला:शिवपुरी राज्य (मध्यप्रदेश)

अनु क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	1	3.640
2.	114	0.010
3.	5	0.637
4.	8	0.656
5.	9	0.857
6.	105	0.418
7.	104	0.031
8.	84	0.052
9.	80	0.199
10.	83	0.261
11.	91	0.136
12.	90	0.062
13.	98	0.135
14.	97	0.063
15.	81	0.010
16.	96	0.031
17.	128	0.021
18.	101	0.115
19.	173	0.157
20.	124	0.146
21.	127	0.021
22.	126	0.240
23.	125	0.105
24.	138	0.324
25.	137	0.219
26.	135	0.397
27.	134	0.294
28.	143	0.052
29.	7	0.334
योग :—कुल क्षेत्रफल		9.623

[सं. O-14016/315/85-जीपी.]

S.O. 5336.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2036 dated 11-8-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Ghapaura Tehsil : Picchore Distt. : Shivpuri

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1.	1	3.640
2.	114	0.010
3.	5	0.637
4.	8	0.656
5.	9	0.857
6.	105	0.418
7.	104	0.031
8.	84	0.052
9.	80	0.199
10.	83	0.261
11.	91	0.136
12.	90	0.062
13.	98	0.135
14.	97	0.063
15.	81	0.010
16.	96	0.031
17.	128	0.021
18.	101	0.115
19.	173	0.157
20.	124	0.146
21.	127	0.021
22.	126	0.240
23.	125	0.105
24.	138	0.324
25.	137	0.219
26.	135	0.397
27.	134	0.294
28	143	0.052
29.	7	0.334
	TOTAL AREA	9.623

[No. O-14016/315/85-G.P.]

का. आ. 5337.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2043 तारीख 11-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम सेमरी : इसागढ़ तहसील : पिछोर जिला : शिवपुरी राज्य (मध्यप्रदेश)

अनु क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	88	0.178
2.	86	0.084
3.	89	0.084
4.	102	0.010
5.	103	0.157
6.	104	0.073
7.	105	0.178
8.	107	0.010
9.	77	0.575
10.	111	0.021
11.	130	0.261
12.	131	0.031
13.	132	0.073
14.	133	0.031
15.	140	0.021
16.	135	0.105
17.	136	0.094
18.	137	0.073
19.	138	0.115
20.	139	0.052
21.	162	0.072
22.	163/1	0.157
23.	163/3	0.094
24.	173	0.031
25.	174/3	0.157
26.	174/1	0.178
27.	23	0.042
योग :	कुल क्षेत्रफल	3.157

[सं. O-14016/322/85-जी. पी.]

S.O. 5337.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2043 dated 11-5-1985 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals, Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Somari Issagarh Tehsil : Picchore Distt. : Shivpuri

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1.	88	0.178
2.	86	0.084
3.	89	0.084
4.	102	0.010
5.	103	0.157
6.	104	0.073
7.	105	0.178
8.	107	0.010
9.	77	0.575
10.	111	0.021
11.	130	0.261
12.	131	0.031
13.	132	0.073
14.	133	0.031
15.	140	0.021
16.	135	0.105
17.	136	0.094
18.	137	0.073
19.	138	0.115
20.	139	0.052
21.	162	0.272
22.	163/1	0.157
23.	163/3	0.094
24.	173	0.031
25.	174/3	0.157
26.	174/1	0.178
27.	23	0.042
	TOTAL AREA	3.157

[No. O-14016/322/85 G.P.]

का. आ. 5338.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4099 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग के अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाईप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : का छीबड़ोदा तह. : बदनावर जिला : धार राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनु क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	983	0.142
2.	994	0.275
3.	1009/2	0.248
4.	1009/1	0.510
5.	1008	0.038
6.	935/2, 1010/2, 1013/2	0.520
7.	1024	0.182
8.	1023	0.348
9.	1022	0.085
10.	1020/1	0.582
11.	1019	0.005
12.	1018/1	0.308
13.	1018/2	0.005
14.	928	0.315

1	2	3
15.	929	0.491
16.	925	0.121
17.	1031	0.032
18.	1032	0.065
19.	1033	0.181
20.	654	0.610
21.	655	0.010
22.	656	0.040
23.	659	0.020
24.	660	0.055
25.	679	0.005
26.	678	0.450
27.	677	0.015
28.	676	0.412
29.	675/1	0.310
30.	675/2	0.220
31.	667	0.040
32.	668	0.290
33.	604	0.065
34.	605	0.051
35.	603	0.201
36.	602	0.065
37.	592 593 591/1	0.575
38.	590 591/2	0.305
39.	589/2	0.115
40.	589/1	0.301
41.	588	0.091
42.	571	0.302
43.	554	0.506
44.	555/1	0.101
45.	480	0.080
46.	570	0.040
47.	479/10	0.240
48.	479/1/1	0.765
49.	479/4	0.070
50.	479/5	0.105
51.	475 476	0.261
52.	606	0.005
53.	469	0.038
54.	568	0.005
55.	664	0.735
	कुल योग क्षेत्र	11.952

[सं. O-14016/353/84-जी.पी.]

S.O. 5338.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4099 dated 1-12-84 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (i) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Kachhibaroda Tehsil : Badnawar Distt. : Dhar

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. In Hectare
1.	983	0.142
2.	994	0.275
3.	1009/2	0.248
4.	1009/1	0.510
5.	1008	0.038
6.	935/2 1010/2 1013/2	0.520
7.	1024	0.182
8.	1023	0.348
9.	1022	0.085
10.	1020/1	0.582
11.	1019	0.005
12.	1018/1	0.308
13.	1018/2	0.005
14.	928	0.315
15.	929	0.491
16.	925	0.121
17.	1031	0.032
18.	1032	0.065
19.	1033	0.181
20.	654	0.610
21.	655	0.010
22.	656	0.040
23.	659	0.020
24.	660	0.055
25.	679	0.005
26.	678	0.450
27.	677	0.015
28.	676	0.412
29.	675/1	0.310
30.	675/2	0.220
31.	667	0.040
32.	668	0.290
33.	604	0.065

1	2	3
34.	605	0.051
35.	603	0.201
36.	602	0.065
37.	592, 593, 591/1	0.575
38.	590, 591/2	0.305
39.	589/2	0.115
40.	589/1	0.301
41.	588	0.091
42.	571	0.302
43.	554	0.506
44.	555/1	0.101
45.	480	0.080
46.	570	0.040
47.	479/10	0.240
48.	479/1/1	0.765
49.	479/4	0.070
50.	479/5	0.105
51.	475, 476	0.261
52.	606	0.005
53.	469	0.038
54.	568	0.005
55.	664	0.735
	TOTAL AREA	11.952

[No. O-14016/353/84 G.P.]

का. आ. 5339.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4406 तारीख 15-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच.बी.जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम मुलथान तहसील बदनावर जिला—धार राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनुसूची

अनु क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	295	0.120
2.	302	0.153
3.	305	0.013
4.	303	0.025
5.	296	0.300
6.	301	0.013
7.	300	0.170
8.	299	0.090
9.	318	0.130
10.	317	0.050
11.	315	0.010
12.	319	0.430
13.	290	0.050
14.	281	0.460
15.	286	0.025
16.	559	0.870
17.	560	0.230
18.	561	—
19.	562	0.040
20.	563/1	0.025
21.	568	0.190
22.	569/3	0.253
23.	569/17	—
24.	569/20	0.021
25.	569/16	0.263
26.	569/24	0.521
27.	569/10	0.359
28.	569/11	0.400
29.	569/9	0.145
30.	1287/1/1	0.319
31.	1287/2	0.481
32.	1287/4	0.442
33.	1285	0.740
34.	1281	0.030
35.	1282	0.210
36.	1280	0.100
37.	1278/1	0.780
38.	1062	0.040
39.	1061/1	0.040

1	2	3
40.	1058	0.280
41.	1057	0.110
42.	1055	0.610
43.	1054	0.050
44.	1053	0.060
45.	1052	0.025
46.	1051	0.040
47.	1035/1	0.190
48.	1034	0.010
49.	1036	0.090
50.	1037	0.050
51.	1038	0.101
52.	1039	0.070
53.	1022	0.010
54.	1023/1	0.063
55.	1024/1	0.200
56.	1024/2	—
57.	1025/1	0.025
58.	1025/3	0.200
59.	1019	0.080
60.	1014	0.030
61.	1017	0.150
62.	1018	0.120
63.	982/1	0.290
64.	949/1	0.710
65.	905	0.025
66.	904	0.160
67.	903	0.240
68.	899	0.120
69.	894	0.063
70.	898	0.110
71.	2321/1	0.170
72.	2516	0.013
73.	2344	0.040
74.	2343	0.175
75.	2345	0.030
76.	2340	0.025
77.	2339	0.140
78.	2338	0.070
79.	2337	0.220
80.	2356	0.200
81.	2357	0.050
82.	2358	0.070
83.	2362	0.101
84.	2359	0.360
85.	2360	0.040
86.	2387/1	0.220
87.	2384	0.025
88.	2451	0.640
89.	2450	0.190
90.	2388	0.013
91.	2452	0.035
92.	2453	0.110
93.	2459	0.013
94.	2454	0.160
95.	2458	0.025
96.	2455	0.040
97.	2573	0.040
98.	2574	0.060
99.	2599	0.060
100.	2600	0.380
101.	2601/1	0.245
102.	2596/1	0.040
103.	2596/2	0.030
104.	2602/1	0.210
105.	2603/1	0.038
106.	2604/1	0.280
107.	2607	0.025
108.	2608/1	0.190
109.	2608/2	0.253
110.	2610	0.340
111.	2623	0.710
112.	2620	0.025
113.	2621	0.210
114.	2622	0.220
115.	2698	0.300
116.	2700	0.180
117.	289/4	0.063
118.	289/3	0.151
119.	289/5	0.025
120.	260पे.	0.228
121.	260पे.	0.151
122.	260पे.	0.076
123.	260पे.	0.025
124.	260पे.	0.114
125.	283/5	0.013
126.	283/6	0.063
127.	288/3	0.051
128.	288/8	0.076
129.	288/2	0.051
130.	288/5	0.063
131.	288/4	0.076
132.	288/7	0.063
133.	288/6	0.126

1	2	3
134.	569/1	1.075
135.	284	0.290
136.	287	0.013
137.	255	0.013
138.	545/1	0.063
139.	1050	0.013
140.	1046	0.013

कुल योग : क्षेत्रफल– 22.726

[सं. O-4016/371/84-जी. पी.]

S.O. 5339.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4406 dated 15-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this decalaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Multhan, Tehsil : Badnawar, Distric Dhar (M.P.)

S. No.	Survey No.	Area to be Acquire or R.O.U. Hectars
1	2	3
1.	295	0.120
2.	302	0.153
3.	305	0.013
4.	303	0.025
5.	296	0.300
6.	301	0.013
7	300	0.170
8.	299	0.090
9	318	0.130
10.	317	0.050
11.	315	0.010
12.	319	0.430
13.	290	0.050
14.	281	0.460
15.	286	0.025
16.	559	0.870
17.	560	0.230
18.	561	0.040
19.	562	0.040
20.	563/1	0.025
21.	568	0.190
22.	569/3	0.253
23.	569/17	—
24.	569/20	0.021
25.	569/16	0.263
26.	569/24	0.521
27.	569/10	0.359
28.	569/11	0.400
29.	569/9	0.145
30.	1287/1/1	0.319
31.	1287/2	0.481
32.	1287/4	0.442
33.	1285	0.740
34	1281	0.030
35.	1282	0.210
36.	1280	0.100
37.	1278/1	0.780
38.	1062	0.040
39.	1061/1	0.040
40.	1058	0.280
41.	1057	0.110
42.	1055	0.610
43.	1054	0.050
44.	1053	0.660
45.	1052	0.025
46.	1051	0.040
47.	1035/1	0.190
48.	1034	0.010
49.	1036	0.090
50.	1037	0.050
51.	1038	0.101
52.	1039	0.070
53.	1022	0.010
54.	1023/1	0.063
55.	1024/1	0.200
56	1024/2	—
57.	1025/1	0.025
58.	1025/3	0.200
59.	1019	0.080
60.	1014	0.030
61.	1017	0.150
62.	1018	0.120
63.	987/1	0.290
64.	949/1	0.710
65.	905	0.025
66.	904	0.160
67.	903	0.240
68.	899	0.120
69.	894	0.063
70.	898	0.110
71.	2321/1	0.170
72.	2516	0.013
73.	2344	0.040
74.	2343	0.175
75.	2345	0.030
76.	2340	0.025
77.	2339	0.140
78.	2338	0.070
79.	2337	0.220
80.	2356	0.200
81.	2357	0.050
82.	2358	0.070

1	2	3
83.	2367	0.101
84.	2359	0.360
85.	2360	0.040
86.	2387/1	0.220
87.	2384	0.025
88.	2451	0.640
89.	2450	0.190
90.	2388	0.013
91.	2452	0.035
92.	2453	0.110
93.	2459	0.013
94.	2454	0.160
95.	2458	0.025
96.	2455	0.040
97.	2573	0.040
98.	2574	0.060
99.	2599	0.060
100.	2600	0.380
101.	2601/1	0.245
102.	2596/1	0.040
103.	2596/2	0.030
104.	2602/1	0.210
105.	2603/1	0.038
106.	2604/1	0.280
107.	2607	0.075
108.	2608/1	0.190
109.	2608/2	0.253
110.	2610	0.340
111.	2613	0.710
112.	2620	0.075
113.	2621	0.210
114.	2622	0.270
115.	2698	0.300
116.	2700	0.180
117.	289/4	0.063
118.	289/3	0.151
119.	289/5	0.025
120.	260pe0	0.228
121.	260pe0	0.151
122.	260pe0	0.076
123.	260pe0	0.025
124.	260pe0	0.114
125.	283/5	0.013
126.	283/6	0.063
127.	288/3	0.051
128.	288/8	0.076
129.	288/2	0.051
130.	288/5	0.063
131.	288/4	0.076
132.	288/7	0.063
133.	288/6	0.126
134.	569/1	1.075
135.	284	0.290
136.	287	0.013
137.	255	0.013
138.	545/1	0.063
139.	1050	0.013
140.	1046	0.013
TOTAL AREA		22.726

[No. O-14016/371/84-GP]

का. आ. 5340.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का आ. सं. 3038 तारीख 21-6-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य : गुजरात जिला : सुरत तालुका : मांगरोल

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आरे	सेन्टीयर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
फुवरड़ा	338	0	05	04
	341	0	05	32
	342	0	00	30

[सं. O-14016/374/85-जीपी]

S.O. 5340.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S. O. 3038 dated 21-6-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas, the Competent Authority has, under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the

said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquires for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly –Jagdishpur

State : Gujarat Distric : Surat Taluka : Mangrol

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Kuvarda	338	0	05	04
	341	0	05	32
	342	0	00	30

[No. O-14016/374/85-GP]

का. आ. 5341.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3209 तारीख 4-7-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला पंचमहल तालुका : कालोल

गांव	सर्वे नं.	हैक्टर	आरे	सेन्टीयर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अडादरा	443	0	05	00
	439/1	0	02	00

[सं. O-14016/377/85 जी. पी.]

S.O. 5341.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3209 dated 4-7-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has, under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira to Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Adadara	443	0	05	00
	439/1	0	02	00

[No. O-14016/377/85-GP]

का. आ. 5342.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम] मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1735 तारीख 27-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गाव	गाटा संख्या	लिया गया खाता
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	इस्लाम नगर	भगवन्त नगर	260	0–15–0
				262	0–7–0
				258	0–8–0
				259	0–1–0
				256	0–1–0
				257	0–6–0
				264	0–4–0
				272	0–15–10
				273	0–1–10
				278	0–2–5
				296	0–10–0
				297	0–9–0
				29 4	0–0–10
				295	1–4–0
				279	0–1–15
				283	0–16–0
				281	0–9–5
				282	0–8–5
				284	0–15–0
				332	0–13–0
				229	0–5–0
				233	0–1–10
				334	0–1–0
				328	0–1–0
				263	1–2–0
				265	0–0–10
				271	0–0–2

[सं. O-14016/280/85-जी.पी.]

S.O. 5342.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1735 dated 27-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipeline Project:

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bisauli	Islam Nagar	Bhagwant Nagar	260	0–15–0
				262	0–7–0
				258	0–8–0
				259	0–1–0
				256	0–11–0
				257	0–6–0
				264	0–4–0
				272	0–15–10
				273	0–1–10
				278	0–2–5
				296	0–10–0
				297	0–9–0
				294	0–0–10
				295	1–4–0
				279	0–1–15
				283	0–16–0
				281	0–9–5
				282	0–8–5
				284	0–15–0
				332	0–13–0
				229	0–5–0
				233	0–1–10
				334	0–1–0
				328	0–1–0
				263	1–2–0
				265	0–0–10
				271	0–0–2

[No. O-14016/280/85-G.P.]

का. आ. 5343.—यत: पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3220 तारीख 4-7-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित रकबा एकड़
1	2	3	4	5	6
शाहजहांपुर	सदर	जामौर	हुसनपुर रसकूपा	179	08
				180	−10
				181	1−30
				217	−30
				218	−12
				219	−15
				220	−10
				229	−07
				230	−18
				232	1−45
				265	−20
				279	−25
				448	2−18
				450	1−70
				228	−03
				449	−07

[सं. O−14016/380/85 जी.पी.]

S.O. 5343.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3220 dated 4-7-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Shah jahanpur	Sadar	Jamaur	Hosanpur Raskupa	179	− 08
				180	− 10
				181	1—30
				217	− 30
				218	− 12
				219	− 15
				220	− 10
				229	− 07
				230	− 18
				232	1 45
				265	− 20
				279	− 25
				448	2 18
				450	1 70
				228	− 03
				449	− 07

[No. O—14016/380/85-G.P.]

का. आ. 5344.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3513 तारीख 17-7-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया रकबा (एकड़ में)
1	2	3	4	5	6
शाहजहांपुर	तिलहर	खेड़ाबझेड़ा	जल्लापुर	13	0-25
				14	0-60
				15	0-25
				16	0-01
				17	0-01
				18	0-70

[सं. O-14016/409/85 जी पी.]

S.O. 5344.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S. O. 3513 dated 17-7-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipeline Project

Distt.	Tehisl	Pargana	Village	Plot No.	Aera in Acres
1	2	3	4	5	6
Shah-jhanpur	Tilhar	Khera bajhera	Jallapur	13	0-25
				14	0 60
				15	0 25
				16	0 01
				17	0 01
				18	0 70

[No. O—14016/409/85 G.P.]

का. आ. 5346.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4477 तारीख 12-9-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य : गुजरात जिला : बड़ोदा तालुका : करजन

गांव	सर्वे नं.	हैक्टेयर	आरे	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
सगडोल	कोटार	0	12	00
	262	0	08	40
	264	0	73	80
	263	0	04	80
	271	0	06	00
	273	0	40	80
	274	0	07	20
	277/1	0	44	40
	280	0	22	40
	281	0	11	20
	283	0	15	60
	284/2	0	46	80
	284/3	0	00	30
	285	0	39	60
	319	0	39	60
	318	0	32	40

1	2	3	4	5
	320	0	61	20
	324	0	13	20
	323	0	12	00
	326	0	07	20
	329	0	18	00
	332	0	00	30
	331	0	03	60
	330	0	14	40

[सं. O-14016/489/85-जी०पी०]

S.O. 5345.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4477 dated 12-9-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From Hajira-Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Sagdol	Kotar	0	12	00
	262	0	08	40
	264	0	73	80
	263	0	04	80
	271	0	06	00
	273	0	40	80
	274	0	07	20
	277/1	0	44	40
	280	0	22	40
	281	0	11	20
	283	0	15	60
	284/2	0	46	80
	284/3	0	00	30
	285	0	39	60
	319	0	39	60
	318	0	32	40
	320	0	61	20
	324	0	13	20
	323	0	12	00
	326	0	07	20
	329	0	18	00
	332	0	00	30
	331	0	03	60
	330	0	14	40

[No. O-14016/489/85-G.P.]

का. आ. 5346.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4478 तारीख 12-9-1985 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य : गुजरात जिला : बड़ोदा तालुका : करजन

गाँव	सर्वे नं.	हैक्टेयर	आरे.	सेन्टीयर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मालोद	11	0	37	50
	13	0	13	50
	14	0	10	20
	113	0	01	40
	23	0	43	50
	26	0	01	20
	27/1	0	34	50
	27/2	0	12	00
	27	0	02	10

1	2	3	4	5
	27/3	0	18	00
	106	0	18	00
	37	0	24	00
	36	0	49	20
	40	0	06	00
	41	0	73	20
	46	0	04	50
	45	0	27	60
	58	0	32	40
	57	0	41	80
	60	0	01	20
	कार्टट्रेक	0	08	40

[सं. O-14016/490/85-जी. पी.]

S.O. 5346.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4478 dated 12-9-85 under sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas authority of India Ltd., free from encumbrances.

SCHEDULE

peline From Hajira-Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Malod	11	0	37	50
	13	0	13	50
	14	0	10	20
	113	0	01	40
	23	0	43	50
	26	0	01	20
	27/1	0	34	50
	27/2	0	12	00
	27	0	02	10
	27/3	0	18	00
	106	0	18	00
	37	0	24	00
	36	0	49	20
	40	0	06	00
	41	0	73	20
	46	0	04	50
	45	0	27	60
	58	0	32	40
	57	0	41	80
	60	0	01	20
	Cart track	0	08	40

[No. O—14016/490/85-G.P.]

का. आ. 5347.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4479 तारीख 12-9-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : अंकलेश्वर

गांव	ब्लाक नं.	हैक्टेयर	आरे	सेन्टीयर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पिपरोड	105	0	26	40
	97	0	43	20
	106	0	51	52
	110	0	20	48
	111	0	00	50
	107	0	00	30
	108	0	55	68
	109	0	11	52

[सं. O-14016/491/85-जी. पी.]

S.O. 5347.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4479 dated 12-9-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From Hajira-Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Ankleshwar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Piprod	105	0	26	40
	97	0	43	20
	106	0	51	52
	110	0	20	48
	111	0	00	50
	107	0	00	30
	108	0	55	68
	109	0	11	52

[No. O—14016/491/85-G.P.]

का. आ. 5348—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 4480 तारीख 12-9-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा;

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : झगड़िया

गांव	सर्वे नं.	हैक्टेयर	आरे	सेन्टीयर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कपल सदी	124	0	25	50
	123	0	24	00
	119	0	22	50
	120	0	09	00
	107	0	15	00
	कार्टट्रेक	0	03	00
	135	0	36	50
	136	0	67	50
	139	0	82	50
	99	0	21	00
	100	0	16	50
	69	0	30	00
	68	0	11	25

[सं. O—14016/492/85—जी० पी०]

S.O. 5348.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4480 dated 12-9-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From Hajira-Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Zaghadiya

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Kapalsadi	124	0	25	50
	123	0	24	00
	119	0	22	50
	120	0	09	00

1	2	3	4	5
	107	0	15	00
	Cart track	0	03	00
	135	0	36	50
	136	0	67	50
	139	0	82	50
	99	0	21	00
	100	0	16	50
	69	0	30	00
	68	0	11	25

[No. O—14016/492/85-G.P.]

का. आ. 5349.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4481 तारीख 12-9-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य : गुजरात जिला : बड़ोदा तालुका : करजन

गांव	ब्लाक नं.	हैक्टेयर	आरे	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
मोटी कोरल	118	0	51	30
	117	0	17	10
	120	0	28	80
	121	0	10	50
	122	0	21	00
	123	0	18	50
	115	0	10	00
	कार्ट ट्रेक	0	03	60
	192	0	13	20
	190	0	03	30
	191	0	11	25
	कार्ट ट्रेक	0	06	00
	206	0	20	40
	207	0	12	00
	275	0	24	00
	280	0	48	00
	279	0	14	40
	278	0	25	12

[सं. O-14016/493/85-जी०पी०]

S.O. 5349.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4481 dated 12-9-1985 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submited report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From Hajira-Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Moti Koral	118	0	51	30
	117	0	17	10
	120	0	28	80
	121	0	10	50
	122	0	21	00
	123	0	18	50
	115	0	10	00
	Cart track	0	03	60
	192	0	13	20
	190	0	03	30
	191	0	11	25
	Cart track	0	06	00
	206	0	20	40
	207	0	12	00
	275	0	24	00
	280	0	48	00
	279	0	14	40
	278	0	25	12

[No. O-14016/493/85 G.P.]

का. आ. 5350.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4482, तारीख 12-9-1985 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी ;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य गुजरात जिला : भरुच तालुका : झगड़िया

गांव	ब्लाक नं.	हैक्टेयर	आरे.	सैन्टीयर
1	2	3	4	5
वाघापुरा.	275	0	36	00
	274	0	35	05
	278	0	25	45
	279	0	16	80
	280	0	38	40
	281	0	09	60
	252	0	21	60
	251	0	24	00
	309	0	14	40
	310	0	20	40
	312	0	05	76
	311	0	13	20
	303	0	48	00
	302	0	30	00
	301	0	08	40
	6	0	20	40
	12	0	18	00
	कार्टट्रेक	0	01	80
	36	0	32	00
	32	0	01	60
	35	0	16	80
	34	0	31	20

[सं. O-14016/494/85-जी.पी.]

S.O. 5350.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4482 dated 12-9-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has, under Subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by subsection (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall, instead of vesting in Central Government, vests on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From Hajira-Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Zaghadiya

Village	Block No.	Hectare	Are	Centaire
1	2	3	4	5
Vaghpura	275	0	36	00
	274	0	35	05
	278	0	25	45
	279	0	16	80
	280	0	38	40
	281	0	09	60
	252	0	21	60
	251	0	24	00
	309	0	14	40
	310	0	20	40
	312	0	05	76
	311	0	13	20
	303	0	48	00
	302	0	30	00
	301	0	08	40
	6	0	20	40
	12	0	18	00
	Cart track	0	01	80
	36	0	32	00
	32	0	01	60
	35	0	16	80
	34	0	31	20

[No. O-14016/494/85-G.P.]

का.आ. 5351 :—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4483, तारीख 12-9-1985 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : झगड़ीया

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे	सेंटीयर
1	2	3	4	5
वंधेवाल	कोटार	0	15	00
	153	0	54	00
	134	0	28	50
	151	0	25	50
	150	0	30	00
	149	0	22	50
	148	0	02	00
	147	0	52	00
	144	0	19	50
	145	0	43	50
	गमतल	0	27	75
	184	0	00	50
	7	0	09	75
	6	0	02	50
	5	0	20	50
	3	0	00	75
	2	0	02	50
	कार्ट ट्रक	0	06	00
	1	0	02	50
	204	0	57	00
	203	0	22	00
	23	0	09	75

[सं. O-14016/495/85-जी.पी.]

S.O. 5351.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4483 dated 12-9-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall, instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From Hajira-Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Zaghadiya

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Vantheval	Kotar	0	15	00
	153	0	54	00
	134	0	28	50
	151	0	25	50
	150	0	30	00
	149	0	22	50
	148	0	02	00
	147	0	52	00
	144	0	19	50
	145	0	43	50
	Gamtal	0	27	75
	184	0	00	50
	7	0	09	75
	6	0	02	50
	5	0	20	50
	3	0	00	75
	2	0	02	50
	Cart track	0	06	00
	1	0	02	50
	204	0	57	00
	203	0	22	00
	23	0	09	75

[No. O-14016/495/85-G.P.]

का. आ. 5352.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4484, तारीख 12-9-1985 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार से निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य : गुजरात जिला: भरुच तालुका : झगड़ीया

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे०	सेंटीयर
1	2	3	4	5
सुल्तानपुर	364	0	22	50
	363/ए	0	39	00
	365	0	00	50
	361	0	14	50
	कार्ट ट्रेक	0	06	00
	398	0	14	62
	397	0	00	30
	399	0	28	50
	400	0	24	00
	407	0	32	00
	408	0	03	00
	406	0	34	00
	405	0	15	00
	कार्ट ट्रेक	0	07	50
	421	0	04	50
	513	0	20	25
	512	0	06	75
	511	0	27	75
	510	0	37	00
	514	0	08	00
	508	0	39	00
	कोटार	0	13	50
	505	0	25	50
	498	0	25	50
	499	0	18	00
	504	0	01	00
	500	0	30	00
	472	1	06	50
	478	0	06	00

[सं. O—14016/496/85-जी.पी.]

S.O. 5352.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4484 dated 12-9-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From Hajira-Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Zaghadiya

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Sultanpur	364	0	22	50
	363/A	0	39	00
	365	0	00	50
	361	0	14	50
	Cart track	0	06	00
	398	0	14	62
	397	0	00	30
	399	0	28	50
	400	0	24	00
	407	0	32	00
	408	0	03	00
	406	0	34	00
	405	0	15	00
	Cart track	0	07	50
	421	0	04	50
	513	0	20	25
	512	0	06	75
	511	0	27	75
	510	0	37	00
	514	0	08	00

1	2	3	4	5
	508	0	39	00
	Kotar	0	13	50
	505	0	25	50
	498	0	25	50
	499	0	18	00
	504	0	01	00
	500	0	30	00
	472	1	06	50
	478	0	06	00

[No. O-14016/496/85-G.P.]

का. आ. 5353.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4485, तारीख 12-9-1985 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य : गुजरात जिला : बड़ौदा तालुका : करजन

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आरे	सेंटीयर
1	2	3	4	5
पुरा	367	0	09	60
	कार्ट ट्रेक	0	03	60
	365	0	04	50
	366	0	10	80
	368	0	10	80
	369	0	15	00
	362	0	12	60
	372	0	01	00
	373	0	23	00
	356	0	03	00
	355	0	10	80
	353	0	12	00
	352	0	06	00
	351	0	04	80
	350	0	06	00
	349	0	04	80
	348	0	05	10
	344	0	02	70
	343	0	12	00
	337	0	00	48
	336	0	02	22
	293	0	18	00
	291	0	05	05
	290	0	03	00

[सं. O-14016/497/85-जी.पी.]

S.O. 5353.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4485 dated 12-9-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From Hajira-Barcilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Pura	367	0	09	60
	Cart track	0	03	60
	365	0	04	50
	366	0	10	80
	368	0	10	80
	369	0	15	00
	362	0	12	60

1	2	3	4	5
	372	0	01	00
	373	0	23	00
	356	0	03	00
	355	0	10	80
	353	0	12	00
	352	0	06	00
	351	0	04	80
	350	0	06	00
	349	0	04	80
	348	0	05	10
	344	0	02	70
	343	0	12	00
	337	0	00	48
	336	0	02	22
	293	0	18	00
	291	0	05	05
	290	0	03	00

[No. O—14016/497/85-G.P.]

का. आ. 5354.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 4486 तारीख 12-9-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य : गुजरात जिला : वड़ोदा तालुका : करजन

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आरे	सेंटीयर
1	2	3	4	5
वेमार	312	0	07	50
	311	0	33	60
	305	0	01	68
	306	0	34	80
	294	0	33	00
	287	0	54	00
	282	0	04	40
	286	0	29	20
	कार्ट ट्रेक	0	02	40
	256	0	13	50
	263	0	42	00
	264	0	12	80
	241	0	12	80
	242	0	30	80
	243	0	36	00
	244	0	18	00
	229	0	34	80
	230	0	01	00
	228	0	09	60
	215	0	01	50
	216	0	31	80
	212	0	46	08
	213	0	01	92
	203	0	10	80
	204	0	27	36
	202	0	06	00
	201	0	13	60
	200	0	18	00
	197	0	48	00
	199	0	18	20
	198	0	14	08
	कंस	0	19	20
	138	0	21	20
	139	0	10	24
	कंस	0	12	80
	137	0	18	00

[सं. O-14016/498/85-जी.पी.]

S.O. 5354.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 4486 dated 12-9-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
VEMAR	312	0	07	50
	311	0	33	60
	305	0	01	68
	306	0	34	80
	307	0	30	00
	294	0	33	00
	287	0	54	00
	282	0	04	40
	286	0	29	20
	Cart track	0	02	40
	256	0	13	50
	263	0	42	00
	264	0	12	80
	241	0	12	80
	242	0	30	80
	243	0	36	00
	244	0	18	00
	229	0	34	80
	230	0	01	00
	228	0	09	60
	215	0	01	50
	216	0	31	80
	212	0	46	08
	213	0	01	92
	203	0	10	80
	204	0	27	36
	202	0	06	00
	201	0	13	60
	200	0	18	00
	197	0	48	00
	199	0	18	20
	198	0	14	08
	Kans	0	19	20
	138	0	21	20
	139	0	10	24
	Kans	0	12	80
	137	0	18	00

[No. O-14016/493/85-GP]

का. आ. 5355.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4487, तारीख 12-9-1985 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : झगड़ीया

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेंटीयर
1	2	3	4	5
अविधा	1013	0	15	00
	1014	0	10	25
	1091	0	15	00
	1092	0	08	05
	1093	0	18	00
	1096	0	48	00
	1097	0	18	00
	1098	0	15	00
	1099	0	04	10
	1100	0	10	00
	कार्ट ट्रेक	0	02	40
	1115	0	35	10
	1116	0	19	50
	1120	0	16	50
	1121	0	15	00
	1122	0	22	50
	1132	0	18	00
	1131	0	25	10

1	2	3	4	5
	1129	0	01	00
	1150	0	21	00
	1151	0	04	80
	1149	0	04	80
	1152	0	15	00
	कोटार	0	08	40
	159	0	24	60
	152	0	48	00
	153–154–155	0	03	00
	151	0	07	50
	150	0	09	00
	175	0	09	00
	184	0	21	00
	182	0	05	00
	183/ए	0	09	35
	181	0	16	50
	कार्ट ट्रेक	0	05	10
	233	0	33	00
	66	0	00	75
	65	0	12	60
	64	0	39	60
	63	0	02	40
	61	0	45	00
	356	0	01	20
	60	0	01	20
	कार्ट ट्रेक	0	01	00
	366	0	18	00
	365	0	19	50
	364	0	08	05
	377	0	08	00
	378	0	25	50
	379	0	21	00
	381	0	19	50
	382	0	01	92
	383	0	39	00
	392	0	00	20
	389	0	30	00

[सं. O–14016/499/85-जी.पी.]

S.O. 5355.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4487 dated 12-9-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat; District : Bharuch; Taluka : Zaghadiya

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
AVIDHA	1013	0	15	00
	1014	0	10	25
	1091	0	15	00
	1092	0	08	05
	1093	0	18	00
	1096	0	48	00
	1097	0	18	00
	1098	0	15	00
	1099	0	04	10
	1100	0	10	00
	Cart track	0	02	40
	1115	0	35	10
	1116	0	19	50
	1120	0	16	50
	1121	0	15	00
	1122	0	22	50
	1132	0	18	00
	1131	0	25	10
	1129	0	01	00
	1150	0	21	00
	1151	0	04	80
	1149	0	04	80
	1152	0	15	00
	Kotar	0	08	40
	158	0	24	60
	152	0	48	00
	153+154+155	0	03	00
	151	0	07	50
	150	0	09	00
	175	0	09	00
	184	0	21	00
	182	0	05	00
	183/A	0	09	35
	181	0	16	50
	Cart Track	0	05	10
	233	0	33	00
	66	0	00	75
	65	0	12	60
	64	0	39	60
	63	0	02	40
	61	0	45	00
	356	0	01	20
	60	0	01	20
	Cart Track	0	01	00
	366	0	18	00
	365	0	19	50
	364	0	08	05
	377	0	08	00
	378	0	25	50
	279	0	21	00

1	2	3	4	5
	381	0	19	50
	382	0	01	92
	383	0	39	00
	392	0	00	20
	389	0	30	00

[No. O-14016/499/85-G.P.]

का. आ. 5356.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4488 तारीख 12-9-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : झगड़ीया

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे०	सेंटीयर
1	2	3	4	5
जरसद	100	0	12	00
	99	0	48	00
	97	0	37	50
	124	0	40	50
	125	0	10	00
	41	0	21	50
	128	0	33	00
	130	0	39	00
	131	0	10	50
	132	0	15	60
	133	0	08	75
	कोटार	0	07	50
	182	0	11	10
	185	0	11	00
	186	0	34	80
	190	0	30	00
	191	0	00	50
	188	0	03	75
	कोटार	0	18	00
	234	0	14	45
	237	0	14	45
	235	0	10	50
	230	0	06	00
	229	0	38	10
	228	0	03	90
	224	0	13	50
	222	0	22	50
	210	0	27	00
	215	0	01	00
	217	0	00	50

[सं. O-14016/500/85-जी.पी.]

S.O. 5356.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4488 dated 12-9-1985 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Barellly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Zaghadiya

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
JARSAD	100	0	12	00
	99	0	48	00
	97	0	37	50
	124	0	40	50
	125	0	10	00
	41	0	21	50

1	2	3	4	5
	128	0	33	00
	130	0	39	00
	131	0	10	50
	132	0	15	60
	133	0	08	75
	Kotar	0	07	50
	182	0	11	10
	185	0	11	00
	186	0	34	80
	190	0	30	00
	191	0	00	50
	188	0	03	75
	Kotar	0	18	00
	234	0	14	45
	237	0	14	45
	235	0	10	50
	230	0	0(	00
	229	0	38	10
	228	0	03	90
	224	0	13	50
	222	0	22	50
	210	0	27	00
	215	0	01	00
	217	0	00	50

[No. O-14016/500/85-GI]

का. आ. 5357.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4489 तारीख 12-9-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : अंकलेश्वर

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे	सेंटीयर
1	2	3	4	5
उवारदर	250	0	40	80
	177	0	48	00
	175	0	40	80
	173	1	12	80
	कोटार	0	21	60
	158	0	16	80
	161	0	07	20
	160	0	08	40
	162	0	24	00
	163	0	16	80
	167	0	48	00
	131	0	48	00
	130	0	26	40
	129	0	24	00
	31	0	40	80
	32	0	14	40
	33	0	12	00
	34	0	88	80
	35	0	33	60
	127	0	03	00
	45	0	12	00
	86	0	45	60
	कोटार	0	04	80
	85	0	39	60
	79	0	09	60
	88	0	26	40

[सं. O-14016/501/85-जीपी.]

S.O. 5357.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4489 dated 12-9-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby, declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the

right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Ankleshwar

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
	2	3	4	5
Uvadar	250	0	40	80
	177	0	48	00
	175	0	40	80
	173	1	12	80
	Kotar	0	21	60
	158	0	16	80
	161	0	07	20
	160	0	08	40
	162	0	24	00
	163	0	16	80
	167	0	48	00
	131	0	48	00
	130	0	26	40
	129	0	24	00
	31	0	40	80
	32	0	14	40
	33	0	12	00
	34	0	88	80
	35	0	33	60
	127	0	03	00
	45	0	12	00
	86	0	45	60
	Kotar	0	04	80
	85	0	39	60
	79	0	09	60
	88	0	26	40

[No. O-14016/501/85-GP]

का. आ. 5358.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं 4491 तारीख 12-9-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : झगड़िया

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे	सेंटीयर
1	2	3	4	5
भालोद	661	0	22	50
	660	0	00	30
	663	0	21	00
	664	0	27	00
	कार्ट ट्रेक	0	03	00
	743	0	26	50
	742	0	00	50
	746	0	12	00
	747	0	13	50
	741	0	58	50
	740	0	45	50
	739	0	01	00
	कार्ट ट्रेक	0	56	25
	720	0	10	50
	719	0	16	50
	718	0	15	75
	717	0	12	00
	707	0	01	50
	706	0	34	50
	924	0	40	50
	कार्ट ट्रेक	0	04	50
	919	0	29	25
	929	0	03	75
	918	0	60	00
	कार्ट ट्रेक	0	01	80
	13	0	22	50
	12	0	22	50
	30	0	02	62
	31	0	27	00
	29	0	13	50
	कार्ट ट्रेक	0	09	00
	168/2	0	13	50
	167	0	08	00
	943	0	24	00

1	2	3	4	5
	कार्ट ट्रेक	0	03	00
	36	0	24	00
	38	0	03	00
	39	0	04	50

[सं. O-14016/503/85-जी.पी.]

S.O. 5358.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4491 dated 12-9-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby, declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Zaghadiya

Stage	Survey No.	Hectare	Area Centiare
	2	3	4	5
Bhalod	661	0	22	50
	660	0	00	30
	663	0	21	00
	664	0	27	00
	Cart track	0	03	00
	743	0	26	50
	742	0	00	50
	746	0	12	00
	747	0	13	50
	741	0	58	50
	740	0	45	50
	739	0	01	00
	Cart track	0	56	25
	720	0	10	50
	719	0	16	50
	718	0	15	75
	717	0	12	00
	707	0	01	50
	706	0	34	50
	924	0	40	50
	Cart track	0	04	50
	919	0	29	25
	929	0	03	75
	918	0	60	00
	Cart track	0	01	80
	13	0	22	50
	12	0	22	50
	30	0	02	62
	31	0	27	00
	29	0	13	50
	Cart track	0	09	00
	168/2	0	13	50
	167	0	08	00
	943	0	24	00
	Cart track	0	03	00
	36	0	24	00
	38	0	03	00
	39	0	04	50

[No. O-14016/503/85-GP]

का. आ. 5359.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4492 तारीख 12-9-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : झगड़िया

गांव	सर्वे नं.	हैक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
रून्ड	कार्ट ट्रैक	0	04	50
	422	0	24	00
	423	0	00	50
	431	0	16	50
	432	0	10	50
	433	0	06	00
	434	0	01	00
	440	0	30	00
	435	0	12	00
	437	0	04	40
	438	0	13	50
	455	0	18	00
	454	0	07	00
	453	0	07	00
	452	0	18	00
	451	0	18	00

[सं. O-14016/504/85-जी. पी.]

S.O. 5359.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4492 dated 12-9-1985 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Baruch Taluka : Zaghadiya

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Rundh	Cart track	0	04	50
	422	0	24	00
	423	0	00	50
	431	0	16	50
	432	0	10	50
	433	0	06	00
	434	0	01	00
	440	0	30	00
	435	0	12	00
	437	0	04	40
	438	0	13	50
	455	0	18	00
	454	0	07	00
	453	0	07	00
	452	0	18	00
	451	0	18	00

[No. O-14016/504/85-GP]

का. आ. 5360 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4493 तारीख 12-9-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य : गुजरात जिला : बड़ौदा तालुका : करजन

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
कहोणा	248	0	18	00
	249	0	42	00
	250	0	21	60
	253	0	17	20
	252	0	17	54
	254	0	21	80
	255	0	36	00
	256	0	11	40

1	2	3	4	5
	257	0	13	20
	260	0	31	20
	258	0	04	20
	259	0	04	20
	263	0	21	92
	264	0	01	60
	265	0	00	64
	266	0	02	24
	267	0	03	20
	268	0	24	40
	कार्ट ट्रेक	0	08	40
	58	0	66	00
	कार्ट ट्रेक	0	03	60

[सं. O-14016/505/85-जी. पी.]

S.O. 5360.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4493 dated 12-9-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Kamona	248	0	18	00
	249	0	42	00
	250	0	21	60
	253	0	17	20
	252	0	17	54
	254	0	21	80
	255	0	36	00
	256	0	11	40
	257	0	13	20
	260	0	31	20
	258	0	04	20
	259	0	04	20
	263	0	21	92
	264	0	01	60
	265	0	00	64
	266	0	02	24
	267	0	03	20
	268	0	24	40
	Cart track	0	08	40
	58	0	66	00
	Cart track	0	03	60

[No. O-14016/505/85-GP]

का.आ. 5361—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 4494 तारीख 12-9-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग के अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य : गुजरात जिला : पंचमहल तालुका : लोम खेड़ा

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
घुटिया	29	0	11	00
	38/पी	0	04	50

[सं O-14016/506/85-जी. पी.]

S.O. 5361.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4494 dated 12-9-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (I) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands, shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hazira Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Limkheda

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
GHUTIYA	29	0	11	00
	38/P	0	04	50

[No. O-14016/506/85-GP]

का. आ. 5362.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4495 तारीख 12-9-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य : गुजरात जिला : पंचमहल तालुका : दहोद

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेन्टीयर
कठला	45	0	02	90
	211	0	10	84
	212	0	15	69

[सं. O-14016/507/8 5-जी.पी.

S.O. 5362.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4495 dated 12-9-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Dahod

Village	Block No.	Hectare	Are	Centi-are
KATHALA	45	0	02	90
	211	0	10	84
	212	0	15	69

[No. O-14016/507/85 G.P.]

का. आ. 5063.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4496 तारीख 12-9-1985 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : अंकलेश्वर

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेन्टीयर
करारवेल	305	0	19	20
	15	0	16	64
	306	0	14	40
	302	0	00	80
	301	0	64	80
	307	0	40	80
	294	0	00	80
	292	0	40	80
	293	0	24	00

[सं. O-14016/503/85-जी. पी.]

S.O. 5363.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4496 dated 12-9-1985 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira Bar illy to Jagdishpur

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Ankleshwar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
KARARVEL	305	0	19	20
	15	0	16	64
	306	0	14	40
	302	0	00	30
	301	0	64	80
	307	0	40	80
	294	0	00	80
	292	0	40	80
	293	0	24	00

[No. O-14016/508/85-G.P.]

का०आ० 5364.— यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ०सं० 4497 तारीख 12-9-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य : गुजरात जिला : बड़ौदा तालुका : करजन

गांव	ब्लाक नं.	हैक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
आलमपुर	150	0	24	00
	149	0	02	00
	148	0	22	20
	146	0	20	40
	145	0	14	40
	142	0	26	20
	141	0	00	47
	163	0	14	20
	140	0	06	12
	139	0	00	64
	162	0	04	50
	165	0	09	00

[सं. O-14016/509/85-जी. पी.]

S.O. 5364.—Whereas by notification or the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4497 dated 12-9-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira Barcilly to Jagdishpur

State : Gujarat District: Vadodara Taluka : Karjan

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Alampur	150	0	24	00
	149	0	02	00
	148	0	22	20
	146	0	20	40
	145	0	14	40
	142	0	26	20
	141	0	00	47
	163	0	14	20
	140	0	06	12
	139	0	00	64
	162	0	04	50
	165	0	09	00

[No. O-14016/509/85-G.P.]

का. आ. 5365.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4498 तारीख 12-9-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य : गुजरात जिला : बड़ौदा तालुका : करजन

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेन्टीयर
लिलोड	कार्ट ट्रेक	0	08	40
	92	0	10	80
	93	0	16	20

1	2	3	4	5
लिलोड—(जारी)	94	0	14	40
	86	0	38	40
	86/1	0	31	20
	82/2	0	00	30
	कार्ट ट्रेक	0	04	80

[सं. O-14016/510/85-जी. पी.]

S.O. 5365.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4498 dated 12-9-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines [Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962)] the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notifiction for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification,

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira – Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
LILOD	Cart track	0	08	40
	92	0	10	80
	93	0	16	20
	94	0	14	40
	86	0	38	40
	86/1	0	31	20
	86/2	0	00	30
	Cart track	0	04	80

[No. O-14016/510/85-G.P.]

का. आ. 5366.—यत : पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4499 तारीख 12-9-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : अंकलेश्वर

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
जीतालो	517	0	40	80
	520	0	21	60
	518	0	11	52
	519	0	50	40
	528	0	24	00
	565	0	33	60
	567	0	19	20
	573	0	15	36
	574	0	69	60
	575	0	52	80

[सं. O-14016/511/85-जी. पी.]

S.O. 5366.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4499 dated 12-9-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines [Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962)] the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira Barelly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Ankleshwar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centi-are
JITALI	517	0	40	80
	520	0	21	60
	518	0	11	52
	519	0	50	40
	5.8	0	24	00
	565	0	33	60
	567	0	19	20
	573	0	15	36
	574	0	69	60
	575	0	52	80

[No. O-14016/511/85-GP]

का. आ. 5367.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4500 तारीख 12-9-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : झगड़ीया

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
फुलवाड़ी	117	0	19	50
	कार्ट ट्रेक	0	03	00
	109	0	16	50
	111	0	20	25
	107	0	04	50
फुलवाड़ी (जारी)	105	0	50	00
	104	0	00	50
	106	0	00	50
	58	0	07	50
	59	0	37	50
	60	0	07	00
	61	0	39	00
	62	0	34	50
	64	0	27	00
	65	0	18	00
	69	0	00	50
	68	0	18	00
	67	0	3	00
	कार्ट ट्रेक	0	03	00
	365	0	21	80
	370	0	08	70
	369	0	28	00
	368	0	09	00
	552	0	39	00
	545	0	37	50
	554	0	33	00
	539	0	33	00
	540	0	28	50
	534	0	28	50
	535	0	09	00
	532	0	21	00
	509	0	31	50
	497	0	29	50
	513	0	05	25
	514	0	22	50
	496	0	22	50
	495	0	24	00
	कार्ट ट्रेक	0	03	00
	491	0	51	00
	490	0	01	00
	492	0	07	50
	कार्ट ट्रेक	0	03	00
	454/पी	0	48	00
	456	0	30	00
	कोटार	0	39	00

[सं. O-14016/512/85-जी. पी.]

S.O. 5367.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4500 dated 12-9-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines [Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962)] the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notifiction for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira Bardilly to Jadishpur

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Zaghadiya

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
FULWADI	117	0	19	50
	Cart track	0	03	00
	109	0	16	50
	111	0	20	25
	107	0	04	50
	105	0	50	00
	104	0	00	50
	106	0	00	50
	58	0	07	50
	59	0	37	50
	60	0	07	00
	61	0	39	00
	62	0	34	50
	64	0	27	00
	65	0	18	00
	69	0	00	50
	68	0	18	00
	67	0	3	00
	Cart track	0	03	00
	365	0	21	80
	370	0	08	70
	369	0	28	00
	368	0	09	00
	552	0	39	00
	545	0	37	50
	554	0	33	00
	539	0	33	00
	540	0	28	50
	534	0	28	50
	535	0	09	00
	532	0	21	00
	509	0	31	30
	497	0	29	50
	513	0	05	25
	514	0	22	50
	496	0	22	50
	495	0	24	00
	Cart track	0	03	00
	491	0	51	00
	490	0	01	00
	492	0	07	50
	Cart track	0	03	00
	454/P	0	48	00
	456	0	30	00
	Kotar	0	39	00

[No. O-14016/512/85-G.P.]

का. आ. 5368.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4501 तारीख 12-9-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य : गुजरात जिला : बड़ौदा तालुका : करजन

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
फतेपुर	191	0	94	80
	192/1	0	30	00
	कार्ट ट्रेक	0	06	00
	167	0	93	60
	169/1	0	12	48
	169/2	0	16	64
	137	0	60	00
	135	0	09	00
	130	0	12	92
	128	0	18	00
	123	0	05	40
	127	0	45	60
	124	0	31	20
	कार्ट ट्रेक	0	08	40
	73	0	32	40
	74	0	19	20
	75	0	44	40
	कार्ट ट्रेक	0	10	80
	49	0	92	40
	50	0	51	60
	कार्ट ट्रेक	0	04	80

[सं. O-14016/512/85-जी.पी. 1

S.O. 5368.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4501 Dated 12-9-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962)] the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira Bareilly to Jagdishpur
State : Gujarat District : Vadodra Taluka : Karjan

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
FATEPUR	191	0	94	80
	192/1	0	30	00
	Cart track	0	06	00
	167	0	93	60
	169/1	0	12	48
	169/2	0	16	64
	137	0	60	00
	135	0	09	00
	130	0	12	92
	128	0	18	00
	123	0	05	40
	127	0	45	60
	124	0	31	20
	Cart track	0	08	40
	73	0	32	40
	74	0	19	20
	75	0	44	40
	Cart track	0	10	80
	49	0	92	40
	50	0	51	60
	Cart track	0	04	80

[No. O-14016/513//85-G.P.]

का. आ. 5369—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4502 तारीख 12-9-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर
राज्य : गुजरात जिला : सूरत तालुका : मांगरोल

गांव	ब्लाक नं	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
बोरोद्रा	173	0	07	20
	174	0	20	40
	175	0	44	40
	185	0	84	60
	179	0	05	40
	192	0	54	00
	183	0	05	40
		0	04	80
	192	0	26	40
	191	0	42	00
	194	0	66	00
	195	0	18	00
	197	0	30	00
	198	0	21	00
	196	0	30	00

[सं. O-14016/514/85-जी.पी.]

S.O. 5369.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4502 Date 12-9-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines [Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962)] the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hijra—Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Surat Taluka : Mangrol

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
BORIDRA	173	0	07	20
	174	0	20	40
	175	0	44	40
	185	0	84	60
	179	0	05	40
	19?	0	54	00
	183	0	05	40
	Cart track	0	04	80
	19?	0	?6	40
	191	0	4?	00
	194	0	66	00
	195	0	18	00
	197	0	30	00
	198	0	?1	00
	196	0	30	00

[No. O-14018/514/85-G.P.]

का. आ. 5370.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4503 तारीख 12-9-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और, यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य : गुजरात जिला : सूरत तालुका : मांगरोल

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
बकापुर	106	0	28	80
	कार्ट ट्रेक	0	04	80
	71	0	63	60
	70	0	59	20
	75	0	01	60
	68	0	21	60
	67	0	13	20
	66	0	13	20

[सं. O-14016/515/85-जी.पी.]

S.O. 5370.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4503 Dated 12-9-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines [Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962)] the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notifiction for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
BAKAPUR	106	0	?8	80
	Cart track	0	04	80
	71	0	63	60
	70	0	59	?0
	75	0	01	60
	68	0	21	60
	67	0	13	?0
	66	0	13	?0

[No. O-14016/515/85-GP]

का. आ. 5371.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4504 तारीख 12-9-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 के उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य :— गुजरात जिला :— बड़ौदा तालुका :—करजन

गांव	ब्लोक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
सिमली	153	0	34	80
	152	0	09	60
	154	0	24	00
	147	0	00	80
	21	0	04	40
	22	0	19	20
	24	0	24	00
	25	0	32	40
	30	0	03	20
	27	0	24	40
	29	0	28	80
	33	0	30	00
	34	0	03	72
	कार्ट ट्रेक	0	02	40
	136	0	30	00
	कार्टट्रेक	0	04	80
	94	0	19	20
	95	0	11	30
	84	0	30	00
	92	0	24	00
		0	03	60
	47	0	26	40
	48	0	28	80
	49	0	12	00
	50	0	14	40
	52	0	08	80
	749	0	45	60
	756	0	26	80
	5	0	08	00
	141	0	31	12
	76	0	10	88
	206	0	09	00
	276	0	10	20
	320	0	18	60
	408	0	27	60
	कार्ट ट्रेक	0	06	00
	687	0	37	20
	719	0	33	60
	718	0	7	00
	723	0	19	80
	712	0	06	60

[सं० O-14016/516/85-जी.पी.]

S.O. 5371.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4504 daetd 12-9-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines and [Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962)] the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
SIMALI	153	0	34	80
	152	0	09	60
	154	0	24	00
	147	0	00	80
	21	0	04	40
	22	0	19	20
	24	0	24	00
	25	0	37	40
	30	0	03	20
	27	0	24	40
	29	0	28	80
	33	0	30	00
	34	0	03	72
	Cart track	0	02	40
	136	0	30	00
	Cart track	0	04	80
	94	0	19	20
	95	0	11	30
	84	0	30	00
	92	0	24	00
	Cart track	0	03	60
	47	0	26	40
	48	0	28	80
	49	0	12	00
	50	0	14	40
	52	0	08	80
	749	0	45	60
	756	0	26	80
	5	0	08	00
	141	0	31	12
	76	0	10	88
	206	0	09	00
	276	0	10	20
	320	0	18	60
	408	0	27	60
	Cart track	0	06	00
	687	0	37	20
	719	0	33	60
	718	0	27	00
	723	0	19	80
	712	0	06	60

[No. O-14016/516/85 GP]

का. आ. 5372.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4505, तारीख 12-9-1985 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य : गुजरात जिला : बड़ौदा तालुका : करजन

गांव	सर्वे नं.	हैक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
कोठाव	50	0	14	00
	55	0	04	80

[सं. O-14016/517/85-जी. पी.]

S.O. 5372.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4505 dated 12-9-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notifiction for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notifiication.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat; District : Vadodara; Taluka : Karjan

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
KOTHAV	50	0	14	00
	55	0	04	80

[No. O-14016/517/85-GP]

का. आ. 5373.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4506, तारीख 12-9-1985 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : झगडिया

गांव	सर्वे नं.	हैक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
कराड	389	0	39	00
	388	0	61	50
	387	0	37	50
	366/पी.	0	04	20
	कार्टट्रेक	0	30	00
	382	0	20	40
	381	0	20	40
	374	0	18	60
	कार्ट ट्रेक	0	06	00
	375	0	18	00
	372	0	21	00
	371	0	07	50
	31	0	14	50
	36	0	05	00
	35	0	26	20
	42	0	26	10
	कोटर	0	07	50
	277	0	15	00
	276	0	21	90
	275	0	12	60
	273	0	12	60
	274	0	09	60
	कोटार	0	04	50
	58	0	24	00
	57	0	05	60
	60	0	00	62
	61	0	74	35
	62	0	02	75
	71	0	16	50
	72	0	12	00
	73	0	09	00
	74	0	07	50
	कोटार	0	20	00
	193	0	22	50
	174	0	02	75
	192	0	11	30
	191	0	15	00
	175	0	33	00
	168	0	36	00
	178	0	27	00
	177/ए	0	07	50
	406	0	32	10
	158/बी	0	02	00
	159	0	28	50
	405	0	01	00
	160	0	13	50
	161	0	31	50
	162	0	05	40
	कार्ट ट्रेक	0	03	60
	146	0	24	00
	145	0	27	00

[सं. O-14076/518/85-जी. पी.]

S.O. 5373.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4506 dated 12-9-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira–Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat; District : Bharuch; Taluka : Zaghadiya

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
KARAD	389	0	39	00
	388	0	61	50
	387	0	37	50
	366/P	0	04	20
	Cart track	0	30	00
	382	0	20	40
	381	0	20	40
	374	0	18	60
	Cart track	0	06	00
	375	0	18	00
	372	0	21	00
	371	0	07	50
	31	0	14	50
	36	0	05	00
	35	0	26	20
	42	0	26	10
	Kotar	0	07	50
	277	0	15	00
	276	0	21	90
	275	0	12	60
	273	0	12	60
	274	0	09	60
	Kotar	0	04	50
	58	0	24	00
	57	0	05	60
	60	0	00	62
	61	0	74	35
	62	0	02	75
	71	0	16	50
	72	0	12	00
	73	0	09	00
	74	0	07	50
	Kotar	0	20	00
	193	0	22	50
	174	0	02	75
	192	0	11	30
	191	0	15	00
	175	0	33	00
	168	0	36	00
	178	0	27	00
	177/A	0	07	50
	406	0	32	10
	158/B	0	02	00
	159	0	28	50
	405	0	01	00
	160	0	13	50
	161	0	31	50
	162	0	05	40
	Cart Track	0	03	60
	146	0	24	00
	145	0	27	00

[No.O-14016/518/85-GP]

का. आ. 5374.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4507, तारीख 12-9-1985 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य : गुजरात जिला : बडौदा तालुका : करजन

गांव	सर्वे नं.	हैक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
देरोली	कोटार	0	09	60
	149	0	15	90
	141/5	0	05	40
	148/1	0	13	60

1	2	3	4	5
	148/2	0	06	60
	141/9	0	20	80
	147	0	03	60
	141/2	0	05	00
	141/7	0	38	80
	141/3	0	42	80
	140	0	50	00
	156	0	04	40
	157	0	01	60
	159/1	0	03	52
	159/2	0	03	20
	159/3	0	01	44
	150	0	27	00
	152	0	22	32
	153	0	23	28
	154/1	0	08	88
	175	0	34	80
	176	0	34	00
	174	0	02	40
	कार्ट ट्रेक	0	03	60

[सं. O-14016/519/85-जी. पी.]

S.O. 5374.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4507 dated 12-9-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly to Jagdispur

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
DEROLI	Kotar	0	09	60
	149	0	15	90
	141/5	0	05	40
	148/1	0	13	60
	148/2	0	06	60
	141/9	0	20	80
	147	0	03	60
	141/2	0	05	00
	141/7	0	38	80
	141/3	0	42	80
	140	0	50	00
	156	0	04	40
	157	0	01	60
	159/1	0	03	52
	159/2	0	03	20
	159/3	0	01	44
	150	0	27	00
	152	0	22	32
	153	0	23	28
	154/1	0	08	88
	175	0	34	80
	176	0	34	00
	174	0	02	40
	Cart track	0	03	60

[No. O-14016/519/85-GP]

का. आ. 5375.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4508, तारीख 12-9-1985 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन

राज्य : गुजरात जिला : बड़ौदा तालुका : करजन

गांव	सर्वे न.	हैक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
मेथी	कार्ट ट्रेक	0	16	80
	164	0	17	92
	165	0	30	80
	166	0	07	20
	170	0	24	00
	171	0	05	28
	229	0	30	00
	केन्स	0	10	80
	231	0	54	00
	236	0	00	85
	237	0	32	40
	238	0	04	48
	239	0	37	60
	225	0	02	40
	264	0	07	20
	265	0	41	40
	266	0	05	76
	272	0	09	00
	271	0	16	80
	273	0	30	00
	294	0	18	75
	293	0	44	27
	292	0	04	48
	311	0	30	80
	312	0	05	20
	कार्ट ट्रेक	0	02	40
	328	0	14	00
	329	0	00	40
	327	0	49	20
	कार्ट ट्रेक	0	08	40
	343	0	40	72
	361	0	02	88
	344	0	00	80
	355	0	46	08
	359	0	01	92
	358	0	14	00
	369/ए	0	12	00
	375	0	08	40
	374	0	07	50
	373	0	07	00
	372	0	01	40
	371	0	07	20
	370	0	16	80
	387	0	05	60
	386	0	37	20
	385	0	11	20
	कार्ट ट्रेक	0	04	80
	385/पी	0	06	60

[सं. ओ 14016/520/85-जी.पी.]

S.O. 5375.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4508 dated 12-9-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Compptent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquire for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Barcilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Methi	Cart track	0	16	80
	164	0	17	92
	165	0	30	80
	166	0	07	20
	170	0	24	00
	171	0	05	28
	229	0	30	00
	Kans	0	10	80
	231	0	54	00
	236	0	00	85
	237	0	32	40
	238	0	04	48
	239	0	37	60
	225	0	02	40

1	2	3	4	5
	264	0	07	20
	265	0	41	40
	266	0	05	76
	272	0	09	00
	271	0	16	80
	273	0	30	00
	294	0	18	75
	293	0	44	27
	292	0	04	48
	311	0	30	80
	312	0	05	20
	Cart track	0	02	40
	328	0	14	00
	329	0	00	40
	327	0	49	20
	Cart track	0	08	40
	343	0	40	72
	361	0	02	88
	344	0	00	80
	355	0	46	08
	359	0	01	92
	358	0	14	00
	369/A	0	12	00
	375	0	08	40
	374	0	07	50
	373	0	07	00
	372	0	01	40
	371	0	07	20
	370	0	16	80
	387	0	05	60
	386	0	37	20
	385	0	11	20
	Cart track	0	04	80
	385/P	0	06	60

[No. O-14016/520/85-GP]

का. आ. 5376.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4509 तारीख 12-9-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उक्त धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : अंकलेश्वर

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
भादी	219	0	48	00
	201	0	48	00

[सं. O-14016/521/85-जी पी]

S.O. 5376.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4509 dated 12-9-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquuire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

No, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declararion in the Gas Authority of India Limited, free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira–Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat; District : Bharuch Taluka : Ankleshwar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
BHADI	219	0	48	00
	201	0	48	00

No O-14016/521/85-GP]

का. आ. 5377.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4510 तारीख 12-9-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य :– गुजरात जिला :– बड़ौदा तालुका : करजन

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
हीरजीपुरा	84	0	28	80
	89	0	34	20
	26	0	25	04
	22	0	10	00
	25/2	0	18	00
	24/2	0	15	60
	128/1	0	24	00

[सं. O-14016/522/85-जीपी]

S.O. 5377.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4510 dated 12-9-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

No, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquire for laying the pipeline;

And furthehr in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira–Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat; District : Vadodara; Taluka : Karjan

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
HIRJIPURA	84	0	28	80
	89	0	34	20
	26	0	25	04
	22	0	10	00
	25/2	0	18	00
	24/2	0	15	60
	128/1	0	24	00

[No. O-14016/522/85-GP]

का. आ. 5378.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4511 तारीख 12-9-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : झगड़िया

गांव	सर्वे नं.	हेक्टयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
ददेड़ा	258	0	15	00
	कोटर	0	03	00
	186	0	69	50
	185	0	05	50
	कार्ट ट्रेक	0	04	50
	188/ए	0	00	50
	187	0	30	00
	कार्ट ट्रेक	0	03	00
	179	0	16	50
	178	0	22	50

1	2	3	4	5
	18 0	0	09	00
	177	0	28	50
	176	0	46	50
	174	0	78	00
	173	0	07	50
	170	0	33	00
	171	0	00	50
	164	0	60	00
	कार्ट ट्रेक	0	06	00
	155	0	00	50
	138	0	36	00
	137	0	38	50
	136	0	18	00
	139/बी	0	19	50
	131/बी	0	06	00
	131/ए	0	90	00
	126	0	48	00

[सं. O-14016/523/85-जीपी]

S.O. 5378.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4511 dated 12-9-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquuire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declararion in the Gas Authority of India Limited, free from encumbrances

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat; District : Bharuch; Taluka : Zaghadiya

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
DADHEDA	258	0	15	00
	Kotar	0	03	00
	186	0	69	50
	185	0	05	50
	Cart track	0	04	50
	188/A	0	00	50
	187	0	30	00
	Cart track	0	03	00
	179	0	16	50
	180	0	09	00
	177	0	28	50
	176	0	46	50
	174	0	78	00
	173	0	07	50
	170	0	33	00
	171	0	00	50
	164	0	60	00
	Cart track	0	06	00
	155	0	00	50
	138	0	36	00
	137	0	37	50
	136	0	18	00
	139/B	0	19	50
	131/B	0	06	00
	131/A	0	90	00
	126	0	48	00

[No. O-14016/523/85-GP]

का. आ. 5379.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4490 तारीख 12-9-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उक्त धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य—गुजरात जिला—भरुच तालुका—वालीया

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
1	2	3	4	5
कोंध	1189	0	15	00
	1190	0	44	25
	1193	0	12	15
	1194	0	12	15
	1195	0	36	00

1	2	3	4	5
	1196	0	48	68
	1197	0	02	12
	1222	0	52	50
	1221	0	15	00
	1220	0	22	50
	1241	0	06	00
	1242	0	07	50
	1218	0	82	50
	1246	0	12	00
	1147	0	33	00
	114	0	23	50
	110	0	02	50
	109	0	01	25
	108	0	21	00
	107	0	36	50
	96	0	00	25
	99	0	01	50
	100	0	30	00
	89	0	45	00
	90	0	13	50
	कार्ट ट्रैक	0	07	50
	222	0	15	00
	224	0	43	63
	69	0	08	87
	225	0	67	50
	218	0	43	50
	216	0	19	50
	कोटर	0	15	00
	230	0	05	62
	228	0	58	88
	253	0	16	50
	254	0	04	50
	252	0	18	00
	231	0	37	50
	251	0	00	50
	232	0	03	70
	248	0	53	25
	247	0	10	50
	242	0	30	00
	241	0	13	50
	238	0	22	50
	237	0	25	50
	239	0	10	50

[सं० O-14016/502/85-जी पी]

S.O. 5379.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4490 dated 12-9-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Mioerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquuire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act(submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act. the Central Government hereby declared that the right of user in the said lands specified in the schedule appended tothis notification hereby acquired for laying the pipeline;

And furthehr in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declarartion in the Gas Authority of India Limited, free from encumbrances

SCHEDULE

Pipeline from Hajira Bareilly to Jagdishpur
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vallya

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Kandh	1189	0	15	00
	1190	0	44	25
	1193	0	12	15
	1194	0	12	15
	1195	0	36	00
	1196	0	48	68
	1197	0	02	12
	1222	0	52	50
	1221	0	15	00
	1220	0	22	50
	1241	0	06	00
	1242	0	07	50
	1218	0	82	50
	1246	0	12	00
	1147	0	33	00
	114	0	23	50
	110	0	02	50
	109	0	01	25
	108	0	21	00
	107	0	36	50
	96	0	00	25
	99	0	01	50
	100	0	30	00
	89	0	45	00
	90	0	13	50
	Cart Tract	0	07	50
	222	0	15	00
	224	0	43	63
	69	0	08	87
	225	0	67	50
	218	0	43	50
	216	0	19	50
	Kotar	0	15	00
	230	0	05	62
	228	0	58	88
	253	0	16	50
	254	0	04	50
	252	0	18	00
	231	0	37	50
	251	0	00	50
	232	0	03	70
	248	0	53	25
	247	0	10	50
	242	0	30	00
	241	0	13	50
	238	0	22	50
	237	0	25	50
	239	0	10	50

[No. O-14016/502/85-GP]

का. आ. 5380.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का आ. सं. 2037 तारीख 11-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

एच० बी. जे. गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

ग्राम बैजापारा तहसील भाण्डेर जिला—ग्वालियर राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

क्रम क्र.	खसरा नं.	उपयोग,अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	250	0.774
2.	251/1	0.052
3.	249	0.157
4.	156	0.002
5.	254	0.105
6.	255	0.344
7.	256	0.408
8.	257	0.209
9.	242	0.042
10.	244	0.261
11.	241	0.344
12.	268	0.105
13.	188	0.177
14.	186	0.533
15.	191	0.291
16.	177	0.052
17.	176	0.072
18.	175	0.229
19.	174	0.072
20.	151/1	0.177
21.	172	0.147
22.	173	0.020
23.	171	0.324
24.	169	0.030
25.	170	0.209
26.	167	0.020
27.	166	0.314
28.	164	0.177
29.	165	0.052
30.	77	0.052
31.	80	0.306
32.	81	0.010
33.	74	0.020
	योग :—कुल क्षेत्रफल	6.087

[सं. O-14016/316/85-जी पी]

S.O. 5380.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2037 dated 11-5-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land. Act. 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declared that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And furthehr in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipeline Project

Village Bejapara, Tehsil : Bhander, Distt. : Gwalior

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hector
1	2	3
1.	250	0.773
2.	251/1	0.052
3.	249	0.157
4.	156	0.002
5.	254	0.105
6.	255	0.344
7.	256	0.408
8.	257	0.209
9.	242	0.042
10.	244	0.261

1	2	3	4	5
11.	241	0.344		
x2.	268	p.105		
13.	188	0.177		
14.	186	0.533		
15.	191	0 291		
16.	177	0.052		
17.	176	0.072		
18.	175	0.229		
19.	174	0.072		
20.	151/1	0.177		
21.	172	0.147		
22.	173	0 020		
23.	171	0.324		
24.	169	0.030		
25.	170	0 209		
26.	167	0.020		
27.	166	0.314		
28.	164	0.177		
29.	165	0 052		
30.	77	0 052		
31.	80	0.306		
32.	81	0 010		
33.	74	0.020		
	Total Area	6.087		

[No. O-14016/316/85-GP]

का. आ. 5381.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 731 तारीख 23-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम-हिनोतिया तहसील—गुना जिला—गुना राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (क्षेत्रफल में)
1	2	3
1.	17	0.042
2.	195/1मी.	0.105
3.	195/1मी.	0.627
4.	182	0.062
5.	189	0.324
6.	185	0.073
7.	186	0.355
8.	187	0.052
9.	188	0.261
10.	282	0.063
11.	278	0.439
12.	279	0.178
13.	276	0.240
14.	251	0.011
15.	275	0.073
16.	254	0.325
17.	253	0.157
18.	242	0.042
19.	257	0.366
20.	237	0.199
21.	239	0.314
22.	227	0.052
23.	216	0.261
24.	217	0.303
25.	212/1	0.314
26.	209	0.010
27.	210	0.105
28.	211	0.240
29.	203	0.136
30.	204	0.125
31.	19	0.230
32.	115	0.042
33.	195/2	0.157
34.	207	0.021
35.	202	0.042
36.	197	0.042
37.	195/4	0.272
38.	195/5	0.157
39.	218	0.010
40.	277	0.031
41.	172	0.010
42.	280	0.010
योग :—कुल क्षेत्रफल		6.878

[सं. O-14016/73/85—जी पी]

एम. एस. श्रीनिवासन, निदेशक

S.O. 5381.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1731 dated 23-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

No, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declared that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And furthehr in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government direcrs that the right of user in the said lands shall insted of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declararion in the Gas Authority of India Limited, free from all encuumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Hinotiya Tehsil : Gun Distt. : Guna

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Haetor
1	2	3
1.	17	0 042
2.	195/1 M.	0 105
3.	195/1 M.	0 627
4.	182	0 052
5.	189	0 324
6.	185	0 073
7.	186	0.355
8.	187	0 052
9.	188	0 261
10.	282	0.063
11.	278	0.439
12.	279	0.178
13.	276	0 240
14.	251	0.011
15.	275	0 073
16.	254	0 325
17.	253	0 157
18.	242	0 042
19.	257	0 366
20.	237	0.199
21.	239	0.314
22.	227	0.052
23.	216	0 261
24.	217	0.303
25.	212/1	0.314
26.	209	0.010
27.	210	0.105
28.	211	0 240
29.	203	0.136
30.	204	0 155
31.	19	0 230
32.	115	0 042
33.	195/2	0.157
34.	207	0 021
35.	202	0.042
36.	197	0.042
37.	195/4	0 274
38.	195/5	0.157
39.	218	0.010
40.	277	0.031
41.	172	0.010
42.	280	0.010
	Total Area :	6.878

[No. O-14016/73/85-GP]

M.S. SRINIVASAN, Director.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर 1985

(आयकर)

का. आ. 5382.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23ग) के उपखंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ "रामकृष्ण वेदान्त मठ, कलकत्ता" को कर-निर्धारण-वर्ष 1984-85 से 1987-88 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6475 (फा. सं. 197/97/84-आ. क. (नि.-1)]

आर. के. तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

New Delhi, the 29th October, 1985

(INCOME-TAX)

S.O. 5382.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Ramakrishna Vedanta Math, Calcutta" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1984-85 to 1987-88.

[No. 6475/F. No. 197/97/84-IT (AI)]

R. K. TEWARI, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1985

आदेश

स्टाम्प

का. आ. 5383.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा महाराष्ट्र राज्य वित्त निगम को केवल चार लाख, चौहत्तर हजार तीन सौ पचहत्तर रुपये के उस समेकित स्टाम्प शुल्क की अदायगी करने की अनुमति देती

है, जो उक्त निगम द्वारा जारी किए जाने वाले केवल छः करोड़ बत्तीस लाख, पचास हजार रुपये अंकित मूल्य के ऋणपत्रों "9.75" म. रा. वि. नि. बन्धपत्र 1998 (II सिरीज में) क्रम संख्या 1 से 275 तक पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है ।

[सं. 39/85-स्टाम्प-फा. सं. 33/50/85-वि. क.]

New Delhi, the 13th November, 1985

ORDER

STAMPS

S.O. 5383.—In exercise of the powers cnoferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the Maharashtra State Financial Corporation, Bombay to pay consolidated stamp duty of Four lakhs, seventy four thousand three hundred and seventy five rupees only, chargeable on account of the stamp duty on bounds in the from of debentures described as "9.75" M.F.S.C. Bonds 1998 (II series) bearing serial numbers 1 t o275 and of the face value of Six crores thirty two lakhs and fifty thousand rupees only to be issued by the said Corporation.

[No. 39/85-Stamps—F. No. 33/50/85-ST]

आदेश

स्टाम्प

का. आ. 5384.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को छूट देती है जो आवास तथा शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले केवल तीस करोड़ रुपये मूल्य पर "9.75% बन्धपत्र-1998 XXIII सिरीज" के रूप में उल्लिखित ऋणोपत्रों पर प्रभार्य है ।

[सं. 40/85-स्टाम्प-फा. सं. 33/53/85-वि. क.]

बी. आर. मेहमी, अवर सचिव

ORDER

STAMPS

S.O. 5384.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of Debentures described as "9.75 per cent debentures—1998 XXIII Series" to the value of Thirty crores rupees only to be issued by Housing and Urban Development Corporation Limited, New Delhi, are chargeable under the said Act.

[No. 40/85-Stamps-F. No. 33153/85-ST]

B. R. MEHMI, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1985

का. आ. 5385.—राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 (1981 का 61) की धारा 19 के खण्ड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 21 और 22 नवम्बर 1985 की अवधि के दौरान 100 रुपए प्रतिशत मूल्य पर, 13 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले जारी किए जाने वाले 46 करोड़ रुपए (छयालीस करोड़ रुपए केवल) के बांडों पर देय ब्याज का दर 9.75 प्रतिशत (नौ दशमलव पचहत्तर प्रतिशत) तय करता है । राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को उक्त अधिसूचित राशि से 10 प्रतिशत अधिक तक अभिदान की राशि अपने पास रख लेने का अधिकार होगा ।

[संख्या 10(94)/85-ए. सी.]

के. पी. पान्डियन, अवर सचिव

Department of Economic Affairs

(Banking Division)

New Delhi, the 1st November, 1985.

S.O. 5385.—In pursuance of clause (a) of Section 19 of the National Bank for Agriculaure and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981), the Central Government hereby fixes 9.75 per cent (nine and three fourth per cent) per annum as the rate of interest payable on the bonds of Rs. 46 crores (Rupees forty six crores only) to be issued at Rs. 100.00 per cent during the period from 21st and 22nd November, 1985 with right to retain subscriptions received upto 10 per cent in excess of notified amount with a maturity period of 13 years by the National Bank for Agriculture and Rural Development.

[No. 10(94)/85-AC]

K. P. PANDIAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1985

का. आ. 5386—भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1984 (1984 का 62) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के उपखण्ड (ii) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एन. वघुल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड, बम्बई को श्री एस. एस. नादकर्णी के स्थान पर भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक का निदेशक नामित करती है ।

[संख्या एफ. 7/8/85-बी. ओ.-I]

New Delhi, the 7th November, 1985.

S.O. 5386.—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Reconstruction Bank of India Act, 1984 (6 of 1984), the Central Government hereby nominates Shri N. Vaghul, Chairman and Managing Director, Industrial Credit and Investment Corporation of india Ltd. Bombay, as Director of Industrial Reconstruction Bank of India Vice Shri S. S. Nadkarni.

[No. F. 7/8/85-BO.-I]

का. आ. 5387—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (V) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री पी० आर० लाटे, सचिव तथा महानिदेशक (तकनीकी विकास) उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के निदेशक के रूप में नामित करती है ।

[संख्या 7/12/85-बी. ओ.-I]

S.O. 5387.—In pursuance of sub-clause (v) of clause (c) of sub-section (1) of section 6 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964), the Central Government hereby nominates Shri P. R. Latev, Secretary and Director General (Techincal Development), Ministry of Industry New Delhi as a Director of the Industrial Development Bank of India.

[No. 7/12/85-BO-I]

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1985

का. आ. 5388--राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1970 की धारा 3 की उपधारा (ज) के अनुसरण मे केन्द्रीय सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) नई दिल्ली के अपर सचिव श्री शरद केलकर को श्रीमती ओतिमा बोर्डिया के स्थान पर एतद्द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या 9/24/85-बी. ओ-I]

एस. एस. हसूरकर, निदेशक

New Delhi, the 13th November, 1985.

S.O. 5388.—In pursuance of sub-clause (h) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government heregy appoint shri S. M. Kelkar, Additional Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi as a Director of Punjab National Bank vice Smt. Otima Bordia.

]No. F. 9/24/85-BO-I[

S. S. HASURKAR, Director

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1985

का. आ. 5389--निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् एतद्द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, बम्बई के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक श्री एस. एस. नादकर्णी को श्री एम. आर. बी. पुंजा के स्थान पर 13 नवम्बर 1985 से दो वर्ष की अवधि के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के निदेशक के रूप में नामित करती है।

[संख्या एफ. 6/4/85 बी. ओ.-I]

एम. एस. सीतारामन, अवर सचिव

New Delhi, the 13th November, 1985.

S.O. 5389.—In pursuance of the provisions of clause (e) of sub-section (1) of section 6 of the Deposit Insurance and Credit GuaranteeCorporation Act, 1961 (47of 1961), the Central Government, after consultati on with the Reserve Bank of India hereby nominates Shri S. S. Nadkarni, Chairman and Managing Director, Industrial Development Bank of India Bombay as a director of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation for a period of two years with effect from 13th November, 1985 vice Shri M. R. B. Punja.

[No. F. 6/4/85-BO-I]

M. S. SEETHARAMAN, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय : मध्यप्रदेश

इन्दौर, 15 नवम्बर 1985

अधिसूचना संख्या 9/85

का. आ. 5390--मध्यप्रदेश समाहर्तालय इन्दौर के निम्नलिखित अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, समूह "ख" निवर्तन की आयु प्राप्त करने पर उनके नाम के आगे दी गई तिथियों को शासकीय सेवा से निवृत्त हुए।

क्रम सं.	नाम	दिनांक
1	2	3
सर्वश्री		
(1)	वी. बी. वरन्दानी	30-6-1985 (अपराह्न)
(2)	वी. एल. भागवत	31-7-1985 (अपराह्न)
(3)	जे. के. अहिर	31-7-1985 (अपराह्न)
(4)	डब्लू. डब्लू. गुर्जर	31-7-1985 (अपराह्न)
(5)	पी. जी. मुद्रे	31-8-1985 (अपराह्न)
(6)	पी. के. केके	31-8-1985 (अपराह्न)
(7)	एम. बी. अथाले	31-8-1985 अपराह्न)

[पत्र संख्या II(3) 7--गोप/85/6035]

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE M.P.

Indore, the 15th November, 1935

NOTIFICATION NO. 9/85

S.O. 5390—The following Superintendents of Central Excise Group 'B' having attained the age of superannuation retired from Government Service on the dates shown against each :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date
1	2	3
Shri/		
1.	V.B. Varandani	30-6-1985(A.N.)
2.	V.L. Bhagwat	31-7-1985(A.N.)
3.	J.K. Ahir	31-7-1985(A.N.)
4.	W.W. Gurjar	31-7-1985(A.N.)
5.	P.G. Mudre	31-8-1985(A.N.)
6.	P.K. Kekre	31-8-1935(A.N.)
7.	M.B. Athale	31-8-1985(A.N.)

[C NO II(3)7-Con/85/6035]

अधिसूचना संख्या 10/85

का. आ. 5391.—अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह "ख" के पद पर पदोन्नत होने पर निम्नलिखित निरीक्षकों, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (व. श्रे.) ने उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथियों को अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह "ख" के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिये है।

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	तैनाति स्थान	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	एम. टी. जानवाडे	अधीक्षक सांख्यिकी, के. उ. शु., प्रभा का., इन्दौर	7-8-1985 (पूर्वाह्न)
2.	टी. आर. कुरील	अधीक्षक, लेखा (लेखा परीक्षा) के. उ. शु., मु. का. इन्दौर	5-8-1985 (पूर्वाह्न)
3.	आर. डी. झरिया	अधीक्षक (निवारक) के. उ. शु, प्रभा. का., सागर	30-8-1985 अपराह्न)
4.	पी. पी. छवेरिया	अधीक्षक, के. उ. शु. रेंज-1 उज्जैन	29-8-1984 (पूर्वाह्न)
5.	बी. डी. चौधरी	अधीक्षक, के० उ. शु. रेंज-1 नागदा	31-8-1985 (अपराह्न)
6.	एम. पी. सारस्वत	अधीक्षक, के. उ. शु., रेंज-11, नागदा	31-8-1985 (अपर ह्न)

[पत्र संख्या II(3) 7-गोप/85/6067]

एस. वी. रामकृष्णन, समाहर्ता

NOTIFICATION NO. 10/85

S.O. 5391.—Consequent upon their promotion as Superintendent, Central Excise, Group 'B' the following Inspectors of Central Excise (SG) have assumed their charges as Superintendent, Central Excise, Group 'B' with effect from the dates as shown against each :—

Sl. No.	Name of the Officer	Place of posting	Date of Assumption of charge
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	M.T. Janawade	Supdt. (Sttcs.), C.Ex., Divl. Office, Indore.	7-8-1985(F.N.)
2.	T.R. Kureel	Supdt. (Audit), C.Ex., Hqrs. Office, Indore.	5-8-1985(F.N.)
3.	R.D. Jharia	Supdt. (Prev.), C.Ex., Divl. Office, Sagar	30-8-1985(A.N.)
4.	P.P. Chavoria	Supdt., C.Ex., Range-I. Ujjain	29-8-1985(F.N.)
5.	B.D. Choudhary	Supdt., C.Ex., Range-I, Nagda.	31-8-1985(A.N.)
6.	M.P. Saraswat	Supdt., C.Ex., Range-II. Nagda.	31-8-1985(A.N.)

[C. No. II(3)7 Con/85/6067]

S.V. RAMAKRISHNAN, Collector

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1985

का. आ. 5392.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स कोरोमंडल पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज 43-1-42, मेन रोड, काकिनाडा को अल्युमिनियम फोस्फाइड का निम्नलिखित मदों के लिए धूम्रक के रूप में प्रयोग करते हुए, धूम्रकरण के लिए अभिकरण के रूप में 24 नवम्बर 1985 से एक और वर्ष की अवधि के लिए मान्यता देती है।

1. तेल रहित चावल की भूसी ; और
2. हड्डी का चूरा, खुर और सींग।

[फाईल सं. 5 (6) /84 ई.आई. एण्ड ई पी]

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 18th November, 1985

S.O. 5392.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a further period of one year w.e.f. 24th November 1985 M/s. Coromandal Pest Control Services, 43-1-42, Main Road, Kakinada as an agency for the fumigation using aluminium phosphide as a fumigant for the following items:—

1. De-oiled Rice Bran; and
2. Crushed Bones, Hooves and Horns.

[F. No. 5(6)/84-EI&EP]

का०आ० 5393.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एस०जी०एस० इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फोरशोर रोड, काकीनाडा-533001 (पूर्व गोदावरी जिला) आन्ध्र प्रदेश को जिनका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 35 मुर्जबान रोड, पोस्ट बाक्स नं० 508, बम्बई-400001 में स्थित है, 12 नवम्बर, 1985 से निम्नलिखित मदों के धूम्रकरण के लिये अभिकरण के रूप में एक और वर्ष की अवधि के लिये मान्यता देती है :—

1. तेल रहित चावल की भूसी; और
2. हड्डी का चूरा, खुर और सींग

[फाइल सं० 5(7) 82-ई आई एण्ड ई पी]

S.O. 5393.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a further period of one year with effect from12th November 1985 SGS India Private Ltd., Foreshore Road, Kainada—633001 (East Godavari District) Andhra Pradesh, having their registered office at 35 Murzban Road, Post Box No. 508, Bombay-400001 as an agency for the fumigation of following items—

1. De-oiled Rice Bran; and
2. Crushed Bones Hooves and Horns.

[F. No. 5(7)/82-EI&EP]

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1985

का०आ० 5394.— केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति उपदान नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति उपदान (संशोधन) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति उपदान नियम, 1981 में—

(1) नियम 2 के उपनियम (5) में, "2500/- रु०" के स्थान पर "4000/- रुपये" रखे जायेंगे ;

(2) नियम 6 के उपनियम (क) में, "36000/- रुपये" के स्थान पर "50000- रुपये" अंक रखे जायेंगे ;

(3) उक्त नियमों के नियम 12 में,—

(1) विद्यमान पहले पैरे को उपनियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जायेगा और निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि यदि नामनिर्देशन करते समय कर्मचारी का कुटुम्ब है, तो नामनिर्देशन अपने कुटुम्ब के सदस्यों से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नहीं होगा";

(2) दूसरे पैरे को उपनियम (2) के रूप में में संख्यांकित किया जाये और निम्नलिखित पैरे उपनियम (3) से (8) के रूप में जोड़े जायेंगे, अर्थात् :—

(3) कोई कर्मचारी नामनिर्देशन में यह उपबंध कर सकेगा —

(क) कि किसी ऐसे विनिर्दिष्ट नामनिर्देशिती के संबंध में, जिसकी मृत्यु कर्मचारी से पहले हो जाती है या जिसकी मृत्यु कर्मचारी के पश्चात् किन्तु उपदान का भुगतान प्राप्त करने से पहले हो जाती है, उस नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार ऐसे अन्य व्यक्ति को चला जायेगा, जैसा नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

परन्तु यह कि नामनिदेशन करते समय कर्मचारी का कुटुम्ब है जिसमें एक सदस्य से अधिक सदस्य हैं तो इस प्रकार विनिर्दिष्ट व्यक्ति उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति नहीं होगा :

परन्तु यह और कि जहां कर्मचारी के कुटुम्ब में केवल एक सदस्य है और नामनिर्देशन उसके पक्ष में किया गया है तो यह कर्मचारी पर निर्भर करता है कि वह किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं , के के पक्ष में आनुकल्पिक नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों का का नामनिर्देशन करें;

(ख) कि उसमें उपबन्धित अनिश्चित घटना घटित होने की दशा में नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जायेगा।

(4) किसी ऐसे कर्मचारी द्वारा, जिसका नामनिर्देशन करते समय कुटुम्ब नहीं था नामनिर्देशन किया गया या उपनियम (3) के खंड (1) में दूसरे परन्तुक के अधीन कर्मचारी द्वारा किया गया नामनिर्देशन, जहां उसके कुटुम्ब में केवल एक सदस्य है, यथास्थिति, बाद में कर्मचारी के कुटुम्ब होने या कुटुम्ब में अतिरिक्त सदस्य आने की दशा में अविधिमान्य हो जायेगा।

(5) कोई भी कर्मचारी किसी भी समय, कार्यालय के प्रधान को लिखित में सूचना भेजकर नामनिर्देशन रद्द कर सकेगा ;

परन्तु यह कि वह ऐसी सूचना के साथ , इस नियम के अनुसार किया गया नया नामनिर्देशन भेजेगा।

(6) किसी ऐसे नामनिर्देशिती की मृत्यु पर, जिसकी बाबत उपनियम (3) के खंड (1) के अधीन नामनिर्देशन में कोई भी विशेष उपबंध नहीं किया गया है या किसी घटना के घटित होने पर, जिसके कारण उस उपनियम के खंड (ii) के अनुसरण में नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाता है , सरकारी सेवक तुरन्त कार्यालय के प्रधान को इस नियम के अनुसार किये गये नये नामनिर्देशन के साथ नामनिर्देशन रद्द करते हुए लिखित में सूचना भेजेगा।

(7)(क) इस नियम के अधीन कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक नामनिर्देशन (दो गयी रद्दकरण की प्रत्येक सूचना सहित) कार्यालय के प्रधान को भेजा जायेगा।

(ख) कार्यालय प्रधान, ऐसा नामनिर्देशन प्राप्त होने के ठीक बाद उस पर प्राप्ति की तारीख डालकर प्रतिहस्ताक्षर करेगा और उसे अपनी अभिरक्षा में रखेगा ;

परन्तु कार्यालय का प्रधान अपने अधीनस्थ अधिकारियों को नामनिर्देशन प्ररूपों पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा।

(ग) नामनिर्देशन की प्राप्ति के संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में की जायेगी।

(8) कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक नामनिर्देशन और दी गयी रद्दकरण की प्रत्येक सूचना, उस सीमा तक जहां तक वह विधिमान्य है, उस तारीख से प्रभावी होगी जिसको वह कार्यालय के प्रधान को प्राप्त होती है ।

(4) उक्त नियमों के नियम 7 के उपनियम (ग) में :—

(1) "तीस वर्ष" के अधीन नहीं होगी शब्दों के स्थान पर "तैंतीस वर्ष" से अधिक नहीं होगी और वह उसे अधिवर्षिता की आयु के पश्चात् नहीं ले जाती है" शब्द रखे जायेंगे ।

(2) उपनियम (ग) के नीचे विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जायेगा, अर्थात् :—

परन्तु यह कि इस उपनियम के अधीन बढ़ाई गयी पांच वर्षों की अवधि उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगी जिनके मूल नियमों के नियम 56 के खंड (ब) के अधीन लोकहित में अभिकरण द्वारा समय से पहले ही सेवा-निवृत्ति कर दिया गया है ।

(5) उक्त नियमों के प्ररूप 2 में :—

(1) निम्नलिखित स्तम्भ (5) के रूप में जोड़ा जायेगा और विद्यमान स्तम्भ (5) और (6) को स्तम्भ (6) और (7) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा, अर्थात् :—

वे अनिश्चित घटनाएं जिनके घटित होने पर नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाए।	

(2) उक्त प्ररूप 2 के अंत में निम्नलिखित "टिप्पण" जोड़ा जायेगा और विद्यमान टिप्पण को टिप्पण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा, अर्थात् :—

टिप्पण : किसी ऐसे अभिदाता के मामले में, जिसकी नामनिर्देशन करते समय कुटुम्ब नहीं था, बाद में कुटुम्ब हो जाता है, नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा । अभिदाता को नामनिर्देशन में ऐसी अनिश्चित घटना और संदेय अंश को स्पष्ट रूप से उपदर्शित करना चाहिए ।

[फाइल सं० 3(12)/76-ईआई एंडईपी]

पाद टिप्पण : का०आ० सं० 1607 तारीख 30-5-1981
का०आ० सं० 2140 तारीख 21-6-1982
का०आ० सं० 830 तारीख 17-3-1984
का०आ० सं० 832 तारीख 17-3-1984

1093 GI/85—11

New Delhi, the 30th November, 1985

S.O. 5394.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export Inspection Agency, Death-cum-Retirement Gratuity Rules, 1981, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export Inspection Agency, Death-cum-Retirement Gratuity (Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export Inspection Agency, Death-cum-Retirement Gratuity Rules, 1981,—

(1) in sub-rule (1) of Rule 2, the figure 'Rs. 4,000' shall be substituted for 'Rs. 2,500' ;

(2) in sub-rule (a) of Rule 6, the figure 'Rs. 50,000' shall be substituted for 'Rs. 36,000' ;

(3) in Rule 12 of the said rule,—

(i) the existing first paragraph be numbered as sub-rule (1) and the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that if at the time of making the nomination the employee has a family, the nomination shall not be in favour of any person or persons other than the members of his family" ;

(ii) the second paragraph may be numbered as sub-rule (2) and the following paragraphs shall be added as sub-rules (3) to (8), namely :—

"(3) An employee may provide in the nomination—

(a) that in respect of any specified nominee who predececases the employee, or who dies after the death of the employee but before, receiving the payment of gratuity, the right conferred on that nominee shall pass to such other person as may be specified in the nomination :

Provided that if at the time of making the nomination the employee has a family consisting of more than one member, the person so specified shall not be a person other than a member of his family :

Provided further that where an employee has only one member in his family, and a nomination has been made in his favour, it is open to the employee to nominate alternate nominee of nominees in favour of any person or a body of individuals whether incorporated or not;

(b) that the nomination shall become invalid in the event of the happening of the contingency provided therein.

(4) The nomination made by an employee who has no family at the time of making it, or the nomination made by an employee under the second proviso to clause (i) of sub-rule (3) where he has only one member in his family shall become invalid in the event of the employee subsequently acquiring a family, or an additional member in the family, as the case may be.

(5) An employee may, at any time, cancel a nomination by sending a notice in writing to the Head of Office ;

Provided that he shall, along with such notice, send a fresh nomination made in accordance with this rule.

(6) Immediately on the death of a nominee in respect of whom no special provision has been made in the nomination under clause (i) sub-rule (3) or on the occurrence of any event by reason of which the nomination becomes invalid in pursuance of clause (ii) of that sub-rule, the Government servant shall send to the Head of Office a notice in writing cancelling the nomination together with a fresh nomination made in accordance with this rule.

(7) (a) Every nomination made (including every notice of cancellation, if any, given) by an employee under this rule, shall be sent to the Head of Office.

(b) The Head of Office shall, immediately on receipt of such nomination countersign it indicating the date of receipt and keep it under his custody :

Provided that the Head of Office may authorise his subordinate officers to countersign nomination forms.

(c) Suitable entry regarding receipt of nomination shall be made in the service book of the employee concerned.

(8) Every nomination made, and every notice of cancellation given, by an employee shall, to the extent that it is valid, take effect from the date on which it is received by the Head of Office.

(4) In sub-rule (c) of Rule 7 of the said rules :—

(i) the words "thirty three years and it does not take him/her beyond the date of superannuation" shall be substituted for the words "thirty Years."

(ii) the existing proviso below sub-rule (c) shall be substituted by the following proviso, namely :—

"Provided that the weightage of five years under this sub-rule shall not be admissible in cases of those employees who are prematurely retired by the Council in public interest under Clause (j) of Rule 56 of the Fundamental Rules."

(5) In the Form-II of the said rules :—

(i) the following shall be added as column (5) and the existing columns (5) and (6) shall be renumbered as (6) and (7), namely :—

"Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid."

(ii) the following 'Note' shall be added in the end in the said Form-II and the existing Note be numbered as Note-I, namely :—

"Note 2.—A nomination shall become invalid in case of a subscriber who had no family at the time of nomination subsequently acquiring a family. Subscriber should clearly indicate such contingency clause in the nomination and the share payable."

[File No. 3(12)/76-EI&EP]

Foot Note.—S.O. No.1608 dated 30-5-1981.
S.O. No. 2141 dated 21-6-1982.
S.O. No. 829 dated 17-3-1984.
S.O. No. 831 dated 17-3-1984.

का.आ. 5305.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964, में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) द्वितीय संशोधन नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में ;

(1) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(कक) "अपर निदेशक" से परिषद् या अभिकरण का अपर निदेशक अभिप्रेत है' ;

(2) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(खख) 'प्रमाण पत्र" से अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित या मान्यताप्राप्त किसी अभिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र अभिप्रेत है जिसमें यह कथन किया गया हो कि वस्तु क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से संबंधित शर्तों के अनुरूप है' ;

(3) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

परिषद् या अभिकरण का संयुक्त निदेशक अभिप्रेत है ;' ।

3. उक्त नियमों के नियम 7 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"7 (क) दस्तावेजों के अधिप्रमाणन का प्राधिकार और अधिप्रमाणन की रीति—भारत के बाहर किसी स्थान से प्राप्त कोई दस्तावेज जो उस पर या उससे ऐसे किसी व्यक्ति की मुद्रा और हस्ताक्षर लगाने, छापित या प्रस्तुत करने के लिए तात्पर्यित है जो राजनयिक और कौंसलीय ऑफिसर (शपथ और फीस) अधिनियम, 1948 (1948 का 41) की धारा 3 द्वारा नोटरी संबंधी कार्य करने के लिए प्राधिकृत है, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 10 की (7) (ख) के प्रयोजन के लिए सम्यक रूप से अधिप्रमाणित मानी जाएगी" ।

4. उक्त नियमों के नियम 11 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"11क. प्रमाण पत्र के संशोधन, निलम्बन या रद्दकरण के लिए प्रक्रिया—(1) जहां अभिकरण के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन जारी किया गया प्रमाण-पत्र उक्त धारा 7 की उपधारा (3क) में वर्णित किसी त्रुटि से ग्रस्त है वहां अभिकरण माल का पुनः परीक्षण निम्नलिखित के दौरान कर सकेगा।

(1) निर्यातकर्ता या विनिर्माता या निर्यातक अभिकर्ता या पोत परिवहन अभिकर्ता के परिसरों या भांडागार और शीताधार भंडारकरण के दौरान में ;

(2) खंड (1) उल्लिखित परिसरों से पोत लदान बंदरगाहों तक माल के परिवहन के दौरान किसी भी स्थान पर ;

(3) लदाई के पत्तन पर उतारे जाने के दौरान ;

(4) जलयान या विमान में लादने के दौरान ;

(5) जलयान में समुद्र यात्रा के दौरान ;

2. निम्नलिखित रीति से माल का पुनः परीक्षण किया जाएगा :—

(क) अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक के लिखित आदेश द्वारा पुनः परीक्षण प्राधिकृत किया जाएगा, और ऐसे अधिप्रमाणन पर संबंधित परेषण के लिए जारी किया गया निरीक्षण का प्रमाण पत्र निलम्बित रखा जाएगा।

(ख) पुनः परीक्षण निर्यात निरीक्षण परिषद् या अभिकरण के ऐसे एक या अधिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा जिन्होंने पहले से संबंधित परेषण का निरीक्षण नहीं किया है।

(ग) निर्यातकर्ता और/या विनिर्माता के प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में पुनः परीक्षण किया जाएगा। वस्तु का पुनः परीक्षण उस तारीख से जिसको प्रमाण पत्र निलम्बित किया जाता है, सात दिनों की अवधि या अधिनियम की धारा 17 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसी वस्तुओं के लिए पहले से ही विहित अवधि के भीतर, जो भी बाद में हो, किया जाएगा।

(घ) पुनः परीक्षण के परिणामों पर विचार करने के पश्चात् अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक लिखित आदेश देगा कि :—

(1) परेषण निर्यात के लिए अनुमत होगा ;

(2) इससे पहले जारी किया गया प्रमाण पत्र परेषण के उस भाग तक संशोधित किया जाएगा जो मानक विनिर्देशों को पूरा करता है।

(3) इससे पहले जारी किया गया प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा ;

(4) कोई अन्य आदेश जो उचित समझे जाएंगे।

परन्तु किसी भी ऐसे प्रमाण पत्र को संशोधित, निलम्बित या रद्द करने से पहले प्रमाण पत्र को संशोधित निलम्बित या रद्द करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी उसके धारक को ऐसे आधार प्रस्तुत करेगा, जिनमें प्रमाण पत्र का संशोधन/निलम्बन और/या रद्दकरण अपेक्षित है और उसको उक्त सूचना की प्राप्ति के तीन दिन के भीतर आधारों के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा और अभ्यावेदन, यदि कोई है, पर उक्त अधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा और तत्पश्चात् वह अभ्यावेदन की प्राप्ति के तीन दिन के भीतर अन्तिम आदेश जारी करेगा।"।

5. उक्त नियमों के नियम 14 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जारी किया जाएगा, अर्थात् :—

"14क.—अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन मान्यता प्राप्त अभिकरणों द्वारा प्रमाणित माल का पुनः परीक्षण-निदेशक या जहाँ वह ऐसी वांछा करें वहाँ वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा संयुक्त निदेशक से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी को ऐसे माल का जिनके लिए अधिनियम 7 के अधीन किसी मान्यता प्राप्त अभिकरण द्वारा प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है, नियम 11क के अधीन यथाविहित रीति में पुनः परीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और ऐसे पुनः परीक्षण के दौरान मान्यता प्राप्त अभिकरण का एक प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेगा।"।

[मि. सं. 3(69)/64-ई आई एण्ड ईपी]
एन.एस. हरिहरन, निदेशक

पाद टिप्पण :

मूल नियम का.आ. 3317 तारीख 1-10-1964 द्वारा प्रकाशित किए गए और उनका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :

का.आ. 3100 तारीख 29-9-1965
का.आ. 3963 तारीख 6-11-1967
का.आ. 377 तारीख 18-1-1969
का.आ. 3713 तारीख 13-7-1968
का.आ. 1355 तारीख 22-7-1972
का.आ. 103 तारीख 6-1-1973
का.आ. 2603 तारीख 20-3-1977
का.आ. 2745 तारीख 23-9-1973
का.आ. 2365 तारीख 30-9-1973
का.आ. 1496 तारीख 26-9-1981
का.आ. 1551 तारीख 19-3-1983

S.O. 5395.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Export (Quality Control and Inspection) Second Amendment Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2,

(i) after clause (a), the following shall be inserted, namely :—

'(aa) "Additional Director" means the Additional Director of the Council or Agency';

(ii) after clause (b), the following shall be inserted, namely :—

'(bb) "Certificate" means certificate issued under sub-section (3) of section 7 of the Act by any of the Agencies either established or recognised under sub-section (1) of section 7 of the Act stating that the commodity conforms to the condition relating to Quality Control and Inspection;

(iii) after clause (h), the following clause shall be inserted, namely :—

'(hh) "Joint Director" means the Joint Director of the Council or Agency;'.

3. After rule 7 of the said rules, the following shall be inserted, namely :—

"7(A) Authority of authentication and the manner of authentication of documents—Any document received from any place outside India purporting to have affixed, impressed or submitted thereon or thereto, the seal and signature of any person who is authorised by section 3 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), to do any notarial acts shall be deemed to be duly authenticated for the purpose of section 10C(7) (b) of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963".

4. After rule 11 of the said rules, the following shall be inserted, namely :—

"11A—Procedure for Amendment, suspension or cancellation of the certificate—(1) Where the Agency has reason to believe that the certificate issued under sub-section (3) of section 7 of the Act suffers from any of the defects mentioned in sub-section (3A) of the said section 7, the Agency may carry out re-examination of the goods—

(i) during storage, at the premises of exporter or manufacturer or clearing agent or shipping agent or at warehouses and cold storage;

(ii) during the transportion of goods, at any place from the premises as mentioned in clause (i) to the port of shipment;

(iii) during unloading, at the port of shipment;

(iv) during loading, in vessel or aircraft;

(v) during voyage, in vessel.

(2) The re-examination of goods shall be carried out in the following manner :—

(a) The re-examination shall be authorised by the Additional Director or the Joint Director by an order, in writing, and on such authorisation, the certificate of inspection issued for the concerned consignment shall stand suspended.

(b) The re-examination shall be carried out by one or more officers of the Export Inspection Council or Agency who have not inspected the concerned consignment earlier.

(c) The re-examination shall be carried out in the presence of authorised representative of the exporter and/or manufacturer. The re-axamination of the commodity shall be completed within a period of seven days of the period already prescribed for such commodity for the rules framed under section 17 of the Act, whichever is later, from the date when the certificate stands suspended.

(d) After consideration of the results of re-examination, the Additional Director or the Joint Director may order in writing that :—

(i) the consignment shall be released for export;

(ii) the certificate issued earlier shall be amended to the extent of the part of the consignment that meets the standard specifications.

(iii) the certificate issued earlier shall be cancelled.

(iv) Any ther orders which may be deemed fit.

Provided that before amending, suspending or cancelling any such certificate the officer authorised to amend, suspend or cancel the certificate shall furnish the ground which require amendment/suspension and/or cancellation of certificate to the holder thereof who shall be given an opportunity to represent against the grounds within 3 days of the receipt of the said notice and the representation, if any shall be considered by the said officer and thereafter, he shall pass final order within three days from the receipt of the representations.".

5. After rule 14A of the said rules, he following rule shall be issued, namely :—

"14B—Re-examination of the goods certified by the Agencies recognised under sub-section (1) of Section 7 of the Act, the Director or where he so desires by a general or special order may authorise any officer not below the rank of a Joint Director to carry out the re-examination of goods certificate of which has been issued by any of the Agencies recognised under section 7 of the Act, in the manner as prescribed under rule 11A and during such re-examination, a representative of a recognised agency shall be present.".

[F. No. 3/69/84-EI&EP]

N. S. HARIHARAN, Director

Foot Note :

The Principal rules were published vide S.O. 3317 dated 1-10-1964 and amended by :

S.O. 3100 dated 29-9-1965, S.O. 2603 dated 20-8-77, S.O. 3965 dated 6-11-1967, S.O. 2745 dated 23-9-78, S.O. 277 dated 18-1-1969, S.O. 2865 dated 30-9-78, S.O. 2718 dated 23-7-1968, S.O. 2496 dated 26-9-81, S.O. 1855 dated 22-7-1972, S.O. 1551 dated 19-3-83, S.O. 103 dated 6-1-1973.

उद्योग मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1985

का०आ० 5396:—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 6 की उपधारा (1) के परन्तुक के अन्तर्गत न्यायमूर्ति श्री एस० मधुसूदन राव ने 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 4 अक्तूबर, 1985 अपराह्न को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के अध्यक्ष के पद को रिक्त कर दिया।

[पी एफ जी (476)सी एल ए/81-प्रशा०-I]

एल०सी० गोयल, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 6th November, 1985

S.O. 5396.—Under the proviso to sub-section (i) of Section 6 of the MRTP Act, 1969 (54 of 1969), Justice Shri S. Madhusudan Rao, on attaining the age of sixty five years, has demitted the office of the Chairman, MRTP Commission on the afternoon of 4th October, 1985.

[PFG (476) CLA/81-Adm. I]

L. C. GOYAL, Under Secy.

योजना मंत्रालय

(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1985

का. आ. 5397.— इस विभाग का दिनांक 9 जुलाई, 1985 का अधिसूचना सं. एस-12011/2/85 समन्वय का आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम, 1959 की धारा 8(1) के अंतर्गत वर्ष 1986 87 के लिए गठित समिति को केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 31 दिसम्बर, 1985 तक और समय दिया गया है।

[सं. एम-12011/2/85-समन्वय]

आर. एम. सुन्दरम अवर सचिव

MINISTRY OF PLANNING

(Department of Statistics)

New Delhi, the 31st October, 1985

S.O. 5397.—In partial modification of this Department Notification No. M-12011/2/85-Coord. dated 9th July, 1985 the Committee set up under Section 8 (1) of the Indian Statistical Institute Act, 1959 for the year 1986-87 has been given further time up to 31st December, 1985 to submit its report to the Central Government.

[No. M-12011/2/85-Coord.]

R. M. SUNDARAM, Under Secy.

खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1985

का. आ. 5398.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 8 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन 376 लाइसेंसों के ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, उनका मई 1984 में नवीकरण किया गया है।

अनुसूची

क्रम संख्या	सीएम/एल संख्या	वैध तक
(1)	(2)	(3)
1.	0000202	1985-04-30
2.	0000606	1985-04-30
3.	0015013	1985-06-30
4.	0018524	1985-05-31
5.	0018625	1985-03-31
6.	0018726	1985-04-30
7.	0029226	1985-05-15
8.	0039623	1985-03-31
9.	0039835	1985-08-31
10.	0055934	1985-04-30
11.	0057534	1985-03-31
12.	0060826	1985-03-31
13.	0064329	1985-04-15
14.	0080529	1985-05-31
15.	0080630	1985-05-31
16.	0083737	1985-05-31
17.	0098043	1985-04-30
18.	0102109	1985-03-31
19.	0103414	1985-03-31
20.	0103515	1985-03-31
21.	0104517	1985-05-15
22.	0105721	1985-05-15
23.	0113316	1985-03-31
24.	0118528	1985-05-15
25.	0126931	1985-05-31
26.	0142424	1985-04-15
27.	0146331	1985-05-15
28.	0177746	1985-03-31
29.	0184844	1985-04-31
30.	0187244	1985-03-31
31.	0191942	1985-04-30
32.	0194342	1985-03-31
33.	0194544	1985-03-31
34.	0194645	1985-03-31
35.	0195243	1985-03-31
36.	0195448	1985-04-30
37.	0197752	1985-05-15
38.	0226228	1984-09-30
39.	0226834	1985-03-31
40.	0228737	1985-05-31
41.	0228838	1985-05-31
42.	0231726	1985-03-31
43.	0232425	1985-05-15
44.	0235431	1985-04-30
45.	0251126	1985-04-15
46.	0257239	1985-05-15
47.	0259344	1985-03-15
48.	0261432	1985-03-31
49.	0263133	1985-03-31
50.	0264842	1985-03-31
51.	0264943	1985-03-31
52.	0265036	1985-03-31
53.	0274542	1985-03-15
54.	0276849	1985-03-31
55.	0276950	1985-03-31
56.	0281438	1985-05-15
57.	0281842	1985-05-31
58.	0292140	1985-03-31
59.	0298859	1985-03-31
60.	0300618	1985-03-31
61.	0301721	1985-03-31
62.	0304424	1985-04-30
63.	0323327	1985-05-15
64.	0340630	1985-03-31

(1)	(2)	(3)
65.	0357243	1985-4-30
66.	0364240	1985-05-15
67.	0366951	1985-05-31
68.	0367044	1985-05-31
69.	0370942	1985-04-30
70.	0371742	1985-03-31
71.	0373544	1985-05-15
72.	0379758	1985-04-15
73.	0380541	1985-05-31
74.	0382343	1985-04-30
75.	0382545	1985-04-30
76.	0387959	1985-04-15
77.	0388355	1985-05-15
78.	0391041	1985-08-15
79.	0391950	1985-05-15
80.	0413429	1985-05-15
81.	0425032	1985-04-30
82.	0425840	1985-04-30
83.	0426842	1985-03-31
84.	0427440	1985-03-31
85.	0430227	1985-05-15
86.	0430328	1985-04-15
87.	0431126	1985-04-15
88.	0431532	1985-04-15
89.	0431754	1985-04-15
90.	0436037	1985-05-15
91.	0438041	1985-05-15
90.	0436037	1985-05-31
93.	0440432	1985-03-31
94.	0443034	1985-04-30
95.	0447850	1985-05-15
96.	0451134	1985-02-31
97.	0457954	1985-04-15
98.	0485252	1985-03-15
99.	0491247	1985-03-15
100.	0491348	1984-12-31
101.	0493554	1985-04-30
102.	0493756	1985-01-01
103.	0495457	1985-04-30
104.	0504432	1985-04-30
105.	0505636	1985-03-15
106.	0510629	1985-03-15
107.	0513433	1985-04-15
108.	0514839	1985-04-30
109.	0515235	1985-04-30
110.	0515639	1985-04-30
111.	0516338	1985-05-15
112.	0517239	1985-05-15
113.	0519445	1985-05-15
114.	0520733	1985-05-15
115.	0520834	1985-04-30
116.	0522030	1985-03-31
117.	0522131	1985-03-31
118.	0522232	1985-03-31
119.	0525440	1985-04-30
120.	0526139	1985-03-31
121.	0527343	1985-05-31
122.	0528042	1985-04-30
123.	0528143	1985-04-30
124.	0586359	1985-03-31
125.	0589870	1985-05-15
126.	0597970	1985-03-31
127.	0599570	1985-03-15
128.	0599671	1985-03-15
129.	0599772	1985-03-15
130.	0600428	1985-03-15
131.	0600933	1985-03-31
132.	0602533	1985-04-30
133.	0602634	1985-04-30
134.	0603030	1985-03-31
135.	0603636	1985-03-31
136.	0803737	1985-03-31
137.	0604436	1985-04-30
138.	0604537	1985-04-30
139.	0604840	1985-04-30
140.	0605438	1985-03-31
141.	0606137	1985-04-30
142.	0607240	1985-04-30
143.	0608242	1985-05-15
144.	0608444	1985-05-15
145.	0616039	1985-04-30
146.	0631641	1985-05-31
147.	0639756	1985-05-15
148.	0651243	1985-04-30
149.	0666256	1985-01-31
150.	0636561	1985-04-30
151.	0674356	1985-04-30
152.	0674760	1985-02-15
153.	0675560	1985-03-31
154.	0680654	1985-03-15
155.	0681050	1985-03-15
156.	0684662	1985-03-15
157.	0685866	1985-04-30
158.	0689571	1985-04-30
159.	0689975	1985-03-31
160.	0691962	1985-03-31
161.	0692257	1985-04-15
162.	0695465	1985-04-15
163.	0695768	1985-04-15
164.	0696669	1985-04-15
165.	0700634	1985-05-15
166.	0718249	1984-12-31
167.	0737758	1984-11-30
168.	0745757	1985-03-15
169.	0746658	1984-11-15
170.	0748965	1985-04-30
171.	0752350	1985-05-15
172.	0760551	1985-03-31

(1)	(2)	(3)
173.	0762353	1985-03-31
174.	0762856	1985-03-31
175.	0763557	1985-03-31
176.	0764155	1985-03-31
177.	0764761	1985-03-31
178.	0767565	1985-03-31
179.	0770655	1984-05-01
180.	0771859	1985-04-30
181.	0771930	1985-04-30
182.	0772055	1985-04-30
183.	0772556	1985-01-31
184.	0773156	1985-04-30
185.	0773762	1985-04-30
196.	0774057	1985-05-15
187.	0774158	1985-05-15
188.	0774562	1985-05-15
189.	0774966	1985-05-15
190.	0775261	1985-05-15
191.	0775463	1985-05-15
192.	0777972	1985-05-31
193.	0778868	1985-05-31
194.	0778570	1985-05-31
195.	0789474	1985-04-30
196.	0793869	1985-03-15
197.	0806446	1985-03-31
198.	0812746	1985-04-30
199.	0827456	1985-04-30
200.	0841349	1985-03-15
201.	0841652	1985-03-35
202.	0842654	1985-03-15
203.	0842856	1985-03-15
204.	0843959	1985-03-15
205.	0845660	1985-03-15
206.	0846864	1985-04-16
207.	0847583	1985-03-31
208.	0848868	1985-04-30
209.	0848969	1984-03-31
210.	0849768	1985-03-31
211.	0851251	1985-03-31
212.	0851352	1985-03-31
213.	0851959	1985-03-31
214.	0853861	1985-04-15
215.	0854762	1985-04-15
216.	0859671	1985-04-15
217.	0860050	1985-04-15
218.	0863765	1985-04-15
219.	0864159	1985-04-30
220.	0864866	1985-04-30
221.	0865969	1985-04-30
222.	0866163	1985-04-30
223.	0667266	1985-04-30
224.	0867670	1985-05-15
225.	0870053	1985-03-31
226.	0914653	1984-11-30
227.	0914754	1984-11-30
228.	0925860	1984-12-31
229.	0938969	1985-02-15
230.	0942052	1985-02-15
231.	0943155	1985-11-15
232.	0943963	1985-02-28
233.	0944258	1985-02-28
234.	0944569	1985-02-28
235.	0964567	1985-04-30
236.	0946666	1985-03-31
237.	0952459	1985-03-31
238.	0952560	1985-03-31
239.	0952863	1985-03-31
240.	0953764	1985-03-31
241.	0956366	1985-03-31
242.	0956467	1985-03-31
243.	0956568	1985-03-31
244.	0956669	1985-03-31
245.	0957772	1985-05-31
246.	0958471	1985-03-31
247.	0958673	1985-03-31
248.	0958774	1985-03-31
249.	0959170	1985-03-31
250.	0959271	1985-03-31
251.	0960155	1985-04-15
252.	0962159	1985-04-15
253.	0962260	1985-04-15
254.	0962765	1985-04-30
255.	0963262	1985-04-30
256.	0963565	1985-04-30
257.	0963969	1985-04-30
258.	0964062	1985-04-30
259.	0964668	1985-04-30
260.	0965468	1985-04-30
261.	0965569	1985-04-30
262.	0965670	1985-04-30
263.	0966167	1985-04-30
264.	0966268	1985-04-30
265.	0966470	1985-04-30
266.	0966571	1985-04-30
267.	0966975	1985-05-15
268.	0967169	1985-05-15
269.	0967270	1985-05-15
270.	0970562	1985-05-31
271.	0970764	1985-05-15
272.	0970966	1985-05-31
273.	0971160	1985-05-31
274.	0972669	1985-05-31
275.	0981769	1985-05-15
276.	1014117	1984-12-15
277.	1014824	1984-12-15
278.	1026831	1985-03-31

(1)	(2)	(3)
279.	102 31	1985-01-31
280.	1027833	1985-01-31
281.	1029635	1985-03-31
282.	1035630	1985-02-15
283.	1041827	1985-03-15
284.	1043427	1985-03-15
285.	1043538	1985-04-30
286.	1060932	1985-03-15
287.	1050525	1985-03-15
288.	1052125	1985-03-15
289.	1054634	1985-03-31
290.	1055030	1984-06-15
291.	1055939	1985-05-31
292.	1058137	1985-03-31
293.	1058339	1985-03-31
294.	1058440	1985-03-31
295.	1058642	1985-03-31
296.	1059139	1985-03-31
297.	1059240	1985-03-31
298.	1060331	1985-03-31
299.	1062330	1985-04-15
300.	1068342	1985-03-31
301.	1070733	1985-04-30
302.	1071533	1985-04-30
303.	1072434	1985-04-30
304.	1072737	1985-04-30
305.	1073133	1985-04-30
306.	1073537	1985-05-15
307.	1073638	1985-05-15
308.	1073941	1035-04-30
309.	1074236	1985-04-30
310.	1075440	1985-05-15
311.	1075743	1985-05-15
312.	1077141	1985-05-15
313.	1077848	1985-05-15
314.	1079549	1985-05-31
315.	1079852	1985-05-31
316.	1080231	1985-05-31
317.	1081435	1985-05-31
318.	1085742	1985-05-31
319.	1084037	1985-05-31
320.	1086546	1985-05-31
321.	1090234	1985-05-31
322.	1095850	1985-07-15
323.	1100110	1985-05-31
324.	1102518	1985-04-30
325.	1109734	1984-08-31
326.	1128839	1984-11-15
327.	1148037	1985-01-15
328.	1159547	1985-02-15
329.	1160936	1985-03-31
330.	1168043	1985-03-15
331.	1171638	1985-03-31
332.	1174240	1985-03-31
333.	1172539	1985-03-31
334.	1172943	1985-03-31
335.	1173340	1985-03-31
336.	1175444	1985-03-31
337.	1177044	1985-04-15
338.	1177347	1985-04-15
339.	1178753	1985-04-15
340.	1179048	1985-04-15
341.	1179654	1985-05-15
342.	1179855	1985-04-30
343.	1179957	1985-04-30
344.	1180033	1985-04-30
345.	1180134	1985-04-30
346.	1180235	1985-04-30
347.	1180740	1985-04-30
348.	1180841	1985-05-15
349.	1181742	1985-04-30
350.	1182239	1985-04-30
351.	1182340	1985-04-30
352.	1182441	1985-04-15
353.	1183140	1985-05-15
354.	1183241	1985-05-15
355.	1183746	1985-05-15
356.	1184142	1985-05-15
357.	1184344	1985-05-15
358.	1184546	1985-05-15
359.	1184647	1985-05-15
360.	1184740	1985-05-15
361.	1184849	1985-05-15
362.	1184950	1955-05-15
363.	1185043	1985-04-03
364.	1185043	1985-04-03
365.	1185144	1985-05-15
366.	1185750	1985-05-15
367.	1186146	1985-05-15
368.	1186247	1985-05-15
369.	1186348	1985-05-15
370.	1187249	1985-05-15
371.	1187451	1985-05-15
372.	1187552	1985-05-15
373.	1187754	1985-05-31
374.	1188655	1985-05-31
375.	1196755	1985-05-15
376.	1204122	1985-03-31

[सं. सी.एम.डी 13 : 1:]

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 31st October, 1985

S. O. 5398 In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations 1955, as amended from time to time, the Indian

Standards Institution, hereby, notifies that 376 licences, particulars of which are given in the following Schedule, have been renewed during the month of May 1984 :

SCHEDULE

Sl. No.	CM/L No.	Valid upto
(1)	(2)	(3)
1.	0000202	1985-04-30
2.	0000606	1985-04-30
3.	0015013	1985-04-30
4.	0018524	1985-05-31
5.	0018625	1985-03-31
6.	0018726	1985-04-30
7.	0029226	1985-05-15
8.	0039633	1985-03-31
9.	0039835	1985-03-31
10.	0055934	1985-04-30
11.	0057536	1985-03-31
12.	0060826	1985-03-31
13.	0064329	1985-04-15
14.	0080529	1985-05-31
15.	0080630	1985-05-31
16.	0083737	1985-03-31
17.	0098043	1985-04-30
18.	0102109	1985-03-31
19.	0103414	1985-03-31
20.	0103515	1985-03-31
21.	0104517	1985-05-15
22.	0105721	1985-05-15
23.	0113316	1985-03-31
24.	0118528	1985-05-15
25.	0126931	1985-05-31
26.	0142424	1985-04-15
27.	0146331	1985-05-15
28.	0177746	1985-03-31
29.	0184844	1985-04-31
30.	0187244	1985-03-31
31.	0191942	1985-04-03
32.	0194342	1985-03-31
33.	0194544	1985-03-31
34.	0194645	1985-03-31
35.	0195243	1985-03-31
36.	0195748	1985-04-30
37.	0197752	1985-05-15
38.	0226228	1984-09-30
39.	0226834	1985-03-31
40.	0228737	1985-05-31
41.	0228838	1985-05-31
42.	0231726	1985-03-31
43.	0232425	1985-05-31
44.	0235431	1985-04-30
45.	0251126	1985-04-15
46.	0257239	1985-05-15
47.	0259344	1985-03-15
48.	0261432	1985-03-31
49.	0263133	1985-03-31
50.	0264842	1985-03-31
51.	0264943	1985-03-31
52.	0265036	1985-03-31
53.	0274542	1985-03-15
54.	0276849	1985-03-31
55.	0276950	1985-03-31
56.	0281438	1985-05-15
57.	0281842	1985-05-31
58.	0292140	1985-03-31
59.	0298859	1985-03-31
60.	0300618	1985-03-31
61.	0301721	1985-03-31
62.	0304424	1985-04-30
63.	0323327	1985-05-15
64.	0340630	1985-03-31
65.	0357243	1985-04-30
66.	0364240	1985-05-15
67.	0366951	1985-05-31
68.	0367044	1985-05-31
69.	0370942	1985-04-30
70.	0371742	1985-03-31
71.	0373544	1985-05-15
72.	0379758	1985-04-15
73.	0380541	1985-05-31
74.	0382343	1985-04-30
75.	0382545	1985-04-30
76.	0387959	1985-04-15
77.	0388355	1985-05-15
78.	0391041	1985-08-15
79.	0391950	1985-05-15
80.	0413429	1985-05-15
81.	0425032	1985-04-30
82.	0425840	1985-04-30
83.	0426842	1985-03-31
84.	0427440	1985-03-31
85.	0430227	1985-05-15
86.	0430328	1985-04-15
87.	0431128	1985-04-15
88.	0431532	1985-04-15
89.	0431734	1985-04-15
90.	0436037	1985-05-15
91.	0438041	1985-05-15
92.	0439245	1985-05-31
93.	0440432	1985-03-31
94.	0443034	1985-04-30
95.	0447850	1985-03-15
96.	0451134	1985-03-31
97.	0457954	1985-04-15
98.	0485252	1985-03-15
99.	0491247	1985-05-15
100.	0491348	1984-12-31
101.	0493354	1985-04-30
102.	0493756	1985-01-01
103.	0495457	1985-04-30
104.	0504432	1985-04-30
105.	0505636	1985-03-15
106.	0510629	1985-03-15
107.	0513433	1985-04-15
108.	0514839	1985-04-30
109.	0515235	1985-04-30
110.	0515639	1985-04-30
111.	0516338	1985-05-15
112.	0517239	1985-05-15
113.	0519445	1985-05-15
114.	0520733	1985-05-15
115.	0520834	1985-04-30
116.	0522030	1985-03-31
117.	0522131	1985-03-31
118.	0522232	1985-03-31
119.	0525440	1985-04-30
120.	0526139	1985-03-31

(1)	(2)	(3)
121.	0527343	1985-05-31
122.	0528042	1985-04-30
123.	0528143	1985-04-30
124.	0586359	1985-03-31
125.	0589870	1995-05-15
126.	0597970	1985-03-31
127.	0599570	1985-03-15
128.	0599671	1985-03-15
129.	0599772	1985-03-15
130.	0600428	1985-03-15
131.	0600933	1985-03-31
132.	0602533	1985-04-30
133.	0602634	1985-04-30
134.	0603030	1985-03-31
135.	0603636	1985-03-31
136.	0603737	1985-03-31
137.	0604436	1985-04-30
138.	0604537	1985-04-30
139.	0604840	1985-40-30
140.	0605438	1985-03-31
141.	0606137	1985-04-30
142.	0607240	1985-04-30
143.	0608242	1985-05-15
144.	0608444	1985-05-15
145.	0616039	1985-04-30
146.	0631641	1985-05-31
147.	0639758	1985-05-15
148.	0651243	1985-04-30
149.	0666256	1985-01-31
150.	0667561	1985-04-30
151.	0674356	1985-04-30
152.	0674760	1985-02-15
153.	0675560	1985-03-31
154.	0680654	1985-03-15
155	0681050	1985-03-15
156.	0684662	1985-03-15
157.	0685866	1985-04-30
158.	0689571	1985-04-30
159.	0689975	1985-03-31
160.	0691962	1985-03-31
161.	0692257	1985-04-15
162.	0695465	1985-04-15
163.	0695768	1985-04-15
164.	0696669	1985-04-15
165.	0700634	1985-05-15
166.	0718249	1984-12-31
167.	0737758	1984-11-30
168.	0745757	1885-03-15
169.	0746658	1984-11-15
170.	0748965	1985-04-30
171.	0752350	1985-05-15
172.	0760551	1985-03-31
173.	0762353	1985-03-31
174.	0762656	1985-03-31
175.	0763557	1985-03-31
176.	0764155	1985-03-31
177.	0764761	1985-03-31
178.	0767565	1985-03-31
179.	0770655	1984-05-01
180.	0771859	1985-04-30
181.	0771960	1985-04-30
182.	0772053	1985-04-30
183.	0772356	1985-01-31
184.	0773156	1985-04-30
185.	0773762	1985-04-30
186.	0774057	1985-05-15
187.	0774158	1985-05-15
188.	0874562	1985-05-15
189.	0774966	1985-05-15
190.	0775261	1985-05-15
191.	0775463	1985-05-15
192.	0777972	1985-05-31
193.	0778368	1985-05-31
194.	0778570	1985-05-31
195.	0789474	1985-04-30
196.	0793869	1985-03-15
197.	0806448	1985-03-31
198.	0812746	1985-04-30
199.	0827456	1985-04-30
200.	0841349	1985-03-15
201.	0841652	1985-03-15
202.	0842654	1985-03-15
203.	0842856	1985-03-15
204.	0843959	1985-03-15
205.	0845660	1985-03-15
206.	0846864	1985-04-16
207.	0847563	1985-03-31
208.	0848868	1985-04-30
209.	0848969	1984-03-31
210.	0849769	1985-03-31
211.	0851251	1985-03-31
212.	0851352	1985-03-31
213.	0851958	1985-03-31
214.	0853861	1985-04-15
215.	0854762	1985-04-15
216.	0859671	1985-04-15
217.	0860050	1985-04-15
218.	0863763	1985-04-15
219.	0864159	1985-04-30
220.	0864866	1985-04-30
221.	0865969	1985-04-30
222.	0866163	1985-04-30
223.	0867266	1985-04-30
224.	0867670	1985-05-15
225.	0870053	1985-05-31
226.	0914653	1984-11-30
227.	0914754	1984-11-30
228.	0925860	1984-12-31
229.	0938869	1985-02-15
230.	0942052	1985-02-15
231.	0943155	1985-11-15
232.	0943963	1985-02-28
233.	0944258	1985-02-28
234.	0944359	1985-02-28
235.	0964567	1985-04-30
236.	0946666	1985-03-31
237.	0952459	1985-03-31
238.	0952560	1985-03-31
239.	0952863	1985-03-31
240.	0953764	1985-03-31
241.	0956366	1985-03-31
242.	0956467	1985-03-31
243.	0956568	1985-03-31
244.	0956669	1985-03-31
245.	0957772	1985-03-31
246.	0958471	1985-03-31
247.	0958673	1985-03-31
248.	0958704	1985-03-31
249.	0959170	1985-03-31
250.	0959271	1985-03-31
251.	0960155	1985-04-15
252.	0962159	1985-04-15
253.	0962260	1985-04-15
254.	0962765	1985-04-30
255.	0963262	1985-04-30

(1)	(2)	(3)
256.	0963565	1985-04-30
257.	0963969	1985-03-30
258.	0964062	1985-04-30
259.	0964668	1985-04-30
260.	0965468	1985-04-30
261.	0965569	1985-04-30
262.	0965670	1985-04-30
263.	0966167	1985-04-30
264.	0966268	1985-04-30
265.	0966470	1985-04-30
266.	0966571	1985-04-30
267.	0966975	1985-05-15
268.	0967169	1985-05-15
269.	0967270	1985-05-15
270.	0970562	1985-05-31
271.	0970764	1985-05-15
272.	0970966	1985-05-31
273.	0971160	1985-05-31
274.	0972869	1985-05-31
275.	0981769	1985-05-15
276.	1014117	1984-12-15
277.	1014824	1984-12-15
278.	1026831	1985-03-31
279.	1027631	1985-01-31
280.	1027833	1985-01-31
281.	1029635	1985-03-31
282.	1035630	1985-02-15
283.	1041827	1985-03-15
284.	1043427	1985-03-15
285.	1048538	1985-04-30
286.	1060932	1985-03-31
287.	1050525	1985-03-15
288.	1052125	1985-03-15
289.	1054634	1985-03-31
290.	1055030	1984-06-15
291.	1055939	1985-05-31
292.	1058137	1985-03-31
293.	1058339	1985-03-31
294.	1058440	1985-03-31
295.	1058642	1985-03-31
296.	1059139	1985-03-31
297.	1059240	1985-03-31
298.	1060831	1985-03-31
299.	1062330	1985-04-15
300.	1068342	1985-03-31
301.	1070733	1985-04-30
302.	1071533	1985-04-30
303.	1072434	1985-04-30
304.	1072737	1985-04-30
305.	1073133	1985-04-30
306.	1073537	1985-05-15
307.	1073638	1985-05-15
308.	1073941	1985-04-30
309.	1074236	1985-04-30
310.	1075440	1985-05-15
311.	1075743	1985-05-15
312.	1077141	1985-05-15
313.	1077848	1985-05-15
314.	1079549	1985-05-31
315.	1079852	1985-05-31
316.	1080231	1985-05-31
317.	1081435	1985-05-31
318.	1083742	1985-05-31
319.	1084037	1985-05-31
320.	1086546	1985-05-31
321.	1090234	1985-05-31
322.	1095850	1984-07-15
323.	1100110	1985-05-31
324.	1102518	1985-04-30
325.	1109734	1984-08-31
326.	1128839	1984-11-15
327.	1148037	1985-01-15
328.	1159547	1985-02-15
329.	1160936	1985-03-31
330.	1168043	1985-03-15
331.	1171638	1985-03-31
332.	1174240	1985-03-31
333.	1172539	1985-03-31
334.	1172943	1985-03-31
335.	1173340	1985-03-31
336.	1175444	1985-03-31
337.	1177044	1985-04-15
338.	1177347	1985-04-15
339.	1178753	1985-04-15
340.	1179048	1985-04-15
341.	1179654	1985-05-15
342.	1179856	1985-04-30
343.	1179957	1985-04-30
344.	1180033	1985-04-30
345.	1180134	1985-04-30
346.	1180235	1985-04-30
347.	1180740	1985-04-30
348.	1180841	1985-05-15
349.	1181742	1985-04-30
350.	1182239	1985-04-30
351.	1182340	1985-04-30
352.	1182441	1985-04-15
353.	1183140	1985-05-15
354.	1183241	1985-05-15
355.	1183746	1985-05-15
356.	1184142	1985-05-15
357.	1184344	1985-05-15
358.	1184546	1985-05-15
359.	1184647	1985-05-15
360.	1184748	1985-05-15
361.	1184849	1985-05-15
362.	1184950	1985-05-15
363.	1185043	1985-04-30
364.	1185043	1985-04-30
365.	1185144	1985-05-15
366.	1185750	1985-05-15
367.	1186146	1985-05-15
368.	1186247	1985-05-15
369.	1186348	1985-05-15
370.	1187249	1985-05-15
371.	1187451	1985-05-15
372.	1187552	1985-05-15
373.	1187754	1985-05-31
374.	1188655	1985-05-31
375.	1196755	1985-05-15
376.	1204122	1985-03-31

[No. CMD/13 : 12]

का. आ. 5399:—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन मुहर) विनियम 1955 के विनियम 4 के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 3 के उपविनियम (1) के अनुसार प्राप्त अधिकारों के अधीन यहां अनुसूची में दिए भारतीय मानकों के संशोधन जारी किए जाते है।

अनुसूची

क्रम सं.	संशोधित भारतीय मानक की पद संख्या एवं शीर्षक	जिस राजपत्र में भारतीय मानक के निर्धारित होने की सूचना छपी थी उसकी संख्या तिथि एवं शीर्षक	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन का संक्षिप्त विवरण	संशोधन लागू होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	IS: 413–1974 गोल छेदकों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एस.ओ. 1982 दिनांक 1976-01-10	संख्या 1 अगस्त 1982	खंड 4 के स्थान पर नया खंड दिया गया है।	1982-08-3
2.	IS: 418–1978 टंग्स्टन फिलामेंट के सामान्य कार्य के बिजली के लैंपों की विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)	एस०ओ 2584 दिनांक 1981-10-03	*संख्या 2 अप्रैल 1982	(पृष्ठ 3, खंड 0.3 अंतिम वाक्य हटा दें)	1982-04-30
3.	IS: 513–1973 ठंडी वेल्लित कार्बन इस्पात की चद्दरों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एस. ओ. 2537 दिनांक 1975-08-09	†संख्या 2 अगस्त 1982	इस भारतीय मानक में "पंक्तियों" को सम्मिलित करने के उद्देश्य से इस संशोधन को जारी करने का निर्णय किया गया है।	1982-08-31
4.	IS: 736–1974 (सामान्य इंजीनियरी कार्यों के लिए पिटवां एल्यूमिनियम एवं एल्यूमिनियम मिश्र धातु की प्लेट की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एस. ओ. 1092 2238 दिनांक 1978-08-05	संख्या 2 अगस्त 1982	सारणिया 1, 2 और परिशिष्ट बी का संशोधन किया गया है।	1982-08-31
5.	IS: 1038–1975 इस्पात के दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एस.ओ. 2239 दिनांक 1978-08-05	संख्या 1 अगस्त 1982	(1) आकृति 2 सी, आकृति 5 और आकृति 28 का संशोधन किया गया है। (2) खंड 6-2-3 का संशोधन किया गया है।	1982-08-31
6.	IS: 1135–1973 स्वचल वाहनों के निलम्बन के लिए पत्तीदार कमानियों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	—	संख्या 2 अप्रैल 1981	खंड 14.2 (बी) का संशोधन किया गया है।	1981-04-30
7.	IS: 1498–1970 सामान्य इंजीनियरी कार्यों के लिए मृदा वर्गीकरण और पहचान (पहला पुनरीक्षण)	एस. ओ. 51, दिनांक 1974-02-23	संख्या 1 अगस्त 1982	(1) खंड 3.8 के बाद खंड 3.9 को जोड़ा गया है। (2) पृष्ठ 14 पर, स्तम्भ 5 के अन्तर्गत क्रम संख्या (2) के सामने नई सामग्री जोड़ी गई है।	1982-08-31

*भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिन्ह योजना हेतु यह संशोधन 1982-12-16 से लागू होगा।

† भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिन्ह योजना हेतु यह संशोधन 1982-11-01 से लागू हुए।

1	2	3	4	5	6
				(3) सारणी 5 के अन्तर्गत टिप्पणी 4 के बाद एक नई टिप्पणी 5 जोड़ी गई है। (4) सारणी 7 के बाद सारणी 8 जोड़ी गई है।	
8. IS:2339–1963 सामान्य कार्यों के लिए दोहरे डिब्बे में एल्युमिनियम रोगन की विशिष्टि	एस. ओ. 2647 दिनांक 1963-09-14	*संख्या 2 अगस्त 1982		4 लीटर से अधिक की क्षमता वाले दोहरे डिब्बों में एल्युमिनियम के रोगन की पैकिंग में निर्माताओं द्वारा अनुभव की गई कठिनाईयों को दूर करने के लिए यह संशोधन जारी किया जा रहा है।	1982-08-31
9. IS:2720 (भाग 2)–1973 मृदा परीक्षण पद्धतियां, मात्रा ज्ञात करना (दूसरा पुनरीक्षण)	एस. ओ. 3069 दिनांक 1975-09-13	संख्या 1 अगस्त 1983		(1) खंड 4.1 और 16.1 का संशोधन किया गया है। (2) पृष्ठ 4 और 8 पर "+" और "×" चिन्हों वाली पाद टिप्पणियों के स्थान पर नई पाद टिप्पणियां दी गई है। (3) खंड 28.3 एवं 28.4 के अन्तर्गत दी गई टिप्पणियों के स्थान पर नई टिप्पणियां दी गई हैं।	1982-08-31
10. IS:2720 (भाग-4—1975 मृदा परीक्षण पद्धतियां: भाग 4 कण के आकार का विश्लेषण (पहला पुनरीक्षण)	एस. ओ. 3531 दिनांक 1978-11-25	संख्या 1 अगस्त 1982		(1) खंड 3.1.2. 4.1.2. 4.2, 3.1.3.2, और 5.13.4. का संशोधन किया गया है। (2) पृष्ठ 5 पर "×" वाली, पृष्ठ 6 पर "+" चिन्ह वाली, पृष्ठ 7 पर "×" एवं "+" चिन्ह वाली और पृष्ठ 13 एवं 17 पर "×" चिन्ह वाली पाद टिप्पणियों के स्थान पर नई पाद टिप्पणियां दी गई है।	1982-08-31
11. IS:2911 (भाग1/खंड 1)–1979 पाइल नींवों के निर्माण एव डिजाइन की रीति संहिता भाग	—	संख्या 1 अगस्त 1982		(1) खंड 6.2, ए–1.1, एवं ए-3.1 का संशोधन किया गया है।	1982-08-31

*भारतीय मानक संस्था के प्रमाणन चिन्ह योजना हेतु यह संशोधन 1982-12-16 से लागू हुआ।

	1 कंक्रीट के पाइल, खंड 1 एवं स्थान पर ठोक कर डाली गई कंक्रीट की पाइल (पहला पुनरीक्षण)		(2) पृष्ठ 15 एवं 19 पर क्रमानुसार "††" और "×" चिन्हों वाली पाद-टिप्पणियों के स्थान पर नई पाद टिप्पणियां दी गई है। (3) पृष्ठ 15, खंड 6.1 लाइन (2) — : 804–1978" के बाद : 1489–1976"(×) को जोड़ा गया है। (4) पृष्ठ 15 पर "ππ" चिन्ह वाली पाद टिप्पणी के बाद "§§" चिन्ह वाली एक नई पाद टिप्पणी जोड़ी गई है।	
12.	IS:2911(भाग 1/खंड-2) 1979 पाइल नीवों के निर्माण एवं डिजाइन की रीति संहिता : भाग 1: कंक्रीट पाइल खंड 2 बोर करके एवं स्थान पर डाली पाइल (पहला पुनरीक्षण)	—	संख्या 1 अगस्त 1982	(1) खंड 6.1 के स्थान पर नया खंड दिया गया है। (2) खंड 6.2, बी- 1.1 एवं बी–2.2, का संशोधन किया गया है। (3) पृष्ठ 15 पर "††" चिन्ह वाली और पृष्ठ 23 पर "×" चिन्ह वाली पाद टिप्पणियों के स्थान पर नई पाद टिप्पणियां दी गई है। (4) खंड ए-3.1 (सी) से (एफ) तक के अन्तर्गत वर्तमान सामग्री के स्थान पर नई सामग्री दी गई है। (5) पृष्ठ 24 आकृति 1 के स्थान पर नई आकृति दी गई है। (6) खंड 5.11.1 के बाद एक नई टिप्पणी जोड़ी गई है। (7) पृष्ठ 15 पर "‖‖" चिन्ह वाली पादटिप्पणी के बाद "ππ" चिन्ह वाली एक नई पादटिप्पणी जोड़ी गई है।	1982-08-31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	IS : 2911 (भाग 1/खंड 3)—1979 पाइल नींवों के निर्माण एवं डिजाइन की रीति संहिता भाग 1 कंक्रीट पाइल खंड 3 पूर्व निर्मित ठोक कर डाली पूर्व निर्मित कंक्रीट पाइलें (पहला पुनरीक्षण)	—	संख्या 1 अगस्त 1982	(1) खंड 6.2, 7.5.7, ए-1.1, ए-2.2, ए-2.3, 5.1, 5.11.6.1 और 6.1 का संशोधन किया गया है। (2) पृष्ठ 28 पर "+" चिन्ह वाली और "×" चिन्ह वाली के स्थान पर नई पाद टिप्पणी दी गई है। (3) पृष्ठ 29 की आकृति 1 के स्थान पर नई आकृति दी गई है। (4) खंड 5.11.7.1 के बाद नई टिप्पणी जोड़ी गई है। (5) पृष्ठ 17 पर "//" चिन्ह वाली पादटिप्पणी के बाद "× ×" चिन्ह वाली नई पाद टिप्पणी जोड़ी गई है।	1982-08-31
14.	IS : 3082—1973 षड्भुज साकेट पेंच की चाबियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस. ओ० 4690 दिनांक 1975-11-01	संख्या 1 अगस्त 1982	(1) खंड 4.6 और 9 के स्थान पर नए खंड दिए गए हैं। (2) खंड 8.1 का संशोधन किया गया है। (3) पृष्ठ 2 पर व्याख्यात्मक टिप्पणी का संशोधन किया गया है।	1982-08-31
15.	IS : 4338—1974 गृह कार्यों के लिए सिलाई की मशीनों के खड़े दोलायमान शटलों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस० ओ० 3494 दिनांक 1976-10-02	संख्या 2 अगस्त 1982	(1) खंड 4.1, 4.2 और 6.1 के स्थान पर नए खंड दिए गए हैं। (2) खंड 5 के अन्तर्गत अनौपचारिक सारणी का संशोधन किया गया है। (3) (पृष्ठ 2, खंड 6.2 से 6.4)—हटा दें।	1982-08-31
16.	IS : 4775—1976 स्वचालित एवं अंडरपिक करघों के लिए पिकिंग स्टिकों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस० ओ० 99 दिनांक 1980-01-12	संख्या 2 अगस्त 1982	(1) खंड 2.1 के अन्त में एक वाक्य जोड़ा गया है। (2) खंड 6.4 के बाद परिशिष्ट "ए" जोड़ा गया है।	1982-08-31
17.	IS : 5085—1976 ऊन की बुनी टोपियों (बेरेट) की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस० ओ० 3823 दिनांक 1979-11-24	संख्या 1 अगस्त 1982	यह संशोधन निम्नलिखित दो उद्देश्यों में लागू किया गया है। टोपियों की बुनाई में प्रयुक्त हौजरी धागे का दृढ़न भार निर्धारित करना; और यदि ये टोपियां रक्षा	1982-08-31

1	2	3	4	5	6
				मंत्रालय द्वारा मांगी गई हैं तो पोछे की बजाय बेवेल की दाई और नाकों के लिए विकल्पी स्थान का प्रावधान करना ।	
18.	IS : 5554–1970 लग वाले ताल के वाशरों की विशिष्टि	एस० ओ० 3305 दिनांक 1972-10-21	संख्या 2 1982	(1) खंड 5 के स्थान पर नया खंड दिया गया है। (2) पृष्ठ 2, "×" चिन्ह वाली पादटिप्पणी हटा दें।	1982-08-31
19.	IS : 5366–1978 मोर्स गाव-दम शेंकों की कोरड़िल, की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस० ओ० 2271 दिनांक 1981-08-29	संख्या 1 अगस्त 1982	सारणी 1 का संशोधन किया गया है।	1982-08-31
20.	IS : 5695–1970 चश्मे के लेन्सों की विशिष्टि	एस० ओ० 3544 दिनांक 1971-09-25	संख्या 2 अगस्त 1982	खंड 2का संशोधन किया गया है।	1982-04-30
21.	IS : 6550–1971, समान्तर-शैंक वाले चुड़ी ताले सिंकिंग कर्तकों की विशिष्टि	एस० ओ० 1853 दिनांक 1974-07-27	संख्या 2 अगस्त 1982	खंड 1 के स्थान पर नया खंड दिया गया है।	1982-08-31
22.	IS : 6554–1972 सीधे आर-पार जोड़ों की जोड़चुड़ी झलाई फेरूल की विशिष्टि	---	संख्या 1 अगस्त 1982	(1) खंड 1.3 एवं सारणी 1 का संशोधन किया गया है। (2) खंड 5 के बाद नया खंड 5.1 जोड़ा गया है।	1982-08-31
23.	IS : 6583–1972 रेल गाड़ों में प्रकाश व्यवस्था के लिए पट्टे की विशिष्टि	एस० ओ० 1853 दिनांक 1975-08-09	संख्या 1 दिसम्बर 1981	खंड 6.2 का संशोधन किया गया है।	1981-12-31
24.	IS : 6948–1973 जहाजों के लिए निचला अस्तर देने के लिए तैयार मिश्रित संश्लिष्ट रोगन की विशिष्टि	एस० ओ० 2558 दिनांक 1975-08-09	संख्या 1 अगस्त 1982	(1) खंड 3.1, 3.5, 6.2 और ए-2.2 का संशोधन किया गया है। (2) पृष्ठ 4 पर "††" चिन्ह वाली एवं "‖" चिन्हों वाली और पृष्ठ 7 पर "+" चिन्ह वाली पादटिप्पणियों के स्थान पर नई पाद टिप्पणियां दी गई हैं। (3) पृष्ठ 5, "×" चिन्ह वाली पादटिप्पणी)— "(पुनरीक्षित)" के स्थान पर (दूसरा पुनरीक्षण) कर लें। (4) (पृष्ठ 8, "+" चिन्ह वाली पादटिप्पणी)— "(पुनरीक्षित)" के स्थान पर "(दूसरा पुनरीक्षण)" कर लें।	1982-08-31

1	2	3	4	5	6
25.	IS : 7406 (भाग 1)—1974 उर्वरक भरने के लिए पटसन के बोरों की विशिष्टि भाग 1 407 ग्राम/मी², 85×39 तिरपाल के कपड़े के बने परतदार बोरे।	एस० ओ० 1232* दिनांक 1976-04-03	संख्या 4 अगस्त 1982	(1) सारणी 1 का संशोधन किया गया है। (2) खंड बी-1.2, बी-1.4.1 और बी-1.5 के स्थान पर नए खंड दिए गए हैं। (3) खंड बी-.0.1 के बाद खंड बी-0.2 जोड़ा गया है।	1982-08-31
26.	IS : 7406 (भाग 2)—1980 खाद भरने के लिए पटसन के बोरों की विशिष्टि भाग 2,380 ग्राम मी² 2, 68×39 तिरपाल के कपड़े से बने परतदार बोरे।	—वही—	* संख्या 1 अगस्त 1982	सारणी 1 का संशोधन किया गया है।	1982-08-30
27.	IS : 7597—1974 सतह सक्रियक एजेन्टों से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली	एस० ओ० 3530 दिनांक 1977-11-19	संख्या 1 अगस्त 1982	(1) खंड 4.1.4 के स्थान पर नया खंड दिया गया है। (2) खंड 4.2 का संशोधन किया गया है। और खंड 4.2 के बाद नया खंड 4.2.1, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.7, 4.2.1.8, 4.2.2, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3 जोड़े गए हैं।	1982-08-31
28.	IS : 7784 (भाग 1)—1975 अरवार जल निकास कार्यों के डिजाइन की रीति संहिता भाग 1 सामान्य विशेषताएं	एस० ओ० 3351 दिनांक 1978-11-25	संख्या 2 अगस्त 1982	खंड 7.4.4.1 (बी) और खंड 7.4.4.2 का संशोधन किया गया है।	1982-08-31
29.	IS : 8301—1976 115° कोण की बरमों के लिए (टाइप ए बी) कारबाइड टिप माप	एस० ओ० 415 दिनांक 1980-02-23	संख्या 1 अगस्त 1982	(1) खंड 2 के अन्तर्गत वर्तमान आकृति के स्थान पर नई आकृति दी गई है। (2) खंड 2 के अन्तर्गत अनौपचारिक सारणी के अन्त में नई सामग्री जोड़ी गई है।	1982-08-31
30.	IS : 9113—1979 पटसन के टाट की विशिष्टि सामान्य अपेक्षाएं	एस० ओ० 1342 दिनांक 1982-04-03	संख्या 2 अगस्त 1982	(1) खंड 14 एवं 14.2 का संशोधन किया गया है। (2) खंड 15 एवं 15.1 के स्थान पर नए खंड दिए गए हैं।	1982-08-31

*इन संशोधनों की प्रतियां भारतीय मानक संस्था, मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली एवं अहमदाबाद, बम्बई, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कलकत्ता, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, पटना एवं तिरुवेन्द्रम स्थित शाखा कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं।

[सं० सीएमडी/13 : 5]

बी० एन० सिंह, अपर महानिदेशक

S.O. 5399.—In pursuance of regulation 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulation, 1955, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that amendment(s) to the Indian Standard(s) given in the schedule hereto annexed have been issued under the powers conferred by the sub-regulation (1) of Regulation 3 of the said Regulations.

SCHEDULE

Sl. No.	No. and title of the Indian Standard amended	No. and Date of Gazette Notification in which the establishment of the Indian Standard was notified	No. and Date of the amendment	Brief Particulars of the amendment	Date from which the amendment shall have effect
1	2	3	4	5	6
1.	IS : 413—1974 Specification for round punches (Second Revision)	S.O. 182 dt. 1976-01-10	No. 1 Aug 1982	Clause 4 have been substituted by a new one	1982-08-31
2.	IS : 418—1978 Specification for tungsten filament general service electric lamps (Third Revision)	S. O. 2584 dt. 1981-10-03	*No. 2 Apr 1982	(Page 3. clause 0.3, last sentence) Delete	1982-04-30
3.	IS : 513—1973Specification for cold rolled carbon steel sheets (Second Revision)	S.O. 2557 dt. 1975-08-09	**No. 2 Aug 1982	(In order to cover 'strips' in this Indian Standard, it has been decided to issue this amendment)	1982-08-31
4.	IS : 736—1974 Specification for wrought aluminium and aluminium alloys, plate (for general engineering purposes) (Second Revision)	S. O. 1092 dt. 1977-04-09	No. 2 Aug 1982	Tables 1, 2 and Appendix B have been amended	1982-08-31
5.	IS : 1038—1975 Specification for steel doors, windows and ventilators (Second Revision)	S.O. 2239 dt. 1979-08-05	No. 1 Aug 1982	(i) Fig 2C, Fig 5 and Fig 7B have been amended (ii) Clause 6.2.3. has been amended	1982-08-31
6.	IS : 1135—1973 Specification for leaf springs for automobile suspension (Second Revision)		No. 2 Apr 1981	Clause 14.2 (b) has been amended	1981-04-30
7.	IS : 1498—1970 Classification and identification of soils for general engineering purposes (First Revision)	S.O. 510 dt. 1974-02-23	No. 1 Aug 1982	(i) Clause 3.9. has been added after clause 3.8. (ii) New matter has been added at page 14, under col. 5 against Sl No. (ii) (iii) A new note 5 has been added under table 5 after note 4 (iv) Table 8 has been added after table 7	1982-08-31
8.	IS : 2339—1963 Specification for aluminium paint for general purposes, in dual container	S.O. 2647 dt. 1963-09-14	*No. 2 Aug 1982	(This amendment is being issued to overcome the difficulties experienced by the manufacturers for the packing of aluminium paint in dual containers above 4 litre capacity.)	1982-08-31
9.	IS : 2720 : (Part II)—1973 Methods of test for soils Part II Determination of water content (Second Revision)	S.O. 3069 dt. 1975-09-13	No. 1 Aug 1982	(i) Clauses 4.1 and 16.1 have been amended (ii) Foot-notes with '+' and '*' marks at pages 4 and 8 have been substituted by new ones (iii) Notes under clauses 8.3 and 8.4 have been substituted by new ones	1982-08-31

*For purposes of ISI Certification Marks Scheme, this amendment came into force with effect from 1982-11-16

†For purposes of ISI Certification Marks Scheme, this amendment came into force with effect from 1982-11-01

1	2	3	4	5	6
10.	IS : 2720 (Part IV)–1975 Methods of test for soils : Part IV Grain size analysis (First Revision)	S.O. 3351 dt. 1978-11-[illegible]	No. 1 Aug 1982	(i) Clauses 3.1.[illegible], 4.1.2, 4.2, 5.1.3.2 and 5.1.3.4. have been amended. (ii) Foot-note with '*' mark (page 5), with '+' mark (page 6), with '* and +' mark (page 7) and with '*' mark (page 13 and 17) have been substituted by new ones	1982-08-31
11.	IS : 2911 (Part I/Sec 1)–1979 Code of practice for design and construction of pile foundations; Part I Concrete piles; Section 1 Driven cast in-situ concrete piles (First Revision)		No. 1 Aug 1982	(i) Clauses 6.2, A-1.1 and A-3.1 have been amended (ii) Foot-notes with '‡†' and '*' marks at page 15 and 19 respectively have been substituted by new ones (iii) (Page 15, clause 6.1, line 2) —Add, 'IS : 1489–1976££ after 'IS : 8041–1978£ (iv) A new foot-note with '££' mark has been added after foot-note with with '§§' mark at page 15.	1982-08-31
12.	IS : 2911 (Part I/Sec 2)–1979 Code of practice for design and construction of pile foundations; Part I concrete piles; Section 2 Board cast-in-Situ piles (First Revision)		No. 1 Aug 1982	(i) Clause 6.1 has been substituted by a new one (ii) Clauses 6.[illegible], B-1.1 and B-[illegible].2 have been amended (iii) Foot-notes with '≠' mark (page 15) and with '*' (page 23) have been substituted by new ones (iv) Existing matter under clause A–3.1 (c) to (f) has been substituted by a new one (v) Fig 1 (page 24) has been substituted by a new one (vi) A new note has been added after clause 5.11.1 (vii) A newfoot-note with '£ʒ' mark has been added after foot-note with with '‖‖' mark at page 15	1982-08-31
13.	IS : 2911 (Part I/Sec 3)–1979 Code of practice for design and construction of pile foundations; Part I Concrete piles; Section 3 Driven precast concrete piles (First Revision)		No. 1 Aug 1982	(i) Clauses 6.2, 7.5.7, A–1.1, A–[illegible], A–[illegible].3, 5.1, 5.11.6.1 and 6.1 have been amended (ii) Foot-note with '≠' mark and with '*' mark (page 28) have been substituted by new ones (iii) Fig 1 (page 29) has been substituted by a new one (iv) A new note has been added after clause 5.11.7.1 (v) A new foot-note with '**' mark has been added at page 17 after foot-note with '£' mark	1982-08-31
14.	IS : 308[illegible]–1973 Specification for hexagon socket screw keys (First Revision)	S.O. 4690 dt. 1975-11-01	No. Aug 1982	(i) Clauses 4, 6 and 9 have been substituted by new ones (ii) Clause 8.1 has been amended (iii) Explanatory note at page [illegible] has been amended	1982-08-31
15.	IS : 4338–1974 Specification for vertical oscillating shuttles for sewing machines for household purposes (First Revision)	S.O. 3494 dt. 1976-10-0[illegible]	No. [illegible] Aug 1982	(i) Clauses 4.1, 4.[illegible] and 6.1 have been substituted by new ones (ii) Informal table under clause 5 has been amended (iii) (Page [illegible], clauses 6.[illegible] to 6.4) —Delete	1982-08-31

1	2	3	4	5	6
16.	IS : 4775—1976 Specification for picking sticks for automatic and underpick looms (First Revision)	S.O. 99 dt. 1980-01-12	No. 2 Aug 1982	(i) A new sentence has/been added at the end of clause 2.1 (ii) Appendix 'A' has been added after clause 6.4	1982-08-31
17.	IS : 5085—1976 Specification for berets, wool, knitted (First Revision)	S.O. 3823 dt. 1979-11-24	No. 1 Aug 1982	(This amendment is being carried out to specify the breaking load value of hosiery yarn used for knitting berets as well as to provide for an alternative in the positions of eye-lets from back to right hand side of the bevel in case of berets required by the Ministry of Defence)	1982-08-31
18.	IS : 5366—1978 Specification for core drills, morse taper shanks (First Revision)	S.O. 2271 dt 1981-08-29	No. 1 Aug 1982	Table 1 has been amended	1982-08-31
19.	IS : 5554—1970 Specification for lock washers with lug	S.O. 3305 dt. 1972-10-21	No. 2 Aug 1982	(i) Clause 5 has been substituted by a a new one (ii) (Page 2, foot-note with '*' mark)—Delete	1982-08-31
20.	IS : 5695—1970 Specification for spectacle lenses	S.O. 3544 dt. 1971-09-25	No. 2 Apr 1982	Table 2 has been amended	1982-04-30
21.	IS : 6550—1971 Specification for thread milling cutters with parallel shanks	S.O. 1853 dt 1974-07-27	No. 2 Aug 1982	Clause 1 has been substituted by a new one	1982-08-31
22.	IS : 6554—1972 Specification for soldering ferrules of straight through joints		No. 1 Aug 1982	(i) Clauses 1, 3 and Table 1 have been amended (ii) A new clause 5.1 has been added after clause 5.	1982-08-31
23.	IS : 6583—1972 Specification for train lighting belting	S.O. 1853 dt. 1974-07-27	No. 3 Dec 1981	Clause 6.2 has been amended	1981-12-31
24.	IS : 6948—1973 Specification for ready mixed paint, under coat, synthetic for ships	S.O. 2558 dt. 1975-08-09	No. 1 Aug 1982	(i) Clauses 3.1, 3.5, 6.2 and A—2.2 have been amended (ii) Foot-notes with '‡', '' '//' and '' marks (page 4) and with '+' mark (page 7) have been substituted by new ones (iii) (Page 5, foot-note with '*' mark)—Substitute '(second revision) for '(revised)'. (iv) (Page 8, foot-note with '+' mark)—Substitute '(second revision)' for '(revised)'.	1982-08-31
25.	IS : 7406 (Part I)—1974 Specification for Jute bags for packing fertilizers; Part I Laminated bags manufactured from 407 g/m2; 85x39 tarpaulin fabric	S.O. 1232 dt. 1976-04-03	*No. 4 Aug 1982	(i) Table 1 has been amended (ii) Clauses B—1.2, B—1.4.1 and B—1.5 have been substituted by new ones (iii) Clause B—0.2 has been added after clause B—0.1	1982-08-31
26.	IS : 7406 (Part II)—1980 Specification for jute bags for packing fertilizers; Part II Laminated bags manufactured from 380 g/m^2; 68 × 39 tarpaulin fabric	-do-	*No. 1 Jun 1982	Table 1 has been amended	1982-06-30
27.	IS : 7597—1974 Glossary of terms relating to surface active agents	S.O. 3530 dt. 1977-11-19	No. 1 Aug 1982	(i) Clause 4.1.4 has been substituted by a new one	1982-08-31

*For purposes of ISI Certification Marks Scheme, these amendments came into force with effect from 1983-01-01

1	2	3	4	5	6
				(ii) Clause 4.2 has been amended and new clauses 4.2.1.1, 4.2.1.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.7, 4.2.1.8, 4.2.2, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3 have been added after clause 4.2	
28.	IS : 7784 (Part I)—1975 Code of practice for design of cross drainage works; Part I General features	S.O. 3351 dt. 1978-11-25	No. 2 Aug 1982	Clauses 7.4.4.1(B) and 7.4.4.2 have been amended	1983-08-31
29.	IS : 8301—1976 Dimensions for carbide tips for drills with point angle 115° (Type AB)	S.O. 415 dt. 1980-02-23	No. 1 Aug 1982	(i) Existing figure under clause 2 has been substituted by a new one (ii) New matter has been added at the end of the Informal table under clause 2	1983-08-31
30.	IS : 9113—1979 Specification for jute sacking : General requirements	S.O. 1347 dt. 1983-04-03	No. 2 Aug 1982	(i) Clauses 14 and 14.6 have been amended (ii) Clauses 15 and 15.1 have been substituted by new ones	1983-08-31

Copies of these Indian Standards are available with Indian Standards Institution, Manak Bhawan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi and from its Branch Offices at Ahmedabad, Bombay, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Calcutta, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Mohali, Patna and Trivandrum.

[No. CMD/13 : 5]
B.N. SINGH, Addl. Director General

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1985

का.आ. 5400.—यतः फार्मेसी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 3 के खण्ड (ख) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित व्यक्तियों को 9 सितम्बर, 1985 से भारतीय फार्मेसी परिषद् का सदस्य मनोनीत किया है नामतः

1. श्री आई. ए. मोदी
बी. एस. सी. टेक (फार्म)
प्रबन्ध निदेशक,
कैडिला लेबोरेट्रीज,
घोडसर मनिनगर,
गुजरात ।

2. डा. बी. डी. मिगलानी,
एम. फार्म, पी. एच. डी.
सम्पादक, इण्डियन जर्नल आफ अस्पताल
फार्मेसी एवं प्रिंसिपल, कालेज आफ फार्मेसी
पुष्पा विहार, सेक्टर-3
नई दिल्ली ।

3. डा. बी. के. गुप्ता,
प्रोफेसर,
फार्मास्यूटिकल सेवा विभाग,
जोधपुर विश्वविद्यालय,
जोधपुर ।

4. श्रीमती एस. एस. पंडित,
चीफ फार्मासिस्ट,
नैयर अस्पताल,
बम्बई ।

5. श्री एल. बी. काले,
एडवोकेट,
एल० आई० जी. 29/30
महन्तेश नगर, मालमारूति एक्सटेंशन,
बैलगांव, कर्नाटक ।

6. श्री के. अनिल कुमार,
बी. ई.
3-2-1, राष्ट्रपति रोड,
सिकन्दराबाद,
हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व मंत्रालय के 21 दिसम्बर, 1959 के का. आ. संख्या 78, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामतः

उक्त अधिसूचना में शीर्षक 2 के अधीन "खण्ड (ख) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य" के अन्तर्गत क्रम संख्या 1-6 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा प्रविष्टियां रखी जाएं

1. श्री आई. ए. मोदी,
बी. एस. सी. टेक (फार्म)
प्रबन्ध निदेशक,
कैडिला लेबोरेट्रीज,
घोडसर मनिनगर,
गुजरात ।

2. डा. बी. डी. मिगलानी
एम. फार्मा पी. एच. डी.
सम्पादक, इण्डियन जर्नल आफ अस्पताल फार्मेसी
एवं प्रिंसिपल, कालेज आफ फार्मेसी,
पुष्पा विहार,
सेक्टर-3,
नई दिल्ली ।

3. डा. बी. के. गुप्ता, प्रोफेसर
फार्मास्यूटिकल सेवा विभाग,
जाधवपुर विश्वविद्यालय,
जाधवपुर ।

4. श्रीमती एस. एस. पंडित,
चीफ फार्मासिस्ट,
नैयर अस्पताल,
बम्बई ।

5. श्री एल बी. कार्ले,
एडवोकेट,
एल. आई. जी. 29/30 महन्तेश नगर,
मालमारूति एक्सटेंशन,
बेलगांव, कर्नाटक,

6. श्री के. अनिल कुमार, बी. ई.
3-2-1, राष्ट्रपति रोड,
सिकन्दराबाद, हैदराबाद,
आन्ध्र प्रदेश ।

[सं. वी. 13017/1/81-पी. एम. एस.]
पी. आर. दासगुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Deptt. of Health)

New Delhi, the 6th November, 1985

S.O. 5400.—Whereas the Central Government have in pursuance of Clause (b) of section 3 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), nominated the following persons to be members of the Pharmacy Council of India with effect from the 9th September, 1985 namely :—

1. Shri I. A. Modi, B.Sc. Tech (Pharm)
Managing Director
CADILA Laboratories,
Ghodasar, Maninagar.
Gujarat.

2. Dr. B. D. Miglani M. Pharma, Ph.D., Editor, Indian Journal of Hospital Pharmacy & Principal, College of Pharmacy, Pushpa Vihar, Sector-III,
New Delhi.

3. Dr. B. K. Gupta,
Professor,
Depaprment of Pharmaceutical Services.
Jadhavpur University,
Jadhavpur.

4. Shrimati S. S. Pandit,
Superintendent of Pharmacy,
Topiwala National Medical College and
B.Y.L. Nair Charitable Hospital,
Dr. A. L. Nair Road,
Bombay.

5. Shri L. B. Karale,
Advocate,
LIG 29|30,
Mahantesh Nagar,
Malmaruti Exten.,
Belgaum,
Karnataka.

6. Shri K. Anil Kumar, BE,
3-2-1, Rashtrapati Road,
Secunderabad, Hyderabad,
Andhra Pradesh.

Now, therefore, in pursuance of secion 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the late Ministry of Health No. S.O. 7, dated the 21st December, 1959, namely:—

In the said notification, under the heading "II. Members nominated by Central Government under clause (b)", for serial numbers 1 to 6 and the entries relating thereto the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

"1. Shri I. A. Modi, B.Sc. Tech (Pharm),
Managing Director,
CADILA Laboratories,
Ghodasar, Maninagar,
Gujarat.

2. Dr. B. D. Miglani M. Pharm., Ph.D., Editor, Indian Journal of Hospital Pharmacy and Principal, College of Pharmacy, Pushpa Vihar, Sector-III,
New Delhi.

3. Dr. B. K. Gupta,
Professor,
Department of Pharmaceutical Services,
Jadhavpur University,
Jadhavpur.

4. Shrimati S. S. Pandit,
Superintendent of Pharmacy,
Topiwala National Medical College and
B.Y.L. Nair Charitable Hospital,
Dr. A. L. Nair Road,
Bombay.

5. Shri L. B. Karale,
Adovcate,
LIG 29|30,
Mahentesh Nagar,
Malmaruti Extn.,
Belgaum,
Karnataka.

6. Shri K. Anil Kumar, BE,
3-2-1, Rashtrapati Road,
Secunderabad, Hyderabad,
Andhra Pradesh.

[No. V-13017|1|81-PMS]
P. R. DASGUPTA, Jt. Secy.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1985

पूर्व अक्षयनिधि अधिनियम, 1980 के मामले में

और

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान के मामले में

का०आ० 5401:—केन्द्रीय सरकार को इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति को, भारत के पूर्व-अक्षयनिधि के कोषाध्यक्ष में निहित करने के लिये एक आवेदन किया गया है, जिसका प्रयोग भारत सरकार के भूतपूर्व शिक्षा

मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 1955, तारीख 25 जून, 1962 में प्रकाशित स्कीम के अनुसार किया जायेगा,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पूर्व अक्षयनिधि अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्वोक्त आवेदन किये जाने पर, यह निदेश देती है कि उक्त सम्पत्ति भारत के पूर्व अक्षयनिधि के कोषाध्यक्ष में निहित होगी, जो उसके द्वारा धार्य होगी, और यह भी निदेश देती है कि उक्त सम्पत्ति और उसकी आय का उपयोग, पूर्वोक्त स्कीम में कथित निबन्धनों के अनुसार किया जायेगा ।

अनुसूची

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान की ओर से 50,000,00 रु० (पचास लाख रु०) की राशि डाकखाने में 5 वर्षीय आवधिक जमा खाता में विनिहित होगी जो 6 अगस्त, 1985 से प्रभावी होगा और जो 6 अगस्त 1990 को 11.5% वार्षिक दर की ब्याज के साथ प्रतिसंदेय होंगे ।

[सं० एफ० 21-19/85-स्कूल-5]

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Education)

New Delhi, the 18th November, 1985

In the matter of Charitable Endowments Act, 1890

AND

In the matter of the National Foundation for Teachers' Welfare.

S.O. 5401.—Whereas an application has been made to the Central Government for vesting the property, specified in the Schedule appended hereto, in the Treasurer of Charitable Endowments for India, to be applied in accordance with the Scheme published with the notification of the Government of India in the late Ministry of Education No. S.O. 1955, dated the 25th June, 1962.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890), and on the application as aforesaid, the Central Government hereby directs that the said property shall vest in the Treasurer of Charitable Endowments for India to be held by him and directs that the said property and the income thereof shall be applied in accordance with the terms set out in the aforesaid Scheme.

SCHEDULE

A sum of Rs. 50,00,000 (Rs. 50 lakhs) invested on behalf of the National Foundation for Teachers' Welfare in 5-Year Post Office Time Deposit Account, the deposit being effective from the 6th August, 1985 repayable on the 6th August, 1990, with interest at the rate of 11.5% per annum.

[No. F. 21-19/85-School-5]

का०आ० 5402—केन्द्रीय सरकार को इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति को, भारत के पूर्व-अक्षयनिधि के कोषाध्यक्ष में निहित करने के लिये एक आवेदन किया गया है, जिसका प्रयोग भारत सरकार के भूतपूर्व शिक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 1955, तारीख 26 जून, 1962 में प्रकाशित स्कीम के अनुसार किया जायेगा ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पूर्व अक्षयनिधि अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्वोक्त आवेदन किये जाने पर, यह निदेश देती है कि उक्त सम्पत्ति भारत के पूर्व अक्षयनिधि के कोषाध्यक्ष में निहित होगी, जो उसके द्वारा धार्य होगी, और यह भी निदेश देती है कि उक्त सम्पत्ति और उसकी आय का उपयोग, पूर्वोक्त स्कीम में कथित निबन्धनों के अनुसार किया जायेगा ।

अनुसूची

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान की ओर से 3,00,000,00 रु० (3 करोड़ रु०) की राशि डाकखाने में 5 वर्षीय आवधिक जमा खाता में विनिहित होगी जो 19 सितम्बर, 1984 से प्रभावी होगा और जो 19 सितम्बर, 1989 11.5% वार्षिक दर की बजाय के साथ प्रतिसंदेय होंगे ।

[सं० एफ० 21-19/85-स्कूल-5]

श्रीमती रेणुका मेहरा, अवर सचिव

S.O. 5402.—Whereas an application has been made to the Central Government for vesting the property, specified in the Schedule appended hereto, in the Treasurer of Charitable Endowments for India, to be applied in accordance with the Scheme published with the notification of the Government of India in the late Ministry of Education No. S.O. 1955, dated the 25th June, 1962.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890), and on the application as aforesaid, the Central Government hereby directs that the said property shall vest in the Treasurer of Charitable Endowments for India to be held by him and directs that the said property and the income thereof shall be applied in accordance with the terms set out in the aforesaid Scheme.

SCHEDULE

A sum of Rs. 3,00,000,00 (Rs. 3 crores) invested on behalf of the National Foundation for Teachers' Welfare in 5-Year Post Office Time Deposit Account, the deposit being effective from the 19th September, 1984 repayable on the 19th September, 1989, with interest at the rate of 11.5% per annum.

[No. F. 21-19/85-School-5]

(MRS.) RENUKA MEHRA, Under Secy.

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1985

का०आ० 5403 :—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिये प्रयोग (नियम), 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में सिंचाई और विद्युत मंत्रालय (विद्युत विभाग) के निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके कर्मचारिवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एतद्द्वारा अधिसूचित करती है :—

1 बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र, बदरपुर नई दिल्ली-110044

2 सिंगरौली सुपर ताप विद्युत परियोजना, पोस्ट आफिस शक्ति नगर, जिला मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)

3. विंध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना, जिला सीधी (मध्य प्रदेश)

4. रिहंद सुपर ताप विद्युत परियोजना, जिला-मिर्जापुर (उत्तरप्रदेश)

5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ताप विद्युत परियोजना, पोस्ट आफिस मुरादनगर, जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)

6. परियोजना कार्यालय, ग्राम विद्युतीकरण निगम, माईथ इस्टेट, अप्पर कैथु, शिमला-171003

[सं० ई० 11017/13/84-हिन्दी]

गायत्री रामाचन्द्रन, उप सचिव

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

(Department of Power)

New Delhi, the 30th September, 1985

S.O. 5403.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following Offices, of the Ministry of Irrigation and Power (Department of Power) the staff whereof have acquired a working knowledge of Hindi :—

1. Badarpur Thermal Power Station, Badarpur, New Delhi-110044.

2. Singrauli Suner Thermal Power Project, P.O. Shakti Nagar, District Mirzapur (Uttar Pradesh).

3. Vindhyachal Super Thermal Power Project, District Sidhi (Madhya Pradesh).

4. Rihand Super Thermal Power Project, District Mirzapur (Uttar Pradesh).

5. National Capital Region Thermal Power Projects, P.O. Muradnagar, District Ghaziabad (Uttar Pradesh).

6. Project Office, Rural Electrification Corporation Maith Estate, Upper Kaithu, Simla-171003.

[No. E-11017/13/84-Hindi]

GAYATHRI RAMACHANDRAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1985

का. आ. 5404—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित अधिकारियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी और कानूनी प्राधिकरण के समतुल्य पंक्ति के अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है और उक्त अधिकारी उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अपनी-अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर भाखड़ा-व्यास प्रबंध बोर्ड के स्थानों अथवा उनके द्वारा पट्टे पर लिए गए अथवा खरीदे गए स्थानों की बाबत उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे।

सारणी

अधिकारी का पदनाम	सम्पदा अधिकारी का पदनाम	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1 अधीक्षण इंजीनियर भाखड़ा बांध सर्किल, नांगल टाउनशिप	सम्पदा अधिकारी, भाखड़ा-व्यास प्रबंध बोर्ड, नांगल	रोपड़ (पंजाब) और ऊना (हिमाचल प्रदेश) जिलों में भाखड़ा-व्यास प्रबंध बोर्ड (सिंचाई और विद्युत खंडों) के प्रबंध और नियंत्रण के अधीन अथवा उनके द्वारा पट्टे पर लिए गए अथवा खरीदे गए स्थान।
2. अधीक्षक इंजीनियर, व्यास सतलुज लिंक सर्किल सं 3 भाखड़ा	सम्पदा अधिकारी, भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड, सुन्दर नगर	मंडी, बिलासपुर, कुल्लू और शिमला (हिमाचल प्रदेश) जिलों में भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड (सिंचाई और विद्युत खंडों) के प्रबंध और नियंत्रण के अधीन अथवा उनके द्वारा पट्टे पर लिए गए अथवा खरीदे गए स्थान।
3. अधीक्षण इंजीनियर पोंग बांध सर्किल भाखड़ा-व्यास प्रबंध बोर्ड, तलवाड़ा	सम्पदा अधिकारी, भाखड़ा-व्यास प्रबंध बोर्ड तलवाड़ा, जिला होशियारपुर	होशियार जिला (पंजाब) और कांगड़ा तथा चम्बा जिले (हिमाचल प्रदेश) में भाखड़ा-व्यास प्रबंध बोर्ड (सिंचाई और विद्युत खंड) के प्रबंध और नियंत्रण के अधीन अथवा उनके द्वारा पट्टे पर लिए गए अथवा खरीदे गए स्थान।
4. अधीक्षण इंजीनियर ओ. एंड एम. सर्किल भाखड़ा-व्यास प्रबंध बोर्ड धूलकोट।	सम्पदा अधिकारी भाखड़ा-व्यास प्रबंध बोर्ड, धूलकोट, जिला अम्बाला।	भिवानी, अम्बाला कुरुक्षेत्र, हिसार, करनाल, सिरसा, फरीदाबाद (हरियाणा) जालन्धर, लुधियाना संगरूर (पंजाब) जिलों, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ और दिल्ली में भाखड़ा-व्यास प्रबंध बोर्ड सिंचाई और विद्युत खंड के प्रबंध और नियंत्रण के अधीन अथवा उनके द्वारा पट्टे पर लिए गए अथवा खरीदे गए स्थान।

[फाइल सं 1/8/85-बी (बी एण्ड बी)]

के. पद्मनाभय्या, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 14th November, 1985

S.O. 5404.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoint the Officers mentioned in column (1) of the Table below, being Gazetted Officer of Government and Officers of equivalent rank of Statutory Authority to be estate officers for the purpose of the

said Act, and the said officers shall exercise of the powers conferred and perform the duties imposed on estate officers by or under the said Act, within the local limits of their respective jurisdiction specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table in respect of the premises belonging to or taken on lease or purchased by Bhakra Beas Management Board.

TABLE

Designation of the Officer	Designation of the estate officer	Categories of Public Premises and local limits of jurisdiction
1	2	3
1. Superintending Engineer, Bhakra Dam Circle, Nangal Township.	Estate Officer, Bhakra Beas Management Board, Nangal.	Premises under the management and control of or taken on lease or purchased by the Bhakra Beas Management Board (Irrigation & Power Wings) in districts or Ropar (Punjab) and Una (Himachal Pradesh
2. Superintending Engineer, Beas Sutlej Link Circle No. III Bhakra Beas Management Board, Sunder Nagar, (Himachal Pradesh)	Estate Officer, Bhakra Beas Management Board, Sundernegar.	Premises under the management and control of or taken on lease or purchased by the Bhakra Beas Management Board (Irrigation and Power Wings in, District Mandi, Bilaspur Kulu and Shimla (Himachal Pradesh).
3. Superintending Engineer, Pong Dam Circle Bhakra Beas Management Board, Talwara.	Estate Officer, Bhakra Beas Management Board, Talwara District Hoshiarpur.	Premises under the management and control of or taken on lease or purchased by the Bhakra Beas Management Board (Irrigation and Power Wings) in District Hoshiarpur (Punjab) and District Kangra and Chamba (Himachal Pradesh).
4. Superintending Engineer, O & M Circle, Bhakra Beas Management Board, Dhulkote.	Estate Officer, Bhakra Beas Management Board, Dhulkote, Distt. Ambala.	Premises under the management control of or taken on lease or purchased by the Bhakra Beas Management Board (Irrigation and Power Wings) in District Bhiwani, Ambala, Kurukshetra, Hissar, Karnal, Sirsa, Faridabad (Haryana, Jullunder, Ludhiana, Sangrur (Punjab), Union territory of Chandigarh and Union Territory of Delhi.

[File No. 1/8/85-D(B&B)]
K. PADMANABHAIAH, Jt. Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1985

का. आ. 5405—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. सी—1 (ई)/III एफ. एफ. आर. 297—0785, तारीख 30 जुलाई, 1985 का निरीक्षण वेस्टर्न कोलफील्डस लि., (राजस्व विभाग) कोल एस्टेट, सिविल लाइंस, नागपुर—440001 के कार्यालय में या कलक्टर, बैतुल (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में अथवा कोयला नियंत्रक, 1— काउंसिल हाऊस स्ट्रीट कलकत्ता के कार्यालय में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों चार्टों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, राजस्व अधिकारी, वेस्टर्न कोलफील्डस कोल एस्टेट, सिविल लाइंस, नागपुर—440001 को भेजेंगे।

अनुसूची

तावा विस्तार खंड

पठखेड़ा कोयला क्षेत्र

जिला बेतुल (मध्य प्रदेश)

अनुसूची (क)

रेखांक सं. सी–1 (ई)/III/एफ. ई. आर./297–0785 तारीख 30.7.1985

(पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि)

क्र. सं.	वन का नाम	कंपार्टमेंट सं.	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पणियां
1.	(असीर आरक्षित वन मध्य प्रदेश शासन)	396	बैतुल	बैतुल	79.219	भाग
2.	(असीर आरक्षित वन मध्य प्रदेश शासन)	397	"	"	283.691	भाग
3.	(असीर आरक्षित वन मध्य प्रदेश शासन)	398	"	"	98.078	भाग
4.	(असीर आरक्षित वन मध्य प्रदेश शासन).	400	"	"	66.265	भाग

कुल क्षेत्र : 527.253 हैक्टर (लगभग) या 1302.84 एकड़ (लगभग)

अनुसूची (ख)

रेखांक सं. सी–1(ई)/ III/एफ ई आर/297–0785–

तारीख 30.7.1985

(पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि)

क्र. सं.	स्वामी का नाम	तहसील	जिला	क्षेत्र हैक्टर में	टिप्पण
1.	(पुनर्वास विभाग, मध्य प्रदेश)	बेतुल	बेतुल	162.000	भाग
2.	(मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड, सारणी)	बेतुल	बेतुल	64.000	भाग

कुल क्षेत्र : 226.000 हैक्टर (लगभग) या 558.44 एकड़ (लगभग)

सीमा वर्णन :

क–ख रेखा बिन्दु "क" से आरंभ होती है और कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9 (1) के अधीन का. आ. सं. 2617 तारीख 9 सितम्बर, 1978 द्वारा अधिसूचित पठखेड़ा ब्लाक III की उत्तरी सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु "ख" पर मिलती है।

ख–ग रेखा कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9 (1) के अधीन का. आ. सं. 2617 तारीख 9 सितम्बर, 1978 द्वारा अधिसूचित पठखेड़ा ब्लाक–III की पूर्वी सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु "ग" पर मिलती है।

ग–घ रेखा आंशिक रूप से मध्य प्रदेश, विद्युत बोर्ड द्वारा धारित भूमि से गुजरती है और तब आरक्षित वन की पूर्वी सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु "घ" पर मिलती है।

घ–ङ रेखा कंपार्टमेंट सं. 395 और 396 की सम्मिलित सीमा के साथ–साथ जाती है, तब असीर आरक्षित वन के कंपार्टमेंट सं. 396 से होकर जाती है और कंपार्टमेंट सं. 396 की उत्तरी सीमा के बिन्दु "क" पर मिलती है।

ङ–च रेखा कंपार्टमेंट सं. 396 और 397 की उत्तरी सीमा के साथ–साथ जाती है और "च" बिन्दु पर मिलती है।

च–छ रेखा पुनर्वास क्षेत्र की पूर्वी सीमाओं के साथ साथ जाती है, तब उसी क्षेत्र से चलकर बिन्दु "छ" पर मिलती है।

छ–क रेखा पुनर्वास क्षेत्र की पश्चिमी सीमा के साथ साथ जाती है और आरंभ बिन्दु "क" पर मिलती है।

[सं. 43015/22/85– सी. ए.)]

टी. सी. ए. श्रीनिवासन, निदेशक

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi the 13th November, 1985

S.O. 5115 :—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan bearing No. C-1(E)/III/FFR/297–0785, dated 30th July, 1985 on the area covered by this notification can be inspected at the office of the Western Coalfields Limited (Revenue Section), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440001 or the Office of the Collector, Betul (Madhya Pradesh) or at the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta.

All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of the section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Western Coalfields Limited, Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440001 within ninety days from the date of publication of this notification.

SCHEDULE

TAWA ESTENSION BLOCK

PATHAKHERA COALFIELD

DISTRICT BETUL (MADHYA PRADESH)

SCHEDULE (A)

Drawing No. C—1(E)/III/FFR/
297—0785
dated 30-7-1985

(Showing lands notified for Prospecting)

Sl. No.	Name of Forest	Compartment number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1.	Asir Reserve Forest of Government of Madhya Pradesh .	396	Betul	Betul	79.219	Part
2.	Asir Reserve Forest of Government of Madhya Pradesh .	397	Betul	Betul	283.601	Part
3.	Asir Reserve Forest of Government of Madhya Pradesh .	398	Betul	Betul	98.087	Part
4.	Asir Reserve Forest of Government of Madhya Pradesh .	400	Betul	Betul	66.265	Part
	Total Area :	527:253 hectares (approximately)				
	or	1302.84 acres (approximately)				

SCHEDULE (B)

Drawing No. C—1(E)/III/FFR/
297—0785 dated 31-7-1985

(Showing land notified for prospecting)

Sl. No.	Name of owner	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1.	Rehabilitation Department of Madhya Pradesh	Betul	Betul	162.000	Part
2.	Madhya Pradesh Electricity Board, Sarni	Betul	Betul	64.000	Part
	Total Area :	226.000 hectares (approximately)			
	or	558.44 acres (approximately)			
	Grand Total (A+B) :	753.253 hectares (Approximately)			
		or			
		1861.28 acres (approximately)			

Boundary Description :

A—B : Line starts from point 'A' and passes along the northern boundary of Pathakhera Block-III notified under section 9(1) of Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 vide S.O No. 617 dated 9th September, 1978 and meets at Point 'B'.

B—C : Line passes along the eastern boundary of Pathakhera Block-III notified under section 9(1) of Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 vide S.O. No. 2617 dated 9th September, 1978 and meets at Point 'C'.

C—D : Line passes partly through the land held by Madhya Pradesh Electricity Board and then along the eastern boundary of Reserve Forest and meets at point 'D'.

D—E : Line passes along the common boundary of compartment number 395 and 396, then proceeds through compartment number 396 of Asir Reserve Forest and meets on the northern boundary of compartment number 396 at point 'E'.

E—F : Line passes along the northern boundary of compartment number 396 and 397 and meets at point 'F'.

F—G : Line passes along the eastern boundary of the rehabilitation Area then proceeds through the same area and meets at point 'G'.

G—A : Line passes along the western boundary of the rehabilitation Area and meets at starting point 'A'.

[No. 43015/22/85-CA)]

T C.A SRINIVASAN, Director

परिवहन मंत्रालय

(रेल विभाग)

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1985

का०आ० 5406.—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) और दक्षिण मध्य रेलवे से संबंधित, भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की दिनांक 23 जुलाई, 1983 की अधिसूचना का०आ० सं० 3080 की मद 7(i) और (ii) तथा मैट्रो रेलवे कलकत्ता के संबंध में भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की दिनांक 27 मार्च, 1984 की अधिसूचना का०आ० सं० 1238 की मद (ii) का अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका के कालम (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों को, सरकार का राजपत्रित अधिकारी होने के नाते, उन्हें उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो उपर्युक्त तालिका के कालम 2 के तदनुरूपी सरकारी स्थानों, इन्दराज में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के सम्बन्ध में अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का, अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं में प्रयोग करेंगे और सम्पदा अधिकारी को सौंपे गये कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे।

अधिकारी का नाम	सरकारी स्थानों के वर्ग तथा क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमा
1	2
1(i) सभी मंडल रेल प्रबन्धक, दक्षिण मध्य रेलवे।	दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा स्वामित्व या उपार्जित या किराये के स्थान जो उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आते हैं।
(ii) दक्षिण मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद (बी०जी०), हैदराबाद (मी०जी०), विजयवाड़ा, हुबली और गुंटकल के वरिष्ठ मंडल इंजीनियर तथा मंडल इंजीनियर	दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा स्वामित्व या उपार्जित या किराये के स्थान जो उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आते हैं।
(iii) मुख्य इंजीनियर/सामान्य, मुख्य पुल इंजीनियर, मुख्य योजना एवं विकास इंजीनियर, अपर मुख्य इंजीनियर (मध्य), अपर मुख्य इंजीनियर (पूर्व), उप मुख्य इंजीनियर (सामान्य), उप मुख्य इंजीनियर (योजना), उप मुख्य इंजीनियर (पुल), उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण)	दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा स्वामित्व या उपार्जित या किराये के स्थान जो उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आते हैं।
(iv) अपर मंडल रेल प्रबन्धक, दक्षिण मध्य रेलवे	दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा स्वामित्व या उपार्जित या किराये के स्थान जो उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आते हैं।
(v) वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (समन्वय) दक्षिण मध्य रेलवे	दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा स्वामित्व या उपार्जित या किराये के स्थान जो उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आते हैं।
2. अपर मुख्य इंजीनियर (डिजाइन) मैट्रो रेल, कलकत्ता	कलकत्ता महानगर की सीमाओं में जैसा भूमिगत रेल (संकर्म संनिर्माण) अधिनियम 1978 (1978 का 33) में परिभाषित है, की सीमाओं के अन्तर्गत स्थित मैट्रो रेल के नियंत्रण के अधीन परिसर।

[फाइल सं० 82/डब्ल्यू 2/14/4]

ए०एम० वांचू, सचिव, रेलवे बोर्ड,
भारत के राष्ट्रपति के लिये तथा उनकी ओर से

MINISTRY OF TRANSPORT

(Deptt. of Railways)

(Railway Board)

New Delhi, the 8th November, 1985

S.O. 5406.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of items 7(i) and (ii) of the Government of India, Ministry of Railways (Railway Board) Notification S.O. No. 3080 dated the 23rd July, 1983 pertaining to the South Central Railway and Item (ii) of Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board) Notification S.O. No. 1238 dated the 27th March, 1984 pertaining to the Metro Railway, Calcutta, the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the Table below, being Gazetted Officers of the Government to be estate officers for the purpose of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the estate officers by or under the said Act within the local limits of their jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the Officers	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
1	2
1. (i) All Divisional Railway Manager, South Central Railway.	Public Premises owned or acquired or hired by the South Central Railway which are under their respective administrative control.
(ii) Senior Divisional Engineers and Divisional Engineers of Secundera-	Public Premises owned or acquired or hired by the South Central Railway

1	2
bad (BG) Hyderabad (MG) Vijayawada, Hubli and Guntakul Division of South Central Railway.	which are under their respective administrative control.
(iii) Chief Engineer/General, Chief Bridge Engineer, Chief Planning and Development Engineer, Additional Chief Engineer (Central), Additional Chief Engineer (East), Deputy Chief Engineer (General), Deputy Chief Engineer (Planning), Deputy Chief Engineer (Bridges), Deputy Chief Engineer (Works).	Public premises owned or acquired or hired by the South Central Railway which are under their respective administrative control.
(iv) Additional Divisional Railway Managers, South Central Railway.	Public Premises owned or acquired or hired by the South Central Railway which are under their respective administrative control.
(v) Senior Divisional Engineers (Co-ordination), South Central Railway.	Public premises owned or acquired or hired by the South Central Railway which are under their respective administrative control.
2. Additional Chief Engineer (Design) Metro Railway, Calcutta.	Premises under the control of Metro Railway situated within the limits of metropolitan city of Calcutta as defined in the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978)

[File No. 82/W2/14/4]

A. N. WANCHOO, Secy., Railway Board for and on behalf of President of India.

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1985

का. आ. 5407 :—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंचार विभाग ने चन्नापटना टेलीफोन केन्द्र, कर्नाटक, दिनांक 1-12-1985 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है । है

[सं. 5-24/84-पी०एच०बी०]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunication)

New Delhi, the 11th November, 1985

S.O. 5407.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General Department of Telecommunication, hereby specifies 1-12-1985 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Channapatna Telephone Exchange Karnataka Circle.

[No. 5-24|85-PHB]

का. आ. 5408 :—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक दूरसंचार विभाग ने राऊलापालेम टेलीफोन केन्द्र, आन्ध्र प्रदेश में दिनांक 1-12-1985 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[संख्या 5-23/85-पी एच बी]

S.O. 5408.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General Department of Telecommunicaiton, hereby specifies 1-12-1985 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Ravulapalem Telephone Exchange Andhra Pradesh Circle.

[No. 5-23|85-PHB]

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1985

का.आ. 5409--स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंचार विभाग ने कदम्बाथुर, पेरम्बक्कम, पूण्डी तथा तिरुर टेलीफोन केन्द्रों, तमिलनाडु, में दिनांक 1-12-1985 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है

[संख्या 5-26/85 पी एच बी]

के. पी. शर्मा, सहायक महानिदेशक (पी.एच.बी.)

New Delhi, the 19th November, 1985

S.O. 5409.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunication, hereby specifies 1-12-1985 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Kadambathur, Perambakkam, Poondi and Tirur Telephone Exchange, Tamil Nadu Circle.

[No. 5—26/85-PHB]

K. P. SHARMA, Asstt. Director General (PHB)

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1985

का. आ. 5410 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार इंडियन आइरन एंड स्टील कं. लि. की चासनाला कोलियरी के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-11-1985 को प्राप्त हुआ था ।

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 8th November, 1985

S.O.5410.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Chasnalla Colliery of Messrs Indian Iron & Steel Company Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th November, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 20 of 1985

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1)-(d) of the ID Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Chasnalla Colliery of Messrs. Indian Iron and Steel Company Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen—Shri D. Mukherjee, Secretary Bihar Colliery Kamgar Union.

On behalf of the employers—Shri R. S. Murthy, Advocate.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal

Dated, Dhanbad the 29th October, 1985

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act., 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-20012-(367)|84-D.III(A), dated the 4th March, 1985.

SCHEDULE

"Whether the demand of Bihar Colliery Kamgar Union that S|Shri D. K. Pandey and Md. Allauddin should be given by the management of Chasnalla Colliery of Messrs. Indian Iron & Steel Company Limited the designation of Senior Mechanical Fitter and placed in a proper category of their entitlement with retrospective effect is justified If so, to what relief are these workmen entitled ?'

The case of the workmen is that the two concerned workmen Shri D. N. Pandey and Md. Alauddin were working in Chasnalla Colliery of M|s. IISCO Ltd. since long. In response to the advertisement made by the management in inviting applications from existing employees of the colliery for the post of Senior mechanical Fitter, the concerned workman applied for the same giving their full biodata. Thereafter the management issued interview letter dated 21-4-79 to the concerned workmen for the post of Senior Mechanical Fitter. The concerned workmen were successful in the interview and were selected and they were called for training in the post of Senior Mechanical Fitter for 6 months. The concerned workmen completed the training period successfully. As per advertisement and subsequent selection and terms of appointment the concerned workmen were entitled for the post of Senior mechanical Fitter in Cat. VI after completion of 6 months training period but the management in violation of the aforesaid facts placed the concerned workmen in the post of Fitter Grade D with starting basic daily wage of Rs. 20.90P. After the completion of 6 months training period the concerned workmen were entitled to be placed to the post of Senior Mechanical Fitter in Cat. VI with a starting basic of Rs. 23.33P per day. With an ulterior motive to victimise the concerned workmen, some junior workmen namely S|Shri P. Krishnan and Sadanand Singh were placed in Grade-C by superceding the concerned workmen who were senior to them. The other workmen performing the same and similar nature of job are getting Grade-B and as such the concerned workmen are also entitled to Grade-B on the principal "equal pay for equal work". The concerned workmen several times represented before the management for their proper designation and category|grade but with no effect. Thereafter the union of the concerned workmen, namely, Bihar Colliery Kamgar Union raised an industrial dispute before the ALC(C), Dhanbad which ended in failure. On the failure report submitted before the Govt. of India, Ministry of Labour the present reference was made for adjudication. It has been submitted on behalf of the workmen that the concerned workmen are entitled to the post of Senior Mechanical Fitter in Cat. VI with starting basic of Rs. 23.39P per day with retrospective effect and that they are further entitled for grade-C from the date their juniors S|Shri P. Krishnan and Sadanand Singh were promoted in Grade-C and still further their demand is that they are entitled to Grade-B from the date other workmen are getting Grade-B for doing the similar nature of job.

The case of the management is that the dispute is overstale as it has been raised after a lapse of about 4 years and on this account alone it is liable to be rejected. The other technical objection raised on behalf of the management is that no dispute was directly raised by the workmen before the management . On facts the case of the management is that a serious accident had taken place in the deep mines of Chasnalla Colliery in 1975 and thereafter the said mine was closed. In order to meet the requirement of coking coal for the steel plant of IISCO, Ltd at Burnpur, the management started a mechanised open cast mine at Chasnalla. Prior to 1979 the mechineries and the personnel required for the mechanised open cast mine at chasnalla were provided by contractor M|s. Continental construction Ltd. In 1979 the management decided to work the said mechanised mine departmentally by deploying heavy earth moving machinery like dumper, shovel, excavator, dozers, drills etc. and for operating those machines the management needed workers to operate, repair and maintenance. During the relevant period there was a ban on direct recruitment of workers. As such instead of having regards to direct recruitment from the open market to fill the post of operators and technicians required for operating, repairing and maintaining the aforesaid heavy earch moving machinery, the management decided to invite applications from amongst the departmental candidates employed in all the collieries of the management for making a selection. Accordingly the management issued a notice dated 13-3-79 inviting applications from the departmental workers working in the collieries of the management for the different posts stating the qualifications experience etc. required to be possessed by the candidates. A large number of applications were received by the management in response to the said notice. The concerned workmen Shri D. K. Pandey was working in Coal preparation plant, Chasnalla as helper in Cat. II and the other concerned workmen Shri Md. Allauddin was working in a sand plant as Pantoon Khalasi in Cat. III in Noonodih Jitpur Colliery at that time and they also applied for the post of Senior Mechanical fitter Cat. VI. The concerned workmen did not fulfill the conditions relating to the qualifications and experience for the post of Senior Mechanical Fitter but even then they were interviewed by selection committee and were given practical trade test. The selection committee did not find them fit for the said post of senior mechanical fitter. However the management decided to impart training to the concerned workmen for the post of Sr. Mechanical Fitter. Accordingly they were transferred to E&M department at Chasnalla and were put under training for a period of 6 months tentatively. The letters made it clear that they were being specifically placed under training for a period of 6 months tentatively and that if they were not found suitable after the said training they will be reverted back to their original post. The concerned workmen accepted the said arrangement and they got their training. After the completion of the training the management reviwed their cases with reference to their suitability and the concerned workman were found fit for the post of Fitter in excavation grade D in the NCWA-II pay scale of Rs. 20 90-0 83-30. 86 P. per day on the minimum of the said pay scale. The concerned workmen accepted the post and made no objection or representation whatsoever at that time. The concerned workmen had not 7

years experience as mechanical fitter and were not holding ITI certificate which was the qualification required by the management for the post of Senior Mechanical Fitter as stated in the advertisement. The concerned workmen were not found fit for the post of Senior Mechanical Fitter. It was for management to adjudge whether the concerned workmen were fit for the post of Senior Mechanical Fitter. The demand of the sponsoring union is wholly misconceived and untenable. The qualifications fixed for Excavation Grade-B by the JBCCI for workers employed as Fitter in Grade-I stipulates a highly skill workmen possessing at least 7 years in the accurate fitting and assembling of various types of Excavation equipments besides general repairs and maintenance thereof and that he should be able to undertake dismantling, repairing and overhauling of various types of diesel engine and to diagnose the mechanical fault and rectify them, should be able to read and use instruments for accurate measurement and undertake independently repair jobs and that he should be literate enough to maintain log books for repairs and maintenance and should understand maintenance charts. S|Shri P. Krishnan and Sadanand Singh are not juniors to the concerned workman and no comparison can be made between their cases and the case of the concerned workmen. Shri P. Krishnan and Sadanand Singh had acquired greater skill and proficiency than the concerned workmen and as such they were selected and placed in Grade C. It is also denied by the management that for performing the same job as that of the concerned workman, others are getting Grade-B. On the above plea it is prayed that the reference be answered in favour of the management.

The question to be determined in this reference is whether the concerned workmen are entitled to be designated as Senior Mechanical Fitter and placed in Cat. VI or any other cacategory with retrospective effect.

The workman and the management have each examined one witness in support of their case. The management has produced documents which have been marked Ext. M-1 to M-6 and the documents produced on behalf of the workmen have been marked as Ext. W-1 to W-9.

Some of the facts of the case are admitted. Both the concerned workmen were working in Chasnalla Colliery in lower category and had applied for the post of Senior Mechanical Fitter in response to the advertisement made vide Ext. W-6 dated 13-3-79. It is also admitted that they were called for interview and after trade test they were selected for training for the post of Senior Mechanical Fitter and after they completed their training for 6 months they were placed in the post of Fitter Grade-D with starting basic of Rs. 20.90 P. per day.

The case of the concerned workman further is that they had applied for the post of Senior Mechanical Fitter, they were interviewed for the said post, they were put under training for the said post after they were selected for the post of Senior Mechanical Fitter in Cat. VI but they were not actually placed in Cat. VI but were placed in the post of Fitter Grade-D. It stated that the concerned workmen had made several representations before the management for their proper categorisation and grade and when the management did not pay heed they raised an industrial dispute.

The case of the management on the other hand is that the concerned workmen did not fulfill the qualifications they were required for the post of Senior Mechanical Fitter in Cat. VI in accordance with the notice of advertisement and that the concerned workmen were never found fit for the said post and after training they were found suitable for the post of Fitter Grade-D and accordingly they were placed in the said grade.

Ext. W-6 which is equivalent to Ext. M-6 dated 13-3-79 is the notice of advertisement issued by the management of IISCO. It will appear that the appointments were to be made from the existing employees of the colliery for operating earth moving equipment in Chasnalla and Ramnagar Open Cast Mine and the qualifications and experience along with the category or Grade was stated in respect of each designation of appointment. It will appear from item No. 7, the notice Ext W-6 that the qualifications and experience of Senior Mechanical Fitter as stated in it was that he must have at least 7 years experience as Mechanical Fitter and preferably holding ITI cerificate and that the said post was in Cat. VI. Admittedly the two concerned workmen had not the minimum 7 years of experience as Mechanical Fitter and also they did not hold any ITI certificate. Admittedly Shri D. K. Panday was a mechanical helper when he had applied for the post of Senior Mechanical Fitter which is stated by WW-1 Shri D.K. Pandey himself. The other concerned workman Md. Alauddin Anssari has not deposed and WW-1 has not also stated as to what was the designation of Md. Alauddin Ansai at the time he had applied for the post of Mechanical Fitter. It is stated in para-11 of the W.S. of the management that at the relevant time Shri D. K. Pandey was working in the Coal preparation plant, Chasnalla as helper in Cat. II and that Md. Alauddin was working in sand plant as Pantoon Khalasi in Cat. III in Noonidih Jitpur Colliery. The said fact has not been denied in para-9 of the rejoinder filed on behalf of the workmen. Thus it is clear that none of the concerned workmen had any experience as Mechanical Fitter. It is nowhere stated that the concerned workmen were holding ITI certificate. It is clear therefore that the concerned workmen had no qualifications and experience which was required for the post of Senior Mechanical Fitter in Cat. VI.

I need not go into the documents or evidence relating to the letters of interview and test which have been marked exhibits in this case as these facts are admitted. I would refer to one document which appears to be of some significance for the decision in the case. Ext. W-1 dated 30-8-79 is a letter issued by the Senior Personnel Officer to Alauddin Ansari and Ext. W-2 dated 28-5-79 is issued to the concerned workman Shri D.K. Pandey. It appears from Ext. W-1 that Shri Alauddin Ansari was considered for training for post of Senior Fitter for six months tentatively and was transferred to E & M department, Chasnalla on his existing basic grade and designation keeping other terms and conditions of service as unchanged. It was also stated that in case the concerned workman is not found suitable for promotion after 6 months training he will be reverted back to his original post. Ext. W-2 also shows that Shri D. K. Pandey was considered for training for the post of Senior Mechanical Fitter for 6 months tentatively and that if he was not found suitable for promotion after 6 months training he will be reverted back to his original post. Ext. W-3 dated 2-6-79 also shows that Shri D. K. Pandey was advised to report to E & M department with effect from 4-6-79 as he was selected for the training of the post of Senior Mechanical Fitter. Ext. M-1 dated 2-5-79, Ext. M-4 dated 25-5-79 and Ext. M-5 dated 30-8-79 also are to the same effect. MW-1 Shri S. Acharjar is working as an Executive Engineer at IISCO's Chasnalla Colliery. It will appear from his evidence that the concerned workmen had applied for the post of Senior Mechanical Fitter who were not found fit for the said post. He has stated that the concerned workman were put in training for 6 months for the post of Senior Mechanical Fitter. According to him nobody was selected for the post of Senior Mechanical Fitter at that time. He has stated that the concerned workmen and other were trained by the suppliers of heavy equipment and the foreman and were given theoretical and practical training when their antitude and acquisition of skill was marked. He has stated that after the training the workmen were taken test but were not found fit for theh post of Senior Mechanical Fitter and as such the management decided to place them in Grade-D. He has denied that any assurance was given by the management to the concerned workmen that they will be placed in the post of Senior Fitter after their training. He has stated that the concerned workmen and other workmen who were placed in Grade-D did not make any protest for higher grade at that time. It appears from the evidence of MW-1 that the concerned workmen were not found fit for the post of Senior Mechanical Fitter. WW-1 has stated that the management gave him a letter about his selection as Senior Mechanical Fitter but no such letter has been produced on behalf of the concerned workmen to show that they were selected for the post of Senior Mechanical Fitter. What is apparent from the record is that the concerned workmen were selected for training of the post of Senior Mechanical Fitter and there is no paper to show that the concerned workmen were actually selected for

the post of Senior Mechanical Fitter. The selection for training for the post of Senior Mechanical Fitter is not the same as that of the appointment in the post of Senior Mechanical Fitter. The matter is rather made very clear in Ext. W-1 wherein it is stated that in case the concerned workmen were not found suitable for promotion after 6 months of training they will be reverted back to their original post. The concerned workmen have not, of course, been reverted back to their original post as the management probably decided that the concerned workmen may usefully be employed as Fitter in Excavation Grade-D although they were not suited for the post of Senior Mechanical Fitter in Cat. VI. Had the concerned workmen been selected for the post of Senior Mechanical Fitter it would not have been stated in Ext. W-1 that in case they were not found suitable for promotion after 6 months of training they will be reverted back to their original post. The concerned workmen took their training on the basis of Ext. W-1 and as such they had accepted the terms as laid down in it.

Taking all the above facts into consideration it is apparent that the concerned workkmen were not selected for the post of Senior Mechanical Fitter in Cat. VI and that they were merely selected for training for such post and when they were not found fit for being posted as Senior Mechanical Fitter they were given a lower grade of Fitter in Fitter Grade-D. The fact that the concerned workmen had not raised any obection for a pretty long time also shows that the concerned workmen had accepted Fitter Grade 'D' as they were in know of the full facts that they had not been selected for the post of Senior Mechanical Fitter in Cat. VI.

It is stated that the concerned workmen had made several representations before the management when they were given grade of Fitter Grade-D but they have not filed any copy of representations which is expected to be with them, to show that they had made any objection in their representation about their placement in Fitter Grade-D.

The concerned workmen have filed office order Ext. W-8 dated 28-11-83 in respect of Bharat Coking Coal Ltd. The terms and conditions of service are different than that of WSCO and as such Ext. W-8 cannot be of any use in deciding the question.

It has been stated on behalf of the workmen that Sadanand Singh and P. Krishnan who were junior to them were given Grade-C. MW-1 has stated that the concerned workmen and all other were placed in Grade-D. He has further stated that in 1982 there was selection for the next higher grade 'C' from grade 'D' and thereafter Sadanand Singh and P. Krishnan were selected for Grade-C. He has stated that the concerned workmen were also considered but were not selected in Grade-C. It is thus clear that Sadanand Singh and P. Krishnan who were also in Grade-D were selected in Grade-C in 1982 and that the concerned workmen whose cases were also considered at that time were not selected in Grade-C. Thus there appears no question of seniority of the concerned workmen. It was a question of selection to the higher grade in which P. Krishnan and Sadanand Singh were found fit for Grade-C whereas the concerned workmen were not found fit for the same in year 1982. Thus the question of seniority is also of no importance for decision of the case.

The concerned workmen have produced photo copy of an Award Ext. W-9 passed in Ref. 42 of 1981 dated 27-5-82. The said Award was on different facts and the points for decision in that case were not similar to the facts for decision in the present case and as such the award made in Ext. W-9 also can be of no guide for decision of the point involved in the present reference.

In the result, I hold that the demand of Bihar Colliery Kamgar Union that Shri D. K. Pandey and Md. Alauddin should be given by the management of Chasnalla Colliery of M/s. IISCO Ltd. the designation of Senior Mechanical Fitter and placed in a proper category of their entitlements with retrospective effect is not justified. Accordingly the concerned workmen are not entitled to any relief.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer

Dt. 29-10-1985.

[No. L-20012(367)/84-D. III(A)]

A. V. S. SARMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1985

का. आ. 5411.—मैसर्स धर्मापुरी जिला को-आपरेटिव चीनी मिल लिमिटेड, पैनेकोडे-636808 (टी एन. 08058) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके

स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/228/85—एस. एन.—4]

New Delhi, the 8th November, 1985

S.O. 5411.—Whereas Messrs. Dharmapuri District Co-operative Sugar Mills Limited, Palacode-636808 (TN/8058) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the

employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(228)85-SS.IV]

का. आ. 5412:—मैसर्स शेरुद्दीन खान, ठेकेदार, ई. डब्ल्यू, एस 512, वैशालनगर भिलाई, मध्य प्रदेश (एम पी/2374) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदनकिया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजनक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उस मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014/231/85-एस.एस-4]

S.O. 5412.—Whereas Messrs Sheruddin Khan, Contractor, EWS-512: Vaishalinagar, Bhilai, Madhya Pradesh (MP/2374) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(231)/85-SS.IV]

का.आ. 5413.—मैसर्स के. एल. राटी, स्टील लिमिटेड लोनी रोड, शाहदरा, दिल्ली-110032 (डी.एल./3365) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रामियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य-निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों, को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/230/85-एस.एस.-4]

S.O. 5413.—Whereas Messrs. K. L. Rathi Steel Limited, Loni Road, Shahdara, Delhi-110032 (D.L.)3365) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithsatnding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall beliable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(230)85-SS.IV]

का.आ. 5414.—मैसर्स गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाईजर्स कंपनी लिमिटेड पो.आ. नर्मदानगर-392015, जिला भड़ूच (जी जे/14401) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक, बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अवतरण, निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/222/85-एस.एस-4]

S.O. 5414.—Whereas Messrs. Gujarat Narmada Valley Fertilizer Company Limited, P.O. Narmadanagar-392015 Distt. Bharuch (GJ|14401) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the regional Provident Fund Commissioner, Gujarat, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain, covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurace Corporation of India as already adopteed by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nomminees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee and heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No S-35014/222/85-SS. IV]

का.आ. 5415.—मैसर्स ज्ञान सिंह ठेकेदार वैशाल-नगर प्राईवेट क्वाटर भिलाई मध्य प्रदेश (म.प्र./2113) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सह-बद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों, को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम बीमाकृत राशि

के हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/229/85 -एस एस-4]

S.O. 5415.—Whereas Messrs. Gyan Singh, Contractor, Vaishali Nagar, Private Quarter, Bhilai, Madhya Pradesh, (MP|2113), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expense involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contaiend in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10 Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance orporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|229|85-SS. IV]

का. आ० 5416—मैसर्स सिम्पलेक्स कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड, 5-इंडस्ट्रियल एस्टेट, भिलाई, मध्य प्रदेश (म. प्र. 2045, 2045-ए, बी, सी डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बताए जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/226/85-एस एस I]

S.O. 5416.—Whereas Messrs. Simplex Castings Private Limited, 5, Industrial Estate, Bhilai-490026, Madhya Pradesh (M.P./2045, 2045-A, B, C, D, E, F, G H I and J) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Mescellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Givernment may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of insepection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund of the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhay Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse. the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12 Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(226)|85-SS.IV]

का०आ० 5417.—मैसर्स शा वालिस एण्ड कम्पनी लिमिटेड, 154, थैम्बू चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2ख) के अधीन अपने फर्टिलाइजर एण्ड सुपर फासफेट फैक्ट्री मद्रास, ट्रीवैलोर हाई रोड, अवाडा, मद्रास (टी एन/528) और ब्लू फैक्टरी सल्फूरिक एसिड प्लान्ट, कट्टूवट्टी, मद्रास-600077 (टीएन/844) छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के नियमित कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापनों के नियमित कर्मचारियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिल नाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिल नाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिति/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/214/85-एस. एस-4]

S.O. 5417.—Whereas Messrs. Shaw Wallace and Company Limited, 154, Thambu Chetty Street, Madras-600001 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2B) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) in respect of the regular employees of its units at Super Phosphate Factory, Madras, Trivellore High Road, Avadi, Madras (TN/528) and Glue Factory, Sulphuric Acid Plant, Kaduvetti, Madras-600077 (TN/844).

And whereas, the Central Government is satisfied that the regular employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2B) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the regular employees of said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already

adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(214)/85-SS IV]

का. आ० 5418—मैसर्स दि गुण्टूर डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्राड्यूसर्स को-आप. यूनियन लिमिटेड, वेंडलामुडी-522213, गुण्टूर, डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश (एपी/6038) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुण्टूर को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधि वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुण्टूर के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय

करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशित/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014/223/85-एसएस-4]

S.O. 5418.—Whereas Messrs. The Guntur District Milk Producers Coop. Union Limited, Vadlamudi-522213, Guntur, District, Andhra Pradesh (AP/6038) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Guntur, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establisment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Guntur and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/(223)/85-SS.IV]

का.आ. 5419—मैसर्स आर.डी. वर्मा एण्ड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड, 20-के.एम. स्टोन, मेरठ रोड, गाजियाबाद (उ.प्र./6358) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा निगम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों, को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014/224/85-एस.एस-4]

S.O. 5419.—Whereas Messrs. R. D. Verma and Company Private Limited, 20 K. M. Stone, Meerut Road, Ghaziabad (U.P. 6358) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(224)|85-SS.IV]

का.आ. 5420.—मैसर्स नीलम्बर सिंह, ठेकेदार, क्वाटर नं. एल.आई.जी. 101, भिलाई, मध्य प्रदेश (म.प्र./2373) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहसंबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीयसरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहलेही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है , तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशितो/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं . एस-35014/225/85-एस .एस .-4]

S.O. 5420.—Whereas Messrs. Niteshwar Singh, Contractor, Qtr. No. L.I.G.-101, Bhilai--Madhya Pradesh (M.P. 2373) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain, such accounts and provide such facilities for insnection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under he said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(225)/85-SS.IV]

का.आ. 5421.—मैसर्स चौधरी थियटर, 19-जी.टी. रोड, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश—यू.पी./5411) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952

का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने को व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि वह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014/227/85-एस.एस.-4]

S.O. 5421.—Whereas Messrs. Chandhry Theatre, 19, G. T. Road, Ghaziabad, (UP|5411) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of ac ounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption is liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/227/85-SS.IV]

का.आ. 5422.—मैसर्स कनसोलीडेटिड काफी लिमिटेड, पोलिबेटा-571215, कोडागू (कर्नाटक स्टेट) (के. एन. 549) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधिन अपनी शाखा "कनसोलीडेट काफी लिमिटेड, क्यूरिंग वर्क्स, मोरोकून, बन्दर प्रीमिसिज के अधीन टैलीचेरी (के आर 549) छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त केरल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त केरल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और सही दावा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/206/85-एस. एस.-4]

S.O. 5422.—Whereas Messrs Consolidated Coffee Limited, Pallibetta-571215, Kodagu (Karnataka State) (K.R./549) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) in respect of its unit Consolidated Coffee Limited, Curing Works, Morocoon, Blunder Premises, Tellicherry (KR/549).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Kerala, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Kerala and where any amendment is likely to affect adversely the

interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(206)/85-SS.IV]

का. आ. 5423.—मैसर्स भिलाई स्टील प्लाण्ट, भिलाई-490001 (मध्य प्रदेश) (म. प्र. 1530) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2ख) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के नियमित कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन नियमित कर्मचारियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिदेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य देश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या

इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस.-35014/198/85-एस. एस.-4]

S.O. 5423.—Whereas Messrs Bhilai Steel Plant, Bhilai-490001 (Madhya Pradesh) (M.P./530) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2B) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the regular employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2B) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the regular employees of the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accouts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs the deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased members entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(198)/85-SS.IV]

का. आ. 5424.—मैसर्स मॉडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इंडिया) [लिमिटेड इससे पूर्व मैसर्स मॉडर्न बेकरीज (इंडिया) लि. के नाम से जाना जाता था] उप्पल कलां, हैदराबाद (आ. प्र. 4445) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्म-

कारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 916 तारीख 23-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को 12-2-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 11-2-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तनों से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियम की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/456/82/पी एफ-2(एस एस-4)]

S.O. 5424.—Whereas Messrs Modern Food Industries (India) Limited, (Previously known as M/s. Modern Bakeries (India) Limited, Uppal Kalan, Hyderabad (AP/4445) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act,1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred of sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 916 dated the 23-12-1982 and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 12-2-1986 upto and inclusive of the 11-2-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accouts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased members entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/456/82-PF. II (SS. IV)]

का. आ. 5425.—मैसर्स राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापटनम स्टील प्राजेक्ट, आर. टी. सी. कम्पलैक्स, विशाखापटनम (ए. पी./6986) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 913 तारीख 23-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 12-2-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 11-2-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देता है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामुहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामुहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामुहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि का जाने का व्यवस्था करेगा जिस से कि कर्मचारियों के लिए सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकुल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामुहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामुहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामुहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छुट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए किसी व्यक्ति क्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छुट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/455/पीएफ/82 एस एस-4]

S.O. 5425.—Whereas Messrs Rashtriya Ispat Nigam Limited, Vishkhapatnam Steel Project, R.T.C Complex, Vishakapatnam. (A.P./6986) (hereinafter referred to as the said estalishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 913 dated the 23-12-1982 and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 12-2-1986 upto and inclusive of the 11-2-1989

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establiishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh, maintain such amounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accouts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominations or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased members entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects

[No. S. 35014/455/82-PF. II (SS. IV)]

का. आ. 5426.—मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रामाचन्द्रापुरम, हैदराबाद (ए. पी./2938) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2(ख) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के नियमित कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4262 तारीख 26-11-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन के नियमित कर्मचारी को 18-12-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 17-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी निरीक्षण व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले से सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों

के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8 सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य का मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/264/82/पी.एफ-2/एसएस-4]

S.O. 5426.—Whereas Messrs Bharat Heavy Electricals Limited, Ramachandrapura, Hyderabad, (AP/2938) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2B) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And Whereas, the Central Government is satisfied that the regular employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2B) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4262 date dthe 26-11-1982 and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto the Central Government hereby exempts the regular employees of the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 18-12-1985 upto and inclusive of the 17-12-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charged as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accouts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the sallent features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9 Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/264/82-PF. II (SS. IV)]

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1985

का. आ. 5427.—मैसर्स सिम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एंड फाउण्ड्री वर्क्स (प्राइवेट) लिमिटेड, 65-इण्डस्ट्रियल एस्टेट, भिलाई, 490026 (मध्य प्रदेश) (म. प्र./737, 737ए, बी एण्ड सी) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी है, होने वाले सब खर्चों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले से सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय सत्वरता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/240/85-एस एस-4]

New Delhi, the 18th November, 1985

S.O. 5427.—Whereas Messrs Simplex Engineering and Foundary Works Private Limited, 65, Industrial Estate, Bhilai-490026 (M. P.) (M.P.|737, 737-A, C and D) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed is his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|240|85|-SS. IV]

का. आ. 5428—मैसर्स कोयम्बतूर पाइनीर मिल्स लिमिटेड, "बी" मिल्स, कोयम्बतूर-19 (टी. एन|1033) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बिमा निगम की समूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए, ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिल नाडु को ऐसे विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखना तथा निरीक्षण के लिए ऐसे सुविधाएं प्रदान करना जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिल नाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त, स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/239/85-एस. एस-4]

S.O. 5428.—Whereas Messrs Coimbatore Pioneer Mills Limited 'B' Mills, Coimbatore-19 (TN|1038), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014/239/85-SS. IV]

का. आ. 5429.—मैसर्स हिन्दुस्तान थाम्पसन एसोसिएट्स लिमिटेड लक्ष्मी बिल्डिंग, सर पी. एम. पी. बाक्स नं. 541, बम्बई-400001 (म. एच/3966) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3(क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य-निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12 इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार/नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/241/85-एस.एस-4]

S.O. 5429.—Whereas Messrs Hindustan Thompson Associated Limited, Lakshmi Building, Sir P. M. Road, P. B No. 541, Bombay-400001 (M. H.|3966), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed is his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(241)85-SS. IV]

का. आ. 5430.—मैसर्स एण्ड्र्यू यूले एण्ड कम्पनी लिमिटेड, यूले हाऊस 8, क्लाईव रो, कलकत्ता (प. बं 5223) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं :

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/238/85-एस. एस-4]

S.O. 5430.—Whereas Messrs Andrew Yule and Company Limited, Yule House 8, Clive Row, Calcutta-1 (WB|5223) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insuruance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of theh sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/238/85-SS. IV]

का. आ. 5431—मैसर्स मावाली टिफिन रूम्स, लाल बाग रोड, बंगलौर-27 (के. एन/2366) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किस व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशितों/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/237/85-एस. एस-4)]

S.O. 5431.—Whereas Messrs. Mavalli Tiffin Rooms, Lal Bagh Road, Bangalore-27 (KN/2366), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under teh Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed is his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provision of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to the cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of theh sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case with.n one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/237/85-SS. IV]

का.आ. 5432.—मैसर्स गनानाम्बिकाई मिल्स लिमिटेड, गनानाम्बिकाई मिल्स पोस्ट, कोयम्बटूर-641029 (टी.एन./०) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिल नाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिल नाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/236/85-एस.एस.-4]

S.O. 5432.—Whereas Messrs Gnanambikai Mills Limited, Gnanambikai Mills Post, Coimbatore-641029. (TN/60), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bangal maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed is his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/236/85-SS. IV]

का.आ. 5433.—मैसर्स डेज मेडिकल स्टोर (मैन्यूफैक्चरिंग) लिमिटेड, 6/डी, नैली सेनगुप्ता सारणी, कलकत्ता-700087 (प.बं./3560) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों, को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती विधिक वारिसों को उस राशि का सदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/235/85-एस.एस-4]

S.O. 5433.—Whereas Messrs Dey's Medical Stores (Manufacturing) Limited, 6/D, Nelly Sengupta Sarani, Calcutta-87 (WB/3560) (hereinafter referred as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment, in premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges ect. shall be borne by the employer.

4. The employer shall desplay on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of the default if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer,

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. 35014(235)|85-SS.IV]

का.आ. 5434 :—मैसर्स गुजरात कोपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लि., आनन्द डेयरी रोड, आनन्द (गुजरात) (जी.जे. 7286) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य-निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों

को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सख्या एस-35014/242/85-एस.एस.-4]

S.O. 5434.—Whereas Messrs, Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Limited, Anand Dairy Road, Anand (Gujarat) (GJ|7286) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment, in premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Gujarat maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of the default if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer,

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|242|85-SS.IV]

का.आ. 5435.—मैसर्स टी.टी. (प्राइवेट) लिमिटेड इंजीनियर्स डूर वाणी नगर बंगलौर-16 (कर्नाटक 1132) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण, प्रभारों सन्दाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों, को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामक निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/250/85-एस.एस. 4]

S.O. 5435.—Whereas Messrs T.T. (Private) Limited, Engineers Door Vaninagar, Bangalore-16 (KN|1132) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment, in premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Karnataka maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time totime, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accouts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall desplay on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of the default if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer,

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/250/85-SS.IV]

का. आ. 5436.—मैसर्स एन जी ई. एफ. लिमिटेड, रजिस्टर्ड आफिस, ओल्ड मद्रास रोड, बायाप्पानाबल्ली, पोस्ट बाक्स नं 3876, बंगलौर-560038 (के एन 2835) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय दिए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों, को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अधीन होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/250/85-एस एस-IV]

S.O. 5436.—Whereas Messrs. NGEF Limited Regd Office, Old Madras Road Byappanaballi, P.B. No. 3876, Bangalore-560038 (KN/2835) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provdent Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment, in premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of everymonth.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Reigonal Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of the default if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(249)/85-SS.IV]

का. आ. 5437.—मैसर्स दि नाराशिम्हा मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, नाराशिमा नायकनपलयम, कोयम्बतूर-641031 (टी0 एम0 3427) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियों भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/233/85-एस० एस०-4]

S.O. 5437.—Whereas Messrs The Narasimha Mills Private Limited, Narasimmanaickenpalayam, Coimbatore-641031 (TN/3427) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishmeat are, without making any separate contribution or payment, in premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance whichare more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissione, Tamil Nadu maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of everymonth.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accouts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall desplay on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the emplover fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of the default if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/233/85-SS.IV]

का० आ० 5438——मैसर्स महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लिमिटेड, गेटवे बिल्डिंग, अपोलो बन्दर, बम्बई–400039 (एम एच/4435) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952) (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी का व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस–35014/234/85–एस० एस०–4])

S.O. 5438.—Whereas Messrs Mahindra and Mahindra Limited, Gateway Building, Appollo Bunder, Bombay-400039 (MH/4435) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contributon or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, diret under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said ACT, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accouts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employee than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of the default if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme out for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/234/85-SS.IV]

का० आ० 5439——कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 24 दिसम्बर, 1983 में प्रकाशित, भारत सरकार के तत्कालीन श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 4712, दिनांक 22 नवम्बर, 1983 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में :—

(क) "भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना" और "सामूहिक बीमा योजना" शब्दों, जहां-जहां भी वे आते हैं, के स्थान पर "जीवन बीमा योजना" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) अनुसूची की शर्त 5 में "भारतीय जीवन बीमा निगम" के शब्दों का लोप होगा ;

(ग) अनुसूची की शर्त 10 का लोप होगा और उसके लोप के बाद शर्त संख्या 11 और 12 को क्रमशः शर्त 10 और 11 पुनः संख्यांकित किया जाएगा ;

(घ) अनुसूची की इस तरह पुनः संख्यांकित शर्त 11 में "भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन" शब्दों और अंकों के स्थान पर "दावेदार द्वारा राशि प्राप्त करने के 15 दिन" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[संख्या एस—35014/219/83-पी० एफ०—2 (एसएस)]

S.O. 5439.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) the Central Government hereby makes the following amendments to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) S.O. No. 4712, dated the 22nd November, 1983 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 24th December, 1983 :—

(a) In the said notification for the words 'Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India' and 'Group Insurance Scheme' wherever they occur, the words 'Life Cover Scheme' shall be substituted.

(b) in condition 5 of the Schedule, the words 'to the Life Insurance Corporation of India' shall be omitted ;

(c) the condition No. 10 of the Schedule shall be omitted and after the condition as so omitted, conditions 11 and 12 shall be renumbered as conditions to and 11 respectively ;

(d) in condition 11 of the Schedule as so renumbered, for the figure and words "7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India" the figure and words "15 days of the receipt of the claim from the claimant" shall be substituted.

[No. S-35014/219/83-PF. II (SS. IV)]

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1985

का० आ० 5440——केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ऐचीलेस ट्रैवल्स प्रा० लि०, 145, एल्डाम्स रोड, मद्रास—18, नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[स० एस—35019 (410)/85-(एस० एस० 2)]

S.O. 5440.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Achiles Travels Private Limited, 145, Eldamms Road, Madras-600018 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(410)/85-SS-II]

का० आ० 5441.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एस० सरवानन, टैक्सटाइल मैनयूफैक्चरर्स, सं० 23 सोंदाम्मान कोएल लेन, कोम्मारापालायम, तामिल नाडु। नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और, कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस–35019 (404)/85–एस० एस०–2]

S.O. 5141.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. S. Saravanan, Textile Manufacturers, No. 23, Soundamman Koil Lane, Kommarapalayam. Tamil Nadu, have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(404)/85-SS-II]

का० आ० 5442.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स धर्मपुरी को-ओपरेटिव, प्रिंटिंग प्रेस लिमिटेड, डी० डी० 25, 31, एन० जी० जी० ओ० कालोनी, धर्मपुरी–636705, नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस–35019 (405)/85–एस० एस०–2]

S.O. 5442.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Dharmapuri Co-operative Printing Press Limited, D-D 25, 31, N.G.G.O. Colony, Dharmapuri-636705 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(405)/85-SS-II]

का० आ० 5443.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आर० के० इन्टरप्राइजेज, 12बी, अरकॉट रोड, पोरूर मद्रास-602104 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019 (407)/85-एस एस-2]

S.O. 5443.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs R. K. Enterprises, 12 B, Arcot Road, Porur, Madras-602104 have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(407)/85-SS-II]

का०आ० 5444.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स केवलचंद श्रेनीकराज, कॉटन एंड जनरल मर्चेन्ट्स, न० 17, प्लाट नं 3, राजेन्द्रगंज, रायचूर, नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019 (408)/85-एस एस-2]

S.O. 5444.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kavalchand Shrenikraj, Cotton and General Merchants, No. 17, Plot No. 3, Rajendraganj, Raichur-584102 have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(408|85-SS-II]

का०आ० 5445.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मुरा इन्टरप्राइजेज, विजयपुरम, तिरुवारुर, तामिल नाडु नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(409)/85 एस एस -2]

S.O. 5445.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mura Enterprises, Vijayapuram, Thiruvarur, Tamil Nadu, have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(409)/85-S-II]

का०आ० 5446.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वी०आर० इंडस्ट्रीज ए-4, सिडको इंडस्ट्रियल ईस्टेट, विलीवाक्कम, मद्रास-600049 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और

प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं०एस-35019 (411)/85-एसएस-2]

S.O. 5446.—Whereas it apears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs V. R. Industries, A-4, Sidco Industrial Estate, Villivakkam, Madras-600049 have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(411)/85-SS-II]

का०आ० 5447.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स के धंधापानी एंड कम्पनी प्रा०लि०, 141 लिंगही चेटटी गली, मद्रास-1 और इसकी बंगलौर और कलकत्ता स्थित शाखाएं नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं एस-35019 (412)/85-एसएस-2]

S.O. 5447.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs K. Dhandapani and Co. Private Limited, 141, Linghi Chetty Street, Madras-1, including its branches at Bangalore and Calcutta have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(412)/85-SS-II]

का०आ० 5448.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सत्या पैकेजिंग इण्डस्ट्री, ए-4 यूनिट, इंडस्ट्रीयल इस्टेट, मदुराई 625007 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35019(413)/85-एसएस-2]

S.O. 5448.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sathya Packaging Industry, A-4, Unit, Industrial Estate, Madurai-625007 have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 152), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(413)/85-SS-II]

का०आ० 5449.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बाम्बे सिल्क स्टोर्स, 105, पैलेस रोड, मदुराई-1, तमिलनाडु नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस०-35019 (414)/85-एसएस-2]

S.O. 5449.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bombay Silk Stores, 105, Palace Road, Madurai-1 Tamil Nadu have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(414)/85-SS-II]

का०आ० 5450.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स साई कृष्णा फिल्मस, पोस्ट बाक्स नं० 502, गांधीनगर, विजयवाड़ा-3 आंध्र प्रदेश और इसकी विशाखापट्टनम स्थित शाखा नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (14) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35019 (415)/85-एसएस-2]

S.O. 5450.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sai Krishna Films, Post Box No. 502 Gandhi Nagar, Vijayawada-3 Andhra Pradesh including its Branch at Visakhapatnam have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(415)-85-SS-II]

का०आ० 5441.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वर्मा इलैक्ट्रो-मैकेनिक्स प्रा०लि०, सी-14, इलैक्ट्रोनिक कम्पलैक्स कुशाइगुड़ा, हैदराबाद-500762 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35019 (416)/85-एसएस-2]

S.O. 5451.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Varma Electro-relation to the establishment known as Messrs Varma Electro-guda, Hyderabad-500762, have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(416)/85-SS-II]

का आ 5452.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स म्युनिसिपल कालेज ऑफ एजुकेशन, एम जी रोड चिकबालापुर 562101, कोलार (कर्नाटक) नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण ह उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं एम-35019 (417)/85-एस एस -2]

S.O. 5452.—Whereas it apears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Municipal College of Education, M.G. Road, Chickballapur-562101, Kolar (Dist.) Karnataka have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(417)/85-SS-II]

का आ 5453.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एम टी आर कन्डीमैन्ट नं 11 लालबाग रोड, बंगलौर 560027 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं एस. 35019 (418)/85एस एस-2]

S.O. 5453.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs M.T.R. Condiments, Noll, Lalbaugh Road, Bangalore-27, have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(418)/85-SS-II]

का आ 5454.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सरवीवल इन्डस्ट्रीज सी वी आर बिल्डिंगस, 12 होसुर रोड, बंगलौर-560027 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं एस-35019 (419)/85-एस एस-2]

S.O. 5454.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Servewel Industries, CVR Buildings, 12, Hosur Road, Bangalore-560027, have agreed that the Provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(419)/85-SS-II]

का आ 5455.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वीरांयल (इंडिया) प्रा०लि०, 9/3 हायेस रोड क्रास, बंगलौर-25 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं एस-35019 (420)/85-एस एस -2]

S.O. 5455.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Vieryl (India) Pvt. Ltd., 9|3, Hayes Road, Cross, Bangalore-25, have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(420)/85-SS-II]

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1985

का०आ० 5456.—मैसर्स सुन्दरम फाइनेंस लिमिटेड, सेंट्रल आफिस 190-माउण्ट रोड, मद्रास-600026 और इसकी सभी शाखाएं जो कोड नं० तमिलनाडु 10595 के अधीन आते हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन से पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बकाया राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/267/85-एस०एस०-4]

S.O. 5456.—Whereas Messrs. Sundaram Finance Limited, Central Office, 190, Mount Road, Madras together with all its branches covered under Code No. (TN/10595) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (2A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(267)/85-SS.IV]

का० आ० 5457.—मैसर्स कम्बाइण्ड इण्डस्ट्रियल लि०, साईट नं० 24 और 260, इण्डस्ट्रियल सर्वे, स्टेज, पो० बाक्स नं० 306, मैसूर माउथ मैसूर-570008 (के०एन० 9358) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियम) की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए विलंब की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो संदेय है, छूट न दी गई होती, तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशित/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय त्वरितता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/262/85-एस एस-4]

S.O. 5457.—Whereas Messrs, Combined Industrial Limited Site No. 24 and 26D, Industrial Suburb, III Stage, P. Box No. 306, Mysore South Mysore-570008 (KN|9358) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefit available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|262|85-SS.IV]

आ.आ. 5458.—मैसर्स आई.जी.ई. (इण्डिया) लिमिटेड, निर्मल, 17-मंजिल, नारीमान प्वाइण्ट, बम्बई-400021 (एमएच/4043) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधि-

नियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि का हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/245/85-एस.एस.-4]

S.O. 5458.—Whereas Messrs, I.G.E. (India) Limited Nirmal, 17th Floor, Nariman Point, Bombay-400021 (MH|4043) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain, such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already

adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/245/85-SS.IV]

का.आ. 5459.—मैसर्स सुखबीर सिंह, ठेकेदार, जोगेंद्र सिंह कालोनी, कालोनी, नन्दनी रोड, भिलाई-1, मध्य प्रदेश (म.प्र./2114) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सम्बद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि कर जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्यप्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशितों/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/261/85-एस.एस4]

S.O. 5459.—Whereas Messrs. Sukhbir Singh, Contractor, Jogender Singh Colony, Nandini Road, Bhilai-1 (M.P.) (MP/2114) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment exempted under the said Act, is employed in his member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the the exemption is liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|261|85-SS.IV]

का.आ. 5460.—मैसर्स होवे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, 81—नेहरू प्लेस, नई दिल्ली—110019 (डी.एल/2372) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप समूह बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य-निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदा के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले सदस्यों की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/247/85-एस. एस-4]

S.O. 5460.—Whereas Messrs Howe (India Private Limited, 81, Nehru Place, New Delhi-110019 (DL/2372) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (5A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(247)/85-SS IV]

का.आ. 5461.—मैसर्स महेन्द्र लिण्ट्रेड प्रोडयूसर्स लिमिटेड, 146, बम्बई पूना रोड, पिम्परी, पूना-411018 (एम एच) 6916) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अभिरक्षण, निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को अपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन अपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितीयों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/244/85-एस. एस.-4]

S.O. 5461.—Whereas Messrs Mahindra Sintered Producers Limited, 146, Bombay Poona Road, Pimpri, Poona-411018 (MH/6916) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance

Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to effect adversly the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(244)/85-SS.IV]

का आ 5467.—मैसर्स महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लिमिटेड आटोमोटिव डिवीजन, अकरली रोड, कण्डिवली (पूर्व) पो. बाक्स नं. 7655, बम्बई- 400067 (एम एच. 496) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना, नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस- 35014/243/85-एस.एस.- 4

S.O. 5462.—Whereas Messrs. Mahindra and Mahindra Ltd. Automotive Division, Akurli Road, Kandivli (East) P.B. No. 7655, Bombay-400067 (MH/496) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(243)/85-SS-IV]

का.आ. 5463.—मैसर्स उहदे इंडिया लिमिटेड, उहदे हाउस, आर. बी. शास्त्री मार्ग, विक्रोली पश्चिम बम्बई-400083 (एमएच/14765) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है तो जो कर्मचारी की उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/248/85-एस.एस.-4]

S.O. 5463.—Whereas Messrs. Uhde India Limited, Uhde House, L.B. Shastri Marg, Vikhroli (West) Bombay-400083 (MH/14765) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insrance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the clouse of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the ife Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35104(248)|85-SS-IV]

का.आ. 5464.—मैसर्स कर्नाटक को-आपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड (फॉर्मर्ली कर्नाटक डायरी डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०), सेन्ट्रल आफिस नं. 22, पूर्णीमा बिल्डिंग, जे.सी. रोड, पहली क्रास, बंगलौर–27 (कन/6787) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस–35014/246/85–एस.एस–4]

S.O. 5464.—Whereas Messrs Karnataka Co-operative Milk Producers Federation Limited (formerly Karnataka Dairy Development Corporation Limited) Central Office, No. 22, Poornima Building, J. C. Road, 1st Cross, Bangalore (KN. 6787) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(246)|85-SS.IV]

का. आ. 5465.—मेसर्स कस्तूरबा हास्पीटल, मनीपाल-576119, कर्नाटक (के.एन/5105) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधित किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त

दर्ज करेगा और उसकी बात आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, जो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12 इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/266/85-एस एस -4]
ए. के. भट्टाराई, अवर सचिव

S.O. 5465.—Whereas Messrs Kasturba Hospital, Manipal-566119, Karnataka (KN|5105) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(266)|85-SS.IV]
A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1985

का. आ. 5466.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, टेलीकामयुनिकेशन, टेलीकोम सरकल भोपाल के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-10-1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 11th November, 1985

S.O. 5466.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the Telecommunications. Telecom Circle Bhopal/Central Telegraph Office, Jabalpur and their workmen, which was received by the Central Government on the 30th October, 1985.

BEFORE SHRI V. S. YADAV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(38)/1984

PARTIES :

Employers in relation to the management of Telecommunications Telecom Circle Bhopal/Central Telegraph Office, Jabalpur and their workman, Shri Malloo Prasad Patel, Chowkidar, Village and Post Imlai, P.S. Panagar, District Jabalpur (M.P.).

APPEARANCES :

For Workman—Shri P. D. Pathak, Advocate.

For Management—Shri A. P. Tare, Advocate.

INDUSTRY : Post & Telegraph

DISTRICT : Jabalpur (M.P.)

AWARD

Dated : October 16, 1985

In exercise of the powers conferred by Section10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government in the Ministry of Labour has referred the following dispute, for adjudication, vide Notification No. L-40012(7)/83-D.II(B) dated 7th June, 1984 :—

"Whether the action of the management of P&T Department, in relation to Central Telegraph Office, Jabalpur (MP) in treminating the services of Sri Malloo Prasad Patel, Chowkidar with effect from 29-2-80 is justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. Non-controversial facts of the case are that the workman, Shri Malloo Prasad Patel, is a Chowkidar in the Central Telegraph Office Jabalpur. His services were terminated with effect from 29-2-1980. The workman submitted petitions Ex.M|3 and Ex. M|4 dated 20-3-1980 and 7-8-1980 respectively to the General Manager Telecommunication, M.P. circle and Chairman, P&T Board, New Delhi. During the pendency of the above petitions the workman submited the case for conciliation before the Assistant Labour Commissioner, the outcome of which is this reference. In the meantime competent authority allowed his petition and he was appointed afresh on humanitarian ground on 6th July, 1983 pursuant to which the workman was required to give certain undertaking. The workman accepted and gave those undertakings to the department. He was accordingly appointed a fresh vide order dated 15-10-1983 (Ex. M/7).

3. The case of the workman is that his services were terminated without following any procedure of charge-sheet, enquiry etc. As per the statement of the management his services were terminated due to irregular attendance and availing leave without prior intimation and sanction of leave but no opportunity was given to him with respect to the action taken by the management. His termination amounts to retrenchment, yet he was not given any retrenchment compensation at the time of termination of his services as required under Sec. 25F of the Industrial Disputes Act though he had worked for more than 240 days in the year prior to termination. The order of termination is, therefore, void ab initio.

4. He accepted re-employment reserving his right to challenge the order of termination. On account of poverty he had no option but to accept conditional re-employment. He therefore prays that he is entitled to reinstatement with full back wages.

5. The case of the management stated briefly is that the services of the workman were terminated due to irregular in attendance and availing leave without prior intimation and sanction of leave. He was given adverse entries in this respect practically every year from the year of recruitment but no improvement was noticed. In the year 1979-80 he was awarded the punishment of Censure. Due to above reasons he could not be considered for quasi permanency for consecutive three years. Under the Rules of Department dated 25-10-1979 (Ex. M/2) the services of Government servants can be terminated whose chances of confirmation are remote. Since there were no chances of confirmation his services were terminated under Sub-rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965. However, as pointed out he was re-employed on humanitarian ground.

6. Neither the Post and Telegraph Department is an 'industry' within the meaning of Sec. 2-J nor Shri Patel is a 'workman' within the meaning of Sec. 2(s) of the Industrial Disputes Act, 1947. As such this Tribunal has no jurisdiction.

7. The preliminary objection has been half heartedly pressed before me in view of the earlier decision of this Tribunal and the settled law. Learned Counsel for the management was unable to show any authority in support of his contention. In such circumstances I need not dwell upon this matter at length. The objections over ruled.

8. In support of his case the workman, Shri Malloo Prasad Patel simply gave his statement and did not even file order of termination. On behalf of the management, Shri S. N. Chandalia, Senior Section Supervisor, has been examined who produced and proved documents Ex. M/1 to Ex. M/10. Shri Chandalia has stated that workman, Shri Malloo Prasad was irregular in attendance every year regarding which remarks were incorporated in service book Ex. M/8 which were communicated to him every year. In the year 1979-80 he was given a charge-sheet and after due enquiry he was punished with Censure (part of the record Ex. M/8). Because every year he was given adverse entry he was not found fit for quasi permanent post under Rule 3 of the CCS(Temporary Service) Rules, 1965, hereinafter referred to as the Rules. He was considered five times for the same. Therefore in view of the Circular Ex. M/2 his services were terminated under Rule 5. On the basis of the above evidence it has been contended that his services were terminated in accordance with Rules 1965 and it was a valid termination. However, on his petitions Ex. M/3 and Ex. M/4 the competent authority ordered him to be re-employed, the relevant documents are Ex. M/5 to Ex. M/7.

9. However, on behalf of the workman it has been contended that his termination amounts to retrenchment within the meaning of Sec. 2(oo) of the Act, which defines 'retrenchment' as meaning the termination by the employer of the services of a workman for any reason whatsoever, otherwise than by punishment inflicted by a disciplinary action, but does not include [categories (a) to (c) which admittedly do not apply to the present case]. The words "for any reason whatsoever" are the key words as has been held in the case of State Bank of India Vs. N. Sundramoney (AIR 1976 SC p. 1111). This legal position is, however, not very much agitated before me. On the other hand relying on the service record of adverse entries the Censureship punishment awarded and communicated, the

communication regarding his adverse entries dated 4-5-1979 (all forming part of Ex. M|8) and Ex. M|10 statement of record showing his absence and leave of various kinds, it has been contended that his services were terminated by way of disciplinary action on punishment awarded to him. I am unable to accept this contention. His previous record of unauthorised absence may have been bad but he was punished for the same by censure warning dated 10-1-1980 (part of confidential record Ex. M|8). The censure warning itself says that he is censured and nothing else. After these proceedings when his services were terminated on 29-2-1980 vide order Ex. M|1 it cannot be said that it was on account of disciplinary action initiated, as we know which resulted in warning of censure. For this termination there was no disciplinary action and no disciplinary punishment. His services were terminated simplicitor without any domestic enquiry and punishment. Therefore the workman's case does not fall in the exception to the definition of retrenchment given in Sec. 2(oo) of the Act. His termination therefore will amount to retrenchment.

10. Next provision relied on by the workman is Section 25F of the Act. We had a continuous service is not disputed. Section 25F is reproduced below for the sake of convenience :—

"25F—Conditions precedent to retrenchment of workmen.—No workman employed in any industry who has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until—

(a) the workman has been given one month's notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has expired, or the workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice :

Provided that no such notice shall be necessary if the retrenchment is under an agreement which specifies a date for the termination of service ;

(b) the workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen days' average pay for every completed year of (continuous) service or any part thereof in excess of six months; and

(c) notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government (or such authority as may be specified by the appropriate Government by notification in the Official Gazette)."

From the above it is crystal clear that three conditions are to be fulfilled before an employer can retrench the workman. Admittedly no notice was given as required under clause (a) but the order of termination dated 29-2-1980 (Ex. M|1) had directed that he shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances for the period of notice at the same rate at which he was drawing immediately before the termination of his service or as the case may be for the period of such notice falls short of one month. The second limb of Clause (a) is independent of the first limb. Therefore, the first condition is fulfilled though the workman may have chosen not to avail it. Admittedly no retrenchment compensation was awarded to him as is required under Clause (b). Thus it appears that this provision has not been complied with. The third condition incorporated in Clause (c) does not appear to be a condition precedent which has to be fulfilled before a retenchment can be validly effected. Since it is only intended to give the information to the appropriate Government about the retrenchment. Non-compliance therefore would not invalidate the 'retrenchment. The management having failed to fully comply with the provision of Sec 25F the retrenchment is viod abinitio as has been held in the case of Mohan Lal Vs Management of M|s Bharat Electronics Ltd. (AIR 1981 SC 1253) :—

"Notices and semantics apart, termination by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever would constitute retrenchment except in cases in the section itself. The excepted or excluded cases are where termination is by way of punishment inflicted by way of disciplinary action, voluntary retirement of the workman, retirement of the workman on reaching the age of superannuation if the contract of employment between the employer and the workman concerned contains a stipulation in that behalf and termination of the service of a workman on the ground of continued ill-health."

"In the instant case termination of service of the appellant does not fall within any of the exceptions or to be precise, excluded categories. Undoubtedly therefore the termination would constitute retrenchment. It is well settled that where prerequisite for valid retrenchment as laid down in Section 25-F has not been complied with, retrenchment bringing about termination of service is ab initio viod."

The same view has been reiterated in AIR 1983 SC 1320 Karnataka State Road Transport Corporation, Bangalore Vs. H. Boraiah; AIR 1982 SC p. 854 Robert D'Souza Vs. The Executive Enginreer Southern Railway and another.

11. The retrenchment being void ab initio as a normal rule the workman is entitled to reinstatement. But in the present case the workman has already been re-employed giving him fresh appointment from a certain date. The workman challenges this re-employment and claims reappointment from the date of termination with back wages on the strength of this reference. The question is whether he is entitled to the same. In the case of Gujarat Steel Tubes Ltd. Vs. Its Mazdoor Sabha (AIR 1980 SC p. 1896) it was held —

"Though the normal rule, on reinstatement, in full back wages since the order of termination is non est, even so, the industrial court may well slice off a part if the workmen are not wholly blameless."

In the instant case looking to confidential past record of his every year adverse entry regarding unauthorised absence it cannot be said that for this retrenchment the workman was entirely blameless. Since the workman in the instant case has been re-employed by fresh appointment, to my mind it will be more disadvantegeous to the workman if sliced off wages are granted to him becauuse from the date of fresh appointment he is getting full wages. It will therefore meet the end of juustice if he is reinstated from the date of discharge i.e. 29-2-1980 but he is allowed back wages only from the date of re-employment i.e. 17-10-1983 (FN). Consequently the reference is answered as under :—

The action of the management of P & T Department, in relation to Central Telegraph Office, Jabalpur (MP) in terminating the services of Shri Mulloo Prasad Patel Chowkidar with effect from 29-2-1980 is unjustified. The workman is ordered to be reinstated with effect from 29-2-1980 with the continuity of service. But he is allowed back wages from the date of re-emplolyment with effect from 20-10-1983 (FN) with all incidental reliefs admissible to him. Looking to the facts and circumstances of the case there will be no order as to costs.

V. S. YADAV, Presiding Officer.
[No. L-40012(7)|83-D. II(B)]

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1985

का.आ. 5467.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एयर इंडिया के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2 बम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-11-85 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 22nd November, 1985

S.O. 5467.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, 4th Floor, City Ice Building. 298, Nariman Point Bombay, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Air India and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th November, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2|16 of 1984

PARTIES :

Employers in relation to the management of Air India

AND

Their Workmen

APPEARANCES .

For the Empployers :

1. Shri F. S. Nariman, Sr. Advocate
2. Shri Lalit Bhasin, Advocate.
3. Shri S. K. Bhasin, Advocate
4. Shri K A. Sapat, Dy. Director Personnel
5. Shri George Clement, Industrial Relations Manager
6. Shri S. Narayana Murthy, Personnel Officer.

For the Workmen :

1. Shri C. L. Dudia,
2. Miss Indira Jaising,
3. Shri Anand Grover and
4. Shri Mihir Desai, Advocates.

INDUSTRY : Air lines

Bombay, dated the 30th September, 1985

AWARD

(Dictated in the open Court)

The present reference is an outcome of a demand dated 15-8-1983, Exhibit 4|WI issued by the various unions functioning in Air India. Since there will be a reference to these unions at one stage or the other, it will be necessary to refer to the same. The unions are Indian Pilots' Guild (IPG), Indian Flight Engineers' Association (IFEA), Indian Flight Navigators' Guild (IFNG), Air India Cabin Crew Association (AICCA) who together, it is stated, represent about 1900 members of staff out of total strength of 14000. I am given to understand that 12500 are serving at Bombay. The other unions are All India Aircraft Engineers' Association, (AIAEA), Indian Flight Despatchers' Union (IFDU), Indian Aircraft Technicians' Association (IATA) Air India Employees' Guild (AIEG), Air Corporation Employees Union (ACEU) and Air India Engineers' Association (AIEA). There is also another union known as Air India Officers' Association (AIOA) which although did not picture atleast at the time of conciliation proceedings, has also some interest in the outcome of the present proceedings.

2. The result of the demand was that they had held conciliation proceedings before the Chief Labour Commissioner (Central) on record at Ex. 23|WI, from which in para 8, we find that there were in all 10 topics discussed but ultimately a Memorandum of settlement was arrived at as seen from pages 205 to 207 of File No. F-2, the terms of which settlement were :—

"(1) The parties agreed to apply to the Government jointly for a reference of the matter in dispute to the National Tribunal|Industrial Tribunal for adjudication in the enclosed proforma under sub-section 2 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947.

(2) The Unions|Associations|Guilds representing all employees agreed to restore normalcy and status quo ante with immediate effect" and then there are clauses 3 and 4 with which we are not concerned.

3. On page 212 of the same file, we get a reference to the two issues which are the subject matter of the present Reference and ultimately by the order of the Government No. L-11025(3)|84-D.II(B) dated 24-2-1984 under Section 10(2) of the Industrial Disputes Act, the present reference found the light of the day.

4. The two issues which are required to be adjudicated upon and decided are as follows :—

"(i) Whether the Management of Air India has paid the employees the Additional DA and the Vairable DA effective 1-4-1975 and thereafter in accordance with the terms of agreements|understandings|commitments made with all the Unions|Associations|Guilds relating to the payment of ADA and VDA ? If not, to what relief are the employees entitled and if so, for what period ?

(ii) Whether the agreements, commitments, understandings referred to in clause I above, in so far as they relate to ADA and VDA were arrived at in confromity with the Government approval|directive|circular on the subject issued to Air-India? If not, what has been the resultant loss to the employees? To what relief are they entitled and from what date?"

5. As the issues stand, what is required to be seen is whether the agreements|commitments|understandings etc. referred to in clause i so far as they relate to ADA and VDA, were arrived at in conformity with the Government approval|directive|circular etc. and secondly, issue No. i speaks of the agreements|understandings|commitments and the payments of ADA and VDA thereunder.

6. Although the Reference is a culmination of the joint action of the parties and the two issues for decision are specific, on one hand on the part of the unions an attempt was made to extend the scope of the order of Reference and against this at the last moment an attempt has been made by the Management to constrict the same. The contesting unions tried to urge that this Tribunal is also called upon to determine whether the agreements|settlements|commitments etc. were obtained by fraud or misrepresentation etc. but as seen from the Award Part I, these unions failed in the said attempt and they had to be told that the element of fraud, misrepresentation etc. is outside the scope of the present Order of Reference Against this, as if to suggest that the management is also no less than a match to the unions, it was urged that the second issue does not arise at all because when there are settlements|agreements|commitments etc. assuming there be some directives, the terms of settlements would override those directives and, therefore, the terms of settlements alone can determine the rights of the parties and not the directives. Second limb of this argument was that the Government unless they refer to a general directive as contemplated by Section 34(i) of Air Corporation Act cannot bind the Corporation, and therefore, here again the settlements, commitments etc. must prevail. In this connection, it is pertinent to note that the Corporation which has filed the Written Statement in answer to the statement of claims and also the rejoinder denying specifically various assertions and raising contentions had failed to raise these contentions and a cursery glance to the issues framed would indicate that there is no issue on this question.

7. But assuming that since it is a legal question and, therefore open to be raised even at the last moment, the question still is whether such contention can be raised by the Corporation. Now as a first limb of the argument, it was urged that under Section 18 of the Industrial Disputes Act, the settlements would be binding on the persons stated therein and Sub-Section 3 says that a settlement arrived at in the course of conciliation proceedings would be binding on all the parties to the dispute while those arrived at otherwise than in the course of conciliation proceedings as

seen from sub-Section 1, shall be binding on the parties to the agreement. The definition of settlement we get in Section 2(p) of the Industrial Disputes Act. It is, therefore, urged that since there are certain settlements governing the rights of the parties and since those settlements are binding on these parties, if they go contrary to any directive from the Government, the settlements must prevail. This argument, however does not take into consideration certain salient features. Firstly the record shows that it is not all the unions who have entered into settlements but three of them only and in respect of some others, there is an offer and presumption of acceptance while in the case of others, there is unilateral extension of the benefits.

8. Secondly, if Section 18 is to play that important role as is being tried to be urged, then it would be very much relevant to note that the present reference itself is the creation of such settlement whereby this Tribunal is asked to decide the reference and the points of dispute have been noted in the Order of reference as well as in the conciliation proceedings and the settlement arrived at to which no second reference is needed. If the settlement is so sacrosanct, then this settlement arived at before the Conciliation Officer would be of the same nature and being a settlement arrived at in the course of conciliation proceedings referred to in Sub-Section 3, it woud bind all the parties to the dispute including the Management. Therefore, it is very late in the day for the Management now to try deletion of issue No. ii.

9. Air India Corporation was established under what is known as the Air Corporation Act of 1953. We then get Air Corporation Rules and also Regulations framed in exercise of the powers under Section 45 of the Act. It is true that Section 34(1) empowers the Central Government to give directions as to the exercise and performance of the functions of the Corporation and such directions shall be binding on the Corporation. We, however, find that under Air Corporation Rules of 1954, whenever any financial commitments are involved, the Corporation has to submit either the budget or supplementary estimates and the Rules further indicate that they are subject to the audit by the Auditor General vide Rule 3(4), Rule 4 and proviso to Rule 10. Even from Rule 15, we find that the Corporation is expected to submit annually to the Central Government the Annual Report pertaining to amongst other items, staff and finance and accounts. It is, thereorfe, evident that all the matters which involve finance are being controlled by the Central Government and the rules constituted under the Act. This is so because the Central Government is vitally concerned with those finances since they would be supplying the capital. Now, therefore, the Corporation cannot plead that whatever may be the directives, they are at liberty to act according to their own choice, and the only inference would be that by virtue of the settlement during conciliation proceedings and by virtue of the Rules enunciated above, the issue No. ii of the Order of Reference is very much relevant and requires to be decided.

10. Before we embark upon the discussions of these issues a short history leading to the same would not be out of place. We have already seen that the items which are referred for determination are ADA and VDA. In the year 1964, a reference was made to National Industrial Tribunal presided over by Justice Khosla who passed his Award on 28-1-1966 to be effective from 25-7-1964 whereby part of the DA which the employees till then were earning was merged with basic salary and then depending upon the wage slab, DA ranging from Rs. 55 to Rs. 100 was awarded but was not linked to any index. Thereafter, there were references first to Shri Kamala Sahai Tribunal and then to Shri Mahesh Chandra Tribunal and although certain awards came to be passed, the last one on the strength of the settlement arrived at, the quantum of D.A. as awarded by Justice Khosla remained Unaltered.

11. This gave rise to a demand or a notice in the year 1973 when as per the Staff Notice issued by the management, an interim relief of Rs. 50 was granted from 1-4-1973 to those who were drawing Provident Fund Pay upto Rs. 1000. In their statement of claims, the unions submit that under the staff notice dated 26-11-1973, it was decided to grant interim relief of Rs. 50 p.m. effective from 1-4-1973 and it is further stated that this relief was not applicable to those who were drawing pay in excess of Rs. 1 000 and pay meant as that in Air India Employees' Provident Fund Regulations. This interim relief was also not to count as basic pay for any purpose including provident fund.

12. Subsequently, as referred to on page 19 of the same statement of claim, three settlements were arrived at viz. settlement between the Management and ACEU dated 29-8-74, that between the Management and IATA of even date and lastly, a settlement dated 27-10-1975 between the Managment and IFDU whereby what is known as Additional DA ranging from Rs. 85 to Rs. 180 was sanctioned. We get these settlements at Ex. 7|WI pages 57, 61 and 65 and then we also find that an offer was made to the IFDU and the AIAEA by their letters dated 27-10-1975 and 13-9-1974.

13. Now for the purpose of grant of ADA of Rs. 85 to Rs. 180 a reference must be made to Government's letter dated 18-7-1974 Ex. 9|WI at page 77 of File No. 1 and since this letter as well as another letter dated 10|15-10-1975, Ex. 13|WI at page 100 form the crux of the whole issue they are being quoted ad verbatim :—

"Copy of D.O. No. AV|18015|1|74-AC dated 18-7-1974 from Shri C. L. Dhingra, Dy. Secretary, Ministry of Tourism & Civil Aviation to Shri K. G. Appuswamy Dy. Managing Director, Air India, Bombay.

Please refer to your d.o. letter No. GM|74-63(S) dated 31st May, 1974 regarding wage negotiations with various unions|associations. Your proposal for grant of the following ad-hoc relief as contained in paragraph 9 of your letter and which has been approved by your Board of Directors at its meeting held on the 28th June, 1974, has been approved by Government :—

Total emoluments counting for P. F.		Extent of relief recommended.
Rs.	Rs.	Rs.
upto	250	85
251	300	90
301	450	100
451	550	120
551	650	140
651	750	160
Above	750	180

(The relief above Rs. 750 will be subject to the condition that the existing emoluments plus the relief will not exceed Rs. 2400).

The relief effected would be subjected to the following conditions :—

(i) the relief will be valid for a period of one year from 1-4-1974 to 31-3-1975;

(ii) the Interim Relief of Rs. 50 p.m. granted from the 1st April, 1973 to employees drawing emoluments upto Rs. 1000 and the special compensatory allowance of Rs. 75 granted to Junior Officers should be adjusted;

(iii) the increase in emoluments will not count as pay for any purpose including provident fund;

(iv) It will be in full and final settlement of all demands including increase in emoluments and conditions of service of the unions|associations for the periods upto the 31st March, 1975 regardless of further increase in the cost of living index within this period; and

(v) the relief to person drawing more than Rs. 750 p.m. will be subject to conditions that the existing emoluments plus the relief will not exceed Rs. 2400 p.m., and

(vi) the relief will be subject to Additional Emoluments (Compulsory Deposit Ordinance, 1974).

3. Your proposal regarding increase in the contribution to the Contributory provident Fund from 8-1|3 per cent to 10 per cent has also been considered by Government but it has not been found possible to accept it."

Copy of letter No. AV.18015|2|75-AC dated 10|15-10-75 from Shri C. L. Dhingra, Ministry of Tourism and Civil Aviation to the Managing Director, Air India, Bombay and the Managing Director, Indian Airlines, New Delhi.

Sub :—Increase in employments of the employees of Air India and Indian Airlines.

With reference to the correspondence resting with your letter No. GM|74-63(S)|826 dated 1st October, 1975.

DMD|FA|8094 dated 4th July, 1975 and in continuation of this Ministry's letter No. AV. 180|2|75-AC dated 23rd July, 1975 on the above subject, I am directed to say that it has been decided that the employees of the Corporation may be granted an increase in dearness allowance of Rs. 95 p.m. effective from 1-4-1975 for adjusting the increase in consumer price indices since the date of the last revision made on 1-4-1974. Future adjustments in D.A. will be made at the rate of Rs. 1.30 per point of rise|fall in the average consumer price index, subject to the condition that in respect of employees getting a pay of Rs. 1,000 or less neutralisation shall be made at quarterly intervals (i.e. on 1-7-1975, 1-10-75 etc). For persons drawing a basic pay of above Rs. 1,000 the DA adjustment will be made at half-yearly intervals (i.e. 1-10-1975, 1-4-1976 etc.).

2. Pay plus additional D.A. plus variable DA should not exceed the ceiling of Rs. 2,400 p.m.

3. The payment of additional DA and variable is subject to the provisions of ADA (Compulsory Deposit) Act, 1974.

4. The agreement with Unions|Associations will come into effect from 1-4-1975 and will be for as long a duration as can be negotiated.

14. It is urged on behalf of the unions, that when these two-letters are to be construed, they must be construed in the light of what is appearing therein. They cannot be construed in the light of the conduct of the unions especially who are not parties to the same and any extraneous matter would be irrelevant in this regard. It is, evident that these two letters form the sheet-anchor of the unions' case and at the outset it must be stated that these letters instead of supporting the case of the unions, negative them completely. Under the first letter, Ex. 9|W1, the Government informs its approval to the proposals sent by the Management and it is stated that the proposal for the grant of ad-hoc relief as contained in para 9 of the letter was approved by the Government. It is further stated that the relief above Rs. 750 will be subject to the condition that existing emoluments plus the relief will not exceed Rs. 2,400. It is also stated that the increase in emoluments will not count as pay for any purpose including provident fund and then comes the clause (iv) which says it will be in full and final settlement of all the demands including the increase in emoluments and conditions of service of the Unions|Associations for the period upto 31-3-1975 regardless of further increase in the cost of living index within this period. Then clause (v) says that the relief to persons drawing more than Rs. 750 will be subject to the conditions that the existing emoluments plus the relief will not exceed Rs. 2,400.

15. The letter, therefore, lays down a limit of emoluments not exceeding Rs. 2,400, says that the payment is an ad-hoc payment and further says that whatever may be the further increase in the cost of living index till 31-3-1975, there would be no increase in the quantum of Rs. 85 to Rs. 180.

16. Before we turn to the letter at page 100 which ultimately is to determine the fate of the Reference, certain facts and definitions will have to be borne in mind. Under Air India Employee Service Regulations, the word 'Pay' in clause (1) of Regulation 3 means the amount drawn monthly by employees as (i) basic pay, (ii) personal pay and (iii) any other emoluments which may be classed as pay for any specific purpose.

17. Although such is the definition of the term in the Regulations, in Air India Employees' Provident Fund Regulations which are equally binding on the parties, the terms 'Pay' means basic pay and includes where admissible, command pay, efficiency bonus, navigation allowance, R|T allowance, overseas operations allowance, jet allowance special parity allowance, technical pay, qualification pay, dearness allowance, non-practising allowance, flight communications allowance and special allowance granted as an increase in emoluments calculated on the emoluments counting for Provident Fund. We have already seen that at the time of grant of interim relief as well as ad-hoc payment, care was taken to see that the relief is given uniformally to the employees. At. Ex. 227|M, there are the copies of the pay slips issued to the different categories of workmen and what I notice is that Capt. S. N. C. Misra is drawing total emoluments of Rs. 4,802 and odd, Capt. Yennamedi is drawing emoluments of Rs. 7,100 and odd, Mr. Vasudevan was drawing Rs. 4,500 and odd and equal were the total emoluments of Mr. Bahadur and then Mr. Bhaskaran was drawing emoluments of Rs. 4000 and odd. This variation in emoluments of these different categories as seen from the details was on account of the various allowances earned by these employees. Capt. Yennamedi was drawing Jet Allowance of Rs. 1000, 747 Flight Allowance also Rs. 1000, and then there are various allowances. If, therefore, the pay as defined in P.F. Regulations is not taken to be the basis of the relief, it may happen that a Captain drawing more than Rs. 5000 will get the relief because his basic pay and DA etc. falls below the line of Rs. 2,400 while others not getting them may be leprived of the same because their basic pay is something high. Therefore, it may happen that a rich may become richer and poor remains poor. To avoid this and to achieve uniformity, the only course open was to consider the emoluments known as P. F. Pay and then decide whether relief is permissible or not. Otherwise, as already stated, there is likely-hood of chaos and the real intention being no carried out.

18. With this we turn to the letter dated 10|15-10-1975 Ex. 13|WI. We have seen that Rs. 85 to Rs. 180 was an ad-hoc relief, we have seen that there were to be no variations in quantum till 31-3-1975 despite rise in price index and further we have also seen that only the employees who were eligible for the said relief were those drawing emoluments plus the relief less than Rs. 2,400 per month.

19. Now the controversy has arisen because in para 2 of the letter Ex. 13|WI what is referred to is Pay Plus ADA plus VDA should not exceed the ceiling of Rs. 2400. We then find in the first para that the Government informed the Corporation their decision that the employees of the Corporation should be granted an increase in D.A. of Rs. 95 per month effective from 1-4-1975 for adjusting the increase in consumer price indices since the date of the last revision made on 1-4-1974. It is further stated that future adjustments in D.A. will be made at the rate of Rs. 1.30 per point of rise|fall in the average consumer price index subject to the condition that the employees getting a pay of Rs. 1000 or less, the neutralisation shall be made at quarterly intervals while those persons drawing basic pay of Rs. 1000 and above the calculations would be half yearly.

20. Even keeping the cannons of construction as convassed by the unions in view, and even concentrating the whole attention on these two letters and another letter from the Government to which reference will be made shortly and not making any reference either to settlements or correspondence etc., it would be noticed that although on the first occasion the Government had laid down that despite the rise in index till 31-3-1975, there would be no variation in the relief, there was departure on the second occasion viz Ex. 13|WI whereby it was stated that increase in D.A. of Rs. 95 per month effective from 1-4-1975 for adjusting the increase in consumer price indices since the date of the last revision on 1-4-1974 shall be granted. There is also a provision for future adjustments in D.A. at the rate of Rs. 1.30 per point of rise|fall in the average consumer price index subject to certain conditions. Therefore, no other conclusion is possible than to hold that the Central Government was aware that in the past, the ad-hoc payment was granted without any linkage, departed therefrom and awarded a sum of Rs. 95 for the period during 1-4-1974 to 31-3-1975 and future adjustments i.e. from 1-4-75 the D.A. was ordered to be released. While construing this letter, it is urged that Rs. 95 is in irreduceable sum not linked with any consumer price index and, therefore, when the Management on fall of the consumer price index paid something less, it amounts to a short fall. It is further urged that whatever may be the conditions in the past, atleast under letter Ex. 13|WI, there was

no condition of P.F. Pay amounting to Rs. 2400 and, therefore, when this relief was denied to those who were drawing, no doubt P.F. Pay above Rs. 2400 but basic pay, D.A. and VDA not in excess thereof, here again there is a deprivation of the legitimate dues resulting in short payments. The caption of the letter indicates increase in emoluments of the employees of Air India and Indian Airlines. In the present reference, we are not concerned with Indian Airlines, and whatever may be the rights of the employees in that Corporation, they have nothing to do with the rights of the employees of Air India although it may be that the service conditions may be uniform. What was, therefore, the fate of an attempt to claim something more by an employee of Indian Airlines in a proceeding decided by Labour Court No. 1, Bombay, legally will have no relevance for the purpose of the present reference.

21. Concentrating on this letter, in the first place, it was attempted to suggest that the management should have taken into consideration the consumer price index for a particular month, deduct 100 as Simla series therefrom and then by multiplying by 1.30 should have arrived at the figure of the VDA. In the alternative, it was suggested that even if such course is not open still the future calculations and adjustment should have been not on the basis of index at 331 but at the index of 258 and naturally any calculations done on the basis of 331 will result in shortfall.

22. I am scrupulously avoiding to refer to various settlements|correspondence and what passed between the parties at about the relevant time since all along it is contended on behalf of the unions that extraneous matters are not relevant for the purpose. There is, however, a slight diversion amongst the two sets of unions one represented by Miss Jaising and the other by Shri Dudhia. When Miss Jaising wants me to ignore all other attendant and surrounding circumstances, Shri Dudhia conceded that some of them would be relevant for the purpose of construction. He argued that to a certain extent, the agreements and settlements can be read for determining what was conveyed by the Government. However, since there is an insistance atleast by some of the unions, those events shall have to be kept out of consideration and I shall concentrate on the letters and the terminology used therein and the intention of the Government as revealed therefrom and then shall look into the attendant circumstances and the settlements etc., for the purpose of getting an assurance regarding the correctness of the inferen e or the interpretation. The words in paragraph 1 indicate that what was granted was an increase in D.A. of Rs. 95 effective from 1-4-1975 and it is further stated that this was for adjusting the increase in consumer price indices from the date of last revision made on 1-4-1974. What was, therefore, granted earlier viz. Rs. 85 to Rs. 180 in the past teated as an ad-hoc payment was decided to be increased by Rs. 95 and this Rs. 95 was for adjusting the increase in consumer price indices during the period from 1-4-1974 to 14-4-1975. It was urged that the very reference as Rs. 95 per month made it an irreduceable sum otherwise there was no need to state so and it is further stated that in the payslips of various employees, mention was to the sum of Rs. 95 only. Now when an increase was to be made and necessarily for making an increase the time factor had to be mentioned, so merely because it was stated as Rs. 95 per month cannot make the sum irreduceable because what was granted was increase in D.A. for adjusting the increase in consumer price index and then there followed a clause whereby the adjustments were to be depended on use or fall. When the entire letter is read as a whole, therefore, the only conclusion possible is that first the Government decided to grant increase in the D.A. till the time of letter the period of contemplation was 1-4-1974 to 1-4-1975 they determined the quantum which is evident from the words "adjusting the increase in consumer price index since the date of last revision made on 1-4-1974" and for the purpose of future adjustment i.e. from 1-4-1975, the rate was laid down. They could have also done without making the calculations leaving them for the parties to calculate for the period between 1-4-1974 to 1-4-1975 but might be as a prudent course they thought that since the period related to the past, it is better to make the calculations state the figure and leave the further things for the parties to calculate.

23. The figure of Rs. 95 was not taken at random. If it is found that to the knowledge of the parties, the increase to be taken care of was 73 points, then applying the same rate as sanctioned for the future adjustments we arrive at the figure of Rs. 95, suitably rounded up. On record there is a letter dated 1-4-1975 at page 41, File No. 5, the letter which was called for from the Management wherein there is a discussion about these various figures. On page 3, para. 5.2 at the bottom it is stated :—

> "From the informal discussions with the Bureau of Public Enterprises, it is understood that the thinking of the Government on this issue is that public undertakings which are not already having a formula should adopt a uniform formula for this purpose and their suggestion would appear to be that we should follow the formula already adopted by several undertakings, under which the variable Dearness Allowance will be Rs. 1.30 for every point increase in consumer price index, the review and adjustment being made on a quarterly basis.' This then is followed by the statement—"If this formula is adopted (viz., formula means Rs. 1.30 per point rise) we have to base our existing level of Additional Dearness allowance granted from 1-4-1974 on the average of the three months, October, Novoember and December, 1973, and grant immediate increase on the average of October, November and December, 1974. The relevant figures are as follows :—

	1973	1974
October	254	335
November	259	331
December	200	326
Average	258	331

24. In paragraph 5.3 the opening sentence is "the immediate increase of Rs. 95 on an increase of 73 points which will be uniform at all levels of pay". It is, therefore, crystal clear that the figure was not quoted as it occured to the authority, but there was an application of mind and calculations and a readily available figure was quoted instead of leaving it to the parties to make calculations upto a particular day. It was to be an increase in D.A., a D.A. which atleast till 1-4-1975 was to remain static under the earlier letter and the future adjustments were taken care of.

25. It was tried to be urged that if it was to be linked with the earlier Dearness Allowance, there will remain a gap between 240 and 258 and the very fact that this gap remains uncovered shows that the characteristic of Rs. 95 was the same as in the case of earlier grant viz., ad-hoc relief while the future from 1-4-1975 may be called as VDA. It is already pointed out that though the Government, in the past, was firm that whatever may be the increase in the index till 1-4-1975 there would be no increase in the corresponding D.A. for one reason or the other, the position was relented and the increase was agreed to be paid. Therefore, it is not that Rs. 95 gets the character of ad-hoc relief in the past under letter at page 77 but on the contrary, the earlier payment assumes the characteristic of a variable figure. What was to remain constant in the past was agreed to be increased because of the rise in the indices and as such when these two letters are read together, no other conclusion is possible then to note that Rs. 95 is also a variable figure and not a constant one and so also the future payment or adjustments. It is just possible that because the index figure did not fall below 258, the earlier payment was not required to be varied but because Rs. 85 to Rs. 180 remained untouched does not mean that the Management would not have touched even Rs. 95. It was granted for adjusting the increase in the consumer price indices and was getting the same characteristic as that of future adjustment which depended upon rise or fall and therefore if shortly thereafter when the index figure went below 331, the payment was required to be pruned it does not mean that there is any short fall.

26. By letter dated 22-10-1975, Ext. 28|W1 page 219 the Government made the position further clear. Under this letter which was in continuation of the earlier letter dated 15-10-1975, in paragraph 2 it is stated that while calculating future adjustments in D.A. as mentioned in para. 1 of the earlier letter, the average consumer price index for the

months of October, November, and December, 1974. All India Index published by the Labour Bureau of Simla 1960=100 should be taken as 331. A reference is already made to the earlier letter which talks of 258 and 331 while in this letter dated 22-10-1975 also, we get a mention of the index as 331. It would not have been intention of the Government, therefore, as seen from the two letters, to keep D.A. static. It would not have been the intention of the Government to segregate Rs. 95 from the VDA payable from 1-4-1975 and confer different characteristic but on careful construction of the two letters, it must be held that the attempt to suggest that Rs. 95 was an irreducible sum must fail.

27. Same is the case with the attempt to suggest that Pay plus ADA plus VDA means the basic pay and not the P. F. Pay. We have already seen the rationale behind the thinking of the Government in the past viz., to achieve uniformity so far as the payments of increases were concerned. Now, if the Government wanted to state the pay as basic pay, in the first place, there would have been a mention thereto. We cannot believe that the Government was obvious the distinction between the basic pay and the pay including all allowances etc. It is also seen from para. 1 where they were referring to Rs. 1000. It was stated that for persons drawing basic pay of Rs. 1000, the D.A. adjustments would be made in a particular manner and secondly, we have already seen that there is one type of D.A. i.e. Khosla D.A. varying from Rs. 65 to Rs. 100 which was also paid to the employees. There was, therefore, pay, Khosla D.A., there was ad-hoc relief of Rs. 85 to Rs. 180, there is Rs. 95 and ultimately there is VDA from 1-4-1975. Now if the sentence Pay plus ADA plus VDA is read as it is laying down the ceiling of Rs. 2400 and if the pay is to be treated as basic pay, what is to happen to Khosla D.A. ?, was it to be excluded ? At least there could not have been any such intention as the record speaks. The caption of the letter speaks of emoluments and the emoluments as in the case of first letter must embrace all types of payments. Furthermore, if the intention was to restrict the limit to Pay plus ADA plus VDA as Rs. 2,400, there was no need to add the words 'the ceiling' and the sentence would have been very easily framed as Pay plus ADA plus VDA should not exceed Rs. 2400. The reference to 'the ceiling' is because the matter deals with the topic which was in continuation from the past and because it was granting an increase for the period from 1-4-1974 to 1-4-1975. Here again, the same construction viz. if pay is to be treated as basic pay, it would create an anomaly as already explained in the sense that some persons drawing wages of even Rs. 7000 would be saved of the ceiling while those drawing less than that would be the target of the ceiling. The Government must have considered all the circumstances and to achieve uniformity so that no injustice is done to anybody, the words 'the ceiling' must have been inserted.

28. It was tried to be urged that the periods of these two letters are different and that it is just possible that the Government policy might have been changed by that time and therefore though the authority issuing is one and the same, certain phrases he has refrained from referring. On record there is no evidence of the change in policy. Even in the case of Government servants the ceiling is Rs. 2400. In their case normally they do not earn anything else except the paltry local allowance etc. but here are the employees whose allowance exceeds even the basic pay. Normally when some relief was to be restricted to a particular category of workmen the total emoluments as the caption of the letter indicates must have been taken into consideration and hence the words pay plus D.A. plus VDA not exceeding the ceiling of Rs. 2400 per month are used.

29. These two letters, therefore, even if taken in isolation from other factors on record, in my view, do not support the case of the workmen. They speak of Rs. 95 to be variable allowance and also speak that only those persons are entitled to this relief who are drawing P.F. pay less than Rs. 2400. I am not coining the word P.F. Pay and though the P.F. Regulations etc., do not say so, the parties at one stage or the other used the same terminology which I chose to adopt. Yet the question remains whether I have arrived at a correct conclusion and for that purpose, I shall refer to the past events, the conduct of the parties and the various happenings.

30. The employees of Air India comprise of highly technical personnel like Pilots, Flight Despatchers, Engineers etc. It is, therefore, not possible to believe that such employees would be negligent of their own rights particularly when even if the amount of Rs. 95 may not be big, the payment of Rs. 180 which the categories drawing high salary will get, cannot be said to be a small sum and such employees would not have remained silent from the year 1975 to 1982 when for the first time they raised a voice of shortfall in payments. There were their unions to safeguard their interests. Not only that but the Air Corporation Rules in Chapter 9 speak of Labour Relations Committee who advises the Corporation in all the matters which relate to the welfare of the employees or which are likely to promote and secure good relations between the two. Atleast this Committee would have been approached for the redressal of the grievance if there be any. Some of the members are the representatives of the employees and processing of such grievance would not have been time consuming as the present one. That no such step was taken almost for about seven years speaks that there must not have been any force in the contention but subsequently somebody must have led himself to believe that there is a case of shortfall, then started looking here and there, for a word here or for a phrase there and taking the matter disjunctively and not fashion, the plea of injustice seems to have been built up. At Ex. 144|WD, page 62 of File No. 7, we have got before us the record note of the discussions held on 10-10-1975 between the representatives of ACEU and IATA and the management and the note speaks that the Managing Director in the meeting had informed the representatives of the unions the Government's approval to the Management's proposal regarding increase consisting of an increase in D.A. of Rs. 95 which was linked to the consumer price index. There is also a reference to the H.R.A. and the reaction of the representatives as seen from page 63 is significant in the sense that they were disappointed about the House Rent arrangements but only grievance against ADA of Rs. 95 was that ADA should be included for the purpose of P.F. calculations. The record shows that all along whatever was being paid was to be kept out of the PF calculations in the sense that it was not be considered for 8¼ per cent contribution to the P.F. That these representatives when there was an explanation, only suggested that this D.A. should be included for the purpose of P.F. calculations indicates their acceptance of the Management's proposal.

31. Regarding this issue, there were three settlements first with ACEU, then with IATA and lastly with AIAEA. These settlements are respectively on pages 79, 85 and 90 dated 13-10-1975, 9-1-1976 and 10-3-1976. In Ex. 10|W on page 79(80) we get a reference to the ADA and it is stated that the existing ADA will be increased by Rs. 95 and will be linked with the All India Consumer Price Index. Similar clause is to be had in the remaining two settlements. Now because the members of the ACEU might not be falling within the category of drawing more than Rs. 2400 as P.F. Pay, the settlement is silent but in the case of remaining two settlements, it is specially staed that ADA would be admissible subject to the condition that the existing emoluments counting for P.F. plus ADA will not exceed Rs. 2400 per month. This categorical statement to which the members of two unions were parties support the conclusion that what was meant by the ceiling was the celling of PF pay of Rs. 2400 and nothing else.

32. In the rejoinder at page 231 of Ex. 31|M, File No. 2 there is an assertion that on 27-4-1976 the payment of ADA and H.R.A. with which we are not concerned effective from 1-4-1975 was offered to AICCA which offer was accepted by their letter dated 18-3-1977. The letter of offer is on record at Ex. 70|M page 101 of File No. 4. The letter does not speak of ceiling, might be because the category of employees did not reach that level of pay. Similarly, on page 232, there is a reference to the offer to IFDU dated 17-6-1978, Ex. 75|M page 111 of File 4. This, however, informs the union of the fact of ceiling.

33. At about the time when the events were taking place, therefore, the Management as well as the unions were construing the Government's directive in the manner in which the construction is being put and this vindicates the correct-

ness of the finding for which purpose the help is now being taken. A similar letter was also addressed by the management to the IFDU, Ex. 11|W1, page 95 where also the fact that ADA will be increased by Rs. 95 and will be linked with the consumer price index and also the fact of the ceiling were being referred to. The Union was also told that if the Management would not hear from them within one week the acceptance will be presumed and suitable instructions would follow.

34. On 10-7-1979, a circular was issued Ex. 12|WI, page 98 File No. 1, whereby it was declared that VDA would by paid with effect from 1-12-1978 to the employees who were not in receipt thereof on account of the ceiling of Rs. 2400 fixed by the Government and, therefore, from the said date all the categories of employees who were not in receipt of this D.A. shall start getting it on the basis applicable to the employees drawing salary of Rs. 1000 and above. Similar declaration is also to be had at page 99 dated 8-9-1979, communicated to IFDU whereby they were told that VDA has been extended to all employees drawing PF Pay of more than Rs. 2400.

35. At Ex. 62|M, page 57, File No. 4, there is a settlement dated 27-10-1975 entered into with the IFDU whereby is clause 3, the employees/members of the union like Asstt. Flight Despatchers, Flight Despatchers and Senior Flight Despatchers became eligible for the purpose of ADA of Rs. 180 from 1-4-1974 subject to the emolument counting for Provident Fund not in excess of Rs. 2400. At page 103, Ex. 71|M of File 4, there is a draft of the agreement for payment of HRA and second D.A. submitted by IFDU to the Management which suggests an addition of a sentence in the draft prepared by the management to the effect that :—

> "Last sentence must be accompained by clarification to state that as and when the Government lifts/waives its reported restriction in this regard, the same Additional Dearness Allowance of Rs. 95 adjusted on sliding scale must be included in to Provident Fund."

The contentions of the unions all along is that Rs. 95 is an irreduceable sum. But the suggestion in the draft itself treats it to be on sliding scale.

36. At Ex. 72|M, page 108 the receipt of this draft has been acknowledged. At Ex. 75|M, page 111 of the same file the same condition viz. P.F. pay of Rs. 2400 is to be noticed while at Ex. 76|M, page 113-114, there is a charter of demands submitted by the IATA dated 7-4-1978 where the only demand in connection with VDA is that it should be at the rate of Rs. 2 per point and not at Rs. 1.30 and the charter of demands conspicuously is silent on other points which are now being convassed on their behalf.

37. There is another charter of demands submitted on behalf of ACEU dated 15-4-1978, Ex. 77|M File No. 4, regarding the D.A., the demand was that, in addition to the fixed D.A. which was referred to in clause 2.1 there shall be ADA linked with consumer price index number 258 at Rs. 95 and its escalation or de-escalation will be as per clause 2.3 which clause speaks of consumer price index rise per point at Rs. 2 instead of Rs. 1.30 as settled by the management. These were the occasions when the demands were being submitted. When whatever grievance existed in the minds of these employees should have surfaced and taken tangible shape of the charter of demands, and if knowing full well that Rs. 95 at consumer price index below 331 was being reduced and knowing full well that those employees who were drawing more than Rs. 2400 P.F pay were not being paid either ADA or VDA, if no voice was raised against the same, the inference naturally would be that the position as pleaded by the management was accepted till sometime in the year 1982 when the unions effected a change in stand for one reason or the other and started agitating.

38. We have already seen that before the letter Ex. 13|WI i.e before 1974, the ceiling categorically was on PF pay and it is, further pointed out that the terms used in the course of the same transaction being in continuation of the past, carries the same meaning. I will then refer to the Settlements at Ex. 10/WI dated 13-10-1975, 9-1-1976 and 10-3-1976 effected with ACEU, IATA and AIAEA, laying down the ceiling on PF Pay where the circumstances demanded it.

39. At the time when it was lifted as seen from the letter by the Management at page 99 of File No. 1, reference was to PF pay. Same is the case at Ex. 12|WI page 98, File No. 1. Even in the offer to the IFDU under Ex. 11|WI page 95, File 1, we get the reference to the same type of ceiling.

40. In my view, therefore, when the two letters of the Government are scrutinised independently of the extraneous evidence and when for the purpose of correctness of conclusion reached, circumstances and the conduct of the parties are considered, they lead to only irresistible conclusion that Rs. 95 was never to be irreduceable sum but was linked with the consumer price index and, further that the ceiling was not on basic pay but was on what is known as P.F. pay i.e. inclusive of allowances enumerated in the relevant regulations.

41. Besides contesting the reduction in Rs. 95 and imposition of ceiling of PF Pay, it is further contended that for the purpose of calculations sake the Management was not following the general directions issued by the Government in other words was not calculating the increase in consumer price index on the basis of average of the preceding quarter or six months as the case may be depending upon the pay package but was calculating the same on the basis of the last but one preceding quarter and it is urged that this has caused loss to the employees. The method of calculation in this fashion stands admitted which was followed and then given up as stated by Mr. Dudhia in the course of his argument from 1-4-1983. Although, we find a reference to the general notification in this regard and we have got a notification in connection with the General Insurance dated 27-5-1974 Ex. 112|WI talking of last preceding quarter, so far as Air India is concerned till 1983 it seems the practice in vogue was last but one preceding quarter. We have already seen that when the average of 258 and 331 was taken into consideration, the quarter was not immediately preceding but last but one preceding. Even in the year 1981, as seen from Ex. 17|WI at page 115, File No. 1, for effecting the increase or decrease on 1st January or 1st July, respectively, the average of half yearly was considered to be April to September and October to March. Had the practice of immediately preceding quarter been scrupulously followed or required to be followed, such departure could not have been noticed. It is therefore evident by consent of the parties, there was a departure regarding the method of calculation and till the time of agitation the unions were not averse to it. Moreover, that was more convenient in the sense that the figures of average in the immediately preceding quarter may not be available even in the first and second month of the quarter and it might have held up the calculations, to avoid which, the parties found a convenient way of relying upon the last but one preceding quarter. It is not that the unions are scrupulously following the Government's directives because at Ex. 15|WI at page 111, File 1, though the Government insisted and on this occasion the notice was issued by the B.P.E. in the shape of a general directive, that the payment of arrears should be deposited in P.F. and which was done in the case of Government servants, the employees were not prepared to do so. I am not drawing any inference from it but one fact is certain that as and when convenient, particularly by consent of both parties, there were certain departures to be noticed and, therefore, mere departures should not give rise to the grievance nor can it be a cause of action for recovery of some money.

42. In the course of the subsequent events, as already indicated, the ceiling was lifted and even those who were not drawing ADA or VDA on account of their salary being in excess of Rs. 2400 pay became entitled to the same. However, the grievance in this regard is that though they were eligible for ADA plus VDA, what was paid was VDA namely Rs. 180 for these categories. The Management, however, has brought on record various settlements first dated 2-2-1979 between Management and ACEU, second dated 10-6-1979 between Management and IATA then between the Management and IFNG dated 1-4-1982, another of even date with IPG and there are also settlements at

Sr. No. 6, 7, 8, 9 and 10 ranging from 8-4-1982 to 13-9-1982 with various unions, whereby the ADA which was payable was merged into the basic pay and the parties were agreeable to the same. If the rights of the parties are to be determined in the light of the agreements and settlements or commitments, as the unions want me to do, while deciding the claims, the very principle would be applicable to these settlements also and unless they are avoided by resorting to one method or the other, the settlements would be binding on the parties and atleast in the present Reference no relief against these settlements would be possible.

43. Strictly speaking since the claim is restricted to ADA and VDA, claimed for wage rise on account of increases would not be within the purview of the present reference. However since the claim for ADA and VDA has been rejected there cannot be any question of increase of 10 per cent or 15 per cent inclusive of the said sum as tried to be demanded and therefore this claim also fails.

44. In the light of above discussions, it is now convenient for me to answer various issues :—

ISSUES	FINDINGS
1. Is the reference as it stands vague and therefore bad?	When the reference was under Section 10(2) of the Industrial Disputes Act referred by common consent, something was tried to be added when the issue regarding vagueness was framed but I must note that nobody even argued this matter and, therefore, finding has to be noted in the negative. Furthermore, when by common consent the are of dispute was demarcated, nothing can be effected by vagueness.
2. What is the effect of the order passed by the Labour Court No. 1, Bombay in application under Section 33C(2) of the Act interpreting various settlements, on the rights of the parties ?	An order was passed while deciding the application under Section 33C(') preferred by an employee when he tried to claim VDA viz. X-100 x 1.30 on a given date in which attempt he failed. However, since Indian Airlines is an Independent Corporation, though established under the same Act and since the rights are independent of the rights of the employees of Air India, there cannot be any bar analogous to res-judicata nor the decision in the said application will have any relevancy for the purpose of the present controversy.
3. If the settlements, commitments and understandings effective from 1-4-1975 were understood and implemented in the manner in which the management asserts, what is the effect of the subsequent conduct of the parties on the settlements ?	Subsequent conduct is being only considered for determining the correctness of the interpretation of the Government circulars.
4. Whether the management of Air India has not paid to the employees ADA and VDA effective 1-4-1975 and thereafter in accordance with the terms of agreements or understandings or commitments made to the Associations or Unions or Guilds or employees, as the case may be ?	Has paid which is evident from the fact that the interpretations put forward by the management are found to be correct.
5. Whether the agreements or commitments or understandings referred to above in so far as they relate to ADA and VDA for the period effective 1-4-1975 and thereafter are not in conformity with the Government approvals and directives and circulars on the subject of ADA and VDA ; If yes, is there any short payments ?	The agreements/commitments/understandings are completely in accordance with the Government directives effective from 1-4-75 relating to ADA and VDA and, therefore, there is no question of any short payment.
6. Whether the workman covered by the ceiling of Rs. 2400 were not paid the ADA in the wage period with effect from 1-4-1978 and thereafter and if so what is its effect ?	The ADA was payable from 1-12-1978 to those who were covered by PF ceiling of Rs. 2400 but as already stated, by virtue of the settlements the same was merged into basic pay and, therefore, no relief is possible in the present Reference.
7. Whether the management of Air India was not entitled to link ADA of Rs. 95 per month to the Consumer Price Index ?	No repetition is necessary as Rs. 95 was rightly linked with the Consumer Price Index and as such the Management had not erred in this connection.
8. Whether the ADA of Rs. 95 per month is in an irreducible minimum payable to the workman and ought not to be linked to the Consumer Price Index ?	Rs. 95 is found to be linked with Consumer Price Index and, therefore not an irreducible minimum as tried to be agitated.
9. Whether as a result of the said action of the management of Air India of linking ADA of Rs. 95 per month to Consumer Price Index there has been a shortfall in the payment of ADA to the employees ?	In view of the finding on issue No. 8, there arises no question of any shortfall. The arguement that the payment should have been with Consumer Price Index on a particular day minus 100 of Simla Series multiplied by 1.30 has not found favour with me and on the contrary, I find that after

ISSUES	FINDINGS
	additlon of Rs. 95 which was also linked with CPI and further rises were to be linked and calculations were to be effected accordingly.
10. Whether the Air India Management was bound to link the payment of Rs. 1.30 per point rise/fall in the All India Consumer Price Index Number 100 (Simla series 1960) ?	No
11. If not what was the basis of fixation under the agreement ?	It has been correctly linked.
12. Whether the payments made by the Air India in this behalf have resulted in short payments ?	When we arrive at these conclusions, there is no chance of any short-payment.
13. Whether the management of Air India was bound to make payment of VDA on the variation of CPI of the quarter or six month period in accordance with the Notification of the Government of India in the Gazette dated 27th May, 1974 i.e. based on the immediately preceding quarter prior to the quarter in which the VDA was payable ?	Last preceding quarter was a mode prescribed but the parties might be for their convenience or for other sake departed therefrom by consent and, therefore, there is no relief flowing from the same. Furthermore, as already stated, this practice was abolished in the year 1983.
14. Whether the management of Air India was liable to pay ADA and VDA to those of its employees whose pay for the purpose of provident fund exceeded Rs. 2400 from 1st April, 1975 to 31st March, 1978 ?	When pay is construed as P.F. pay, the denial of VDA and ADA till the time of lifting of the ceiling cannot be said to be erroneous and during that period, nothing was payable to them.
15. Whether as a result there have been any short payment or non-payment of VDA and ADA to the employees concerned ?	There is, therefore, no question of any short payment.
16. What is the effect of the settlement entered into by concerned unions/Associations for wage revision for the period 1-4-1978 and thereafter thereby merging ADA in basic pay ?	The merger of ADA into the basic pay under the various settlments takes away the right of the concerned employees from claiming any relief on the basis of the same, in the parameters of the present reference.
17. Whether any finding regarding the alleged non-payment of ADA and VDA in the wage period 1-4-1978 and thereafter is relevant for determination of the present reference ?	Certainly in the light of the issues referred as they are framed, even period 1-4-1978 and thereafter is relevant till the ADA retained its character but that has not happened because of the merger and there is no dispute about the VDA.
18. If yes whether there are any short payments in ADA and VDA in the wage period 1-4-1978 and onwards ? If yes, to what relief if any these workmen are entitled ?	There is, therefore, no short payment under this category and the net result is that issue No. I of the Schedule of Reference has to be answered that the payments have been made in accordance with the terms of agreements, understandings and commitments and therefore, no relief is possible regarding issue No. II of the Terms of Reference also the answer will be that they are in conformity with the approval/directives and therefore, there is no question of any relief.
19. To what relief the workmen are entitled ?	

Award accordingly.

M.A. DESHPANDE, Presiding Officer
[No. L-11025(3)/84-D. II(B)]

का.आ. 5468. —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उत्तरीय रेलवे, लखनऊ, के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-11-85 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 5468.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Northern Railway, Lucknow and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th November, 1985.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, KANPUR

Reference No. L-41012/66/83-D.II (B) dated 17-7-84

Industrial Dispute No. 59 of 1984

In the matter of dispute between :

Shri S. N. Shukla C/o The Zonal President Uttar Railway Karamchari Union, Ganesh Ganj, Roshan Lal Bajaj Lane, Lucknow.

AND

Senior DSTE Northern Railway, Lucknow.

APPEARANCE :

Shri B. D. Tewari—for the workman.
None—for the Management.

AWARD

1. The Central Government Ministry of Labour vide its

Notification No. L-41012/66/83-D.II (B) dated 17-7-84 has referred the following dispute for adjudication :—

Whether the action of the Railway Administration in relation to Sr. DSTE Northern Railway, Lucknow, in superseding Shri S. N. Shukla High Skilled Diesel Motor Mechanic Gr. II by his Junior Shri Sriram from September, 1982 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?

2. The case of the workman is that he was recruited on 26-8-71 as DSL-cum-motor Mechanic Lucknow after trade test. He was senior to Shri Sriram Khalasi in the matter of appointment after trade test. He was held junior to said Sriram who superseded him and was later promoted as DSL-cum-motor mechanic high skilled grade II and in this way the workman suffered a loss of wages. The union has consequently prayed that the workman be held entitled to senior above said Sriram highly skilled Grade II DSL-cum-motor Mechanic.

3. In this case the workman objected to the appearance of advocate who applied for time to file written statement. Later Shri Ravi Jauhari Law assistant of the management appeared and on 5-1-85 was fixed for written statement. After 5-1-85, 15-2-85 was fixed for workman's affidavit evidence. On the next date i.e. 12-2-85 none appeared for the management and the workman filed affidavit evidence consequently the case was ordered to proceed exparte and 16-3-85 held for arguments. On 16-3-85 Shri Ravi Jauhari for the management appeared and applied to recall the exparte order and the same was allowed on cost of Rs. 50. On the next date i.e. 8-4-85 the management again applied time for filing written statement and it was ordered that the management should pay cost and file written statement on 1-5-85 failing which the right of defence shall stand struck. On 1-5-85 none appeared for the management consequently 14-5-85 was fixed for argument and orders. On 14-5-85 the workman filed three papers and he was required to file affidavit to prove the documents. On 15-5-85 the workman filed affidavit to prove the documents filed earlier on 14-5-85.

4. In the affidavit dated 14-5-85 the workman testified that the documents filed are photostat true copies of the original documents. The first document filed is trade test of Shri S. N. Shukla the concerned workman. A perusal of the same it appears that the workman was already trainy DSL cum-motor mechanic and he was tested for DSL Motor Mechanic and the result of the test that he secured 61 marks out of 100 marks on trade test held on 15-1-1979 and was declared passed. The said result sheet was produced before trade test panel on 19-2-79 which was to be put up in the service record of the candidates. The trade test of Shri Ram Khalasi was also taken on 15-1-79 his date of appointment there is shown as 21-1-71 i.e. he was junior to the workman whose date of appointment is 26-8-71. Said Shri Ram passed the trade test on 15-1-79 and secured 58 marks out of 100 marks and his result sheet was also submitted before the panel of trade test for being put up on his service book. Despite the fact that S. N. Shukla secured higher marks that of Sriram Khalasi and was senior in date of initial appointment, it appears that the workman was shown junior hence the applicant moved an application to the Divisional Personnel Officer, Northern Railawy, Lucknow for correction wrong done to the workman Shri S. N. Shukla. In his representation to the D.P.O. Northern Railway Lucknow, the workman averred that he had been working as diesel mechanic grade II in scale Rs. 330—480 (revised scale) in construction wing and worked there upto 3-4-78, thereafter he was transferred from the said wing to the Division w.e.f. 4-4-78, the applicant was absorbed by division in the said scale and was drawing his basic as 354 on 3-4-78 but the applicant vide order of the DPO in screening was reverted to the post of DSL Motor Mechanic in the scale of Rs. 260—400 w.e.f 4-4-78 and his pay was fixed accordingly. The workman averred in that representation that taking his trade test for the post of DSL Mechanic in scale 260—400 was wrong as he was working in higher grade i.e. 330—480 w.e.f. 4-4-78 after under going trade test. He has further averred that the trade test for the post of DSL Mechanic grade II scale 330—480 was held by administration but the applicant was not called for the said trade test. Only Sriram DSL Mechanic was called who was junior to the applicant. Said Sriram become DSL Mechanic on 30-4-79 whereas the workman is working as DSL Mechanic w.e.f. 4-4-78, despite all this and despite representation it is averred in the affidavit that Sriram was declared at serial No. 2 in panel as senior to the deponent who was placed at Serial No. 3 in the said panel.

5. There is nothing on record as to under what circumstances the workman who was officiating in scale 330—480 and was getting Rs. 354 as pay on 3-4-78 was reverted under orders of the DPO Northern Railway Lucknow, vide order dated 7-3-80. When the documents filed on the record show that the workman was senior to Sriram in matter of initial appointment and in the matter of securing higher marks than Sriram and in the matter of working as DSL Motor mechanic from earlier date than Sriram.

6. The documents on record apparently shows that the workman should have been shown senior to Sriram. In the absence of any cogent reason for revertion and showing the working junior to Sriram who was senior to him in all other respects the management was not justified in superseding him without any rhym or reason, the result is that the action of the railway administration in superseding Shri S. N. Shukla high skilled Diesel motor mechanic Gr. II by his junior Shri Sriram from September, 1982 is not justified.

7. The result is that the workman is entitled if not higher but equal pay that of Shri Ram from September 82 and shown above said Sriram in the seniority list.

8. I, therefore, give my award accordingly.

Dated : 31-10-1985.

R. B.SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-41012(66)/83-D.II (B)]

का.आ. 5469.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार राउरकेला स्टील प्लांट, स्टील अथोरटी ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, भुवनेश्वर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-11-85 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 5469.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Bhubaneswar, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Rourkela Steel Plant of Steel Authority of India Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th November, 1985.

INDUSTRIAL TRIBUNAL, ORISSA, BHUBANESWAR

PRESENT :

Shri K. C. Rath, B.L., Presiding Officer, Industrial Tribunal, Orissa, Bhubaneswar.

Industrial Dispute case No. 12 of 1982 (Central)
Dated, Camp : Balangir, the 25th October, 1985

BETWEEN

The employers in relation to the Management of Rourkela Steel Plant of Steel Authority of India Ltd.—

First-party

AND

Their workmen—Second-party

APPEARANCES :

Shri G. C. Misra, Dy. Manager (Law), Rourkela Steel Plant, Rourkela—For the first-party.

Shri J. Nag, Vice-President, Rourkela Mazdoor Sabha, Rourkela—for the second-party.

AWARD

Dispute referred to by the Central Government under Section 7-A, and Clause (d) of Sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, vide Notification No. L-29012/12/81-D.III (B) dated 19-8-1982 of the Ministry of Labour, reads thus :

"Whether the action of the management of Rourkela Steel Plant of Steel Authority of India, Limited,

in not giving the benefit of services, linked personal grade schemes to Shri Alekh Prasad Ray, Librarian-cum-Stores Assistant, Barsua Iron Mines is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

2. Both the parties filed a Memorandum of Settlement along with a petition praying to pass an Award in terms of the settlement. They admitted the terms of the settlement before me and stated that they had entered into the settlement amicably without any duress or coercion in the interests of industrial peace and harmony. The settlement appears to be fair. Hence I pass this Award in terms of the settlement, and the Memorandum of Settlement do form part of the Award.

Dated : 20-10-1985.

K. C. RATH, Presiding Officer

[No. I-29012/12/81-D.III (B)]

MEMORANDUM OF SETTLEMENT DATED 21 SEPTEMBER, 85 BETWEEN THE MANAGEMENT OF STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD., ROURKELA STEEL PLANT, ROURKELA AND ROURKELA MAZDOOR SABHA REPRESENTING SRI A. P. RAY, LIBRARIAN-CUM-STORES ASSISTANT, PL. NO. 34152, BARSUA IRON MINES

Representing Management :

1. Sri R. C. Mohanty,
   Dy General Manager (M&Q)
2. Sri S. Acharya,
   Dy. Chief Personnel Manager (IR&M)
3. Sri G. C. Mishra,
   Dy. Manager (Law.)

Representing Union :

1. Sri Jagadish Nag,
   Vice-President, RMS.
2. Sri P. K. Patnaik,
   Executive Member, RMS, BIM,

Short Recital of the case

Sri A. P. Ray was appointed as Librarian-cum-Stores Assistant on 21-7-66 in the grade of Rs. 117—300 (A-1). Subsequently, his post was upgraded to Rs. 340—589 with effect from 7-5-1973 and Sri Ray was placed in the scale. Management fixed the basic pay of Sri A. P. Ray with effect from 17-5-1973. Later, the basic pay of Sri A. P. Ray was altered. Rourkela Mazdoor Sabha raised a dispute demanding fixation of his basic pay appropriately in the higher grade and to provide a suitable channel of promotion to Sri Ray. The matter was thereafter referred for adjudication before the Industrial Tribunal, Orissa, on the following schedule and was registered as I. D. Case No. 12/82(C) :

"Whether the action of the Management of Rourkela Steel Plant of Steel Authority of India Limited, in not giving the benefit of service linked personal grade scheme to Sri Alekh Prasad Ray, Librarian-cum-Stores Assistant, Barsua Iron Mines, is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

During the pendency of the dispute, Rourkela Mazdoor Sabha discussed the issues involved in the case of Sri A. P. Ray and after prolonged negotiations, the matter has been settled amicably between the Management and the Union on the following terms :

Terms of Settlement

It is agreed that :

1. Sri A. P. Ray will be given benefit under Service Linked Personal Grade with effect from 17-5-1983 and his pay will be appropriately fixed in the aforesaid grade and the payment will be made within 3 months.
2. Sri Ray will be designated as Librarian-cum-Sr. Stores Assistant in N-8 scale with the designation and scale personal to him.
3. This settlement fully and finally settles the issues concerned in the I. D. Case No. 12/82(C).
4. The union and Sri A. P. Ray agree not to raise any dispute concerning the aforesaid terms of settlement. It is further agreed that both the parties will jointly approach the Hon'ble Industrial Tribunal, Orissa, by a joint petition to pass an Award in terms of this settlement.

SIGNATURE OF THE PARTIES

(R. C. Mohanty)
(S. Acharya)
(G. C. Mishra)
(Jagadish Nag)
(P. K. Patnaik)

का आ. 5470—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स मैगनेजाइट एंड मिनरल्स लिमिटेड के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-11-85 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 5470.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Magnesite and Minerals Limited, P.O. Chandok Pithoragarh (U.P.) and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th November, 1985.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 207/84

Reference No. L-27015(2)/83-D.III(B) dt. 28th August, 1984

In the mater of dispute

BETWEEN

Shri H. S. Karki Jauhari Bazar Baman Khoka Almorah (U.P.).

AND

The General Manager Magnesite and Mineral P.O. Chandok, District, Pithoragarh.

APPEARANCE :

Shri P. N. Rai representative—for the management.

Shri Girish Chandra Bhartiya—for the workman.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification no. L-27015(2)/83-D.III(B) dated 28th August, 1984 has referred the following dispute for adjudication;

Whether the action of the management of M/s. Magnesite Minerals Limited P.O. Chandok, Pithoragarh (U.P.) in terminating the services of Shri H. S. Karki, Foreman (Maintenance) with effect from 30-11-79 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled?

2. It is common ground that the workman Shri Hari Singh Karki was appointed in management concerned as Foreman Maintenance on 30-4-79 which a condition to provide him two free rooms accommodation and that his services would be terminated on three months notice or salary in lieu of either side. It may be mentioned that in the appointment letter which is paper no. I of the Annexure to written statement, there is no mention that the workman Shri Karki is appointed foreman would be on probation for any period. The workman was terminated by two telegrams w.e.f. 30th

November, 1979 mentioning that you would be paid three months salary in lieu of notice. In the telegram the designation of the workman was mentioned as Mechanical Foreman but in the other it mentions only mechanical.

3. The case of the workman Shri Karki is that his services were terminated on account of his trade union activities. The management's case is that termination order was a termination simplicitor with no strays or stigma attached and in terms of appointment order the services were terminated with three months notice pay. It is emphatically denied that his services were terminated on account of any trade union activities of the workman. The management however, raised two preliminary objection; firstly that the workman Shri Karki did not come within the definition of the workman as given under section 2(s) of the I.D. Act as his duties were supervisory and was drawing pay exceeding Rs. 1600 per month and that the workman should be stopped prosecuting the reference on assumption that he was indulging in trade union activities and was victimised for that.

4. From the appointment letter and the termination telegram it is found/evident that the workman worked with the management only for about 7 months. Comming to the point of preliminary objection that Shri Karki is not a workman reference is made to sub-clause (iv) of Clause (s) of section 2 of the I.D. Act wherein workman has been defined and word over clause (iv) takes out definition of that category from the definition of workman. It reads as folows :

Who being employed in a supervisory capacity towards wages exceeding Rs. 1600 per mensum... ..

5. The management has referred me ruling Burmah Shell Oil Storage and Distributing Company of India Limited Versus Staff Association AIR 1971 SC page 922 in which criterian is laid down to adjudge who is workman. In that case foreman shell oil storage was held not be workman being employed in supervisory capacity and drawing salary in excess of Rs. 500 per mensum.

6. The management has further referred me ruling 1982 Lab. I.C. page 1081 Madras High Court. In that ruling also persons working as foreman, whose nature was main work is to be found supervisory and his salary exceeded Rs. 500 even then excluding a person from the definition of workman." Even if a foreman is found to have possess supervisory capacity he still be a workman if his pay does not exceed Rs. 1600. In the instant case the pay and emoluments of the workman did not exceed Rs. 1600 on the date of reference.

7. In this context reference be made to the appointment letter which does not show that while appointing him as foreman maintenance he was to perform any of the supervisory duty. The word supervisor connotes supervision over work of others placed directly or indirectly under him. On the point that the workman was performing supervisory duty reference has been made to paper no. 4 dated 6-7-79 filed by the management which is addressed to one Shri G. C. Khatri fitter by Mines Manager of the Management insisting him to report to the workman foreman maintenance and work as per his direction and instruction. Working as per direction and instruction does not mean having of supervision over the work of fitter Shri G. C. Khatri but as the words used therein show he was to work as per orders and instruction of Shri Karki This simply means either assisting Shri Karki workman in his work or providing him with hands, to participate in furtherence of work desired by Shri Karki. I do agree with the arguments of counsel for the management that the work as per direction and instruction connotes that Shri Karki supervise fitter Shri Khatri. The management has filed a list of workman allegedly working under the supervision of Shri Karki the workman. It is paper no. 6 of the document filed by the workman The workman in his deposition has deposed that none of the six papers mentioned in paper no. 6 of the document filed by the management does not bear the signatures of any one and further that there is no order in writing that those six persons named therein will work under Karki Thus in the absence of any specific order in writing there is nothing on record to show that six persons mentioned in management paper no. 6 or even Shri G. C. Khatri fitter who was directed to work under the instruction and direction of Shri Karki were under his direct control and the workman was required to supervise their work. Thus there is no evidence that Shri Karki was performing supervisory duty

8. The question of his emoluments whether above Rs. 1600 or below pales into significance as the workman has not found to be performing supervisory duty. In this connection it may be mentioned that reference was made on 28-8-84 and the law as stood on that day has to be seen and not when the notice of demand or dispute before A.L.C. (Central) was arise. Admittedly the salary of the workman was Rs. 950 per month and he was paid house rent at the rate of Rs. 300 which would be deemed to be par on his emoluments as it was one of the condition of employment that he would be provided with two roomed accommodation. Thus in the alternative when he was given Rs. 300 as house allowance in place of free accommodation this will be par of emoluments which will come to Rs. 1250. Thus even on that count also it can not be said that the workman drawing wages exceeding Rs. 1600. All the amended definition of the workman giving this maximum limit of wages had come into effect seven days earlier to the reference order i.e. 28-8-84.

9. Now coming to the point of estoppel it may be mentioned that industrial dispute act being a special legislation, the technical plea of estoppel is out of place in an industrial dispute as observed in Soman Tea State case reported in A.I.R. 1967 page 420 Supreme Court. In the instant case it can be seen from the circumstances as decifered from the documents whether the termination of the workman brought about for his trade union activities as alleged or as termination telegram shows that it is a case of termination simplicitor. Even payment of retrenchment compensation after retrenchment, the employees are not stopped from questioning validity of the retrenchment as held in Somu Kumar Vs. District Signal Telecommunication 1970 I. and S page 629. Similarly existence of terminal benefits such as provident fund and gratuity can not be considered as acquisence on the part of discharge workman as held in management of Mysore Electrical Engineering Versus Kadiah 1979 Lab. IC No. 31 Karnatak. Thus even if the workman took all his duties as mentioned in paper no. 11 of the document paper filed by the management from paper No. 12 and paper No. 13 (final receipt) will not stopped the workman from raising industrial dispute that his termination was on account of his trade union activities.

10. Now coming to the point if the termination was termination simplicitor or on account of trade union activity. The management has drawn my attention to the termination telegram. No reason for termination has been given in telegram order which is paper no. 9 filed by the management. In this telegram order even this is not written that your services are being terminated as no more required. It may be mentioned that in his designation he was mentioned as Mechanical foreman where as appointment orders shows that he was appointed as foreman maintenance. The normal meaning of foreman is technical man incharge. In the appointment order it is mentioned that he was appointed as foreman maintenance. The work maintenance is also quite significant meaning thereby that he was technical man incharge which was served for maintenance of articles and Machinery used by the management. Whereas foreman mechanical indicates that he was a technician incharge of section which was actually involved in operational work in which Mechanic etc. are used. The workman in his statement as well as in his deposition has stated that he had nothing to do with the operation side and was simply incharge of maintenance when ever there was any break down. It has been argued by the counsel for the workman that the word Mechanic before the word foreman used in his telegram is deliberate as in mechanical section a foreman is supposed to take work from a good number of workman working in mechanical section. Be it as it may the fact appears that he was appointed as foreman maintenance and foreman mechanical. It is further significant that before his termination in some of the letters addressed to him by the management his designation was shown as foreman mechanical as in letter dated 17-11-79 which is paper No. 6 of the management and the again in letter dated 24th August, 1979 in which he was designated as mechanical foreman The management has not tried to draw any inference of it but the workman counsel has suggested that this changed designation with intent to bring him in the category of a supervisory officer by showing that the good number of mechanic i.e. drillers, fitters and compressor operators were working under him. This point has rendered a new story when the mangement witness Shri Vivekanand Dwivedi

has admitted in his cross examination that mining operation is separate from maintenance and in mechanical section operation work is separate in which mechanical operation is involved. He has further explained that supervisor informs the driller where to drill. The supervisor is known as mining mate or mining foreman. The compressor operator operates the compression machine and operates the drills and all this known as operational work. Thus when maintenance is of separate department as admitted by this witness from operation there is no question of this six pesrons mentioned paper no. 6 of the management as working under the workman as driller. Thus merely calling workman as foreman mechanical will not change his designation from foreman maintenance to foreman mechanical. Paper no. 3 filed by the management does not bear the signatures of workman Shri Karki. This unsigned document could be a deliberate document prepared by the management as it is dated 9-10-79 of a period within two months of his termination and in this his designation is written as Mechanical Foreman and not Foreman Maintenance. As observed earlier till July 1979, the management described hm as foreman maintenance as is evidence from paper no. 4 filed by the management. The workman has always described himself as Foreman/M i.e. Foreman Maintenance and never used the word Foreman Mechanical as is evident from the document paper no. 5.

11. The workman in his claim statement has averred that he started taking part in trade union activities which was not liked by the management who started harassing the workman on one pretext or other and changed his designation from Foreman Maintenance to Foreman Mechanical and the Commercial Manager in his letter dated 3-11-79 informed the workman that his work and performance was found not satisfactory hence your probation period was extended for a further period of six months. That letter is paper No. 8 filed by the workman. The services of the workman were admittedly terminated on 30-11-79 by giving three months pay in lieu of notice, hence there was no question of extending his probation for further six months. Further as observed earlier there was no stipulation in the appointment letter that the workman will be on probation which may be extended for any further time. The workman counsel has argued that this letter shows that the management were contemplating to terminate the workman on any of the ground may it be not extension of further probation and showing that he was a foreman mechanic on which post he was supervising the work of Mechanics under him. The counsel for the management however did not press this letter and admitted that some papers to have been issued under some mis-information.

12. There is yet another letter of the management dated 17-11-79 paper no. 9 filed by the workman asking the workman to vacate the residential accommodation before 20th November, 1979 as the building was required to be handed over to the owner. This letter was received by the workman on 19-11-79 and only 24 hours time was given to vacate the premises which also shows that the management was not favourably inclined to him or was not inclined to give any reasonable time to search out a reasonable accommodation.

13. It has been argued by the counsel for the management that the burden of establishing the plea of the victimization is on the person pleading it. In support of his contention the management has referred me the ruling Management of Bharat Kala Kendra Versus Shri R. K. Baveja 1981 Lab. i.e. page 893 wherein it was observed :

> The mere fact that there is an employees union and that the concerned employee is a member of an active office bearer is not sufficient to establish the plea of victimization. More allegation, vague suggestion and insinuations are not enough to establish the plea of victimization.....again it would be difficult to infer victimization when there is no evidence on record to show that there was any strain relationship between the employee and the employer because of the former union activity.

14. The main stay of the workman is that his services were terminated on account of his trade union activities. In support of his contention he has filed paper no. 16 by Deputy Labour Commissioner Haldwani showing that in the letter dated 15-10-79 received by the workman/workers union of the management concerned intimating therein that the trade union has been registered trade union and the workman's designation therein shown as Upsabhapati and that the said union is registered with the Registrar of Trade Union on 15-10-79. This it is significant in view of the fact that the services of the workman were terminated on 30-11-79 by giving him three months notice pay in lieu of notice. The workman has filed letter dated 24th August, 1979 written by works manager showing him to proceed Lucknow and meet Mr. G. K. Panda, General Manager for certain discussion. In consequence thereof the workman did visit Lucknow on 26th August, 1979 leaving for Lucknow on 25th August, 1979. The workman did visit Lucknow on 26th August, 1979 and admittedly did not join duty till 30th August, 1979. The workman was given a charge sheet dated 31-8-79 paper no. 6 filed by the workman in which it was mentioned that after discussion on 26th August, 1979 the workman was advised to go to Delhi for some official work but he was seen in Labour Commissioner's Office, Kanpur was hale and heartly having no sickness. He was required to explain within three days why action for misconduct, insubordination and misuse of time on false pretext. The workman replied the charge sheet on that very day by letter dated 31st August, 1979 which is paper no. 7 in which he informed that on 26th August, 1979 he had talked with the General Manager regarding workers union. He could not attend duty next day regarding which he sent information of his illness by telephone. The workman admitted that on 30th August, 1979 he was present in the Labour Commissioner's Office at Kanpur as alleged in connection with Labour Union and management coordination was that the workman go on peacefully. In this connection it may be mentioned that there is no written order filed on behalf of the management that any order was given to the workman to proceed to Delhi to attend some official work which the workman failed to preform. Further the very fact that in the charge sheet it is mentioned that you are found hale and hearty having no sickness indicated that he had absented from duty on account of some information about his sickness which the management had noted. This lend support to the workman's contention that he had informed about his illness by telephone. In reply to the letter dated 17-11-79 paper no. 9 of the workman, the workman replied that letter on 19-11-79 showing his inability and complaining that he was being unnecessarily harassed by the management by asking him to vacate the house within two days. He further expressed his feelings that he was not able vardoff his impression and he was being harassed on account of being active trade union worker. Four days letter the union wrote to the management on 24-11-79 that the workman who is a trade union worker should not be haarsed for his trade union activities and the management should stop the same failing which the union will take recourse to hunger strike. It was after this threat from the union that the management terminated the services of the workman by telegram w.e.f. 30h November, 1979. The workman before raising industrial dispute sent a notice of demand dated 10-12-79 paper no. 14 that the workman demanding the management to withdraw the termination order within seven days failing which he will take legal action. Thus on the point of victimization the workman representative has drawn inference in cronological order paper no. 6 i.e. laying charges of misconduct insubordination and misuse of time, its reply of even date paper no. 7 paper no. 16 showing that the workers' union was registered on 15-10-79, paper no. 8 dated 3-11-79 that his probation period was extended when admittedly the workman was appointed on probation, paper no. 9 dated 17-11-79 alleging no breathing time to the workman to vacate the premises occupied by him within 24 hours i.e. before 20-11-79, that the workman received that letter on 19-11-79. The letter of the workman dated 19-11-79 showing that he was being harassed for his trade union activities and ultimately the letter of the union dated 24-11-79 paper no. 11 giving the management a threat of hunger strike and ultimately termination of the workman by two telegrams paper no. 12 and 13 of even days i.e. 30-11-79 all filed by the workman lead to one and only one inference that the workman was harassed on account of his trade union activities as he was Vice President of the Trade Union and has despite asking by G. M. Shri K. K. Pande on 26th August, 1979, did not give up his trade union activities. Thus the circumstances referred in chronological order lead to one and only

one inference that the workman was harassed and ultimately was terminated for his trade union activities. Obviously management will not give out details of circumstances what annoyed them but from the action taken by them against the workman who is shown to be the Vice President of the union, it can be safely inferred that the management was not favourably disposed towards him, harassed him for one cause or the other and ultimately terminated the services of the workman. Even though in the termination order no reason has been given and apparently it appears to be the simpliciter terminated yet the circumstances referred above shows that it was not simpliciter termination but was by way of victimization which is unfair labour practice, and is illegal and amounts to be set aside. In Bihar State Road Transport Corporation Versus State of Bihar A.I.R. 1979 S.C. page 1217 wherein it was held:

> Even though the order of termination may be couched in terms or order of termination simpliciter, the labour court to which the industrial dispute is referred for adjudication is entitle to go beyond apparent language of the order in question and consider whether order is termination simpliciter or is proposed by way of punishment.

In Indian Tourism Development Corporation Vs. Presiding Officer, F.L.R. 1981 Vol. II page 372 wherein it was held:

> The Industrial Tribunal or the court is competent to interfere whether the impugned discharge has been made in exercise of the power under the contract of employment or was in fact the result of misconduct alleged against the employee and the discharge was punitive. In such a case form of order could not be conclusive and the tribunal will have the jurisdiction to go beyond the order and then consider whether the termination was a colourable exercise or power resulting in victimization of unfair labour practice.

The naxous that the management was sour with the workman and wanted to get rid of him is to be found in letter dated 3-11-79 paper no. 8 whereby his probation period was extended by six months though wrongly and in which also mentioned that his work was not found satisfactory. The workman should have been properly watched if there was any misconduct he should have been given punishment and not discharged him by way of a simple order of discharge. In Kanpur Jute Udyog Vs. L.C. Lucknow, 1984 L&S No. 46 Allahabad wherein it was observed thus:

> The form of order is not conclusive and a court particularly labour court is entitle to hear the wail and see its pith and substance.

15. In view of the circumstances discussed above, and further believing the workman and the documents relied, I hold that the action of the management M/s. Magnisite Minerals Limited P.O. Chandok, Pithoragarh (UP) in terminating the services of Shri H. S. Karki Foreman (Maintenance) w.e.f. 30-11-79, being malafide and colourabale exercise of powers is not justified. The result is that the workman is entitled to be reinstated with full back wages.

16. I, therefore, give my award aaccordingly.

Let six copies of this award be sent to the Government for its publication.

Dated : 30-10-85

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-27015(2)/83-D.III(B)]

का.आ. 5471.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डिवीजनल रेलवे मैनेजर, उत्तरीय रेलवे हजरत गंज, लखनऊ के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-11-85 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 5471.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Divisional Railway Manager, Northern Railway Hazrat Ganj, Lucknow and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th November, 1985.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL KANPUR

Reference No. L-41011|29|83-D.II (B) dated 9-12-83.

Industrial Dispute No. 247|83

In the matter of dispute between :

S/Shri Abad Ali, Ram Lakhan, Jagprasad, Kanhaiyalal, Faikoo Ali and Ram Jiyavan Gangmen C/o Shri B. D. Tewari Zonal working President, URKU, Ganeshganj, Roshan Lal Bajaj Lane, Lucknow

AND

The Divisional Railway Manager Northern Railway Hazrat Ganj, Lucknow.

APPEARANCE

Shri B. D. Tewari—for workman.

Shri Ravi Jauhari—for management

AWARD

1. The Central Govt. Ministry of Labour vide its notification No. L-41011/29/83-D.II(B) dated 9-12-83 has referred the following dispute for adjudication;

> Whether the action of the management of northern railway in relation to Divisional Railway Manager Lucknow in not absorbing and terminating the services of S|Shri 1. Abad Ali, 2. Ram Lakhan, 3. Jag Prasad, 4. Kanhaiyalal, 5. Faikoo Ali and 6. Ram Jivan Gangmen from 14-6-81 is justified ? if not, to what relief are the workmen concerned entitled ?

2. The case of all the workmen mentioned in the reference is that they had worked under Permanent Way Inspector Nihalgarh Assistant Engineer, Sultanpur and through them under the Divisional Railway Manager Lucknow and General Manager Northern Railway Baroda House New Delhi. All the workmen had worked from 1972 onward from time to time and from 1973 onward upto 16-8-81 continuously as temporary gangmen under the management. The services of the workmen were terminated by the management on 16-8-81 without notice and without payment of retrenchment compensation, although the work in that section continued. The management has assigned no reason while terminating the services of the workmen and neither any letter was given to the workmen nor appropriate government was informed. It is further alleged that the concerned workmen completed 240 days each in the year preceding but the management has not produced any record to this effect before conciliation proceedings. It is further alleged that the officers of the management has admitted the number of days worked by the workmen. In the end it is averred by the workmen that the action of the management in terminating their services is ilegal ultravires and non existent and that the workmen's services have not ceased to exist, hence all the workmen are entitled to reinstatement with full back wages, and all consequential benefits including regularisation and seniority assignment.

3. It is important to note that several dates were given to the management to file written statement but the management failed and ultimately on 8-4-85 exparte arguments were heard on behalf of the workmen.

4. Shri Abad Ali one of the concerned workmen has filed his affidavit wherein the deponent has deposed that he worked under P.W.I Nihalgarh, and other senior officers of the

management. He has further deposed that the deponent worked from 1972 onwards from time to time and from 1973 onward upto 16-8-81 continuously as temporary gangman under railway authorities. The deponent has further deposed that the services were retrenched by the management without notice or notice pay on and from 16-8-81 and without payment of retrenchment compensation. It is further stated by the deponent that he had worked for 303 days in a calendar year. It is further deposed by the deponent that the management has also admitted the number of working days done by the workmen concerned.

4. From the deposition of Shri Abad Ali it appears that all the workmen had completed more than 240 days in one calender year and thus they had acquired temporary status. Moreover, their services should not have been terminated without following the provisions laid down under the law. If a workman completes 120 days of work continuously he is entitled to scale rate of pay as is provided under different circulars of the management, as such in the instant case all the workman had completed more than 240 days of work in one span they had acquired status of temporary workman.

5. Management has not appeared in the instant case to substantiate its case. The representative for workmen has substantiated the claim statement by filing affidavit of one of the concerned workman i.e. Shri Abad Ali.

6. I am supported with my view with the ruling given in the case of Mohan Lal Vs Bharat Electronics 1981(2) S.C.R. 11, D.C.M. Versus S. M. Mukherjee 1978 (i) S.C.R. 591 and Robert De'Souza Vs Southern Railway Administration AIR 1982 SC 854.

7. Thus in view of the discussions and law discussed above I hold that the action of the management of northern railway in relation to Divisional Railway Manager, Lucknow in not absorbing and terminating the services of S/Shri Abad Ali Ram Lakhan, Jag Prasad, Kanhaiyalal, Faikoo Ali and Ram Jiawan Gangmen from 14-8-81 is not justified.

8. The result is that the workmen are entitled to be reinstated, with full back wages, in service.

9. I, therefore, give my award accordingly.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-41011|29|83-D. II (B)]

का आ 5472 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डिवीजनल रेलवे मैनेजर, उत्तरीय रेलवे, लखनऊ के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजक और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-11-85 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 5472.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Divisional Railway Manager, Northern Railway, Lucknow and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th November, 1985.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, KANPUR

Reference N. L-41012(61)|83-D.II(B) dt. 25th August, 1984

Industrial Dispute No. 206 of 1984

In the matter of dispute between

Shri Sheo Pal, C/o Zonal President, U.R.K.U. 96|166 Roshan Lal Bajaj Lane, Ganesh Ganj, Lucknow.

AND

The Divisional Railway Manager, Northern Railway, Lucknow.

APPEARANCE

Shri B. D. Tewari—representative for the workman.

Shri Hamid Qureshi—for the management.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-41012(61)|83-D-II(B) dt. 25th August 1984, has referred the following dispute for adjudication;

> Whether the action of the Divisional Railway Manager, Northern Railway, Lucknow in effecting reduction in rank from Driver C to shunter in respect of Shri Sheo Pal, Driver Loco Shed Lucknow vide order No. TPC|377 up 2|3|82 dt. 18-10-82 is justified ? If not to what relief the concerned workman is entitled

The case of the workman is that he was punished by the management with one year's reduction in rank from driver Grade 'C' to shunter Grade C from pay Rs. 360|- per month as driver to Rs. 350 as shunter. This was done after an enquiry in which no reasonable facility or self defence was provided to the workman. The charge against the workman was that while acting as driver of 377 up from Allahabad to Lucknow you demanded coal at Raibareli when there was enough coal at Rai Bareli in the engine and as a result of that there was loss of time to the tune of 2 hours 32 minutes at Rai Bareli. The defence of the workman is that the coal supplied to him at Allahabad was not a good quality coal and included coal dust as a result of which it was taking time in producing steam. In this connection the workman intimated to the power controller firstly through station master Atrampur that the coal supplied to the engine was extremely bad and was causing loss of time. No one came to inspect the coal on way from Atrampur to Rai Bareli. The workman gave second message throgh station master Dariyapur to the power controller and shed assistant Rai-Bareli for supply of coal at Rai Bareli. The workman deposited coal sample on 3-3-82 which was examined four months after its delivery yet its report that the coal contain 54 per cent coal dust. At Rai Bareli Shri Girdhari Lal Assistant Station Master ordered detachment of train engine of 377 up for proceeding to loco shed and there fresh coal was received. The workman was also relieved at Rai Bareli by driver Ram Nath who brought the train from Rai Bareli to Lucknow. The enuiry was entrusted to Senior Fuel Inspector. The statement of defence is namely of Shri Ram Nath Driver Lucnow and Lallan Porter at Dariyapur whom the message was given. Girdhari Lall, Asstt. Station Master, Rai Bareli and A.S.M. Atrampur were not examined by the enquiry officer on the threat of suspension would continue if the enquiry prolongs. The workman had submitted statement of Ram Nath Driver and Lallan Porter whom they not summoned and their statement was also not considered. Ultimately no speaking order was recorded by the punishing authority and the appellate authority and thus the reasoning on the basis of which conclusion was arrive was not disclosed to the workman. The workman has further averred that one Junior Fuel Inspector Shri S. K. Nigam examined on behalf of the management in the enquiry who was on leave during the period and who had not investigated in the preliminary enquiry. Further the power controller and shed Assistant Rai

Bareli and the Driver Shed Ram Nath were not examined thus the enquiry is based on presumption conjuncture and surmises and not on facts deposed by persons having personal knowledge and hence the enquiry was null and void. It is further averred that the sample given by driver should have been examined soon after and not after three months enabling interested persons to temper with its evidence. Further the management should have collected representative sample right at Rai Bareli or soon after at Lucknow and got it examined by Chemist cum Metallurgist which was not done at all. Further the workman had requested only for better coal at Rai Bareli which could have been supplied to him without delay and if driver was to be changed Ram Nath should have assured the charge then and there to take the train up to Lucknow on same coal at Rai Bareli, thus the enquiry and punishment order by appellate authority being non speaking order deserves to be set aside.

3. The management in its reply has averred that the workman has been lawfully punished with one years deduction in rank from drive grade C to shunter grade B from pay Rs. 350/- of driver grade C to pay 350 for shunter grade B and has thus suffered no loss. It is averred that the junior fuel inspector Lucknow and D.M.E. Lucknow found the coal deposited was not representative but collected sample. In the end it is averred that the suspension punishment order of the appellate authority are considered and fully legal and are liable to be not set aside.

4. The management later filed additional written statement alleging that there being sufficient coal to work the train upto Lucknow. The driver Sheo Pal lost two hours 32 minutes and train suffered detention at Rai Bareli for taking fresh coal. For this loss workman Sheo Pal was held responsible and was placed under suspension on 4-3-82. During enquiry only two witnesses were examined namely Shri S. K. Nigam, Junior Fuel Inspector and the driver Sheo Pal. Said Shri S. K. Nigam, Junior Fuel Inspector, Lucknow, stated before enquiry officer that Sheo Pal had deposited coal sample at Lucknow on 2-3-82 which was inspected by him as well as Astt. Mechanical Engineer (I), Lucknow and was found that coal sample which was deposited by driver was not representative sample but was collected sample. The result of the coal sample which have been received from chemist and Metallurgist also reveals that the coal sample deposited was representative sample and the result was as under-Ash 54.5 per cent, Moisture 1 per cent, UHV 1241 K Coal Kg. It is further averred that nine engines were loaded before and after the engine worked by the workman from the same stock and six engine of Lucknow division and did not loose time on account of bad coal at Rai Bareli 5 tonnes of coal were taken and the engine started wth 11 tonnes of coal; that the driver changed and Ram Nath driver was working the train and he reached Lucknow without loosing any time when 7.5 tonnes of coal were still there, which showed that the workman was not justified for demanding coal at Rai Bareli. It is further averred that he would submit written statement of Ram Nath driver and of token porter within three days and the enquiry may be concluded as he was under suspension. Consequence thereof the enquiry officer held the charges against Sheo Pal proved. The appellate authority D.R.M. Lucknow after perusing and examining the record rejected the appeal.

5. The management has filed certified copy of the enquiry officer's report certified under section 139 of the Indian Railway Act. The enquiry officer himself has written that the result of the coal sample deposited which have been received from C&M also reveals that the coal sample deposited was not representative sample. It appears that in additional written statement as well as in the aandavit of Shrimati Urmila Nigam management witness it is wrongfully written that the coal sample which has been received from C&M also reveals that the coal sample deposited was representative sample. According to the enquiry report the charge of driver Sheo Pal was causing detention of 2 hours 32 minutes at Rai Bareli for taking coal when coal on tender was sufficient to work the train upto Lucknow. The discussion of the enquiry officer in his enquiry report before coming to the finding is based on conjuncture and surmises and not on legal evidence. First reasoning he has given about distance travelled between Allahabad and Rai Bareli and the distance left between Rai Bareli and Lucknow. According to him the driver had left Allahabad with 11 tonnes of coal and covered a distance of 123 K.M. of consuming 6 tonnes as 5 tonnes was still left at Rai Bareli so he could have easily travelled the distance of Rai Bareli and Lucknow about 78 K.M. with 5 tonnes of coal left with him. That would have been done but as the driver was lossing time in order to safe his skin he went on complaining from Atrampur and Dariyapur and ultimately got relieved at Rai Bareli and so he was not to blame that the engine detached at Rai Bareli for loading fresh coal. Secondly as Ram Nath Driver was provided who brought the engine from Rai Bareli to Lucknow after taking fresh coal, the enquiry officer has inferred in the following words :

> It clearly proves that relief crew might have been demanded by Shri Sheo Pal Driver at Rai Bareli on arrival which also caused detention at Rai Bareli Shed.

The workman had been demanding that the enquiry be made from Girdhari Lal A.S.M. Rai Bareli who could have clearly proved as to why and under what circumstances and under whose instruction the engine was detached for refunctioning. In the absence of direct proof the conjunture is uncalled under any law. That would have also clearly proved that whether the driver given any memo for detaching the engine or that was done under instruction from superiors. It would not be just and proper to presume in the absence of any memo that as he had given memo to station master Dariyapur and Atrampur he must have given memo for detachment to ASM Rai Bareli. As regards the coaling particulars received from Allahabad shed that can not be called to be the legal evidence as no witness was produced to prove the same nor was given any opportunity. Lastly it cannot be said that the coal sample deposited by the workman was not representative sample when the same was examined after three months. The sample should have been examined soon after it was deposited by the driver. Moreover it was the duty of the management to have taken sample of the coal when the train arrived at Lucknow and got it examined. The report of the C&M shows that the coal contain 54.5 per cent ash which indicates that the case was not of good quality. The driver Ram Nath who brought the train upto Lucknow should have been examined. In the absence

of legal evidence, the findings of the enquiry officer is based on conjuncture surmises and inferences and is not based on legal evidence. Hence it can not be said that the enquiry conducted was fair and proper and that the finding is based on legal evidence.

6. The workman has filed the order of the punishing authority who has simple written that the findings of the enquiry officer is accepted and the appellate authority while rejecting the appeal has ordered as follows.

> The driver has failed not only to perform satisfactory duty as a driver but also to get coal taken in the stipulated manner whie being relieved. I am afraid he has tried to manipulate a sort of defence which has in fact put him in an awkward situation.

The appellate authorities order is just as putting a cart before the horse. He has not given reasons how and under what circumstances he failed to perform satisfactory duty. Further the management should have collected the coal sample when he was relieved at Rai Bareli or latest at Lucknow. I fail to understand how he manipulated the defence when he himself given the sample at Lucknow without loosing time which the management examined after three months and not soon after. The management could have taken representative sample even at Lucknow and got it examined which was never done.

7. The management witness Smt. Urmila Nigam has deposed that she has no personal knowledge about averments of her affidavit and that the averments stated therein is based on records. No attempt was made to find out from the Station Master Darivapur and Atrampur whether the driver sent any message as alleged.

8. Under these circumstances believing deposition of the workman I hold that the enquiry was not fair and proper as opportunity to examine defence witnesses were not allowed and the report given hurriedly mainly on conjurcrures and surmises and punishing authority adopted the reasoning of the enquiry officer which is not based on legal evidence and is not fair and proper. I consequently hold that the action of the management DRM Northern Railway Lucknow in effecting reduction in rank from Driver C to shunter in respect of Shri Sheo Pal Driver Loco Shed Lucknow vide order dated 18-10-82 is the basis of the enquiry report which is not fair, proper and legal is not justified.

9. The result is that it will be deemed that the workman never reduced in rank and continued as Driver Grade C.

10. I, therefore, give my award accordingly.

Let six copies of this award be sent to the Government for its publication.

Dt. 30-10-85

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-41012/61/83-D.II(B)]

HARI SINGH, Desk Officer.

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1985

का. आ. 5473.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, बंबई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 11 नवम्बर, 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 18th November, 1985

S.O. 5473.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of National Industrial Tribunal, Bombay as shown in the annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Grindlays Bank Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th November, 1985.

BEFORE THE NATIONAL INDUSTRIAL TRIBUNAL, BOMBAY

PRESENT :

Dr. Justice R. D. Tulpule Esqr., Presiding Officer

Reference No. NTB of 1980

PARTIES :

Management of Grindlays Bank Limited

AND

their workmen.

APPEARANCES :

For the emplpoyer—Mr. C. Krishnamurthi, Manager-Industrial Relations, Mr. Vima Dalal & Mr. Rele, Advocates.

For the Federation—Mr. P. N. Subramanyan, General Secretary and Mr. Madan Phadnis, Advocate.

For the Association—Mr. Gadkari, Advocate.

INDUSTRY : Banking STATE : Maharashtra

Bombay, the 29th day of August, 1985

AWARD PART-II

Of the three questions referred to this Tribunal by the order of reference dated 12th February, 1980, by reason of an award delivered on the 26th March, 1985, one of the questions referred to the Tribunal, namely, bonus demand for the year 1976 and onwards has been considered and rejected. The award also dealt with certain preliminary contentions which were raised by the Bank, thus producing a bar to the reference and adjudication of the dispute referred on the 12th February, 1980. It was held that the preliminary contentions raised by the Bank to the jurisdiction and entertainability of the reference were not sound and that the Tribunal has the jurisdiction to entertain the reference and that the demands could be legitimately raised, the settlements covering the field of the demands having been duly terminated.

2. At the time when this part award was delivered the parties had, as a matter of fact led evidence and also made their submissions on merits with regard to the demand for increased additional allowance, lunch allowance, canteen subsidy and housing loan, as also the demand of the Bank for "further extension of mechanisation" in its branches and offices. Almost at the conclusion of the arguments, the Bank moved an application on the 25th January, 1985 that it considered desirable to "facilitate full and complete adjudication of demand No. 3" that it submit a tentative proposal of "how, when, where and in what phases it intended to further mechanise/computerise the system of working in the Bank"

and that it should be allowed time to submit its proposal and its further evidence in this behalf and then only the parties should be heard on their submission with a view to completely adjudicate on issue No. 3. During the course of the arguments and particularly, as I pointed out at the end on the 24th of January, 1985, the difficulties in considering and dealing with and specifying particularly the extent and conditions, in case scope for further extension of mechanisation in the offices and branches of Grindlays Bank was found was brought to the notice of the Bank and the parties, the Bank moved its application dated the 25th of January.

3. By an order passed on the 8th February 1985, as stated in that order, further evidence was allowed. It may be mentioned that amongst the contesting bodies of workmen, All India Grindlays Bank Employees' Federation, hereinafter referred to as "the Federation" which spearheaded this dispute did not raise any objection. Objections were raised only by the All India Grindlays Bank Employees Association, hereinafter referred to as the "Association", on the basis of what it contended as implied conditions of the settlement of 8th September, 1983. That contention of the Association was negatived as is observed in para 2 of the order. The application was allowed with a view to completely adjudicate the matter and in the interests of justice. The Bank was also enjoined to examine author of the report and whateer expert evidence it considered desirable and necessary.

4. Thereafter, the Bank filed a project report prepared by one of its officers, Mr. Chaudhary, dated 15th March, 1985, who is also examined. Dr. Y. B. Damle, Executive Director and Adviser, Management Services Department, Reserve Bank of India was also examined as an expert witness. After the conclusion of the evidence, arguments were again heard which were restricted only to the question of mechanisation covered by issue No. 3, as the arguments on the other part of the matter regarding demand for increased additional allowance, lunch allowance, housing loan, etc. were already heard.

5. It may be mentioned that though arguments and evidence relating to the demand for increased allowances, housing loan and canteen subsidy were already advanced and heard, one of the principal subjects of controversy between the prties then was whether the Grindlays Bank should be likened with other foreign banks operating in India and whether the foreign banks alongwith the Grindlays Bank were a class by themselves and merited separate and different consideration other than the nationalised and other banks in India. For the bank, it was urged that on the principle of industry-cum-region, Grindlays Bank was classified as 'A' class Bank alongwith other nationalised and Indian banks, as also foreign banks. There was no necessity and scope for creating a class within a class. Where banks are classified for certain purposes in a particular class and their service conditions required and determined on the basis of that classification there was, according to the Bank, no justification for creating a further sub-division or class within a class of foreign banks. According to it, the genesis of such banks would not justify their separate treatment. For the workmen, it was on the other hand contended that the foreign banks in India fall into a distinct group, separately identifiable on account of various factors and history. Their working conditions and conditions governing their operation in India are not the same as other Indian banks. For purposes of fiscal and policy control by the Reserve Bank of India, foreign banks in India have been treated as a distinct class historically also. Conditions of service in foreign banks for the staff have remained different and separate than those in Indian banks. By and large, conditions of service in the Indian banks have tended to remain in a similar or uniform pattern. The growth of the Indian banks has been phenomenal. Their expansion and problems arising on account of increase in the field of their activities have been different. Such a situation is not faced and it has not occurred in the case of foreign banks. Geographical expansion, growth in volume of business, financial strength and manpower of the Indian banks phenomenally increased and for out-classed the foreign banks, though for purposes of the Banks Award, these banks have been put together in 'A' class. It was the workmen's contention that even taking the principle of industry-cum-region, it would be improper to compare and consider Grindlays Bank as falling in the same class as such nationalised Indian banks like, State Bank of India, Punjab National Bank, Dena Bank and some such other five banks to which a reference has been made. They have been physically and historically put together on earlier occasions, as falling in one class or category from the point of view of resources, size volume of business, nature of business and obligations. Even though the Indian banks in class-A, mentioned above and the foreign banks have been put together, they are not at par and can not be treated as falling within the same group at least in the years 1980—85, whereby may have been the reason for doing so on earlier occasions. Their contention is that the relevant paoint of time with reference to which parity of industries and comparable character has to be considered is the situation at the time of the reference and not what it was once upon a time.

6. If demand No. 1 were to have been considered and disposed off at the time when the part-award was made on the 25th of March, 1985, this contention which was much pressed would have required examination and decision on whatever evidence was led at that stage. On the other hand, it appeared that the Bank was meeting the contentions of the workmen with regard to increased allowances, canteen subsidy and housing loan, by emphassing the extension in the level of mechanisation in the other foreign banks. Apparently, the contention then was that same conditions do not prevail and are not obtainable as were prevailing in the case of other foreign banks which materially affect the profitability, so that the demands of the workmen for increase could be considered.

7. By a curious irony of circumstances when it came to the question of justifying the Bank's demand that there exists further scope for increased mechanisation and in particular its submissions and claim arising out of situation and circumstances, coming as a consequence of the 8th September, 1983 settlement between the IBA and AIBEA, the Bank claimed that it should be treated as one of the banks falling in the class of foreign banks operating in India for purposes of mechanisation. Arguments therefore, when they were advanced after additional evidence was led and recorded after 15th of March, 1985, learned counsel for the Bank, Mr. Vima Dalal conceded and stated that foreign banks should be treated as a class and not that the Grindlays Bank should be considered and compared alongwith the other nationalised Indian banks falling in Class A. He hastened to say however, that the Bank would be willing to consider the demand of the workmen for increased allowances, canteen subsidy and housing loan subject to his other contentions at the same level of foreign banks claimed by the workmen, provided the same level of mechanisation was permitted to Grindlays Bank. The edge of the controversy therefore as to whether the Grindlays Bank fell into a different class of foreign banks alongwith the other foreign banks or should it be compared only with other comparable Indian banks in class-A and that there was no justification for creating a class within class became less intense and less sharp. It may be mentioned however that it is common ground that even amongst the foreign banks operating in India, Grindlays Bank is by far the largest in terms of resources, volume of business, geographical spread and its existence in this country compared to the other foreign banks. In the circumstances, with regard to the existence of scope for further mechanisation, if such scope is found, the extent and conditions thereto have acquired larger significance and importance. In dealing therefore hereafter with the two surviving questions. I prefer to deal firstly with the question of mechanisation, existence or otherwise of further scope of doing so and the extent and conditions which might have to be set out in case it is found that there is further scope for extension.

8. I may broadly refer to the positions taken by the parties on the question of existence of further scope for mechanisation without referring in detail to the stand taken in their statements of claim or written statements. I would also indicate while doing so, what are the grounds urged in support of their respective points of view by the parties. A more or less elaboate and greater reference to the submissions of the parties and their contentions in the statements of claim and written statements does appear in the award earlier given. It would not therefore really be necessary to set them out once again here in any detail.

9. So far as the employer, Grindlays Bank is concerned, two distinct stages of contentions appear in its statement of claim. Those stages relate to submissions and statements and written statements filed prior to November, 1982 and those taken in March and July, 1984. On 12th March, 1984, the Bank submitted an application for filing a supplementary written statement or amending its original written statement. By this proposed amendment, it referred to its contentions raised earlier and pointed out that the reference is pending since 1980 and till that time has almost not been heard at all. That an event has taken place on the 8th September, 1983, by which a bipartite settlement was reached. That bipartite settlement was between the Indian Banks Association and the National Confederation of Bank Employees & AIBEA. By that settlement, it says, that a further extension of mechanisation and introduction of computers was agreed upon between the banks represented by the Indian Banks Association and the employees represented by the National Confederation of Bank Employees and AIBEA. It referred in particular to clauses 1.1 and 1.9 of the said settlement and prayed that the Bank be allowed to amend its written statement. That the Tribunal should take notice of this subsequent event and that in order to completely adjudicate on the dispute between the parties, with regard to mechanisation, it should be allowed to state its contentions and seek relief in the light of that settlement.

10. For the workmen, the Federation did not file its reply or objections to the amendment application at the initial stage, while the Association by its reply dated 19th April, 1984, recorded the fact of a settlement having been reached on 8th September, 1983 and concluded saying that it has no objection for taking into account this development while adjudicating on item No. 3 of the reference.

11. By an order which was passed on the 25th of June, 1984, the Bank was granted permission to file a supplementary written statement. But that the question whether the reliefs claimed by the Bank as flowing to it on the basis of the settlement of 8th September, 1983 would be gone into and the submission or contentions raised by the workmen in that behalf enquired. It was the Bank's contention that as a consequence of the settlement it had become entitled to effect mechanisation in terms of the settlement. The Association on the other hand contended that it did not agree to the powers of the Bank as flowing therefrom or that further extension of mechanisation to the fields contemplated in 8th September, 1983 settlement should be straight-way granted. Such a course was opposed by the Association.

12. The Federation on the other hand contended that the settlement was not binding upon it and reliefs merely on the basis of the settlement may not be granted. The Bank will have to justify and establish a case for extension of the scope for mechanisation independent of the settlement as it required by item no. 3 of the terms of the reference. The Bank was thus allowed to file additional written statement for representing its case for further extension of mechanisation in the light of 8th September, 1983 settlement, to enable a complete and final adjudication on issue no 3. The workmen were also allowed to raise whatever contentions they want in regard to the said settlement and as to the manner, nature and extent of reliefs as well as the justification for the Bank to avail of further mechanisation contemplated by the 8th Septemsber, 1983 settlement.

13. It will thus be seen that the Bank's contentions in this behalf fell into two stages. Its earlier contention was that the Bank was free to resort to mechanisation to the extent and at places wherever and whenever it considers necessary to do so, as contemplated by the second bipartite settlement dated the 19th October, 1966. Its further contention was that the workmen are not entitled to object if the Bank undertakes any such mechanisation and its extension as contemplated and permitted by the October, 1966 bipartite settlement. During the course of the arguments, the Bank had also relied upon the award made in reference No. CGIT-24 of 1975 which was given on 21st April, 1984. The terms of that reference were whether the Grindlays Bank was "justified in introducing mechanisation at Bombay" and if that was so, the extent to which it was entitled and the relief to which the workmen were entitled. It also relied upon and referred to the judgement of the Supreme Court in this connection, which was delivered when the matter went to the Supreme Court at the instance of the workmen when the reference was rejected initially by this Tribunal. The Supreme Court in its judgement in Civil Appeal No. 2790 (NL) of 1980 held that there was no question of there being any justification to the introduction of mechanisation in view of the second bipartite settlement of October, 1966. The workmen by that settlement had permitted the Bank to do so and there could be no question of justification. The reference, however, survived and it was necessary to adjudicate upon other conditions which were imposed, namely whether the displacement was minimum or excessive as was contended. If the displacement was above the minimum then the workmen were entitled to relief and that question survived for adjudication and the matter was then sent back to the Tribunal. By a subsequent award of 26th April, 1984 delivered by me, this question was decided. So far as I am aware, there have been no further proceedings taken up by either of the parties against the order of that award.

14. Subsequent to the order allowing the amendment dated 25th June, the Bank contended that AIBEA and NCBE which represented the workmen in the 8th September, 1983 settlement "represents majority of the workman all over India of the concerned banks". The Association which has been joined as a party to this reference represents "majority of the Bank's workman in India." Its further contention was that clauses 6.1 and 6.3 of the said bipartite settlement of 19th October, 1966 stand modified by the 8th September, 1983 settlement. As a consequence, it contended that the Bank was entitled to extend "mechanisation and introduce computers in its workings, as that was authorised and permitted as a consequence of the settlement of 8th September, 1983, clauses 1.1 and 1.9. Therefore, according to it, the employees can not raise any objection or contention with regard to the scope of extension of mechanisation and computers and they may be prevented from doing so. In terms of that settlement, it said that it was free to the fullest extent to avail of the "benefits of mechanisation", electronic machines and computers as also resultant re-organisation, standardisation, rationalisation, centralisation etc. subject to the conditions laid down therein regarding displacement and retrenchment.

15. As stated earlier, the Association, did not file any further statement after the amendment was allowed to the Bank. The Federation had already filed a rejoinder on the 25th June, 1984 and in terms of the order passed on the 25th June, the rejoinder filed by the Federation was treated as its counter to the amendment. By that rejoinder, the Federation contended that the Bank resorted to machnisation at places like Calcutta, Delhi, Madras and Bombay. At Calcutta, Delhi and Madras from 1967 to 1976 and at Bombay from 1973 to 1976. That that was not in accordance with the first bipartite Settlement resulting in excessive displacement of staff. According to it, the right to extend mechanisation is not acquired by the Grindlays Bank by considering what was done by other banks. Its contention is that in the award in reference No. CGIT-24 of 1975, it was observed that "the Bank has displaced staff excessively". Therefore, according to the Federation "there is no scope for any further mechanisation in this bank". The mechanisation allowed by the first bipartite settlement is conditional and any contravention or infringement thereof makes the mechanisation illegal.

16. With regard to the 8th September, 1983 settlement, it said that the settlement was a private settlement between the Indian Banks Association and some of the Bank employees represented by the All India Bank Employees Association and National Confederation of Bank Employees. The bank employees who are its members are not parties to the settlement and the settlement is not binding upon them. So far as the Grindlays Bank was concerned, according to it, the unions at Calcutta, Bombay and Madras are affiliated to the Federation and not to the Association (AIBEA). They are also, therefore, not bound by the said settlement. All these

unions, according to it "contitute overwhelming majority of the employees of the Grindlays Bank". Therefore, according to it, the said settlement is not and can not bind all the employees of the Grindlays Bank and the settlement does not have any legal sanctity. It also raised a contention that since the first bipartite settlement of 1966 has not been terminated by the Grindlays Bank, the 8th September, 1983 settlement does not operate to affect the rights of the employees of Grindlays Bank. In terms of S. 18(3), the first bipartite settlement of October, 1966, not having been terminated, according to the Federation, there can not be any modification and revision in the terms of the settlement of 1966 by the 8th September, 1983 settlement. Besides, the conditions for mechanisation in the new bipartite settlement, it says, are identical with the first bipartite settlement. Further the Bank having resorted to excessive displacement of staff in all its regions, it is not entitled to any further mechanisation in its banking operations. As the employees of the Bank are not parties to the settlement, they have a right to object to the proposed introduction of mechanisation by the Bank.

17. It will thus be seen that whereas the Bank contended that there is further scope for mechanisation in its main office and branches even in terms of the 1966 settlement as mechanisation permitted under that settlement has not been adopted and brought into use by the Bank to its full, further scope for mechanisation and its extent is further available to it, in view of the 8th September, 1983 settlement. That settlement according to it was between a number of banks in the industry and majority of the workmen working in these banks as represented by the AIBEA and National Confederation of Bank Employees. Certain other dimensions to this contention were also lent during the course of the hearing of this reference. They were on the ground that there is a general trend in the banking industry to opt for mechanisation/automation. This tendency and trend has been recognised and accepted and received the sanction of the Banks and the employees by the settlement of 8th September, 1983. Further, the Reserve Bank's directions, the study conducted by it on the question of mechanisation the award made in the Reserve Bank of India's case in reference No. NTB-1 of 79 and the technological explosion in the world of communication required and made it imperative for the banks to move fast in the direction of mechanisation. There has been considerable growth in the banking industry vertically as well as laterally. There has been a growing discontent amongst the customers about the services rendered by the banks. International trade and industry is far ahead in the sphere of mechanistion and is adopting more and more sophisticated automated procedures and means of business and communications. Industry and trade internally in India is resorting to mechanisation and automation progressively and speedily. The customers are demanding speedy rendering of service and rendering it accurately. Where customers' activities are themselves fast moving, the Bank can not continue to carry on the trudge manually for rendering its services to its customers. The banking industry is very vital to the growth and survival of industries. The banks have been rendering greater and many more kinds of services than in the past to its privat customers as well as corporate customers. In order to keep abreast of the movement of the industry, technology and speed with which the world of communication is progressing, banks must, to survive, to remain competetive and even to render normal service, move towards greater and speedier automation. So far as Grindlays Bank is concerned, it was further urged and contended that banks competing with the Grindlays Bank and who were its natural competitions in the banking industry, as distinct from the Indian Banks namely, the foreign banks have and are resorting to use of sophisticated technology and reached a degree of automation and level far out-stripping the Grindlays bank in its efficiency and service, to the customers as well as to the managements. If the Grindlays Bank were to lag behind, it will lose its competitive edge and will yield its place to such banks. There is a protential and real danger of the bank losing its customers. It will not only lose customers who are automated themselves which is the trend but customers who may not be that automated would still require efficiency, and speed in banking services as they will have to deal with in their turn to other automated organisations. Other customers may also switch over to automaion in view of the proven benefits and advantages and for sake this bank.

18. Shipping companies, Airlines, export and import house have not only to deal with internal trade and business, but also external trade. In their business outside the country, they have to deal with banking industries which are fully automated in foreign countries. The Grindlays Bank, has major foreign exchange transactions. Its head office and all its branches all over the world are fully automated. In order to attain parity and same level of efficiency, speed up management information to enable policy decisions and effect transactions, it is imperative for the Grindlays Bank to have its Indian operations organised in the same manner, and at the same level, if not at a higher level, of automation, to continue to play a leading role in the bank's world-wide organisation. It has to have parity of operational efficiency. Apart from the foreign banks operating in India, it was also pointed out that the nationalised Indian Banks are also going in for automation on a largescale. They are also having world-wide operations and increased challenge and competition in the market for international banking facilities and trade. In order to achieve a large expected share and retain its share in the international trade and banking business which is fully automated, the Grindlays Bank must also have for its Indian operations, a level of automation consistent and in keeping with the challenges with which it will be called upon to face in future and meet the requirements of the situation arising from day-to-day and hour to hour in an increasing manner and at an increasing speed in the future. To continue to maintain its position in the industry in India as well as outside India, the bank cannot afford to continue its operations as before manually. These and other aspects of the matter would be discussed in greater detail at a later stage.

19. In the context, it would be advisable firstly to refer to the two settlements one of the year 1966 and the other of the year 1983 and then advert to the terms of reference. The relevant clauses of the 1966 settlement are to be found at Exhibit B-2. They were annexe to the written statement of the Bank. Paragraph 6-1 of the said settlement authorised the Banks to introduce ledger accounting machines, such as N.C.R. accounting machines of Remington Rand, as well as Blue Star for purposes of ledger and statement posting of current accounts, saving bank accounts, deposit accounts, etc. It also permitted the use of IBM or ICT Machines and punches for purposes of maintaining Inter-Branch-Agency Accounts for reconciliation purposes as also Salary and Provident Fund Accounts at Head Office. This was conditioned by sub-clause 3 of chapter VI (6.3), which is material and relevant. It says that that "the question whether the scope of utilisation of the machines referred to above can be extended or not will be considered afresh as early as possible after 31-12-1968". In other words, therefore, the 1966 settlement does envisage consideration of extension of the scope of utilisation of the machines over and above their use as contemplated in sub-paragraphs (i) and (ii) of clause 6.1. It is common ground and as I shall ppresently show from the evidence that mechanisation in the Grindlays Bank even as permitted by the 1966 settlement terms of clauses 6.1(i) and 6.1(ii) has not been completely adopted or extended. I have already earlier pointed that in a matter involving the same parties in the appeal from award in reference No. CGIT-24 of 1975, the Supreme Court held that there could be no question of justification to introduce mechanisation in the Bombay office and branches at Bombay by the Grindlays Bank in the current account department.

20. In a sense, therefore, the settlement of 8th September, 1983 in a modification as was urged by the Bank in terms of the settlement of October, 1966 as empowered in paragraphs 6.1 (i) and 6.1 (ii) and 6.3 thereof. I would now refer to the 1983 settlement which in terms says in clause 1 that "In modification of clauses 6.1 and 6.3 of Chapter VI of the settlement dated 19th October, 1966" the parties thereto agreed that "Accounting Machines electric/electronic, other than computers, may be utilised in banks" for the purposes set out from sub-clauses (a) to (f) below clause 1(i). Though there is a further modification and pro-

vision relating to rural branches and semi-urban branches, we are not at the moment concerned with it Sub-clause (II) of clause 1 permits the banks the use of computers and mini-computers for purpose of operations mentioned in sub-clauses (a) to (i) thereunder. It permits the Bank also to instal a large computer, not more than one at any one centre of the Bank within the specifications mentioned in sub-clause (III) of clause (i). Then, there is a restriction on the use and employment of mini-computers and their number. It is also permits the banks to hire a computer service under certain conditions and provides for a further review of mchanisation and computerisation after a period of three years from the date of settlement. This authority to computerisation, introduction of electronic/electric machines and automation is controlled, as before by sub-clause (VI) of clause (i), prohibiting retrenchment and keeping the displacement to minimum, while it incorporates an additional clause requiring "Maintenance of the present staff strength" and inflow of staff shall be commensurate with the expansion in the banking industry.

21. It is true that the Federation has contended that the said settlement is no binding upon it. Had it been so, the question of justification of further extension of mechanisation/automation would not have survived any discussion. The Federation, therefore, is right in contending that independent of the settlement, the Bank will have to show and establish and make out a case for extention of mechanisation/automation. Nevertheless, even if the settlement is not binding, so as to preclude any objection and prevent raising contentions by the Federation against extension of mechanisation/automation, if the September, 1983 settlement indicates a trend in the banking industry, adopted by overwhelming majority in the industry, and as is contended by a majority of the workmen, then it seems to me that this trend can not be ignored and looked upon as a mere straw in the wind, but is a definite mile-stone and as such reached by the concerned parties in this industry.

22. In this connection, it may be necessary to advert to one of the ancillary matters raised. I have already pointed out that the Bank in its written statement had contended that the Association represents a majority of workmen in this Bank. This claim was stoutly opposed by the Federation. The Association on other hand claimed that it had the majority. It challenged the claim of the Federation to represent a majority of the employees. The parties at one stage desired me to go into the question as to which of the representative of the workmen, namely the Association or the Federation, enjoyed the majority amongst the workmen. I declined to enter into a discussion or decision on the question which was indicated to the parties for two reasons, One is that it was not relevant to the terms of reference and was not required to be decided, and the other is that the Tribunal did not possess the necessary machinery to ascertain which representative union was in majority, which would be unduly embarking upon a task which would be time-consuming and not or any decisive value to the merits of adjudication. It was conceded and admitted position that the settlement was not a settlement in conciliation so as to govern all the workmen in the Bank. Therefore, in law, it would not be binding upon all members of the staff of workmen category of the bank-

That would have further diagressed into an enquiry and question as to whether the settlement was accepted by a majority of the workmen or no and whether it was fair and proper. That would have resulted in widening and enlarging the scope of the reference and I am afraid would have been also without jurisdiction. Therefore the question have to be decided within the parameters of the terms of the reference and on the basis of evidence which was adduced.

23. I may now refer to the terms of the reference in this behalf, which may at the cost of repetition be set out as under :—

(1) "Whether the demands of the workmen of Grindlays Bank Ltd. for increase in the quantum of existing additional allowance, lunch allowance, canteen subsidy and housing loan are justified ? If so, to what extent and from which date ?"

(2) "Whether the demand of the workmen of Grindlays Bank Limited for higher quantum of bonus then what has been paid and or offered by the management for the accounting years commencing in 1976 and onwards is justified ? If so, what exent and for which accounting years ?"

(3) "Whether there is any scope for further extension of mechanisation in offices and branches of Grindlays Bank Ltd. in India ? If so to what extent and with what conditions, if any ?"

24. It will be seen that the reference was made on the 12th of February, 1980. The term requires adjudication on the question whether there is "any scope for further extension of mechanisation". The wording of reference is somewhat ambiguous. At the time when the reference was made October, 1966 settlement held the field. As I have already indicated, it has authorised and permitted the banks to introduce mechanisation in the fields mentioned in paragraphs 6.1 (i) and 6.1 (ii) of that settlement. At the same time, I have already pointed out, the case of the Bank was that it has not adopted and employed mechanisation permitted to the fullest extent to which it was entitled under the said bipartite settlement. This situation has rendered the terms of the reference and in particular phrase "further extention" susceptible to more than one interpretation. The bank, as I have indicated, in the second stage of its contentions, contended that the scope of further extension of mechanisation was over and above that permitted by the October, 1966 settlement and to the extent automation mechanisation permitted by the September, 1983 settlement. Indeed, it was its contention that here should be no question of considering the extent of any scope for further mechanisation/automation in view of the September, 1983 settlement. Apart from the nature of the settlement, it is admitted that this has come to stay and accepted by the banking industry as a whole. Grindlays Bank which is a party to the settlement can not remain out of it and can not be deprived of the benefits of the settlement, particularly when it sought to establish by evidence that National Confederation of Bank Employees and All India Bank Employees Association represented a majority of the workmen in the banking industry. The answer, therefore, according to the bank to the first part of item no. 3 of the terms of reference had to be inevitably that there was scope for further extension of mechanisation/automation in the Grindlays Bank.

25. On the other hand, the two unions, namely, the Association and the Federation stoutly objected to this line of thought and contention. For the Federation, it was contended that the words "further extension" in the context of the circumstances were capable of only one meaning. That meaning according to it was further to what has been already done or achieved by the Grindlays Bank. It pointed out that the Government was aware of the October, 1966 settlement, which is binding on all the employees and the banks. It is also pointed out that it has referred a dispute consequent to the introduction of mechanisation in the Bombay offices and branches of the Grindlays Bank in the year 1975 to the Tribunal. At the time when the reference was made on 12th February, 1980 to the National Tribunal, the Central Government was aware of both these facts and circumstances. There was no demand further raised by the Bank against the workmen for extension of mechanisation over and above the scope permitted to it by the October, 1966 settlement. Therefore, it was the contention of the Federation that the words 'further extension' must be limited to mean extension over and above the level of mechanisation introduced by the Grindlays Bank by 1980 and within the parameters defined by the 1966 settlement. In this view and contention it sought to exclude altogether all over considerations pressed and brought in to justify extension and increase in mechanisation/automation in the light of the trend and world events and advanced technology generally and in the field of communication and also consequent upon the 1983 settlement.

26. I do not think that this contention of the Federation can be accented and the enquiry in this case limited only to a consideration of the scope for mechanisation between what was achieved and what had been achieved by the Bank till

1975, and the extent permitted by the October, 1966 settlement. There are a number of reasons why this contention can not be accepted. The first and the foremost is the different and distinct phraseology and words of the terms of reference to the National Industrial Tribunal of 12th February, 1980 and the CGIT-24 of 1975. I have already set out earlier the terms of reference in both the cases. It would be seen therefrom that while in the reference CGIT-24 of 1975, the enquiry is limited to mechanisation at Bombay main office and current accounts departments in its branches at Bombay of the Grindlays Bank, in the terms of reference NTB-1 of 1980 dated 12th February, 1980, there is no such geographical limitation. It refers to all the "offices and branches of the Grindlays Bank Limited in India". The level of mechanisation achieved by the Bank at its different offices all over the country was different than the one which had been achieved in Bombay. The necessary conclusion therefore from the difference in the terms of reference itself, to my mind, is that the further expansion of mechanisation contemplated in the terms of reference was not over and above what was achieved till then, but what in terms of paragraph 6.3 of 1966 settlement was envisaged and contemplated. There was no question of the Bank being able to expand and adopt mechanisation upto the limit permitted by the October, 1966 settlement. To require the Tribunal to consider that question and to adjudicate upon it would be fatuitous and outside the jurisdiction, both of the Central Government, so far as its power to refer and the Tribunal, so far as its jurisdiction to adjudicate. There would obviously have been no jurisdiction to adjudicate on the question of expansion of mechanisation upto the limit permitted by the October, 1966 settlement. I am therefore, inclined to think that on the basis of the difference in the terms of reference. In the light of the power of the Central Government to make a reference and jurisdiction of the Tribunal to go into the question, the words 'further expansion' in the context and circumstances are capable of only one meaning and that is expansion of mechanisation beyond that which is permitted by the October, 1966 settlement.

27. The other reason, which I think is equally compelling and forcible is that the Central Government must be deemed to be award of, and to have been aware of what the bank could do with reference to the mechanisation in the light of October, 1966 settlement. In that light and in that view, it would have been needless to investigate the scope of further expansion. The Government could not be contemplated to have made a reference which could not be adjudicated. Though the words 'further expansion' therefore, are ambiguous and capable of different interpretations, it appears to me to be quite clear that further expansion contemplated as requiring adjudication by the Tribunal was only with regard to over and above the October, 1966 settlement.

28. Though that is so, the parties tend to appear to have been not clear at least until the bank chose to amend its written statement in 1984, that the further extension could mean over and above that which was permitted by the 1966 settlement, and did not mean over and above that which had already been achieved either before the settlement of 1966 took place, as in the case of the Calcutta branches of the bank, or subsequent to 1966 settlement at other places, and only to the extent permitted by the 1966 settlement. It was not therefore without reason that Mr. Gadakeri learned counsel for the Association at a later stage urged before me that all that the bank wanted was, for the Tribunal to consider the extent and scope for extending the present level of mechanisation upto the level permitted in 1966 and direct the modalities thereof. He referred to the various parts of the written statement of the bank and also the reliefs which the bank had sought in terms of the reference relating to issue no. 3. This may be partly correct, though I can not entirely agree that that was the only demand of the bank. To my mind and as I shall later show, the bank had left the door open for further extension of mechanisation which it may become entitled according to it by later agreements, situations and such other circumstances.

29. Pagraphs 28 to 30 in that behalf of the written statement of the bank are relevant. So far as the Federation is concerned, the stand of the Federation has all along been that the Bank had committed a breach of the 1966 agreement. That it has mechanised and automated work in the bank even beyond the 1966 settlement. It had also committed a breach of the terms and conditions under which it was entitled to introduce mechanisation. It had exceeded by excessive displacement of staff and retrenchment by backdoor the limitations placed in the 1966 settlement. So according to the Federation not only that there was no scope for further extension of mechanisation, but that there was need to require the bank to retrace its steps in the matter of mechanisation.

30. This situation, however, considerably changed after the bank sought an amendment to its written statement and sought to file an additional writen statement or amendment to it. That was by its application dated 12th March, 1984. That application came to be allowed and an amended written statement was taken on record. By that written statement the Bank sought further mechanisation in all its branches in India to the level permitted by the 8th September, 1983 settlement. The main plank of the bank in the amendment was the settlement reached between the IBA and AIBEA and NCBA short for All India Bank Employees Association and National Confederation of Bank Employees.

31. Had the matters rested at the stage they were, prior to 12th March, 1984, and no amendment had been sought, nor any reliance upon settlement dated 8th September, 1983 placed, then perhaps, it would have been a question of considerable difficulty and a matter of argument as to what was meant by the expression 'further extension' and whether it could be extended upto the level permitted by the 1966 settlement where that has not been done, or whether it can go beyond. It appeared during the evidence that the dispute regarding mechanisation between the bank and its employees at other centres in Calcutta, Delhi and Madras were a matter of dispute at one stage. So far as Madras was concerned, there was a reference made to the Tribunal, which held against the workmen and finally there was a settlement Similarly, there was settlement in Delhi and also an award in terms of settlement. The matter is not clear so far as Calcutta is concerned. But it was mentioned at one stage that there also a reference had been made and the matter adjudicated upon, all that would have become relevant, had the settlement of 8th September, 1983 not sought to be relied upon by the Bank as one of the causes or jurisdictions for seeking further extension of mechanisation amongst others. As I have pointed out till 12th March, 1984, it is a fact that the Bank had considered the question to be within the ambit of the 1966 settlement.

32. I have already pointed out what was the stand of the Federation right from the beginning in regard to mechanisation. Consistent with its stand, since it opposed mechanisation even to the level permitted by 1966 settlement, there was no question of it agreeing to any further extension of mechanisation over and above and beyond the 1966 settlement scope or/and increase it, or be a party to computerisation/automation in the banking industry as envisaged by the September, 1983 settlement. On the other hand, the Association in its written statement, acknowledged and admitted the fact that there had been a settlement between the All India Bank Employees Association and National Confederation of Bank Employees (NCBE)) representing the workmen and the Indian Banks Association. According to it, that settlement did permit introduction of automation/computerisation in the banking industry within the frame work of that settlement and to the extent permitted by it. According to it, however, it was conditioned by certain further terms and circumstances which it contended were implied in it. Those implied conditions were that the implementation of automation/computerisation shall be achieved only through negotiations and settlements, and that adjudication on the question was left out by the parties. In my order dated 8th February, 1985, I have referred to these contentions and when allowing the application for amendment of written statement, I negatived the contentions which were then urged, as objections to the amendment. Even after the amendment at the conclusion of the hearing of the reference, on behalf of the Association, the self-service contention was pressed again before me.

33. I do not think that there is any merit in the contention that adjudication on the question as to whether there was scope for further extension of mechanisation was ruled out at least at the time when the reference was made. Such a contention is not raised with regard to the 1966 settlement. I have already observed what the Supreme Court

held in its decision in civil appeal No. 2790 (NL) of 1980 in the matter of CGIT-24 of 1975. If the contention of the Association on the other hand is that adjudication on the question of scope for extension of automation and mechanisation is excluded by reason of the settlement of 8th September, 1983 to the extent permitted by the settlement concerned, then it may be understantable. But in that case, the Association would be clearly and indirectly at least, if not directly, supporting the bank in its demand for extension of mechanisation to the level of 1983 settlement. Alternatively, in view of the Association being a party to the 8th September, 1983 settlement, it is bound by its terms. I shall presently refer to the settlement itself, But having signed the settlement and permited thereby computerisation/automation and further advancement of mechanisation in modification of the 1966 settlement by the very terms of the settlement, the Association can not now be heard to say that there was no scope for extension of mechanisation beyond the 1966 settlement. The members of the Association and the Association is bound by what it has agreed to. So far as therefore, the Association is concerned, it must be held that it can not raise any contention with regard to the scope for further extension of mechanisation upto the level permitted by the 1983 settlement As I indicated earlier, the question can legitimately and alone be raised by the Federation.

34. It is in this context that the question of the character of the settlement of 8th September, 1983 had become relevant from the point of view of its binding nature. The bank in order to hold the Federation also liable and bound by the settlement sought to say that the settlement of September, 1983 was binding upon he workmen, as majority of the workmen as represented by the Association had accepted it. I have already earlier referred to the attempt to induce the Tribunal to go into the question of deciding as to which of the unions is a maiority union having larger membership, and my excluding that question from adjudication and discussion for the reasons which I have given earlier. At this stage, it would therefore, be only necessary to refer to the legal character of the 8th September, 1983 settlement and and consider whether in law it could be binding on a non-signatory union.

35. A settlement is defined in S. 2(p) of the Industrial Disputes Act and means "a settlement arrived at in the course of conciliation proceeding and includes a written agreement between the employer and workmen arrived at otherwise than in the course of conciliation proceeding." Certain other incidental formalities have to be completed in connection with the second clause of the definition of 'settlement'. The effect of these two settlements, i.e. the one which is arrived at in the course of the conciliation proceedings and the other reached otherwise than in conciliation proceeding from the point of view of their binding nature is different. S. 18, sub-section (1) and (3) of which stipulate differently the binding nature of each of these settlements. As laid down in sub-section 3 of S. 18, a settlement "arrived at in the course of conciliation proceedings" is binding on all parties to the industrial dispute, namely, workmen and the employer, that is, workmen as a class and therefore all the workmen in employment, not only presently, but also those who may join the employment later. On the other hand, a settlement arrived at "otherwise than in the course conciliation proceedings" as laid down by S. 18(1), is binding only on the parties to the agreement. It is conceded that the 1983 settlement is. not a settlement in the course of conciliation proceedings Eventhough there does seem to be some reference to the conciliaion in the settlement. It is common ground between the parties that it is not a settlement in terms of S. 2(p) falling under S. 18(3) but a settlement under S. 2(p) falling under S. 18(1) as regards its binding nature. In the circumstances, therefore, the 8th September, 1983 settlement can not be held to be binding in law upon the Federation and the employees represented by it. That takes us to the question of further extension of mechanisation and the some therefor, which is the principal item of controversy between the parties.

36. I have already held and pointed out with reference to the decision of the Supreme Court, and also in view of my award in CGIT-24 of 1975 that the question whether the Grindalys Bank was entitled to mechanise its banking service in its branches to the extent permitted by the 1966 settlement is beyond dispute. There can be no question of pleading and proving any justification fo doing so. The question of any further scope for extension of mechanisation can therefore only be over and above the extension of mechanisation permitted under the 1966 settlement. In view of the foregoing the case of the bank and justification placed by it, together with the evidence for consideration of any further scope for mechanisation will have to be examined on its own merits.

37. We may proceed to do so by examining firstly the relevant portions of the two settlements of 1966 and 1983 on the question of mechanisation only. Some aspects of these two settlements and particularly the later settlement will also have to be referred. When I am dealing with these two settlements, I must not be understood to have thereby considered or held that scope for extension of mechanisation must be held to exist on account of the very existence and fact of the settlement having been reached in 1983 between some of the banks and representative bodies of workmen.

38. The two settlements are at Exhibit B-2 and B-3, and were produced by the bank. A close examination of these two settlements will reveal that the 1983 settlement is undoubtedly an advance not only with regard to the kind of mechanisation and automation and machines permitted to be used, but the areas in which they can be used geographically as well as in the banking departments and also the conditions under which that is to be done. The 1966 settlement, the relevant portion of which is produced and exhibited as Ex. B-2, permitted "Ledger Accounting Machines" to be used "for the purpose of ledger and statement posting of Current Accounts, Savings Bank Accounts, Deposit accounts, General Ledger, Accounts, Inter Branch/Agency Accounts, Salary and Provident Fund Accounts". The IBM or ICT machines on the other hand are restricted only to "maintaining Inter-Branch/Agency Accounts for reconciliation purposes as also Salary and Provident Fund Accounts at Head Office or offices where bank's centralised accounts are maintained".

39. The 1983 settlement on the other hand, as I said is an advance over the 1966 settlement, and in terms in clause-1 says "in modification of" clauses 6.1 and 6.3 of Chapter VI of the settlement of 19th October, 1966. It also leaves open to the banks and their workmen to reach an understanding/agreement/settlement in this behalf between themselves either in regard to modalities of implementation as also extension beyond what was permitted by the settlement, The settlement for the first-time refers to certain branches as rural and semi-urban, with a connotation of less than a particular number and branches in Area-I centre. Such a distinction was not made in 1966 settlement. In regard to some departments, namely, current accounts, savings bank accounts, other deposit accounts, general ledger accounts, cash credit and loan accounts and salary and pay bill, electric/electronic machines, other than computers were permittd to be utilised. Besides, Cash Credit and Loan Accounts were also brought in for the first time under this clause. In semi-urban branches, a limitation was sought to be put upon use of electronic machines with memory. By clause-II, computers including mini-computers wer permitted to be used for a varitey of operation, including salary and pay-roll, where it was already computerised or subject to an agreement. The provisions of clause-2 permitted deptrtments referred to therein also to be brought under machines referred to in clause 1, if the Bank thought it fit. Clause 3 permitted large computers to be used one at each centre with a limitation that it shall not be larger than what the Reserve Bank has. The banks were also further restricted from installing the large computers within 18 months from the date where the banks' branches were less than 500 in number.

40. By clause 4 almost no restriction was placed upon the bank's use of mini-computers and subject only to its needs and exigencies but limited to one for each centre in Area centre, and one more for every 200 branches or offices in that area, subject to a maximum of 18 computers. The settlement also permitted banks either to computerise themselves or to hire computer services from elsewhere. This was however restricted to a period of 2 years at the most.

41. With regard to the conditions within which this computerisation or automation was to be permitted, is, apart from non-retrenchment and minimul displacement, that the staff to be moved out as a consequence of automation was

to be moved within the same city or town. Besides, there is a further provision, requiring "maintenance of the present staff strength and inflow of staff shall be commensurate with the expansion in the banking industry." I have referred to only such conditions which have direct application to the extent of mechanisation in terms of machines and areas geographically as well as departments, and conditions under which they are to be introduced. A look at the tone of the two settlements (pulled out above, will go to show that the September, 1983 settlement is an advance in terms of mechanisation collectively, geographically as well as departmentwise. There were also, in my opinion, further safeguards from the point of view of workmen, and provision not only from loss of employment, but for increase in employment. This feature and situation as well as characteristic of the 1983 settlement of being an improvement in various aspects or fields has to be borne in mind all through in any further discussion on the question.

42. The 1966 settlement was between the Bombay Exchange Banks Association, which association appears to be that of the foreign banks in India, which are 10 in number and the Indian Banks Association representing the three classes of banks, namely classes A, B and C which are about 35 in number several of which were subsequently nationalised and the workmen represented by AIBEA which is also a party to the 1983 settlement and the All India Bank Employees Federation to which the present Grindlays Bank Employees Federation was an associate.

43. The 1983 settlement has a wider coverage. The number of banks which were under one umbrella of the Indian Banks Association are 58. The workmen representative were two organisations, namely the AIBEA and National Confederation of Bank Employees, which seems to have come into existence subsequent to the 1966 settlement and prior to 1983 settlement. The settlement of 1983 is at Exhibit-3 and Schedule-I of it goes to show that most of the foreign banks, including Grindlays Bank which is at Sl. No. 21 was represented through the Indian Banks Association during the negotiations. The All India Bank Employees Association which is party to that settlement is also party to this reference. Amongst those who represented the employers is one S. Mohan Kumar, who is also a witness to the settlement and also gave evidence in this case.

44. I will now refer to Mohan Kumar's evidence, so far as is material. Mohan Kumar was Assistant Personnel Adviser in the Indian Banks Association and in that capacity has been a party to the settlement. According to him, these bodies, namely, the All India Bank Employees' Association and the National Confederation of Bank Employees represent "about 80 to 82% of the award staff." He also had deposed to the procedure with regard to the verification of the representative character of the unions and in his cross-examination stated that this is done by asking "the particular banks to verify" and the banks verify and inform the India Banks Association as to the representative character. According to him, a majority of the banks are represented by the Indian Banks Association and are its members. His evidence further is that the number of unions and bodies affiliated to these two representative organisation, namely, AIBEA and NCBE was available with the Banks Association. That information, according to him, is still available and that in making a statement that the two organisaions represented 80 to 82% of the award staff, it was done so by putting together the membership of the affiliated unions and their percentage of representation. In other words, therefore, the claim of the Indian Banks' Associations and banks represented by it is that the 1983 settlement has been entered into with the bulk of the workmen members working in these banks, who form a very large majority.

45. In this context, I may refer to some of the documents produced by the Association, which is the correspondance between the Bank and the Association.

46. The Association's documents which are produced are filed alongwith an application dated 7th December, 1984. While the Bank had no objection to their production, its contention is that the documents are not relevant. I am only referring to these documents for the purposes of showing what was the position taken up by the bank and the Association at a particular time, with regard to their representative character. The documents are for the period from January, 1983 to April, 1983. No other material has been produced. The 31st January 1983 documents is a notice based on a check off by the Bank, and issued by the Chief Operations Manager of the Grindlays Bank, saying that the check off results show that the union has less membership than the Association. This was followed by 1st March, 1983 letter of the General Secretary of the Association, giving figures of mebership for the three regions, i.e. Northern, Western and Eastern regions. As ascertained on the basis of check off system in the Northern and Eastern India, the Association has a large membership in those two regions, but comparatively less in the Western Region, and small in the Madras area. On an overall basis, however, it was the case of the Association that it has 1969 members all over India, which, according to it, has a majority. The Bank's response is to be found in its letter dated 16th April, 1983 which says that "on the basis of our assessment your Association has at present an "over-all" majority at all-India level". On that basis, the Bank was prepared to deal with the Associaion and proposed certain arrangements for that purpose As have already pointed out, this aspect of the matter is not relevant and material for our purposes.

47. Similarly, I would also refer to some of the portions of cross-examination of Mr. Subramaniam, who is General Secretary of the Federation, on behalf of the Association as well as on behalf of the employers. Mr. Subramaniam claimed that the membership of the Federation amongst the Grindlays Bank employees in September, 1983 was 1850 and not less as contented by the Association. The Association on the other hand contended that it was more. Mr. Subramaniam was similarly cross-examined on behalf of the bank. By an order passed during the course of that evidence, further cross-examination on the question of comparative strength of membership of the Federation was disallowed. As I have indicated earlier, there was no point in enterning upon the numbers-exercise and that it would not have been enough to find out which organisation had a majority of affiliation, but also to further find that the settlement had been accepted by a majority of the workmen and it was fair and proper. That would have meant travelling beyond the terms of the reference. It is sufficient to know the pertinent features of the 1983 settlement. That settlement is between the large majority of banks representing a very large segment of banking industry and the workmen represented by two organisations, which at the time of the settlement according to the evidence had majority representation, amongst the workmen in the banking industry.

48. The settlement, therefore, would be a trend in the banking industry to go in for automation and mechanisation beyond the 1966 settlement and on a much larger scale in more areas of the banking business and also at different centres differently. The share of the banking business enjoyed by these 58 banks is considerably large and may be in the range of 80 to 90%. All the major nationalised banks in India, including the State Bank of India, which holds a commanding position in the Indian Banking industry are parties to it. As claimed by the Indian Banks Association and stated by Mohan Kumar, their representation and apparently workmen of almost all these banks have accepted further automation and mechanisation of the banking industry as something which must take place and inevitably some of the foreign banks which are parties to this settlement have entered into settlements with their workmen which have been produced in this case. These settlements are a further advance over the September, 1983 settlement. There is no evidence on the other hand produced to the contrary by the Federation showing or indicating a dispute between workmen and the vast majority of the Indian nationalised banks controlling major share of the banking industry in India against the settlement. There seems to be on the other hand a quiet on that front. If that is so, it can, I think legitimately be assumed that the 8th September 1983 settlement has been accepted by all parties to the banking industry, namely, the employers and the employees. The settlement is also meant for a period of four years and is to be renewed therefore'. It would not be wrong therefore, to assume and think that if implemented fully and vigorously the banking Industry in India, which includes all the major nationalised Indian banks and also non-Indian banks will be largely automated by 1987. I must, however, confess

that there is tardy evidence laid by the parties in this behalf in the field of mechanisation adopted and introduced by the various banks. The question, however, is not what is the follow up in the implementation of the settlement, but what the settlement points as a policy which will prevail and ought to prevail in the industry and is likely to come into being in the near future. There is, however, apart from the trend established by the September, 1983 settlement, a body of evidence placed by the bank in support of its case for justification and scope for increased and further expansion of mechanisation. I shall now refer to that evidence.

49. Even before the settlement of the year 1983, the issue of mechanisation had appeared as one of the questions in a reference to the National Tribunal, being reference No. NTB-1 of 1979. That was a dispute between the Reserve Bank of India and the workmen represented by the Reserve Bank Employees Union. It is true that the Reserve Bank enjoys a peculiar and unique position in the banking industry of this country. Apart from being a bankers' bank and a bank with which the Governments bank, as well as a national fiscal instrument, the bank has a controlling and directional function and power over the Indian banks. That power, it has over Indian banks which are scheduled banks, nationalised banks, cooperative banks and other private banks and foreign banks, operating in India. Nevertheless, as to what was held and said and found with regard to the question of mechanisation so far as is relevant to the banking industry and affecting it, and concerning it is not out of place to consider here as this stage and refer.

50. The Tribunal observed that the entire country has a stake in mechanisation and computerisation. While framing it conclusions and arriving at them, it pointed out that the objections to computerisation were more "on the general economic policy of India." It was apprehended and contended that introduction of computerisation/automation will eliminate all employment potential. That argument, the Tribunal considered as "not fully correct." That award was more concerned with specific areas of introduction of automation and computerisation by the Reserve Bank and in the light of the work which is required to be handled by the Reserve Bank itself in its relation to the banking industry in the country, vis-a-vis the Government. The apprehension was expressed to be not correct and indeed it was said that on the basis of the seminar on the question of impact of computerisation jointly organised in November, 1978 by the Central Statistical Organisation, Planning Commission and Indian Statistical Institute, that "it would rapidly expand employment." That there would be increase in the direct employment as a consequence of the use of computers in banking and also as a consequence of multiplier effect. Consequently, freeing the question from the general constraints of economic policy and apprehensions about employment, the Tribunal accepted the request in certain areas for employment of computerisation/automation, and granted it on certain conditions, namely, no retrenchment and displacement to be not more than 10%.

51. This was followed by other meaningful steps in that direction. A committee known as Rangarajan committee was appointed. The Rangarajan Committee made its report in the year 1984. The Committee was a high-power committee appointed by the Government of India of important people in the Banking industry to go into the question of the needs of the banking industry and areas in which mechanisation was necessary, and also into various other matters connected therewith. It was presided over by the Deputy Governor of the Reserve Bank, Mr. Rangarajan by whose name the report came to be later known. The Chairman or Managing Directors of the nationalised banks, academicians, and professors of banking as well as experts in the field were members of the committee. The reasons why such a high-power committee came to be appointed are to be found in the introduction to the report, which notes that the banking industry subsequent to 1969 has "undergone a phenomenal transformation." It has grown "not only in terms of the size of operations, number of bank branches", expansion of deposits and manifold increase in advances and number of accounts, but also in "functional diversification." It has set out the number of times by which the industry has grown in different fields and that this had generated a pressing need for accurate "information system for house-keeping for the internal management of the banks."

52. It also noted that a number of working groups and committees were appointed prior to the Rangarajan Committee, to study the various problems facing the banking industry. These committees had recommended "introduction of mechanisation/computerisation as an aid to generation of information systems" and that this was necessary and inevitable in order to improve the customer services, housekeeping and control.

53. The terms of reference to the committee, so far as material for our purpose, amongst the terms, was to "Identify the areas/functions where mechanisation in banks will be essential, including extent of mechanisation necessary at bank branches, regional offices/head offices;". It was also required to go into the question of extent of mechanisation, suggest a programme for mechanisation/computerisation in different areas and different banking set ups and also to recommend type of equipment suitable for the work of processing. The Committee's recommendations are in corporated in several chapters out of which Chapter-2, Chapter-4 and Chapter-7, I considered necessary for our purposes to be looked into.

54. The question of mechanisation/computerisation in the banking industry, according to the Rangarajan Committee's report is undoubtedly closely connected with the growth of industry and diversity of its activities. The banking industry as such, as observed earlier, has grown enormously between the years 1970 and 1980, in terms of deposits, advances, accounts of credit, nature of banking facilities, functions and diversity with increased volume of trade, internal as well as external. The external trade had added a further dimension of growth in the foreign exchange transactions. This has on the other hand presented an increased requirement of collection of information for purposes of administration, control and also decisions, short-term as well as long-term. The number of statistics and returns, which the Reserve Bank required members to submit to it as well as their periodicity has also increased. Apart from this external requirement from the Reserve Bank, within the banks themselves, the need for collection of this information which was generated and accumulated at various places of transactions have to be centrally compiled together and furnished speedily to enable and facilitate speedy decisions both as regards compilation as well as control of the transactions. The Subba Rao committee appointed by the Indian Banks Association considered the productivity of the banks as less and to remedy the situation recommended that "computerisation was the only solution to the problem." The reports of various other committees set up either by the Reserve Bank or by the IBM right from 1972 to 1982 had all recommended change in the present systems and mechanisation/computerisation. The Talwar Committee in 1976 had recommended mechanisation of certain functions to avoid delays in customer service and clearing houses. It will thus be seen that a host of committees and study groups were appointed between the period 1970 and 1982, before the Rangarajan Committee had opined and recommended that in order to improve efficiency and quality of service in the banking industry "judicious use of computers" would be necessary for securing financial management, greater efficiency and higher profitability.

55. Inspite of this, progress towards mechanisation was difficult and no mechanisation at all was attempted until the National Tribunal award (Justice Dighe award) of 1981 followed by the all India settlement of September, 1983.

56. The Rangarajan Committee has identified areas for mechanisation in banking industry, according to the intensity of banking activity throughout the country and grouped them into high, medium and low intensity centres. So far as Grindlays Bank is concerned, majority of its banking activities fall within high intensity centres.

57. The Committee has also recommended that half-hearted or partial attempts at mechanisation would not serve the purpose and yield the necessary results unless

there are appropriate linkages with the branches and exercise of isolated mechanisation would not yield desired adequate results, the reason being that data and material originates at various places and levels. Congregation of date and grouping of that data in to various components and compilation thereof together, and its transfer and communication to a central place is absolutely necessary for speedier and better policy decisions and information to the management. The data must smoothly and promptly flow from the levels at which it originates to the decision making level. This, according to the committee, had degenerated firstly on account of increase in volume and secondly on account of complexity of business. It observed that "the parameters on which information is required have grown so vast that they can no longer be fitted into a manual accounting system. There is, therefore, a need to evolve a partially machine oriented system under which data are captured at the transaction stage and transmitted with the aid of appropriate technology, not only for updating the relevant accounts but also for simultaneously generating the information needed." That in substance seems to be the present day requirement of the banking industry and its present need both from the point of view of the customers and the management, to ensure efficiency and speedy service and profitable decision making, to bring about in general a smooth and rewarding operation.

58. Another circumstances, which the Rangarajan Committee has pointed out, and I think is of considerable significance, is that the banks are not only required to collect internal data in the form of transactions entered into with it and its classification and segragation into various accounts, purposes and nature; collection of external data also on financial monetary and economic aspects of a country's policy in which the Bank is operating as well as the policies of the country with which the bank or its customers deal with and also others in so far as they can produce an impact upon the country, the economy, financial and monetary policies as well as the satistics in that behalf. This data and its further analysis is a basic for long-term planning and short-term programme. The Committee also pointed out that on a practical plane and consideration, immediately of mechanisation, to help improve the customer services. internal house-keeping and prompt transfer of data vital for management decisions was necessary. Indeed, there can be no two opinions that both this kind of information would be vital in making decisions in operatng in the money market as well as foreign exchange.

59. I will only deal with the Rangarajan Committee's report now in so far as foreign exchange is concerned, as that is one of the principal businesses of the bank, and not refer to its recommendations with regard to clearing operations, as that recommendation has been now substantially put into operation. Clearing House functions at Bombay, Delhi, Madras and Calcutta are already computerised and at other major centres, they will soon be brought under that programme. The Reserve Bank controls and runs the clearing house functions in the four metropolitan towns of Bombay, Delhi, Madras and Calcutta. It has also at the same time introduced the M.I.C.R. (Magnetic Ink Character Recognition) Technology for cheques. I will have occasion to refer to it generally however, while dealing with the other part of the evidence in this case.

60. The Rangarajan Committee noted that there was "multi-dimensional growth" in international banking in India. This is on account of an increase in the import and export trade, servicing of a large number of consequential inward and outward remittances, keeping of non-resident accounts and handling foreign currency loans, issuance of guarantees, sale and purchase of foreign exchange against travellers cheques and ordinary currency, as also foreign investments and increase in the banking outlets to facilitate larger number of transactions. This has necessitated adoption of different book-keeping procedure, different from the domestic book keeping ,requiring different amounts of skills, which in its wake underscore the necessity of a separate computerised system. The operation of Foreign Exchange Act, has also according to it, created manifold varieties of operations, such as credit guarantees, subsidies, foreign currency loans, cover transactions, which are all handled by the banks. It also notes that it is a part of banking services to provide customers with international monetary and market information. The banks' foreign business has to be backed up with guarantees to foreign parties, which in turn requires collection and maintenance of system of information vital and necessary for that purpose. The foreign exchange transactions, as a rule, involve greater risk than the domestic transactions. It involves evaluation of credit of the parties thorough schutiny of transaction and the documents, besides compliance with the rules and Acts governing the transactions has also to be secured. The committee also noted that the currency and money market has become volatile and "unforeseen fluctuations in foreign exchange rates may involve serious losses to banks on their uncovered positions." As a part of their foreign exchange operations, the banks have also to make forward sales and purchases in money markets, so that their positions do not remain uncovered and as a protection against exchange rate fluctuations. This can only be done by continuous updating of market reports and their analysis backed, of course by caution and proper judgement. Simultaneously, the banks have also to maintain and see from time to time the currency position of that country and match its forward transactions. After making detailed analysis in which transactions relating to foreign exchange are handled and what they involved, it pointed out that successful operations depend on "uptodate market reports, speedy communications between different tiers and periodic reconciliation of accounts." At present this is all done manually and based on the system as is used for domestic business, which it seems to suggest is hopelessly inadequate. This requirement and the mechanisation/computerisation required for efficient handling of its business and activities is of a different kind and character than handling of domestic business.

61. The Rangarajan Committee has also noted another phenomena and circumstance which is of vital importance. It says that in the held of foreign exchange business, "banks in India operate in direct competition with large international banks, who have the assistance of very sophisticated computer based systems." These computer systems "support all the accounting aspects, provide analysed information and even advise the personnel concerned about the desirability of quoting a certain rate of exchange or a specified deal." Though this may require a high degree of sophistication and fairly much experience and skills, to continue to manually match the expertise and facilities which such international banks have, would be as good as asking the Indian banks to write off their trade or business with such banks

62. It would not be out of place ,to reproduce some of the Rangarajan Committee's conclusions and recommendations. Basically, it must be noted and remembered that the Rangarajan Committe was considering the situation and problems of Indian banks and their requirements in the sphere of all the operations of the bank. Undoubtedly, therefore, there has been emphasis on the physical growth many times of the banking business and its further connected aspects. But there is also emphasis on the dimensional growth of banking business. The factor of physical growth, therefore, though may be absent in the case of Grindlays Bank, the dimensional growth in the banking business, which is common to the country, would be equally available and common to the bank in the present case. The conclusion therefore, are equally relevant bearing in mind the situational difference between the instant bank and other banks. The premise is still valid and not related only to computers being required to service enormously increased number of customers, updating of ledgers, deterioration in customer service and increased facilities and perpetration of frauds, etc. The committee no doubt realised and deduced that as consequence of mechanisation, there may be a reduction of about 10% in the work-load and consequential man-power. But the increase in efficiency according to it was likely to bring in additional volume of business and increase in the "overall employment potential".

63. The Rangarajan Committee's report has to be considered alongwith the evidence of late Dr. Y .B. Damle, who examined as an expert witness in this behalf by the Bank. Dr. Damle was a member of the Rangarajan Committee and also held the position of Executive Director in the Reserve Bank. He had high academic qualifications and was the head of the Computer Division of the State Bank of India from 1970 to 1976, before taking up service with the Reserve Bank. He claimed, which claim was not challenged, his familiarity with computerisation in the banking industry abroad as well as India." According to him, computerisa-

tion has started in a big way in India as a whole and in the banking industry in particular. Both the Government of India as well as the Reserve Bank, according to Dr. Damle, consider computerisation as a must for efficient working of the banks. His evidence discloses that banking industry has grown nine times not merely in terms of branches but also in terms of business. The sheer weight of the growth is such that, according to him it can not be performed and coped without resort to mechanisation. Indeed, according to him, the manual operation system has come to a breaking point. Referring to the Committee's report, he stated that the report "has been accepted by the Government and the Reserve Bank. The recommendations are being implemented in a time bound programme in the next two years from 1st April, 1985." The recommendations of the Rangarajan Committee I have not, though I have extensively referred to it, set out, as they are not fully applicable in the instant case. But it may be mentioned here that they recommend, broadly speaking, mechanisaion or automation at the branch levels and computers at centre or head office level. It contemplates installation of mini-computers or terminals at branch levels hooked on to the main computer at the centre or head office level.

64. Referring to the banking industry abroad, Dr. Damle stated that that is compupterised in Europe, USA and Far East in the last 20 years. Besides, "there has been considerable growth in technology from year to year, during the last three years, resulting in faster and uptodate information. The banks in these countries have no restraint on use and application of that technology. Indian banks on the other hand, according to Dr. Damle find themselves "extremely constrained in dealing with them." The system operating abroad is one of a central computer which is large, the branches being hooked up to the main computer, which have terminals and data processors. Needless to say we do not have any system existing.

65. The committee's recommendations, he clarified "do not deal with foreign banks". Though areas of operations were identified by the committee, that was not done operationwise, but physically with references to offices and branches. The reason to leave alone the foreign banks, according to him, is because, the Reserve Bank has a special responsibillity with regard to Indian banks and their operations and apparently none such corresponding with referance to foreign Indian banks.

66. Dealing generally with the pressure for Mechanisation. Dr. Damle stated that this with reference to Indian banks has increased from 1969 in terms of the volume and nature of business. According to him, this is on account of the change in the nature of services demanded by the society and their diversification, growth of international trade and above all and most important of all, probably is "increase in the world technology". This increase in world technology is in different fields and in different industries. It has undoubtedly a multiplier effect. Consistent and in keeping with the requirement or such a multiplier growth of technology, there has been a considerable and phenomenal growth in the world of communications, storing and retrieval of data, processing of data and capacity and facility of access to that data at a moments notice. This revolution undoubtedly his to have its effect, if the Indian banks have to remain competitive and to service the needs of the Indian industry and the in formation in the banking field For this purpose, it is obligatory for the banks to change their procedures and systems. They can not hone to do so with what instruments and tools they had, when there has been a revolution in technology in terms of speed, process and availability as well as accuracy. According to Dr. Damle, the non-use of modern technology by the foreign Indian banks, as compared to the systems prevalent in USA and UK "has affected these banks in the same measure, as the Indian Banks, which have reached a breaking point". It is true, as has been brought out in evidence, that growth of Indian banks in terms of business, branches, man-power resources is much larger than that of foreign Indian banks. Nevertheless, Dr. Damle has put them all as in the same situation of near "breaking point", in terms of financial and banking interaction between foreign countries and this country.

67. The state of mechanisation/automation in India at various levels amongst the foreign Indian Banks and Indian banks has also been deposed to by Dr. Damle. He stated that foreign Indian banks are switching over to computers "in two fields, namely, customer accounts and communications". It is common knowledge that the growth in communication technology through satellite communication, enables instaneous availability and exchange of information and communication between places and persons. He stated further that the City Bank, Manufacturers Hanover Trust, Bankers Trust and Bank of America have already been granted permission to import equipment for computerisation and they would be computerised soon, if not already. As I shall presently point out to the other evidence which is available, these banks in addition to two others have already been computerised. He started that the Hongkong Bank has already started computer working. I have already referred to Dr. Damle's statement that the Rangarajan Committee's recommendations are to be implemented in a time-bound programme in the next two years from April, 1985. That means, the committee's recommendations, so far as other Indian Banks are concerned with reference to which the Reserve Bank has a special obligation and responsibility, would be implemented in a phased programme in the next two years. Some of that has already been deposed to and has appeared in the evidence. The State Bank of India has been using computers. The Union Bank of India and Dena Bank hired computer services, while Bank of India has adopted computers for its clearing services in Bombay. I will refer to this again later while dealing with the other evidence.

68. The reasons why according to Dr. Damle, the foreign banks operating in India must computerise their operations can be said to be three. Firstly they will not be in unison or in step with their head offices, which have already computerised their operations and that of their other offices abroad. Secondly, foreign Indian banks as also Indian banks are "going in for computerisation". If foreign banks do not do so, they will be pushed out of business. Thirdly, the foreign banks in India "have the role of catalysts and operate, so far as the Reserve Bank of India is concerned" "as windows to the world outside. Through them, it is possible for the country to know "what is happening in the Banking industry outside." The technology which is in use abroad and the kind of businesses and the manner in which these businesses are carried out by the foreign banks. Another aspect of the matter is that Indian banks, which have been entering more and more in the field of international trade and international finance will not be able to carry on their operations in other countries unless the foreign banks are also entitled to operate in India. As these foreign Indian banks have their parent offices elsewhere and in other countries, where ultimate sophistication is the goal and available as it is, in order to be in touch and in unison and in step with their parent organisations, the Indian foreign banks have to be computerised. Consistent with these requirements of policy, Dr. Damle also stated that the Reserve Bank permits more sophisticated technology and machinery for foreign Indian banks, than what is normally permitted for the Indian banks.

69. Dr. Damle's evidence indicates that computerisation/automation in the banking industry in India, so far as Indian Banks are concerned, is coming into reality in a time bound phased programme, implementation of which has begun from April, 1985. That some of the Indian banks have, in fact, taken steps in this direction, while the Reserve Bank has computerised and automated some of its services in accordance with National Industrial Tribunal's award in reference No. NTB-1 of 1979 and has computerised clearing house facility and MICR technology for cheques. Some of the foreign Indian banks have introduced and are importing sophisticated technology for use of computers in their banking operations in India. The foreign Indian banks have their links and umbilical cords outside India, where the banking industry has switched over to sophisticated technology and is going in for more and more sophistication. The ferign Indian counter parts would not be in step and in line with these parent organisations unless they are permitted to automate. Computerisation is the need of the banking industry on account of the phonomenal growth and demands of automated customer operations, international trade, and if the banks have to render their service and

fulfil its functions to the society and economy and not to reach a breaking point. Automation will also, according to him, result in increased efficiency in customer services to attract more business, and by reason of streamlining and efficiating services and information, greater profitability. As a result of efficiency, speedy management decisions and judgements in various matters of trade and dealings will become possible.

70. He rightly pointed out that the effect therefore of automation can not be seen in isolation or with reference to a particular unit in the industry, but as a whole and generally not only for the banking industry, but for the economy.

71. Two criticisms were advanced and seen to be the underlying assumptions to detract the worth of Dr. Damle's evidence. The first is that the effect of computerisation in terms of deposit mobilisation or efficiency of service to customers and cost reduction is not available. Secondly it has been for the first time introduced through the evidence of Dr. Damle that the Grindlays Bank will not be able to survive without computerisation though the bank itself has not pleaded it in the written statement and as justification for introduction or extension of automation or mechanisation as put forward by the bank and sought to be established by evidence by it. Thirdly, it was suggested that the foreign Indian banks indulge in speculative activities in the currency market in foreign exchange which has become highly volatile. That foreign Indian banks alone are permitted to enter into swapping transactions of foreign exchange and they want computerisation, not so much because of customers' interest and to reduce customers cost and increase efficiency in the banking serice, but to increase profitability and benefit by speculative activities on the world currency markets.

72. The criticism, I think, may be partly justified in the sense that even in its supplementary written statement, the bank did not make out a specific case as to why it seeks mechanisation/automation and computerisation dehores the settlement of September, 1983. As I observed earlier, the sheet-anchor of the Bank's claim for further extension of mechanisation/automation is the 8th September, 1983 settlement which permits the bank and allows it to extent mechanisation from the 1966 agreed level. Independent of the settlement, therefore, the Bank has not mentioned why mechanisation and computerisation is a must for Grindlays Bank. One of the reasons why this was not done, perhaps may be that the bank's view of the September, 1983 settlement was that in view of the settlement no justification as such, apart from the settlement, was required to be put forward.

73. Though that is so, it seems to me that the criticism would not be legitimate. Simply because the Bank has not spelt out to the fullest extent the justification for extension of mechanisation/automation in its operations in its written statement, if the matter had been brought home by means of evidence which I have directed to the parties to lay before me and the parties had adequate opportunity of adducing additional evidence and making out their case, it seems to me that a grievance or complaint can not be made. The criticism can not have been advanced for any other purpose except to persuade me to exclude Dr. Damle's evidence. As I shall presently point out, some aspects of this case did appear in the evidence led by the bank even before the project report was filed, of Mr. Malhotra, Operations Manager. After all, the 8th September, 1983 settlement was a trend setter. It showed the direction in which the current thinking in banking relating to the technology was going on.

74. It is a sort of arrangement or compromise between the technological storm sweeping the banking industry and the traditional forces of statusquo and no change. Swimming against it and oppose it may cause considerable damage in the immediate future and irretrievable ruin in the longrun

75. To my mind, Dr. Damle's evidence coupled with the Rangarajan Committee's report does show the direction in which the banking industry in India is going to move in the near future. So far as Indian banks are concerned, with the power and control of Reserve Bank over them, armed with the September, 1983 settlement, the banks should be progressing towards automation and computerisation not only as a pressing need, but also in accordance with the recommendations of the Rangarajan Committee and the directions which may be issued from time to time by the Reserve Bank. This would bring about an atmosphere in the banking industry the impact of which upon those who refuse to see the trend and the winds of change in the air can be industry the impact of which upon those who refuse to a foreseable consequence to an organisation which shuts its eyes and ears and goes about like an ostrich in a fast moving world and surrounding. When he says therefore that the Grindlays Bank, if it continues as it is amongst the foreign Indian banks who are automated and its own parent organisation operating at a highly automated and sophisticated level in the industry elsewhere, will not be able to carry on its business, that is only one part of the picture. The customers of the bank who are also affected and afflicted by the technological revolution and have been progressing speedily in that direction and changing their ways, would equally insist and prefer an automated, speedier and accurate customer service particularly from a bank which supplies vital sinues to the industry and economy, than a non automated and manually operated organisation and operation. The threat to survival is therefore, a projected consequence or possibility, though not in the near future, in the absence of change ultimately. On a shortterm basis, the consequence would be being pushed out of business and the loss of competitive edge. This again is not stipulated in the written statement, but it seems to me that if "justification for further extension of automation/mechanisation" has to be considered by the Tribunal, then it can not also push aside the evidence adduced before it, which seeks to justify it on the spacious ground of absence of specific plea.

76. The survival threat and erosion of competitive capability has been more forcibly brought out in Chaudhury's evidence on behalf of the Bank. Chaudhari holds the post of Manager, Special Projects, Grindlays Bank and has experience outside India of switching over from manually operated banking systems to one which is automated. The specific case of the bank's requirements and need for extension of mechanisation have been given by him in his evidence. Before coming to India, he was the banks Country Operations' Manager in Colombo, Sri Lanka, when the Grindlays Bank there switched over from manual to automatic operations. Some of the important reasons which he has given for the need for automation felt by the Bank are that the Bank is a controlling office and head quarters for the operations of the Grindlays Bank in South Asia, India, Bangladesh and Sri Lanka, of which India alone is manually operating banking services, while Bangladesh and Sri Lanka have fully automated. The second and more equally important reasons is that the competitor banks of Grindlays in India, particularly, the foreign Indian banks are computerised and thirdly, the customers of the bank who are themselves switching over and getting more and more automated, would and do prefer an automated bank than a manually operated bank, consistent with its requirement. If the Grindlays Bank is not automated consistent with the world trend in industry and Banking they will prefer to take their business elsewhere. The Banks important and valued customers are corporate whose operations are not confined to India only and have dealings and transactions outside India also. Lastly, the bank would not be able to compete with its competitors which are fully automated or are being fully automated in the near future. These reasons according to him, and in my opinion in substance, also provide the necessary justification for extension and also the scope for computerisation in the Grindlays Bank. It would not be inappropriate to say that not only that there is justification and scope for computerisation in the Grindlays Bank, but that it is being thrust upon it as a consequence of events in the banking industry. If the Bank does not automate and computerise, then it will go under, as flood of events and the flow of technology affecting the banking business in India will sweep the bank out of the current. In order therefore, to hold its ground and maintain its position and to improve it, to continue to swim in the current, in order that it is not overtaken not only by foreign Indian banks, but also by giant-size Indian Banks which are also required to go in for computerisation/automation, according to the Rangarajan Committee's recommendations and directions of the Reserve Bank, and if it is not to be swept out of its business, it has to go in for automation.

77. Chaudhuri was examined mainly and principally as an author of the Project Report. But he also deposed and was cross-examined as to why computerisation was felt necessary and how its introduction would affect the bank and what it would yield to the bank in terms of costs, profitability, affect man-power, potentiality of jobs and impact on the present deployment and employment of staff. Apart from the introduction of the computerisation in Sri Lanka and Bangladesh, with the Sri Lanka branch of which Chaudhari was associated, he also had knowledge of how the Grindlays Bank head office in London worked. In Sri Lanka he stated that all the operations were automated while the project report there was differently conceived. So far as India was concerned the project report was differently conceived and even differently than the U. K. Pattern. His cross-examination, however, was directed more towards making of the project report, the staff requirements and projected requirements of staff and economic and cost considerations and efficiency in working.

78. The project report in its objectives and chapter on environmental issues, has dealt with these aspects of the matter. So far as the objectives of the project are concerned, it says that the project has been envisaged with a view "to arrest the persistent trend of diminishing growth". In other words, stagnation or losing share of the bank in the entire industry and thereafter recover the ground lost or at least reach the same picture of operations and business which it enjoyed, and secondly and which is important, to meet the "growing business threat from competitors, especially foreign banks". In chapter on environmental issues in the project report, the physical circumstances as compelling and necessitating automation are set out. They are that (1) all major foreign banks are substantially automated of which about ten are listed. They are immediate competitors. (2) They and large-sized Indian banks switching over to automation pose immediate threat to the bank. The report says that "nationalised banks have commenced the first phase of an ambitious technology plan". These banks which are of large size are State Bank of India, Central Bank of India, Bank of India, Punjab National Bank, Canara Bank and Syndicate Bank. (3) It also notes that the Reserve Bank of India has undertaken to automate the All India Clearing system using MICR process. According to him, it makes an obligation on all the banks to computerise their clearing operations partly.

79. Chaudhari has classified the environmental circumstances under three heads or subjects. I have referred to the banking industry already. To the banking industry the customer is at the centre and the most important factor. A bank's needs and requirements and its very existence is dictated by its customers. He has noted there that a cross-section of customers demand now an increased computerised service. Most of the large corporate customers require automated service, because they themselves are automated. A list of the corporate accounts of the Grindlays Bank is annexed to the project report, which makes an impressive reading. The names of the some of the few Indian organisations who have automated themselves and are customers of Grindlays Bank are Larsen & Toubro Ltd., Kirloskar Bros., Bombay Dyeing and Mfg. Co. Ltd., Mahindra & Mahindra Ltd., Hindustan Lever Ltd., Tata Chemicals Ltd., TELCO Ltd., GEW Ltd., Pakistan International Airlines, Quantas, etc. To these must be added the list of other large corporations like Shipping Corporation and Indian Airlines and other airlines.

80. The Project report also gives a factual analysis over a period of years of the growth in the banking industry and the comparative performance of the Grindlays Bank in that behalf, and its percentage with reference to the total activity. That is to show whether the share of the Grindlays Bank has grown, remained stationary or has decreased. That table is to be found at page-1 of the Project Report. It analyses the situation from two aspects, i.e. deposits and advances. Years taken for survey on are from 1979 to 1984. I am omitting 1985 as that is only for a short period. This table shows that the deposits have increased in the banking industry as such from Rs. 28,671 crores in June, 1979 to Rs. 63,732 crores in June, 1984, which indicates a growth of nearly 2-1/4 times Grindlays Bank's deposits have increased from monthly average of Rs. 512 crores in 1979 to Rs. 664 crores in 1984. On that basis the deposits of Grindlays Bank in 1979 stood at a level of 1.79 per cent of the total volume of deposits in the industry, while it came down to 1.04 per cent in 1984, though there has been a much larger average growth of deposits in the banking industry. Banking industry's growth as such in deposits, is found to be 19 per cent (plus) according to the chart, while the same in respect of Grindlays Bank is only 10.67 per cent (plus). Though therefore, the deposits have increased, they have not increased for Grindlays Bank in the same proportion, as they have increased generally in the industry.

81. Similar is the position with regard to advances, which figures have also been similarly set out. If there figures are taken for the month of December, they do show a slightly different picture, but the trend is unmistakably the same. There also, the advances in 1979 in the entire banking system stood at Rs. 19,116 crores and increased to Rs. 43,114 crores in 1984, which increase is more than double. Here against the share of the Grindlays Bank in the total advances has gone down from 1.75 per cent in 1979 to 1.13 per cent in 1984.

82. That is also the evidence of Chaudhary, when he says that "Grindlays Bank share has down substantially". According to him, all the banks are competitors, but the foreign Indian banks are more dangerous in that they pose "a threat to the Bank's survival". Some nationalised banks are also its competitors while the Chartered Bank, Bank of America, City Bank, Hongkong Bank and American Express are close to Grindllays in terms of resources. It is true that he has not been able to give the figures in terms of their share in the entire banking business in the country, but only made a reference to the other foreign Indian competing banks. But that is understandable in as much as these figures may not be readily available.

83. On behalf of the Bank, it was stated during the course of this reference that the Bank is not justifying or seeking automation on the basis of growth in business or branches. I have already pointed out some of the important grounds or reasons appearing in Chaudhary's evidence seeking computerisation or extension of automation. These have to be seen further in the light of Malhotra's evidence to which I shall immediately come. It will however, be necessary to deal with other aspects of Chaudhary's evidence and the three areas in which he had been cross-examined. I shall come to them presently.

84. Malhotra is General Manager (Operations), Grindlays Bank, posted in Bombay. According to him "computerisation is necessary for the bank to meet its customer requirements". The bank has about 280 large customers who are automated. They are very large corporations like airlines and shipping companies. He also stated that most of the foreign-based new banks which are recently opened in Bombay are fully automated. He also spoke of the automatic clearing houses at Bombay, Delhi, Calcutta and Madras, which the Reserve Bank was going to introduce when he gave evidence. As I have already pointed out, according to Dr. Damle and Chaudhary's evidence this has already been done now. Malhotra gave his evidence in August, 1984 while Dr. Damle and Chaudhary sometime in April, 1985.

85. He also referred to the Reserve Banks direction of use of MICR technology for cheques in place of security check papers. He also stated that automated clearing facilities have been introduced by the Bank of India at its Princess Street Branch and certain branches of State Bank of India have introduced computers. That the old foreign banks have already started the process of computerisation and automation. Some of those banks have done so "over and above the settlement of 1983 between IBA and AIBEA" and "entered into settlements with their unions" in this behalf. These settlements have also been produced. The consequence is, according to him, those banks which have switched over to automation are more competitive, efficient and cheaper in rendering service to the customer. As an instance he stated that Diners Club, which had an account with the Bank has gone over to Indo-Suez Bank which is

fully automated. He also spoke about the tendency of large corporations public or otherwise to switch over to automation and their consequent preference for automated service from the banks.

86. In the sphere of foreign exchange, his statement was that automation would help to speedily fulfil the demands of the bank and the transactors' business. That would also help the bank "minimise losses in foreign currency". External banks, i.e. banks based outside India according to him, will not deal with the Grindlays Bank in their operations, if the Grindlays is not computerised and would prefer a bank which is computerised. Computerisation, according to him, would "increase the competitiveness of the Banks with reference to other Banks customer service, management information and productivity". This would also enable the bank to meet the customer preference for automation, speed and accuracy and banking services, which is more and more visible.

87. Some measure of the work which the bank handles are does appear in Malhotra's evidence. It appears that the bank handles 3,500 credit-debit entries per day on an average in Bombay. This may go upto 6,000 entries on a busy peak day. That the Bank's business in terms of money volume has grown "on an average 11 present annually", but according to him, the volume of transactions has remained static. The costs on the other hand have gone up every year by 10 percent. He was unable to say off-hand terms of percentages whether the bank's volume of business has grown, remained static or otherwise. However, we have now these figures in the project report compiled by Chaudhary. Malhotra, nevertheless, did say that it was not correct that the volumue of business transactions and daily work of the "Grindlays Bank has increased and not decreased".

88. It will thus be seen from the evidence of Malhotra and that of Chaudhary, as was stated on behalf of the Bank during the reference, the bank's case for introduction of automation and computerisation is not that its business has grown in terms of volume, in terms of branches or the number of transactions effected per day. It was not on account of growth, the bank claimed justification for introduction of automation or computerisation.

89. The need for computerisation and automation therefore has been placed by the bank on several grounds which may be set out and summed up. It claimed that that was the need of the time as not only the foreign Indian banks, but the Indian banks are also going over to automation and computerisation. In the industry, as a whole computerisation and automation has been accepted as a necessity and a settlement has been reached between major Indian banks and their employees, which covered a very large segment of the industry. It is a need of the times, because both the Reserve Bank of India which controls the banking business in India and the Government of India have emphasised the necessity of computerisation and recommended switching over from manual to automated systems of banking. The banks' customers in a very large majority, consisting of corporate bodies, public corporations and even private customers demand speedier and accurate customer service and also need various other kinds of services. The banks have to effect and put thorough several kinds of foreign exchange transactions in the export-import business. International trade and exchange markets, being completely automated and using sophisticated equipment and machinery, to be in correspondence with them, it is absolutely necessary that the bank must also be automated. The bank must also have automation and computerisation so that the data base and information for speedy and prompt management decisions on a long term and short term basis are made with the maximum coverage of factors influencing such decisions. The complexity of modern trade and international money markets has grown over the years on account of the technological revolutions. The process of decision-making has to keep pace with the speed with which the information can be and is communicated. Communication of information on account of modern technology is nearly instantaneous. If the bank does not computerise and switch over to automated processes, it will have difficulty in meeting its customer requirements as well as getting the management decision material in time, thus delaying appropriate management decisions. Customers who are themselves automated cannot be served with manual operations and they would prefer on the other hand, in view of the growing complexity and growth in terms of volume of business, services which are computerised and automated in other banks, as a consequence, in comparative business and ability to capture its market in a trade which is growing and highly competitive the bank will have to play a losing and diminishing role. Not only that the customers of the bank would prefer more automated foreign banks, but that the bank itself would be thrown out of its business by more ambitious foreign banks and large giant size Indian banks which are also switching over to automation. In an industry, which is turning from manually rendering services to automated services, it would not only be wrong, but unjust to the bank and harmful to it to require it to remain tied down and bound down to manual processes. The bank, for its survival is threatened by competing foreign Indian banks and giant Indian switchig over to automation. Both foreign and Indian banks as well as grant size Indian banks are and would be computerised not only immediately, but also in the near future. The bank must be able to meet and prepared to take these challenges which are threatening it at present and which may engulf it shortly. The workmen have really no reason to be apprehensive as the bank has assured and there is a condition prescribed in the settlement, that there will be no retrenchment, that the displacement would be minimum and that there would be on the other hand, an inflow of staff. Mechanisation and computerisation is likely to lead to cheaper customer service, more up to date and faster information and data available to the customer as well as to the management enabling processing of transactions of customers as well as of the banks in the international as well as domestic markets without mistake and almost in a fraction of time, whereas now they take quite some time.

90. Lastly, the bank being a foreign based Indian bank, it has its world-wise operations fully automated and it acts as head office for South Asian countries, which themselves are automated. It also must switch over to computerisation and automatic processes and system of banking to be in unison and step with its subsidiary and parent organisations. That will eliminate difficulties and delay in communication between the two and help resolve faster organisational and management problems and difficulties. Though the bank has generally grown in its activities in absolute terms, it has not grown in real terms. With a better managed customer service, its accurate and speedy nature, the bank hopes and considers it feasible to attract more customers to increase its share of business in the banking industry as well as to increase its operations. This in turn might reuslt in the growth of employment and increased employment opportunities. Instead of therefore, the employment potential going down, apart from the immediate prospect of increased employment, there can also be a long-term prospect of increased employment. The experience of automation in other units where it has been introduced has not been that there is a loss of employment. On the other hand, the experience is that there is increase and growth which is also envisaged in the September, 1983 Settlement and speaks of inflow of staff with increased business.

91. I have already pointed out the stand taken by the workmen's organisations, i.e. the Federation and the Association in this behalf. The Association cannot really oppose mechanisation, in view of it being a signatory to the September, 1983 Settlement. The association is a member of the All India Bank Employees Association. Curiously, however, it has taken an unusual stand. It has not shown that it has any proof that the settlement contemplates or it was intended and agreed that there will be "further definitive settlements" between different member banks and the respective unions affiliated to central organisations. There is nothing to show as contended that the agreement contemplates that the basis, conditions and reliefs subject to which the automation was to be introduced was to be subject to another round of negotiations between the member banks and its workmen employees' organisations and to their satisfaction.

92. I have already in my order passed on the 8th February, 1985 rejected this contention, as it does not find any support in the terms of the settlement. The Association did not produce any evidence before me as stated above in the form of even an elucidation from the Central organisation that what was intended and what was agreed upon and implied between the banks and the employees when the September, 1983 settlement was reached, was that there will be individual settlements in each bank with regard to the implementation and commensurate reliefs to the workmen. The Association, therefore, can not be held to oppose the existence of any scope for further extension of mechanisation in the Grindlays Bank as was contemplated at the time when the reference was made in the year 1980 and would therefore be only over and above what was agreed by the 1966 bipartite settlement. As I have indicated earlier, the only contestent which can remain in the field is the Federation.

93. Neither the Association nor the Federation adduced any evidence to dis-establish all those factors which have been presented and brought before me and which I have referred to above, as requiring, suggesting, necessitating increased mechanisation and automation/computerisation over and above 1966 settlement and at least to the level permitted by the 1983 settlement. The Federation satisfied itself by suggesting possible reasons for the Grindlays Bank to seek mechanisation which were ulterior in its opinion and collateral. It had, according to the Federation, introduced mechanisation to such an extent that it was a threat to the workmen and was progressively and drastically cutting down the employment potential and staff strength. If further mechanisation is allowed, then perhaps there would be no jobs remaining for the workmen. The case of the bank that greater automation and computerisation would help reduce cost and increased efficiency in customer service, according to it, is hollow. The Rangarajan Committee's recommendations are principally meant for Indian banks which are in a situation of phenomenal growth in banking business. Where a bank does not lay claim to mechanisation or computerisation on the basis of increased and compound growth of business, branches and operations, where its operations have remained static, where it's practice, and policies are against cultivating all kinds of customers and is choosy about the customers who bank with it, if it places unusual, undesirable and restrictive conditions upon its customers that is going to hamper the growth of the banking business of the bank. The reduction in business according to it is a matter of choice and self invited. In that situation it cannot be a justification for further mechanisation when the bank is meeting it's present requirements and liabilities fully and efficiently manually. It is still a prime bank among foreign Indian banks. In an industry which is rigidly controlled by the Reserve Bank of India, so far as domestic banking and foreign exchange are concerned, there is no apparent real scope for customer preference. The bank's contention therefore that there is a threat to its survival is not real, much less can there be any. Where the growth factors in the banking business are controlled by the parameters laid down by the Reserve Bank in terms of lending rates and interest rates, which is really the flesh of the industry, the competition can only be in matters of small service charges. The bank by its own act has thwarted and inhibited its growth by being choosy and dissuading customers from banking with it. In such a situation, it can not hope to attract more customers, larger deposits and make bigger advances. The very factors which would indicate or suggest or requiring going over to automation and mechanisation in this bank, according to the Federation; do not exist and have been deliverately cut off by management policy. The only advantage therefore which would accrue to the bank by automation would be to make considerable profits which it would make in speculative foreign exchange transactions which would not benefit this country, but through the head office of the bank situated in London that office. This is says would be at the cost of employment in India. The pressure which the bank is applying for introduction or mechanisation/computerisation is in the peculiar condition of the volatile international money market, where fast and hot money can be quickly made. It needs for that purpose such sophisticated means of communication. In substance and short, therefore, the Federation's contention is that the Bank's need and justification for automation/computerisation is not real, but ulterior. It would only benefit the bank pater or foreign based owners. On the Indian scene it would not result in more efficient or less costly customer service than before, or also increased busines as long as present policies remain and on the other result in considerable reduction in employment which India can ill of afford. It almost seems to breathe it as it were that it would be antinational to allow computerisation to this bank.

94. As I pointed out this was not sought to be established by direct evidence, but only indirectly through cross-examination and suggestions. The existence of a number of facts, to which I have made a reference earlier, such as customers preference to automation and switching over themselves to automation and computerisation, particularly in large public corporations and private organisations, the complexity and growth in international as well as domestic trade and banking business, the reality of the September, 1983 settlement between the Banks and the employees representing a large segment in the banking industry, the circumstance that some of the foreign banks have gone in for automation/computerisation over and above the September, 1983 settlement, the Rangarajan Committee's recommendations and a time-bound implementation of its recommendations and programme so far as giant Indian banks are concerned and the general competitive nature of the industry and the foreign and giant Indian Banks in particular, could not be wished away by the Federation or disproved. It satisfied therefore, itself by indirectly establishing these circumstances through the cross-examination of witnesses, Malhotra, Dabe and Chaudhary, and placing some statistical evidence before me. I will consider therefore these aspects of the matter as sought to be brought out in the evidence of these three witnesses and the statistical material placed before me. At one stage, it was also the Federation's position that the Bank has not considered and has no project report as to what extent, where and in what areas further machanisation or automation should be introduced and it had also no programme or plan for that purpose, nor had it made a study of the consequences of introduction of any such programme or plan or projections flowing therefrom in terms of economy in costs, growth in business, profitability and effect on manpower. That however was taken care of by what took place subsequent to March, 1985, and the project report prepared by Chaudhary and filed by the bank and the evidence of Chaudhary himself.

95. Malhotra in his evidence, referred to a number of statements required by the Reserve Bank and their periodicity, i.e, weekly, fortnightly, monthly, quarterly, etc. That that involves considerable manual work, involving factors of error. Compilation of such statistical returns and the search for materials manually involves a much larger outlay of man-hours, whereas a computer can adequately store it, simultaneously segregate the material, allow instaneous retrieval classified and ready for timely compliance with the Reserve Bank instructions.

96. Malhotra, in his evidence, by way of example and elucidation stated that the cost of processing a debit or credit entry manually is about Rs. 4.05, while the same mechanically would be about Rs. 1.05. The bank has in all 0.6 million accounts of which 1,20,000 are inoperative. These 0.6 million accounts are made up of 2,44,000 savings bank accounts, 1,88,000 short-term fixed deposits, and 45,000 current accounts. Of these only 24,000 current accounts are covered by the present state of mechanisation. He also admitted that between the year 1974 to 1982, the staff strength in the bank has come down from 5,200 to 4,100. He also admitted that Bank of India and State Bank of India are much bigger than Grindlays Bank in terms of customers, deposits and branches in India. In terms of daily transactions, probably these banks are ten times larger than Grindlays. That was suggested to Malhotra also.

97. It was then suggested in the cross-examination of Malhotra that the reduction in the staff strength has been achieved or exceeded only in branches where mechanisation took place between 1974 and 1984. The contention appeared to be that the staff strength had not gone down no mechanisation was introduced. As that would have involved a considerable amount of cross-examination and reference to a number

of documents, I had directed the bank to produce statements for the period 1974 to 1984, giving the number of employees reduced year by year, branches where reduction took place and the section in which the concerned persons were working. Such statistical material has been furnished by the bank (Ex-B-4). I have gone through those statistical charts. Except for the general disclosure from that of reduction in staff strength pronounced more in some sections and less pronounced in others, no particular pattern emerged, as was suggested that it was only in branches which were mechanised that the staff reduction was more. It was not shown to me during the course of arguments also, as no arguments were advanced on these statistical charts as establishing this contention or other contention that mechanisation directly leads to greater reduction in employment. Malhotra, however, did admit that in Grindlays Bank "staff strength has reduced in terms of daily work and volume of transactions." In other words, less number of people are handling the same amount of daily work or volume of transactions or may be a larger amount of daily work and larger number of transactions.

98. It was directly suggested to him that it was the bank's policy to reduce "its business by bringing the restrictions on account holders and depositors." This contention of course was denied. The suggestion was that small account holders and depositors were discouraged from banking with the bank. Malhotra did admit however that savings accounts and fixed deposit accounts which formerly could be opened with a small amount of Rs. 5 and Rs. 500 has been raised to Rs. 250 and Rs. 2,500. That restrictions have been brought upon checking facilities. Current account now can not be opened with Grindlays Bank without a minimum amount of Rs. 1,000. He claimed however that Reserve Bank has issued guidelines in that behalf when an attempt was made to suggest that nationalised banks do not place any such restrictions upon customers or depositors. Malhotra was unable to say what would be the savings in terms of man-hours for preparation of statements required by the Reserve Bank and satisfied himself by saying that "by and large the work a complished today manually of that particular kind can be accomplished in one-fifth of the time." He was also unable to say by what extent and percentage, bank's profit could increase, as well as its competitiveness by the introduction of computers when interest rates on advances as well as deposits are controlled and fixed by the Reserve Bank. It appears that there is some difference in calculation of interest. Malhotra claimed that Grindlays calculates interest on daily accrual basis and credits it to the customer and not on a term basis or period basis. The benefit thereof to the customer is immediate. This, according to him, is possible by means of automatic operations. This, it was pointed out would benefit customer only and not the bank which is paying the interest. But this would similarly benefit the bank when it charges interest on advances. He admitted that he has not made a study as to what would be the number of members of staff involved, if computarisation is adopted in terms of 1983 settlement. He did not agree, however, with the suggestion that computerisation would considerably reduce manual work. It was suggested for the workmen that this is a natural consequences of relying upon machines in place of human beings for the same work, and that unless various schemes for development and growth and expansion of business are evolved, human material rendered surplus on account of automation can not be absorbed and will have to be thrown out.

99. According to Malhotra, other kinds of jobs will spring up in connection with the computers, such as preparation of input material, checking of input material, checking of output material, and sorting and such other connected work. To a categorical question put by me during his cross-examination on 14th August, 1984, Malhotra stated that he can not "specifically say what would be the savings by way of costs and what would be the number of man-hours or man saved on account of automation." I have already referred to his other answers with regard to volume and growth of business, cost ratio in terms of money-wise increase in the volume of business. Finally, Malhotra stated that in their bank they have not made any "assessment tentative or otherwise", with regard to costs, profits and effect on man-power. He did, however say that introduction of mechanisation or automation at least for the initial years was not going to bring any profits and was going to increase costs.

100. Dr. Damle of the Reserve Bank had no doubt read the project report but had not studied it closely. He only formed his general opinion in that behalf and said that this project report programme is "more in tune with Indian banks' programme of computerisation than in line with foreign banks." This proposed automation policy, though on a U.K. pattern, is on a lower level of sophistication and according to Dr. Damle "will not lead to total automation. It will only expedite the work and improve management control systems." He enumerated the areas in the banking business on the basis of his general apprisal which have been left out of consideration by the project and also opined that according to the Reserve Bank standards, there is no likelihood of "displacement in the operation of the project plan of the Grindlays Bank for mechanisation." In his view, the plan has to be adopted in its entirely and not piecemeal, though its operation can be in phases. Though he agreed that the problems and facts of mechanisation in each bank would differ from bank to bank, so far as the project plan formulated by the Grindlays Bank was concerned, it was said that "broadly this project plan is correct for mechanisation purposes." He also stated that he acts as a consultant not only for the banking companies, but also for non-banking companies for their computerisation plans and for opinions thereon.

101. On the other hand, contrary to Dr. Damle's cross-examination, which was general in nature, Chaudhary was subjected to closer cross-examination on specific aspects of the project report. At the outset, he admitted that the project report is an outline and its full impact can be known only after its implementation. During the course of the implementation, the plan may require to be improved as well as formulated in more details. These include, he stated, systems specification, systems design, the writing of programmes, the testing of programmes and system capabilities, the clerical procedure and conversion and implementation steps." Then alone, a full result, impact and picture in terms of costs, impact on man-power, etc, would be known. The plan was, he admited, larger in size than the City Bank's plans, as the City Bank has not more branches while Grindlays Bank had, but is less sophisticated than the City Bank or the Honk Kong Bank. The report he says was made in accordance with the "business needs of the Bank and the services it renders to the customers" and not for reduction in staff or increase thereof. The project report, however, covered all the operations carried out by the workmen staff.

102. It was Chaudhary's contention and claim that even after automation manual jobs will continue, such as "preparation of input material, checking of input material, operating the machines, checking the output, distributing the output and using the output." But large amount of record keeping will disappear and ledgers would not be maintained mentally. The form of the manual work at present undertaken will change and different series of jobs involving different skills and experience would arise. There would thus be displacement of some of the manual jobs giving rise to some new jobs. For instance, the present plans do not, he admitted "envisage even with complete automation dispensation of manual handling of cash, such as paying in and paying out." Automatic cash handling is a very highly sophisticated system.

103. The project plan worked out by him is broadly speaking one where a mini-computer at the branch and a main computer at the head office will function. At a particular branch whether a mini-computer or a terminal only should be installed will be decided on the basis of volume of transaction, complexity of business and prospect of growth. So far as Programmers and Analysts are concerned, according to him, it can be decided after the programme is put into operation and tested and experience acquired. As also, the project team, after the completion of the project report, would not be completely disbanded, but some of them would be deployed wholly, while others would be continued to work in the same sphere or kind of activity, such as data processors, data communication supervisors and hard-ware engineers. He even felt that their strength may be increased. According to him, it is not possible for him to specify how many manual jobs will still remain, after the implementation of automation plan, as that will depend upon the final development of programmes and procedures.

104. Chaudhuri in his cross-examination stated frankly that though the present practice and procedure was adequate for the present, it "can not cope up with the bank's requirements in future, the bank's customers' needs, the growing competition in the business and future anticipated business developments and environmental changes in the banking industry." He refuted the suggestion that the bank's policy and restrictions "on the deposit mobilisation and stricker conditions for lending money has brought down the bank's business share." These restrictions on deposit mobilisation are those which I have earlier referred to above, such as larger amount for opening balance, restrictions on checking facilities, minimum amount to be deposited or kept in an account and minimum deposit. Though he agreed that a larger net work of bran hes brings in a larger share of deposits, the growth in the deposits was not directly proportional to the number of branches. According to him, notwithstanding "regulation of interest rate on deposits, the Bank expects to increase its business, as in such a market service becomes more important." Therefore, the Bank can increase "its customer service efficiency and the range of the products for the customer," and there by attract more business His reason was that in such a controlled market it is "service" which becomes more important.

105. The bank, in his words "hopes to increase its share in the market by improving the quality and range of the products it will offer to its customers and by using its resources of branch net work and man-power to give a batter service than what the competitors offer" even with all the banks being automated. He denied that overall automation will not improve service or that computerisation will not help in improving export-import trade. It was his hope that it will bring in larger international trade to India. He also refuted the suggestion that "the urgency for automation is felt on account of the volatile nature of the international exchange market." and that the bank needs "this automation and hook up with the head office for greater facility of speculative exchange transactions."

106. He further denied that the computerisation and hook up with the head office was desired for "quicker transfer of information with regard to import-export trade and inward-outward remittances." According to him, this was necessary for all transactions including deposit mobilisation, import export transactions, credit and lending situations and decisions. Earlier he had described the foreign exchange transactions which can arise in three forms, such as import and export trade, inward and out-ward remittances and buying and selling of foreign exchange. It was this last part of the foreign exchange transactions which was sought to be assailed as a speculative activity intended to bring in larger profits for the London head office and not for any benefit to the Indian activities of the bank.

107. I had questioned Chaudhary with regard to certain specific aspects of computerisation and projections if any made by him. He stated that as a consequence "there would be an immediate increase in the standards of timeliness of services rendered to customers, the range of services offered, and improvement in the quality of work that is received from the bank's staff. There is also a great likely improvement in the amount of information that is available both to the bank and to the customers," which is likely to result in cost benefit to the customer. There will be a higher level of service to the customer, though the immediate cost benefit to the bank may not be there. Though he said it was possible to make a forecast in specific areas, the direction or the benefit or effect is not possible to be spelt out exactly. As far as profits were concerned, he did not expect any increase and may be, on the other hand, they would dip initially. But after, 2-3 years, his projection was that "the existing cost plus the additional cost on account of automation will start being repaid.". He could not say, however, when the break-even-point would be reached, but said that the volume of business would start growing and would reach an appreciable stage in a period of 2-3 years. That the staff would require training and qualitative change. His personal experience was that in countries where automation was introduced, such as Pakistan, Sri Lanka and African Middle East, there was a 7 per cent drop in the staff strength on a global basis between 1981 and 1983. In Grindlays in India, he admitted that there has been a 7 per cent reduction in staff strength between 1981 and 1983 even without automation.

108. He had not made any quantitative forecast on the staff strength or automation, as according to him, it was not possible to be done. The project report, however, in annexure 6.1.1 had indicated requirement of the organisation or development team which would be necessary for putting the project into practice. The project report in para 5.4 says that the two systems, namely, manual and automated, will run simultaneously. In para 6.1, the report contemplated that a comprehensive organisation to manage the computerisation project and the continuing development and maintenance of computer systems would be established initially, which will progressively increase and reach the full complement, as contemplated in annexure 6.1.1, in about 5-6 years. That it will "substantially carry on after the main project is completed and then the current organisation pattern will undergo a material change" in the business. Consequentially, the project report in para 7.1 says that some current jobs will cease to exist, while others will remain while their content varies, and several new job positions will be created. The content of all jobs will be considerably enhenced and personnel needs of the bank would change considerably.

109. As an organisational plan and projected man-power requirements and changes skill-wise, capacity wise as well as in terms of numbers are given to some extent in paragraphs 7.1, 7.2 and 7.3. The projection made by him to put it in his own words is as follows, "during the next 4 to 5 years, we will undertake a massive exercise of retraining existing personnel and additionally replace a portion of the natural exists, as and when required, by recruitment as we will not be able to meet our needs entirely from the manpower and skills available."....."We do not see the scope for and neither will there be any retrenchment or adverse effect on the terms and conditions of our employees"..... "new jobs will be offered to exsting staff and filled up by further recruitment only if existing staff are either incapable of manning these positions or unavailable. On the basis of the available man-power and requirements, Chaudhary came to the conclusion that there is an "awkward age profile" of the staff. Therefore a number of persons will leave the organisation within a few years of receiving training in the new systems and procedures, but the bank will have to adjust and make do with it, which might result in keeping a larger number of persons on the pay-roll than the actual needs.

110. To sum up therefore and to adopt the new technical phrases and language, there is a positive discernible and directional trend towards automation and computerisation in the banking industry consequent to the historical efforts of various study-groups and committees, the Government of India's policy direction, the Reserve Bank's need and adoption of Rangarajan Committee's report and recommendations. A revolution brings about considerable changes in a society, its structure, ideology, outlook, value and parctices. If the industrial revolution made a departure from agrarian society, standards, values, economy and concepts, the modern technological revolution has greatly over-run them. A new social structure, a new set of idology, a new pattern of values has emerged, and on that account and on account of fast and overwhelming technological revolution in various spheres of economic, social and international activities seems to be regulating our life and ordering it. The instruments and tools which were known before and which had served their purpose and time are completely outdated and can not match the high demands of science and technology, which is outstripping itself by leaps and bounds within a matter of years. The pace of industrial revolution was comparatively much slower. The pace of technological revolution which is overtaking the modern world is galloping. Its flood is not likely to wait for those who remain behind and may well sub-merge them. The switch over to the modern technology in various industries, a new breed of industries and producers, adoption of modern technology in international trade and availability of speedy, and instantaneous communication has further shrank the world. There is such an inter-action between industry, economy and products, that it is not possible to that think in terms of broad devisions. This revolution has also reached our country and it should be visualised and accepted by the financial institutions, the Government and the people. Coming to the more specific areas, if its (computerisation) automation) need and requirement is felt in the banking world and industry which operates as a lubricant for the industry

economy and the society, it can not remain aloof from the changes which are rapidly taking place around it. If there can be any accusation, the accusation is that it is not fast enough. The Rangarajan Committee's recommendations as well as what was sought by the Reserve Bank, as stated by Dr. Damle, is not what could be achieved and possible on full automation, but only within the boundaries laid down by the 1983 settlement and other considerations. That clearly shows that the banking industry as such, controlled by the Reserve Bank is inevitably marching towards greater automation, computerisation, where it did not exist at all, armed by the 1983 settlement which itself is a progress and a step above mechanisation contemplated in the 1966 settlement. If this trend is to be ignored and if this change which is coming over and has been accepted and considered as a necessary policy requirement, to talk of existence of justificate or otherwise would be simply to close ones eyes and ears to what is happening around. This leaving aside what is happening in the world of foreign Indian banks, to oppose mechanisation and to say that it is not justified beyond the 1966 level to that which is accepted in 1983 by a large majority of banks would be in a sense suffocating the bank and thwarting its growth, and leading it ultimately out of existence. There is, therefore, undoubtedly, a potential and future challenge and prospect of competation of the Indian nationalised banks, as also an immediate threat from friendly competing foreign banks. Even if the justification, therefore does not intrinsically exist, it does exist extrinsically. I do not think also there is any merit in the contention that there would be no cost benefit or rendering of efficient, accurate and speedy customer service on automation.

111. One more contention which was raised on behalf of the Federation is that the claim of the bank is hollow in the matter of saving of costs and cheaper service to the customers. That this benefit would be available to all the automated banks. The Grindlays Bank can not therefore hope and expect to improve its performance and market share, where interest on deposit and advances are controlled in the internal market and the opportunity for making profits is limited and kept within bounds. The benefit of mechanisation, if any in the matter of reducing cost of services will arise in favour of all the banks and not Grindlays alone. That can not, therefore, help the bank, it was urged, to increase its profit or attract more customers. This contention clearly ignores the fact and reality of life. It is not unknown that in service industries, even where near similar circumstances exist, one or the other of them prospers and does better in than the others. For instance, where fares are controlled, like in the case of airlines, even then some airlines make more money and attract more customers. Taking even ordinary instances of catering houses and hotels, some are preferred even for the same kind of food and fare, may be because of service rendered in such places and the atmosphere or surrounding is better than the other. It is the kind, nature and quality of services in a service industry which makes the difference between one service and another, and determines and induces customer preference. It would not therefore, be right entirely to say and contend that in a controlled service industry where units are situated in the same circumstances and the benefits are fixed, there is little choice between one unit and the other for the customers. Or that the units are unlikely to benefit and attract customers as most of the factors determining the cost of service are common and uniform. It seems to me that even then where the Customer has a choice and right of preference to choose one unit to the other, he will choose that unit the service rendered by which is better, speedier, accurate and reliable. This may be even if the charges are more than the other. It is, therefore, quite possible and within the realm of probability that customers having preference will exercise that preference and liberty in favour of better services resulting therefrom larger business to the concerned unit.

112. As against all the evidence adduced by the bank subsequent to the order dated 12th March, 1985, namely the project report dated 15th March, 1985 prepared by Chaudhary and evidence of Dr. Damle and Chaudhary, neither the Association nor the Federation examined any witness or produced any documents. They stated that they do not want to lead any eviedence, which right they had on issue No. 3. Whatever therefore is stated by Dr. Damle and Chaudhary which has not been disproved in the cross-examination stands uncontroverted.

113. The General Secretary of the Federation during his cross-examination stated that "in the present realities of the Bank's affairs, this (benefits to the customer) is of material The cost to the customor will not be less". According to him, service charges will not be reduced and claims that they have been increased after mechanisation, as matter of fact. However, there is no such evidence that they have been increased or that the increased in the cost has been notwithstanding mechanisation and the other cost-input factors remaining the same. He expressed his ignorance and want of knowledge or information as regards computerisation in the Bank of India's Princess Street clearing house, new foreign banks being entirely computerised, and the Union Bank having computerised Savings Bank department at Veer Nariman Road. He denied also that in the case of foreign exchange transactions, interest is calculated in three tiers and method is different. I do not think that Mr. Subramanyam is right in this contention, as the method of calculating such interest in the case of foreign exchange transactions has been more convincingly deposed to by Chaudhary. The stages of transaction would be in the case of import (1) payment in rupee currency at the rates of conversion in the concerned currency when the payment is made, (2) Remittance of the currency to the exporting country and (3) Payment to the exporter in that currency. There is an inevitable time-lag where that is done by the ordinary process of communication and through post. Advices take time to reach either the exporter or the importer. Exchange rates vary from day to day and rapidly, so that from the time the advice is received and the proceeds actually realised, there is a time-lag on all parts of which interest has to be calculated. In the reverse way the same procedure will have to be followed in the case of exports. The advantage of immediate communication on the other hand is that credit and debit are instantaneous and there is a reduced loss on account of fluctuations in foreign exchange rates.

114. Mr. Subramaniyam's principal contention as stayed by him during his evidence is that mechanisation will not benefit the customer by way of cheaper service as interest rates are controlled by the Reserve Bank on borrowings as well as deposits. There is, therefore, no margin so far as fixation of rates are concerned. It is also his say that non-mechanised services would not be slower compared to mechanised with relation to the foreign based bank customer.

115. It was also not attempted to be shown that either the recommendations of Rangarajan Committee or the project report made by Chaudhary go beyond the scope or permissible limits of automation under the September, 1983 settlement. The projected automation, as per Chaudhary's report is also not shown to be beyond the recommendations of Rangarajan Committee. Dr. Damle has already stated that the Rangarajan Committee recommendations do not specifically govern the foreign Indian banks and they are free to go even beyond the recommendations in the matter of automation and computerisation. They can do so by a settlement with the respective unions as has been done in the case of Chartered Bank, Mercantile Bank and City Bank (Ex-B-19 to 21) Dr Damle also stated that the Rangarajan Committee's recommendations, which statement has not been controverted, have been made within the frame-work of the September, 1983 settlement. He stated "so far as Reserve Bank's guidance and directions to the Indian Banks is concerned, it is within that frame work (8th September, 1983 settlement)." I have therefore no hesitation in concluding that there is scope for further mechanisation and indeed it is imperative for the bank to extend mechanisation to automation and computerisation as envisaged and contemplated by the Rangarajan Committee's recommendations and the 8th September, 1983 settlement. The conditions under which this can be done will follow. As regards the extent of automation, I have already indicated above and that extent can also be said to be to the extent of the plan/project report made by Chaudhary

116. I will briefly refer to the documents produced by the Federation in the matter of mechanisation. At one stage during the hearing of the reference, there was a controversy between the parties as to whether the bank in violation of the 1966 settlement was using a computer for its business during the pendency of the reference. On the past of the

bank, it was contended that what was used was not a computer, but a micro-processor or a mini-computer and secondly, whether it was used for banking business or for management information systems as contended by the bank. In view of my overall findings on the question of mechanisation, it is not necessary to deal with this contention. It is also not necessary to refer, as I have already pointed out, that the stages of mechanisation and the status thereof in the different branches of the bank varied and was different during different periods. That again, I am of the view has become irrelevant in the light of my conclusions on the question of mechanisation. An issue of Dataquest for November, 1984 was also produced. That was particularly for the cross-examination of witness Mr. Sawant, the Bank's officer who was sought as witness in this case. The attempt probably was to show that the bank is planning to computerise even before the award in this case was given. Incidentally, this issue shows various stages and plans of different banks with regard to computerisation. This includes foreign Indian banks and Indian banks such as Bank of India, Canara Bank, State Bank of India, Syndicate Bank, and bank of Maharashtra. Particular reference was not made to the material in these write ups, but it can be said from what is set out, that most of the Indian banks which figured in this issue are planning to go automated.

117. It is also not necessary to refer to the various statements filed by the parties in view of the finding and statement that Grindlays Bank should be considered alongwith the foreign Indian banks and the comparative position of that bank and other foreign Indian banks. I may mention that in the context of the evidence and the form which the controversy took subsequent to March, 1985, a number of documents produced by the Federation as well as by the bank have become irrelevant. They had not been referred to also during the course of arguments, such as extracts from various reports on automation and mechanisation statements filed and extraced from Reserve Bank publication in regard to the priorities for advances by scheduled banks for various years, income expenditure and profit of the scheduled banks for various years, distribution of commercial banks in India and foreign exchange operation systems and instructions. It is also not necessary to look to the documents produced by the bank, such as schedule of service charges and various banks in the world with which Grindlays Bank has correspondence, accounts of representation.

118. Coming now to the conditions, I have already pointed out the differential in the 1966 and 1983 settlements and the conditions imposed. Those conditions in the 1983 settlement are no retrenchment, displacement to be at the minimum and in this case displacement has been further given a dimension meaning that displacement shall not take effect outside the town or the city. It also stipulates "maintenance of the present staff strength and inflow of the staff strength commeasurate with the expansion of the banking industry." That obviously means that the present staff strength shall be maintained, and that with the expansion of the banking business, there shall be inflow of staff commensurate with that expansion. It is not possible to predict in what proportion the staff should be increased with the growth in the banking business of the individual bank. That will be more or less a managerial function and it would be wrong to prescribe any percentage, though the proportion, as at present existing between the business of the bank and the staff strength should as far as possible be maintained. The bank has, however stated with reference to this growth and inflow of staff that it has to be on an industry basis and not on he basis of the individual bank. In other words, it was attemped to be suggested that if there is a proportional inflow of staff generally in the industry, no matter which bank is benefitting on account of mechanisation or otherwise and enjoys growth, that would be enough compliance. It also produced a document in support of this contention signed by the representatives of the Indian Banks Association as well as the unions. That is a sort of clarification issued under the signatures of these three people. Whatever may have, however, been the intention either in the clarification or in the terms of the settlement, itself, since I have the right to impose conditions in the present reference and the duty to do so, I direct that inflow of staff shall not be considered on the basis of the entire industry, but the Grindlays Bank in particular. In other words, it shall have to be in the proportion as far as possible, suggested by me above, proportional to the growth and increase in the bank's business.

119. The bank voluntarily and on a query by me submitted the conditions to which it was agreeable as contemplated in issue No. 3. It stated on 8th July, 1985 that "there will be no retrenchment, that "displacement of workmen, i.e. deployment beyond or outside their centre, as a result of full automation as asked for, will not be made except with the consent of the workmen concerned." This however can be permitted though by the settlement, that is not allowed. The workmen will be allotted only such jobs as will be related to such cadres and new jobs attracting special allowance will be first offered to the existing staff. Fresh requirement would be made only if the existing workmen staff are incapable or unsuitable of manning those positions or are not available. It also offered to pay to the workmen, if the project plan in its entirety, was allowed to, be Emplemented, benefits covered by item No. 1 "progressively in parity with the mean prevailing from time-to-time in the main foreign banks." I do not think that that can be put generally as a condition and I shall deal with this aspect covered by issue No. 1 separately.

120. The conditions, therefore, which I direct, shall be followed by the bank, when it implements the project plan, are as under :—

(1) That there shall be no retrenchment from workmen staff.

(2) Present staff strength, namely of workmen staff or award staff, shall be guantumwise retained and its strength frozen. That does not however mean that at any given point of time, it shall not be allowed to go down. That is clearly not practically possible, but there should not be non-filling of vacancies in the present staff strength.

(3) The workmen (award staff) should not be transferred as a result of being rendered surplus or unavailable for the new available jobs out of the town or city, except with their consent.

(4) New jobs should be offered firstly to the staff centre-wise and area-wise preferably in the first instance. Such jobs may be made available to others, if the necessary number of applicants from he centre are not forthcoming. As to what should be the quantum of additional allowance in case of new jobs, shall as far as possible be mutually decided between the union and the bank and failing agreement between the concerned workmen and the bank, and where such allowace is not covered by the awards in existence in banking industry by arbitration or adjudication.

(5) The bank shall not, where there is no competing foreign banks at its branches at Amritsar, Bangalore, Darjeeling, Gauhati, Hyderabad, Kanpur, Simla, Srinagar and Tuticorin, as far as possible, unless it affects the project plan of the bank automate there small branches. The bank may however, instead have them hooked on to a computer at other places, if necessary, and use only a terminal at these branches.

(6) The bank should introduce and consider the feasibility of introducing a voluntary scheme for retirement by the workmen who choose not to take up the new jobs which are offered and for which the bank considers them as incapable or unsuitable. Such a scheme should, as far as possible be devised with the consensus of the unions representing the workmen.

121. What remained now to consider is the demands in connection with item No. 1. That related to the employees' demand for increase in quantum of additional allowance, lunch allowance, canteen subsidy and housing loan. In case it is found that the employees are entitled to increase, then the date from which and the extent to which they would be so entitled, has also to be specified and determined.

122. This question, as pointed out earlier, lost much of its edge and the bank during the arguments, having switched over to the position that foreign Indian banks should be treated as a class even amongst he A class banks in India. That being so, and since the bank did not dispute its paying capacity, the more relevant question which arose was with regard to parity of conditions of comparison between these foreign Indian banks and the Grindlays Bank. It was pointed out for

the Grindlays bank that in three banks, the City Bank, Mercantile Bank and Chartered Bank, there have been settlements entered into in 1982 and 1983 which give almost a carte branches and far-reaching powers even over and above the September, 1983 settlement to these banks to go in for automation|computerisation. Those settlements are produced at Exhibits-B-19 to 21. This contention of the bank is no doubt apparent from the settlements, which are produced. It is not disputed that such settlements were entered into. Amongst the foreign Indian banks, it would also be clear that leaving aside the Grindlays Bank, these banks are also close to Grindlays in terms of resources and capacity. It is true that they do not have as many number of branches as Grindlays has in India and their operations are confined more or less to the metropolitan areas. As I shall presently point out from the comparative table filed in this case, service conditions in these three banks compared with those in Grindlays appear to be more or less similar. Though that is so, the bank is not right in contending that just as in the three banks, certain monetary benefits were conferred upon the employees as quite pro quo and as a consideration for the employees agreeing to allow the bank to mechanise and automate as it thought fit in its operation, the same should be done in their case. Any benefits it was said, if they are to be conferred upon the Grindlays employees, they must be in consideration of such benefit, which these three banks have received from their employees. It was contended that that was necessary in order that there should be a parity in working conditions for these three banks and Grindlays Bank in the banking field.

123. The contention overlooks a factual and historical aspect of the matter. There is no evidence as to what was the level of mechanisation and status of automation in these and other foreign Indian banks between the years 1970 and 1985. It is common ground that what is being paid in the Grindlays Bank with regard to these allowances has remained static since the year 1970. The dispute in this connection started in the year 1975 and particularly, as I have pointed out in part-I award in this matter, after the convention passed resolution directing its secretariat to take steps to seek a revision of the "expired settlements". I have already dealt with that aspect of the matter. It will therefore be safe to take 1975 as the year of commencement of the dispute and for consideration as to what should be or what should have been the level of these allowances and benefits in the Grindlays Bank as compared to the other banks. Fortunately, a comprehensive comparative table has been filed by the Federation at Exhibit F-25, Sl. Nos. 1 to 4. It would be convenient to take the demands under each head, namely, additional allowance, lunch allowance, canteen subsidy and housing loan separately for these periods.

Additional Allowance

The comparative table for additional allowance is at sl. No. 1, pages 1-4. A statement was made during the hearing of the reference that in all these foreign banks, wages are uniform, including the Grindlays Bank. A comparative statement or table showing emoluments paid by different foreign banks to clerical and subordinate staff has also been filed by the Federation and that is at Exhibit F-25 (sl. Nos. 7 and 8).

Coming to the Additional allowance, if we see the comparative table showing what was the amount of additional allowance being paid in the different foreign banks between the years 1970 to 1983, it will be seen that this additional allowance stood frozen at Rs. 1100 in Grindlays Bank since 1970, while in other banks, it has undergone a change between 1975 and 1983 in two stages broadly. The first stage of revision may be taken as in the year 1978 and the second in 1980 and 1981. Thus the additional allowance was revised upward in Chartered Bank firstly in the year 1978 to Rs. 1,500 from Rs. 1,100 and secondly in the year 1980 to Rs. 1,800. From 1971 to 1978, it was at the level of Rs. 1,100 similar to the Grindlays Bank, in the Chartered Bank. In Mercantile Bank, similarly, additional allowance was Rs. 1,100 from 1971 to 1978 and it was revised upwards to Rs. 1,900 in the year 1978. In the British Bank of the Middle East, the additional allowance was raised to Rs. 1,700 from Rs. 1,100 in the year 1973. In French Bank, it was raised to a maximum of Rs. 1,900 in 1978, and it had two tiers at 11 per cent and 14 per cent between the slabs of gross income between Rs. 1,001 to Rs. 10,000 and Rs. 10,001 and above. In American Express also, similarly it was in two stages, but the maximum was Rs. 1,100 per year. It continued till 1981 when the maximum was raised to Rs. 1,900. But the percentage continued to remain the same. In the Dutch Bank or Algemene Bank Nederland N.V., in 1974 its maximum was Rs. 1,200 and in 1978 it was raised to Rs. 1,500 and again raised in 1983 to a maximum of Rs. 2,000 per year. In the Bank of Tokyo, maximum additional allowance paid was Rs. 1,200 in 1973, while it was raised to Rs. 1,900 in 1981. In the City Bank, which is the other comparable bank, it was Rs. 1,000 in the year 1972 and was raised in 1980 to a maximum of Rs. 1,800 for clerks and Rs. 1,400 for sub-staff and again raised to Rs. 1,900 for clerks and Rs. 1,450 for sub-staff in the year 1983. A more unique feature of this additional allowance in the City Bank is that it is paid to all employees whether they pay income-tax or not. It will thus be seen that the pattern with regard to additional allowance appears to be that there is a two stage revision between the years 1975 and 1983 or we may take now 1985. That is once in 1978 and for a second time, which has continued even upto now is in 1980 and 1981, I am inclined to take the year 1978, i.e. with effect from 1-4-1978 and the year 1981, i.e. w.e.f. 1-4-1981, as the years of change. The quantum of additional allowance has not been uniform. At the first stage, i.e. in the year 1978, it has ranged at 11 per cent or Rs. 650 at the minimum to Rs. 1,500 at the maximum, to those probably paying income-tax. Even in the Grindlays Bank, it was stated during the course of the evidence in the reference that additional allowance is paid only to tax payers as per Finance Act, and not the actual amount of tax paid by them. The same pattern and system of working should continue and accordingly additional allowance at the maximum level should be paid at Rs. 1,500 by the bank. From the year 1981 i.e. w.e.f. 14-1-1981, it should be paid at the rate of Rs. 1,900 at the maximum, in the same manner in which it is being paid at present in the bank. It will be seen from the comparative table that in some banks, it is less than Rs. 1,900, while in others it is more than Rs. 1,900 and in others it is Rs. 1,900. In Chartered Bank. It is less, in Hongkong Bank it is the same, while in Dutch Bank it is Rs. 2,000 i.e. more. All these are on account of settlements and it must not be foregotten that in settlements, there is a measure of give and take. By and large Rs. 1,900 appears to be reasonable and common figure from the year 1981, while the figure of Rs. 1,500 appears to be more or less consistent and reasonable from 1978. Generally, I have followed the pattern prevailing in Chartered Bank.

Lunch Allowance

The next item is Lunch Allowance. In Grindlays Bank, this has stayed at the level of Rs. 50 per month right from the year 1970. Once again, this has been revised upwards in most of the foreign banks at various stages between 1971 and 1983. In Chartered Bank, there has been a revision almost every year and in the last settlement, there is a graded revision for 1982, 83, 84 and 1985. In the Mercantile Bank, there is also similar revision in 1974, 1979 and 1982. In American Express it was revised in 1974 and 1981. In Dutch Bank in 1978 and 1983 and in City Bank in 1978, 1979 and 1983, there were revisions of Lunch Allowance. Most of these revisions took place on the expiry of the earlier settlements. In Grindlays Bank, there does not seem to have been any settlement in respect of this matter from 1975, presumably as the matter has been through various stages of conciliation, dispute and reference. Here again, though, as I have pointed out, revision has been different in different banks and at different times, I will adopt the years 1978 and 1981 as the years of change. In this, it is true that the workmen would suffer to some extent, as in Chartered Bank there was a revision in 1975 and again in 1977. But as I pointed out, no uniform pattern, except that the lunch allowance is going up from time to time, emerges, as to what it should be. The maximum lunch allowance paid by these banks has also varied from Rs. 145 in 1983 or 1982 to Rs. 200 and Rs. 220 in 1985. Once again all these changes, as I have pointed earlier were consequent to the revision of settlements and have been as specially stated by way of package deals Fixation of lunch allowance, therefore is difficult and some amount of ad-hocism is bound to enter therein. I would therefore fix the lunch allowance at Rs. 80 in 1978 and Rs. 150 in 1982. Having said that I will prefer to follow the pattern of Chartered Bank, it is less according to what was agreed by the Chatered Bank in 1978, but more than what was agreed to by that bank in 1982.

Canteen Subsidy

With regard to canteen subsidy, the entire material and evidence is not before me with regard to other banks. So far as Grindlays Bank is concerned, canteen subsidy is available at four branches.

It is contended by the bank that the bank gives in addition several other facilities such as payment of electricity bills, utensils, free supply of gas and furniture. There is no evidence whether in other banks, these facilities are available. In the compilation furnished at Exhibit F-25, Sl. No. 3, pages 8 and 9, this has not been brought out. It may be mentioned that out of 10 banks listed, seven are not giving any subsidy. In these banks, daily tea or coffee is given twice to the employees, which appears to be a normal rule. In Grindlays Bank, it is paid at Rs. 6 per employee. Where the canteen subsidy is given, in Chartered Bank, it was raised to Rs. 14 in 1980, from Rs. 12 in 1977. Now it is given at the rate of Rs. 30 per employee. In the Mercantile Bank it is Rs. 12 from 1974. The pattern which I have adopted for additional allowance and lunch allowance, namely, a revision in 1978 and 1981, for reasons of uniformity and in the absence of any specific reason to revise it in a particular year, I think, should be followed also for canteen subsidy, which I direct should be revised and paid at the rate of Rs. 12 from 1978 and at the rate of Rs. 18 from 1981. I have not followed in this case the pattern of Chartered Bank which pays at Rs. 30 from 1983, as that settlement is linked with the settlement regarding complete automation.

Housing Loan

As regards the housing loan, the pattern of revision is not the same as in the case of other allowances. The revision has come about in the year 1980 and what has appeared in the case of other banks as low has reached the same level, as was reached by other banks in the year 1980. The Chartered Bank raised the limit to Rs. 70,000 and Rs. 60,000 in 1980. The Mercantile Bank raised it to Rs. 60,000 for clerks and Rs. 30,000 for sub-staff, in 1979. It was raised to Rs. 75,000 for clerks and Rs. 45,000 for sub-staff in American Express to Rs. 80,000 for clerks and Rs. 40,000 for sub-staff in Bank of Tokyo. Indian banks on the other hand also provide about the same amount of housing loan, maximum being Rs. 75,000 for clerks and Rs. 25,000 for sub-staff In Canara Bank in 1980, Rs. 35,000 for employees drawing below Rs. 1,200 and Rs. 60,000 for employees drawing above Rs. 1200 in Bank of India in 1981, Rs. 60,000 for clerks and Rs. 35,000 for sub-staff in Bank of Baroda in 1979, Rs. 75,000 for clerks and Rs. 35,000 for sub-staff in 1979 in Dena Bank In Reserve Bank since 1978, housing loan is subject to a minimum of Rs. 60,000 and a maximum of Rs. 72,000. The rates of interest, however varied in the Indian banks and the present interest rate seems to be at 5 per cent. The interest rate in Chartered Bank is 2 per cent. I would therefore, direct that housing loan should be granted by the bank from 1980 at the rate of Rs. 70,000 and Rs. 40,000 from 1st April, 1980. Those who have already been granted loan would be entitled to have it revised subject to the maximum, deducting of course, the amount of loan already received by them so far. The loan will also carry interest at 3 per cent from the year of advance under the revised formula.

The bank will pay arrears claimable on account of these allowances, namely, additional allowance, lunch allowance and canteen subsidy from the years of revision directed.

Award accordingly.

R. D. TULPULE, Presiding Officer

[No. L-12025/65/79-D.II(A)/D.IV(A)]

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1985

का.आ. 5474—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लि. के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5 नवम्बर, 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 22nd November, 1985

S.O. 5474.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the Hindustan Commercial Bank Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th November, 1985.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL KANPUR.

Reference No. L-12012/202/80.D-II(A) dt. 20-4-81

Industrial Dispute No.: 60 of 1981

In the matter of dispute between:

Shri V. N. Dhavan Clerk Hindusutan Commercial Bank, Kidwai Nagar Kanpur.

AND

The Chairman Hindustan Commercial Bank Limited Head Office 26/104 Birhana Road, Kanpur.

APPEARANCE:

For the management.—Shri B. G. Agrawal.

For the workman.—Shri V. N. Sekhari.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No.:-12012/202/80.D.II(A) dated 20th April, 1981, has referred the following dispute for adjudication:

Whether the action of the management of Hindustan Commercial Bank Limited, Kanpur, is justified? (a) in depriving Shri V. N. Dhavan from the opportunity of officiate as a special assistant at Kidwai Nagar Branch, Kanpur of the bank and (b) in absorbing and confirming Shri V. N. Dhawan with effect from 11-5-70 without giving any benefit of his past service? If not, to what relief is the workman concerned entitled?

2. The case of the workman is that he joined the management bank at Kidwai Nagar Branch Kanpur on 25-4-67 as senior most clerk. The workman was entitled to be given officiating chance and opportunity to work as special assistant and is entitled to officiating allowance as the only senior clerk Shri J. B. Gupta was debarred from promotions on account of his refusal to act on promotion and further as Shri B. K. Singhal who was officiating and getting the officiating allowance as special assistant has been transferred to Head Office on 7-1-80, hence he was not entitled to claim officiating allowance with retrospective effect alongwith compensation for the period. It is further averred that the workman on being appointed on 25-4-77 completed more than 250 days during the first year of his service upto 24-4-68 with notional breaks. He worked for more than 746 days untill 11-5-70, when he was taken on probation and was confirmed in regular service by the management bank. As workman worked on regular and permanent seats but was designated temporary typist cum clerk to avoid confirmation and consequently benefits in regular cadre. He also completed 248 days in each calender year 1967, 68, 69 and 70 with notional breaks. That those breaks were illegal retrenchment and void under the Industrial Dispute Act. The management despite representations made by the workman did not give him benefits legitimately accruing, hence the applicant is entitle to confirmation after completion of six months service from 25-4-1967, with consequential benefits.

3. The management in its reply raised preliminary issue that the Government has unjustifiably laid the burden of proof on the management when it should have been on the workman. That he having not paid rest in dispute during the period he was temporary between 1967 to 1970, he is stopped from raising any dispute at this late stage and consequently the dispute is barred by principal of Estoppel

and Acquiscence that giving of officiating chance is purely managerial function and hence could not be made a subject matter of Industrial Dispute and that the reference order suffers from misjoinder of issues.

4. According to the management, the workman was appointed as clerk-cum-typist on 11-5-70 at the head office of the management bank at Kanpur and later was transferred to Kidwai Nagar Branch of the management bank. The management had admitted that workman worked as temporary employee at various branches of the bank against purely temporary vacancies and that the workman had never completed 240 days in one spell nor worked on any permanent nature's post. The workman was for the first time given permanent appointment on probation on 11-5-70, hence his seniority has to be determined from that day only. Further it would be wrong to say that Shri V. N. Dhawan concerned workman in this case was the senior most temporary clerk. There were other employees senior to him one of whom Shri V. K. Agnihotri who was given permanent appointment on 27-1-70 and as such the workman was not entitled to get officiating allowance in preference to Shri V. K. Agnihotri. The workman was appointed on temporary basis from time to time to work in a post of purely temporary nature and he never worked on any regular and permanent post prior to 11-5-70.

5. In the rejoinder the workman averred that he worked in various branches of the bank till 22-5-70 on which date he was given a letter of probation as typist-cum-clerk w.e.f. 11-5-70 and that the workman having joined on 25-4-67 i.e. earlier to joining by Shri V. K. Agnihotri at Kidwai Nagar Branch Kanpur was the senior most clerk. In the rejoinder the workman has further averred that the bank had violated the provisions of Sec. 25F & G of the ID Act and para 20.7 and 20.8 of the Bipartite Settlement.

6. The management has not specifically denied that the workman Shri V. N. Dhawan joined the management bank on 25-4-67. According to the management he worked on regular and permanent seats but only on leave vacancies or when exigency of work required. The management has filed circular No. 4 dated 4-2-71 which supercedes head office circular No. 206/59 dt. 24th October, 1959. First condition laid down in that is that the promotion to permanent vacancies in the special assistant cadre will be on the basis of seniority and only those employees would be considered who had put in eight years uninterrupted service with four years service as a clerk. Para 7 of the said circular lays down temporary vacancies of special assistants at a branch necessitated due to leave or transfer orders or delay in the posting of a permanent special assistant from elsewhere, which are not likely to last more than four months, may be filled in on the basis of seniority from amongst the existing staff at the branch subject to his being considered suitable otherwise. The management has filed the seniority list of clerks in UP eligible for posting as special assistant as on 30-6-75, the name of the workman in that list appears at serial No. 84. It appears that this seniority list is based reckoning his appointment on 11-5-70. The management has further filed the memo of particulars of the workman at the time of his appointment on 11-5-70. It is signed by the workman. The management has also filed the memorandum of particulars of V. K. Agnihotri which shows that he joined the bank on 27-1-70. The management has also filed the statement showing intermittant period during which the workman had worked before appointment on probation. According to this the workman started work from 10-5-69 in the management bank branch at Padrauna where he worked for 226 days and subsequently worked of and on mainly at Kanpur in main office most on road branch Latouch Road Branch and at the Head Office at Birhana Road Kanpur, and according to which he had not completed 240 days till then.

7. On the other hand the workman has also filed the banks circular No. 4 dated 4-2-71 which has been filed by the management also. In this it is specifically mentioned that seniority will mean month of service as from the date of appointment of an employee in the service of the bank. The workman has filed certificate of the management's La touch Road branch dated 29-8-79 showing that Shri V. N. Dhawan temporary clerk was paid salary for the period 25-4-67 to 20-5-67 i.e. for 26 days. The workman at present working as permanent staff at Kidwai Nagar, branch of the management bank in Kanpur. As per document filed by the workman it is not established that he worked for 240 days in any span of year reckoning from 24-4-67 till his permanent absorption in the bank. He was however, paid bonus for the years 68 and 69 for number of days which are much less than 240 days. The chart of working days filed by the workman as paper No. 23 shows that he completed more than 250 days in the period 25-4-67 to 24-4-68 and according to the chart 23-M the workman worked for 603½ days from 25-4-67 to 31-5-70. The workman has filed circular no. 206|59 dated 24-10-59 which was effective till it was superceded by circular no. 4 dated 4-2-71. It laid down that general principle be followed for appointment as Head Cashiers and supervisors. According to this circular temporary appointments necessitiated by leave or transfer order or delay in appointment of permanent incumbent likely to lost no longer to three months economical arranagements without regard to area-wise seniority was to be made. Selection was to be made as far as possible from the branch itself but if a suitable man is not available the real selection from a neighbouring branch will be made. In the case of appointments, other than the temporary appointmeint will be made and there would be basis of seniority inter se and to determine the service length in the management was to be seen.

8. In support of its case the management filed the affidavit of Shri Rakesh Singhal. In cross examination he has stated that he has no knowledge that Shri V. N. Dhawan workman and V. K. Agnihotri entered in the bank. He later admitted that V. N. Dhawan came in the bank in the year 1967 as temporary employee but he has no idea about the temporary employment of Shri V. K. Agnihotri. He further stated that with all the best of his knowledge temporary appointment period is not considered for giving seniority for permanent persons.

9. On the other hand the workman has given his affidavit that from 25-4-67 he worked for 832 days before his permanent appointment. It may be mentioned here that in the chart paper no. 23-M supplied by him the number of working days have been shown as 603-1|2. The workman has admitted that he has no document of certification of all the number of working days he claims to have worked in the bank mentioned in document no. 23N and that prior to this case he did not file any other case earlier. For working in different branches he admits that there were verbal orders in 1980 when there was a question of officiation he came to know that one Shri V. K. Agnihotri was shown senior to him. He has further admitted that Shri V. K. Agnihotri was given probation prior to him. From this admission it is clear that Shri V. K. Agnihotri being given permanent appointment earlier was shown senior to him in the list. He further admits that he did not claim continuity of service when he was given probation in 1970 but claimed it only in the year 1979. He further admitted that he did not complete 90 days in any branch prior to his confirmation.

10. Shri V. K. Agnihotri was confirmed earlier to the workman he was rightly shown senior to the workman in the seniority list filed by the management and the management was justified in depriving the workman from opportunity to officiate as special assistant at Kidwai Nagar, Branch, Kanpur. As per confirmation date Shri V. K. Agnihotri was senior to the workman.

11. Though the workman has not been able to substantiate by documentery cogent evidence that he worked for 240 days in any year prior to his permanent appointment in May 1970 even with breaks, yet taking it in consideration for the sake of argument the same will not give him a right of benefit of past services rendered, that may utmost lead to holding the termination after completion of 240 days in one span of year without retrenchment compensation being voiod ab initio he would be entitled to reinstatement as temporary with back wages. Even such long standing temporary services will not give the workman a right to be employed permanent with benefits of his temporary services.

12. The workman has filed copy of agreement 23-B which provides for certain advance increments to be given at the time of permanent appointment considering past long standing temporary services of the workman i.e. effective from

8-5-78 and the present case is not covered by that as the workman was confirmed in the year 1970.

13. The workman has referred me the ruling Harimohan Rastogi Versus Labour Court 1983 Lab IC page 1906 S.C. This ruling does not apply as the workman has failed to substantiate that he worked for 240 days in any calender year with the management, hence there is no question of working out monetary benefits. On that very count the very ruling cited by the workman Gommen India Limited Versus Niranjan Das 1983 Lab IC page 1865, also does not apply to the facts of the present case.

14. The other ruling cited on behalf of the workman is Suresh Circar Versus Food Corporation of India, 1984 Lab IC page 267 Bombay High Court and Jaswant Sugar Mills Versus Badri Prasad 1961 ILLJ page 649 S.C. will also not apply to the facts of the present case as the workman failed to substantiate that he was appointed on a work of permanent nature throughout the year and not on leave vacancy on occasional and casual basis as alleged by the management.

15. There is no question of estoppel against the workman for not having raised the dispute earlier. The question of estoppel being rule of conduct cannot be availed unless it is shown that on account of workmans conduct management altered situations and rights of the parties.

16. There is no evidence that Shri V. K. Agnihotri was appointed as temporary later to workman. Admittedly temporary service of workman was broken for several times. Even if the workman was entitled for reinstatement in view of law laid down in Surendra Kumar Verma and others Versus C.G.I.T New Delhi 1981 (I) LLJ page 386, the period from the date of retrenchment to the date of reinstatement will not be taken into count for the purposes of reckoning seniority of the workman amongst temporary employees. In the case of State Bank of India Vs. Sunder Money, 1976 I LLJ page 478, it was observed that he will not be allowed to claim any advantage in the matter of seniority or other priority inter se amongst the temporary employees.

17. Thus in any view of the matter the workman was being not senior to Shri V. K. Agnihotri was not entitle for opportunity to officiate as special assistant at Kidwai Nagar Branch of the management.

18. Now coming to the question of giving benefits of past services. I fail to understand how the temporary services rendered could be counted while giving permanent appointment on probation. No law has been cited to give that benefit to the workman. My attention has been drawn to an award of Central Government Industrial Tribunal Jabalpur, dated 2nd June 78 wherein it was observed that giving break in temporary service of workman having worked for more than 240 days in 12 months of employment without payment of retrenchment compensation would render termination illegal and he will be deemed to be in continuous service. If such a man is given permanent appointment the temporary services projects and continues further into the permanent service and the increments already earned or those increment which he should have earned during the temporary employment shall not stand forfieted on being appointed in a permanent capacity. In the end it was further observed thus "but where the temporary services continuous and projects into the permanent one as said above the increment earned during the course of temporary service shall survive in the benign shadow of continuity of temporary service into the permanent service. This principal of relating back can be deducted from the provision and for the purposes of confirmation the period of probation shall be adjusted towards temporary services." I do not agree with the reasoning given by the Learned Judge. No doubt under para 20-8 of the Bipartite settlement a temporary workman may be appointed to fill a permanent vacancy. If such a temporary workman is eventually selected for filling vacancy the period of such temporary employment will be taken into account as part of his probation period. The emphasis is on the word eventually selected which is the right of the management based onset rules and principles. It is open to the management at the time when a workman temporarily is eventually selected to say that the periods of three months or six months served by him will be taken into account as part of probationary period and he is given confirmed appointment from the very first date i.e. the date when the workman entered in the bank first time temporarily.

19. On the other hand the management has drawn my attention to another award of the Central Government Industrial Tribunal of Jabalpur dated 22nd October, 84. In that award he confers with my reasoning and has held that the workman is not entitled to any such inclusion of the period rendered by him earlier to his appointment as a probationary nor any advantage of the service done prior to his appointment as probationer.

20. I accordingly hold that the action of the management was justified in depriving Shri V. N. Dhawan from the opportunity to officiate as a special assistant at Kidwai Nagar Branch, Kanpur of the bank and in absorbing Shri V. N. Dhawan and confirming him w.e.f. 11-5-70 without giving him any benefit of his past services.

21. The result is that the workman is not entitled to any relief as claimed.

Let six copies of this award be sent to the Government for publication.

Dated : 31-10-85

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer
[No. L-12012|202|80-D.II(A)|D.IV(A)]
K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1985

का. आ. 5475 :—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (न) के उप-खण्ड (vi) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का. आ. 2251, दिनांक 13 मई, 1985 द्वारा किसी भी खनिज तेल (कच्चा तेल) मोटर और विमानन स्पिरिट, डीजल तेल, मिट्टी का तेल, ईंधन तेल, विविध हाइड्रोजन तेल और उनके मिश्रण, जिनमें सिन्थेटिक ईंधन, स्नेहक तेल और इसी प्रकार के तेल शामिल हैं, के निर्माण या उत्पादन में लगे उद्योग में सेवाओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 20 मई, 1985 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (न) के उप-खण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 20 नवम्बर, 1985 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[संख्या एस-11017/2/84-डी-1 (ए)]
श. ह. सु. अय्यर, अवर सचिव

New Delhi, the 18th November, 1985

S.O. 5475.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 2251 dated the 13th May, 1985 the industry engaged in the manufacture or production of mineral oil (crude oil), motor and aviation spirit, diesel oil, kerosene oil, fuel oil, diversh hydrocarbon oils and their blends including synthetic fuels lubricating oils and the like, to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months, from the 20th May, 1985 ;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 20th November, 1985.

[No. S-11017/2/84-D. I (A)]
S. H. S. IYER Under Secy.

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1985

का.आ. 5475 —लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम 16 और नियम 3 के उपनियम (2) के साथ पठित लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 61) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उड़ीसा राज्य के लिए एक सलाहकार समिति गठित करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

1. मंत्री श्रम और रोजगार, उड़ीसा ।	अध्यक्ष
2. कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण संगठन, विवेकानन्द मार्ग, भुवनेश्वर–2 (उड़ीसा)	उपाध्यक्ष (पदेन)
3. प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) श्रम मंत्रालय, भुवनेश्वर ।	सदस्य (पदेन)
4. श्री पूर्ण चन्द्र महानन्द, विधान सभा सदस्य, तितिलागढ़, उड़ीसा	सदस्य
5. श्री पी.एन. पटनायक, खान मालिक, मुकाम और डाकघर जोदा, जिला–क्योंझर, उड़ीसा	नियोजकों के प्रतिनिधि
6. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उड़ीसा खनिज निगम लिमिटेड, मुकाम और डाकघर बारबिल, जिला क्योंझर, उड़ीसा	नियोजकों के प्रतिनिधि
7. श्री डी.सी. मोहन्ती, अध्यक्ष, क्योंझर खान व श्रमिक यूनियन, मुकाम और डाकघर बारबिल, जिला–क्योंझर, उड़ीसा ।	कर्मचारियों के प्रतिनिधि
8. श्री बी.एस. पाती, जनरल सेक्रेटरी, नार्थ उड़ीसा वर्कर्स यूनियन, मुकाम और डाकघर-बारबिल, जिला क्योंझर, उड़ीसा	कर्मचारियों के प्रतिनिधि
9. श्रीमती बेलारानी दत्ता	महिला प्रतिनिधि
10. कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण संगठन, बारबिल उड़ीसा ।	सचिव

2. उक्त सलाहकार समिति का मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा ।

[संख्या–यू–19012/14/84–कल्याण–2डब्ल्यू ए० (सी)]
रवि दत्तात्रेय, अवर सचिव

New Delhi, the 20th November, 1985

S.O. 5476.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 (61 of 1976), read with sub-rule (2) of rule 3 and 16 of the Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund Rules, 1978, the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee for the State of Orissa consisting of the following members namely :—

1. Minister, Labour & Employment, Orissa.	Chairman
2. Welfare Commissioner, Labour Welfare Organisation, Vivekanand Marg, Bhubaneshwar-2 (Orissa)	Vice-Chairman ex-officio
3. Regional Labour Commissioner (Central) Ministry of Labour, Bhubaneshwar.	Member ex-officio
4. Shri Purna Chandra Mahananda, Member Legislative Assembly, Titilagarh, Orissa.	Member
5. Shri P.N. Patnaik, Mines Owner, At/P.O. Joda, District Keonjhar, Orissa.	Employers' representative
6. Regional Manager, Orissa Mineral Corporation, Limited, At/P.O. Barbil, District Keonjhar, Orissa.	Employers' representative
7. Shri D.C. Mohanty, President Keonjhar Mines, and Forest Workers Union, At/P.O. Barbil, District Keonjhar, Orissa.	Employees' representatives
8. Shri B.S. Pati, General Secretary, North Orissa Workers Union, At/P.O. Barbil, District Keonjhar, Orissa.	
9. Smt. Belarani Dutta	Women representative
10. Welfare Administrator, Labour Welfare Organisation, Barbil, Orissa.	Secretary

2. The headquarter of the Advisory Committee shall be at Bhubaneshwar.

[No-U-19012/14/84-W-II/WA(C)]
R.D. MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1985

का.आ. 5477—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, धोबा बैंक, पालनपुर, के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2, बम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-11-85 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 5477.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Dena Bank, Palanpur and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th November, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/45 of 1985

PARTIES :

Employers in Relation to the Management of Dena Bank, Palanpur

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the Employers : Shri S. B. Turkhud, Advocate.
For the Workman : Shri A. K. Clerk, Advocate.

INDUSTRY : Banking STATE : Gujarat

Bombay, dated the 3rd October, 1985

AWARD

By their order No. L-12012/66/83-D. II(A) dated 21-5-1985 the following dispute has been referred for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 :—

"(i) Whether Shri S. H. Raval is entitled to be absorbed in the service of the Dena Bank on the basis of his selection made in the year 1978, and

(ii) Whether Shri S. H. Raval was wrongfully put out of service with effect from 9th January, 1980 and he is entitled to be reinstated with full back wages ?"

2. It seems that initially the Government was not inclined to make a reference but as directed by the High Court the reference came to be made and although the order seems to have been reviewed, because already a reference was made, it remained. There is a reference in the order No. L-12012/66/83-D. II(A) dated 5-9-1985 that under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act the disputes has already been referred for adjudication.

3. The facts are not much in dispute. Where there is a dispute the reference would be specifically made. The workman concerned namely Shri S.H. Raval was born on 15-3-1953 and from 31-3-1971 till 9-1-1980 he had put in 350 days of service in short spell some even for a day or so, at various branches of Dena Bank. By application dated 1-10-1976 the Bank says he submitted the application on 25-2-1977, the workman applied for absorption in the service of the Bank as a peon stating his date of birth as 15-3-1953 annexure 'B' to the statement of claim. By annexure 'C' the workman was called for interview on 17-6-1978 informing him that a waiting list of the selected candidates would be prepared and as and when necessary appointment would be made. At the same time it was also made clear that by entering the name in the waiting list the Bank is not going to guarantee for service. Under annexure D dated 25-10-1978 the workman was informed of the selection and was called upon to produce his passport size photograph, School leaving certificate, Character certificate, educational qualification certificate of character from relatives, and certificate showing whether he belongs to SC or ST, ex-serviceman's certificate etc. The case of the workman is that he was called for medical examination on 9-11-1978 and was declared fit and from the Zerox copy of letter of appointment dated 13-12-1979, S. No. 2, along with the list of documents filed by the Bank dated 24-9-1985 we find that he was appointed from 12-12-1979 till 9-1-1980 at total emoluments of Rs. 412.96.

4. Non-absorption of the workman in the service subsequent to 9-1-1980 has given rise to the present reference.

5. It is the contention of the Bank that the workman was overaged in the sense he had already crossed 25 years of age on the date of his appointment and he could not be absorbed in the service. Against this the workman has quoted certain instances in the statement of claim where two Driver-cum-Sepoy though overage came to be appointed namely S/Shri G. M. Rathod and P. N. Bahari and there is also instance of Shri A. S. Bhaviya but it was explained that he belonged to SC Category and therefore no comparison with his case is possible. The workman has also in para 10 given four instance where again on completion of 25 years of age certain appointments in the category of sub-staff came to be made. The Bank tried to explain that they were made in certain circumstances but the fact remained that atleast in the case of some of the candidates overage had not come in their path.

6. Further more one fact is certain that on the day when the workman preferred his application dated 25-2-1977, assuming that the date furnished by the Bank is correct he had not crossed 25 years of age. If therefore subsequently some time was taken for processing the application, for interview, for medical examination etc. the workman cannot be blamed, he who was then within the prescribed age limit, because some time was required subsequently cannot be deprived of the post. The Bank has produced along with the list dated 24-9-1985 two certificate from Branch Manager and Regional Manager vindicating the stand of the workman that he deserved to be absorbed in the service and there are also other certificates, one of which being of Taluka Vikas authority certifying the workman to be fit for service. When the workman was within the age limit on the date of application and when he has stated the same in the applicant and had not concealed it from the bank authority and knowing the date he was selected and also had been appointed during a particular period, the Bank will not be allowed to turn around subsequently and say that the workman was over-age, particularly when the very Bank in the case of some others condoned the defect and had allowed the concerned workmen to join service of sub-staff category.

7. In the conciliation proceeding which took place before the Assistant Labour Commissioner (C) Ahmedabad on 1-12-1982 the Bank had agreed to include the names of such candidates who conform to the Bank's norms as to age, qualification etc. The agreement before the Conciliation Officer is as follows :—

"Conciliation proceedings were resumed and the management agreed to include the names of such candidates those who conform to the bank's norms as to age, qualifications etc. for recruitment to subordinate staff at the time of their initial entry in the Bank as Badli Sepoy and who have completed the service of 90 days on or before 15-2-82 and further agreed to include names of these Badli Sepoys who were in employment on 15-2-82 and have complted 90 days of service subsequently till 30-11-82. These Badli Sepoys as above will be called for interview alongwith candidates sponsored by Employment Exchange for absorption and empanaling their names as Badli Sepoys against future openings. To this the Union agreed.

8. Now we have seen that till 9-1-1980 the workman had put in 350 days of service. It was contended that during this period there is no spell for 90 days continuous service but a plain reading of the agreement before the Conciliation Officer does not warrant such a restriction of 90 days continuous service but only speaks of completion of 90 days service on or before 15-2-1982 and insertion of "continuous service" therefore seems to be an after thought. Since we have already seen as on 15-2-1982 the workman had already completed 350 days of service though no continuously, we have also seen that in the interview he was found fit and was selected and also certified to be fit by the Medical Board and therefore when he was conforming to all the requirements, when as already held he was not overage when he appplied and his initial entry in the Bank's service was in the year 1971 the agreement must prevail and atleast from 1-12-1982 when Conciliation agreement was entered into the workman should have been absorbed in the service.

9. It is not a case where the service came to an end on 9-1-1980 even though there was vacancy nor it is found that there was any other vacancy. Had there been proof of vacancy then certainly the non-appointment or non-absorption would have amounted to Unfair Labour Practice yet for the reasons already stated as and when somebody was appointed in the sub-staff category it was incumbent upon the Bank to appoint the workman in that post.

10. The relief therefore the workman gets is that the workman should be deemed to have been absorbed in the service of the Bank in the sub-staff category from 1-12-1982 and he shall be entitled to arrears of back wages from the said date.

11. For these reasons my findings on the issues are :—

ISSUES	FINDINGS
1. Whether the termination of services of the workman on 9-1-1980 amounts to unfair labour practice?	No
2. Was the said termination wrongfully done?	No proof of continuance of vacancy.
3. Was the workman entitled to be absorbed in the service of the Bank?	Yes
4. If yes is the termination valid and legal	He should have been absorbed from 1-12-1982.
5. If not is the workman entitled to reinstatement with back wages?	Arrears from 1-12-1982 and reinstatement.
6. If not is he entitled to re-employment?	Question of re-employment does not arise.
7. Is the action of the Bank justified?	No
8. What award?	As per Award.

Award accordingly.

M.A. DESHPANDE, Presiding Officer

[No. L-12012/66/83-D.II(A)]

का. आ 5478.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, यूनियन बैंक आफ इंडिया, लखनऊ, के प्रबंधतंत्र से सहबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-11-85 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 5478.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Union Bank of India, Lucknow and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th November, 1985.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Reference No. L-120121/1/81-D.II (A) dated 19-12-81

Reference No. L-12012/33/81-D.II(A) dt. 30-1-82.

Industrial Dispute Nos. 194/81 and 100/83

In the matter of dispute

BETWEEN

Shri P. N. Shukla, Shri K. K. Bajpai both C/ Shri Harmangal Prasad, 36/1 Kailash Mandir, Kanpur.

AND

The Assistant General Manager, Union Bank of India, Hotel Clarks Awadh, Lucknow.

APPEARANCE .

Shri Harmangal Prasad—for the workmen.

Shri Satpal—for the management.

AWARD

1. The Central Government vide its notification no. L-12012/1/81-D.II(A) dated 19-12-81 has referred the following dispute to this tribunal for adjudication:

> Whether the action of the management of Union Bank of India in debarring Shri P. N. Shukla Special Assistant from promotion for three years with effect *from 14-8-80 is justified ? If not, to what relief is* the workman concerned entitled?

Further the Central Government vide its notification no. L-12012/33/81-/D.II(A) dated 30-1-82 has referred the following dispute for adjudication:

> Whether the action of the management of Union Bank of India Lucknow in debarring Shri K. K. Bajpai Assistant Special from promotion for three years is justified? If not to what relief is the concerned workman entitled?"

2. On the request of the parties the above noted two industrial disputes were consolidated and I.D. No. 194/81 which was to be leading case.

3. The two cases related to debarring the workmen of the two references from being posted as special assistant for a period of three years . Both the parties filed their respective claims and documents. The management gave affidavit evidence of Shri S. L. Verma but the workman's representative never appeared to cross examine the witness.

4. These cases have been registered in Delhi Tribunal on 28-12-81 and was received in this tribunal on 17-7-84. After several dates for rejoinder workman filed the same on 31-10-84 and the management gave his affidavit evidence on 10-3-85. On 9-5-85, the workman representative stated that he had no instruction to proceed with the case withdrew his authority thus there was no one to cross examine the management witness who was present. The management witness after that appeared on 5 dates but cross examination was not done by the workman through representative.

5. The management witness has testified in his affidavit and filed photo copy of the order showing that Shri K. K. Bajpai was offered temporary officiation as Officer Grade II (Junior management grade scale I) at Sarvodaya Nagar Branch vide memorandum dated 12th September, 1980. Since Mr. Bajpai immediately refused to carry out the temporary officiation issued to him he was debarred for further officiation/promotion for period of three years. Similarly Shri P N. Shukla was deputed to officiate as officer grade II temporarily by the Regional Manager and was relieved on that count on 12th August, 1980. The branch manager sought to serve the memorandum to the workman which he refused to accept on which count the Zonal Manager ordered that since the workman has refused to carry out the temporary officiation he is debarred for further three years.

6. There being no evidence against these averments of the management which is bore out from the document it can not be said that the order was illegal.

7. I therefore, give my award against the workman Shri P. N. Shukla holding exparte that the action of the management of Union Bank of India in debarring Shri P. N. Shukla Special Assistant from promotion for three years with effect from 14-8-80 is justified. The result is that the workman is not entitled to any relief as claimed.

8. Further in the case of Shri K. K. Baipai, I give my award holding that the action of the management of Union Bank of India Lucknow in debarring Shri K. K. Baipai Special Assistant from promotion for three years is justified and the result is that the workman is not entitled to any relief as claimed.

9. I, therefore, give my award accordingly.

10. Let a copy of this award be kept on the record of Industrial Disputes No. 100/83

10. Let six copies of this award be sent to the Government for publication.

Date : 4-10-85

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-12012/33/81-D.II(A)]

का. आ. 5479.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक, चंडीगढ़ के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चंडीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-11-85 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 5479.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India, Chandigarh and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th November, 1985.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH

Case No.I.D. 76/80 (Delhi); 41 of 1984 (CHD)

PARTIES :

Employers in relation to the management of State Bank of India

AND

Their workman, Shri Birbal Verma.

APPEARANCES :

For the Management—S/Shri H. C. Dhall and V. K. Gupta.

For the Workman—None.

ACTIVITY : Banking STATE : Haryana

AWARD

Dated the 29th October, 1985

1. The Central Government, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, hereinafter referred to as the Act, per their Order No. L-12012/34/79-D.II.A dated the 29th of July, 1980 read with S.O. No. S-11925(9)/84-D. IV(B) dated the 6th of October, 1984, referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication:—

"Whether the action of the management of State Bank of India in relation to their Bhiwani branch in Chandigarh region in discharging from service Shri Birbal Verma, Clerk with effect from June 30, 1970 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. To trace a short history of the matter, the petitioner Birbal Verma was posted in the clerical cadre at the Bhiwani Branch of the Respdt. Bank during the years, 1974-75, As a part of his duty he used to handle "Advances". The Branch Manager received complaints against his work and conduct to the effect (i) that he had received certain amount of illegal gratification from one of the Bank client named Daya Kishan Verma in connection with the grant of an 'advance' to him, (ii) that he had received an amount of Rs. 300 from one of his neighbour Khillu Ram Taneja, who had an Account with the Bank, for the purpose of depositing in his credit but instead of doing so the petitioner misappropriated the same; A number of similar complaints from other "Borrowers" were also received. In view thereof the Branch Manager advised him to mend his ways but instead of seeing reason, he misbehaved towards the Branch Manager and also started absenting himself from duty without moving any leave application. It further transpired that the petitioner was misusing his position as a Bank employee and drawing private loans from some of the Account holders who had business dealings with the Bank through his 'Counter'.

3. As the petitioner failed to behave, therefore, the Branch Manager reported him to the Regional Manager who happened to be his Appointing Authority. It was against such back drop that the formal charge sheet dated 1-2-1975 was issued to the petitioner on the following counts :—

"It is proposed to proceed against you in terms of paragraph 521 of the Shastri Award read with paragraph 18 of Desai Award on the basis of the following articles of charges.

1. It has been alleged by one Daya Kishan Verma, Subhash Gali, Bhiwani that you had accepted a sum of Rs. 610 as illegal gratification and misused your position as public servant, while you were working on the seat dealing with advance. This act of your amounts to breach of trust.

2. Shri Khilu Ram Taneja C/o M/s. Taneja Stores, Railway Road, Bhiwani has also complained in writing that a sum of Rs. 300 handed over to you by him for depositing in his account has neither been deposited in their account nor the amount has been returned to them. This act of you amount to breach of trust.

3. Nine other borrowers, mostly cloth vendors, financed under the scheme of Differential Interest Rates have also complained that you have not deposited some instalments handed over to you, in their account. Sixteen (16) receipts/counterfoils which have been handed over to them by you as per their statement have not been Accounted for, in the Bank's record. The counterfoils bear "Paid by Transfer' stamps as well as cash stamps of our Hissar Branch which is an incident of cheating and defrauding both the borrowers as well as the Bank. This act of your amounts to breach of trust.

4. You misbehaved with the Branch Manager by taking possession of letter from his table, which has not, been returned despite a Memorandum served on you on the 18th March, 1974. The said letter also contained certain allegation against you regarding misappropriation of a sum of Rs. 300. This act of yours amounts to insubordination and indiscipline.

5. Further, we also understand that you have borrowed certain amounts from various persons having dealings with the bank, thus infringing the rules governing your service rules.

6. Despite instructions issued to you vide memo dated 4-10-74 you are not desisting from the habit of absenting yourself from the Bank, you have been absenting without application on the 1st January and then on the 8th and 9th January, 1975. This act of your amounts to gross misconduct."

4. Controverting the allegations against him the petitioner replied that he was being maligned by the Branch Manager due to personal vendetta otherwise he had no occasion to raise any private loan from any of Bank's customer, that he never received any money from any Account-holder for depositing to their credit and that the allegation of taking illegal gratification from Daya Kishan Verma was simply outrageous. Similarly he denied having misbehaved with the Branch Manager and explained that his absence from the Bank on 1st, 8th and 9th January, 1975 was duly authorised.

5. The Regional Manager was not satisfied with the petitioner's reply and so he appointed one of his Staff Officer, Shri Nath Mal, as the Inquiry Officer vide order dated 8th June, 1975. Shri Nath Mal conducted the departmental inquiry in which the petitioner also participated alongwith his representatives Shri A. L. Airi and K. K. Bindlish, the Management was represented by the concerned Branch Manager, Shri V. B. Katyal.

6. The management produced 6 witnesses including the aforesaid Daya Kishan Verma from whom the petitioner was alleged to have extracted an illegal gratification of Rs. 610 in a matter concerning the grant of "advance"; besides it, the management also produced 16 Counter foils alleged to have been issued by the petitioner to 9 of the Borrowers showing the repayment of their instalments to him which he did not account for to the Bank. In rebuttal the petitioner examined himself and filed certain Newspaper cuttings high lighting his sincerity to the Bank customers.

7. On concluding with his proceedings, the Inquiry Officer held the petitioner guilty on 1st and 3rd charges but exonerated him of charges No. 2 and 4 on giving him the benefit of doubt. Regarding charge No. 5 no specific finding was given even though one particular instance of raising a private loan from Miss G. L. Sword appeared to be believable. All the same the Inquiry Officer did not condemn the petitioner on this count and passed on with the observation that the petitioner should have avoided it. Similarly even though the petitioner was found to be absent from duty on 1st, 8th and 9th January, 1975 yet no serious view was taken against him because of his subsequent leave applications, and it goes without saying that the leave was due to his credit.

8. Thus holding the petitioner guilty on charges No. 1 and 3 the Inquiry Officer Shri Nath Mal submitted his report dated 22-3-1976 to the Disciplinary Authority i.e. the Regional Manager. In his turn the latter issued a show cause notice dated 15-5-76 to the petitioner revealing "inter-alia" that he was satisfied with the propriety and validity of the inquiry proceedings and proposed to terminate his services on account of adverse findings against him on the aforesaid charges No 1 and 3.

9. The petitioner's reply did not find favour with the Disciplinary Authority and so under hte impugned order dated 16-6-76 his services were terminated. Feeling aggrieved, he raised an industrial dispute through his Union because according to him the inquiry proceedings were not fairly conducted. But the management was found unresponsive despite the intervention of the A.L.C.(C) at the Conciliation stage and hence the Reference.

10. Resisting the proceedings on all counts the Management asserted to the validity of the departmental (domestic) inquiry for the obvious reason because according to him the same was conducted in a very free, fair and equitable manner in which the petitioner had duly participated and availed of the full opportunity not only for demolishing the charges against him but also to project his own defence.

1. The parties were put to trial on the following issues framed by my learned predecessor :—

1. Whether the inquiry is vitiated as alleged? O.P.P.

1(A) Whether the reference is not maintainable for want of filing of appeal by the workman against order of termination to the appellate autority? O.P.P.

2. As in order of reference.

12. In support of his case the petitioner filed his affidavit and then, for the reasons better known to him, disassociated himself from the proceedings. Time and again notices were served on the Union espousing his cause but even they played hide and seek with the Tribunal in the sense that they tried to drag it in unnecessary correspondance for fixing up the dates and venue of the sitting to their choice but still played truant despite the acceptance of heir prayer. In view there of the petitioner was proceeded exparte under Orders dated 10-9-1985. As against this the management filed the affidavit of their representing officer V. B. Katyal and placed on record the original file containing the departmental proceedings.

13. On a careful scrutiny of the entire available data and hearing the Ld. Representative of Management I am inclined to believe that thein was no irregularity, impropriety or illegality in the conduct of the departmental proceedings. On the other hand it stands established that the same were gone through in an open and free atmosphere with due regard to the principles of equity, fair play and natural justice; every sort of opportunity was given to the petitioner to defend himself, and he actually availed of the chance by his full participation with the representatives of his choice. He cross-examined the witnesses examined by the management and also examined himself to deny the charges.

14. It hardly requires any emphasis that a Tribunal sitting as such in the reference proceedings under the Act does not function as a Court of Appeal even though it has to satisfy itself that the findings of the Inquiry Officer are based on some plausible evidence and abide by the well accepted equitable norms of procedure; and it goes without saying that on such touch stone the impunged inquiry proceedings deserve full credence. At the risk of repetition it may be pointed out that the petitioner was found guilty only on two Counts contained in Charges No. 1 and 3; where as rest of the Inquiry Officer without any positive finding on either the charges were either held not proved or left midway by side. And so far as the established charges are concerned they were supported by the first hand version of Daya Kishan Verma and the 16 counter foils produced by the "Borrowers" bearing his signatures to which he had no plausible explanation. In the same sequence it may also be mentioned that during the Inquiry proceeding the petitioner could not impeach the credibility of Daya Kishan Verma, Khillu Ram Taneja; Lekh Ram, and B. P. Sharma all of whom specifically pinpointed his guilt.

15. It is against this back drop that the wilful and deliberate avoidance of the Tribunal proceedings by the petitioner and his Union assumes a significance of its own. After all it was he who could be the best person to project his grievance rightly or wrongly against the conduct of the inquiry proceedings. But for no explicable reason he avaded the acid test or cross-examination on stepping into the witness box; and no amount of wild allegation against any senior officer would cut much ice.

16. I, therefore answer issue No. 1 against the petitioner. And in my considered opinion it knocks out the very bottom of his case, though for the purpose of records I would like to expose the fallacy of management's contention that the Tribunal lacked jurisdication in entertaining the reference for want of regular service appeal by him. In the same sequence it may also be mentioned that since the petitioner was found guilty of monetary deflections including extortion of bribe from one of the Bank customers, therefore, noindulgence could possibly be shown to him in the matter of punishment by virtue of section 11A of the Act.

17. Thus for the reasons recorded above on sustaining the management's action I return my award against the petitioner.

Chandigarh.

Dated : 29-10-1985

I. P. VASISHTH, Presiding Officer

[No. L-12012/34/79-D. II (A)]

का. आ. 5480.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-11-85 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 5480.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India Lucknow and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th November, 1985.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Reference No. I-12012/129/83-D.II(A) dt. 14th December, 1983

Industrial Dispute No. 250/1983

In the matter of dispute

BETWEEN

Shri Shiv Shanker C/o N. C. Pande, C-323 Guruteg Bahadur Nagar, Kareli Housing Scheme, Allahabad

AND

The Regional Manager, Region II Commercial Exchange Building State Bank of India, 24, Mahatma Gandhi Marg, P.B. No. 125, Lucknow.

APPEARANCE :

Shri Mangalvadhekar representative—for the workman & Shri S. C. Upreti—for the workman

Shri Mahesh Chandra representative—for the management.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour vide its Notification No. L-12012/129/83-D.II(A) dt. 14th December, 1983 has referred the following dispute for adjudication :

Whether the action of the management of State Bank of India, Lucknow in relation to their Pariyawan Branch in not absorbing Shri Shiv Shanker, Sub-Staff in Bank's service and terminating his services with effect from 14-1-81 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?

It is common ground that the workman was engaged by the management Pariyawan branch District Pratapgarh on 25-7-80, the day when the branch was opened and was terminated on 15-1-1981 as no longer required. According to the management he was engaged as temporary messenger for purely temporary requirement and engaged for various periods from 25-7-80 to 14-1-81 thus the total number of working days comes to 89 days. After termination of the workman the bank appointed other persons namely Sarvashri K. P. Mishra, Sita Ram and Parmanand. The branch manager was changing the faces only with a view that no employee could claim any benefits as per award or settlement which is highly irregular and unfair labour practice . That the provisions of paras 495/522(4) (5) of the Sastri Award were not complied i.e. neither appointment letter nor any termination letter was given nor 14 days notice sent by the manager to the workman. Provision of section 25-H of the I.D Act has also not been complied with.

3. The management has contested the claim of the workman that the reference is invalid as no demand or claim was put up before the management. It is further contended that para 495/522 (4) (5) of the Sastri Award are neither mandatory nor violative thereof could effect the validity of their services, and the present proceedings under section 2-A of the I.D. Act is not competent.

4. Section 2-A of the I.D. Act is applicable whenever any employee discharges, dismisses, retrenches or otherwise terminates the service of an individual workman, thus by what ever means the services of the workman were brought to an end the case is covered under section 2-A of the I.D. Act and the reference is competent. It is true that the management is free to employ temporary workman as a sub staff or clerk according to the requirements of the management bank. Though for permanent absorption the rules might be different and in that case some provisions of constitution also may come into play. Just as any employer according to exigency of work employ temporary hand they have right to terminate the services when their services are no more required. In industries there are certain limitations with the employer to deal with their employees as given in the industrial dispute act.

As observed in Sunder Money case decided in 1976 according to which termination for any reason whatsoever will amount to retrenchment and for that special provisions have been given in chapter VA Section 25-G of the said chapter if termination of any workman becomes necessary it is the last person employed in the gradation list who is to be retrenched.

6. Section 25-H gives another right to such retrenched persons to be re-employed when exigency of the similar work arises which the other workman are doing. The management in reply to the queries raised in the joint inspection informed per paper no. 421 dated 22-4-85 that Shiv Shanker was paid for the work done on 1-10-80, second October, being national holiday, one Kamla Prasad Mishra was paid for 29 days from 3rd October, to 31st October. They have further informed that prior to 1st October, the workman had worked on 25th and 3rd August, 1980 total for 7 days. They further admitted that the workman worked as temporary messenger from 19th, 20th September, 80 and 21st and 24th September, 80 and for those six days he was paid at the rate of 245 per month whereas Shri Kamla Prasad Mishra worked as temporary messenger from 1st September to 18th September and from 22nd September to 26th September and for work of 23 days he was paid Rs. 425 per month and allowances. Shri Shiv Shanker workman has deposed in his cross examination that no other subordinate staff beside him was appointed at the opening day at Parivawan branch. He stated that Shri Parmanand Pandey and Sita Ram were appointed after his termination and one Shri K. P Mishra was also given work later but none of them were working now. From joint inspection report filed by the parties it is established that from 1-8-80 to 6-8-80, the workman worked for 9 days and was paid for those days at the rate of Rs. 5 per day but in the affidavit filed by the management witness Shri Naval Kishore this period is not mentioned. From the joint inspection it is also clear that the workman worked for 19 days in that month and was paid total Rs. 114 at the rate of Rs. 6 per day. In October, 80 the management admits that the workman worked only for 31st October, 80, but from the joint inspection report it emerges that in the month of October, 80 he worked for 23 days and was paid Rs 138 at the rate of Rs. 6 per day. In the month of November and December, 80 he worked for the entire month and was paid full salary and allowances He was paid for six days in the month of September for work done on 19 and 20 and again on 27 to 30th September, 80. Thus in the month of September, 80, the workman worked for total 25 days when the management has not admitted in its affidavit that the workman worked in the bank as sub staff.

Thus according to these payments made to the workman he worked for 118 days and not for 89 days as alleged by the management. The workman has in his affidavit has averred that he worked as messenger at the management bank at Pariyawan branch district Pratapgarh for total 174 days. Though for the period of 89 days the workman was paid full wages and for the remaining periods he was paid as daily wages labour and that after the termination of the workman the management appointed Sarvashri Sitaram and Parmanand and Shri K. P. Mishra as messenger one after another. If the vacancies was there after termination of workman u/s 25G, he should have been re-employed under section 25H. The management did not give workman a chance to work before employing any of the persons mentioned above as messenger as required under rule 78 of the I.D. (Central Rules). The workman has averred that prior to his appointment at Pariyawan branch he had worked as messenger from 15-10-79 to 24-4-80 at Kunda Branch and it was on account of his past experiences that he was appointed as messenger at Pariyawan Branch of the management bank. If there was anything untowards against the workman, the management should have come forward with the same in writing stating reasons for his termination and not reemploying him.

7. The workman has filed circular No. 329|80 which show that the branch manager have been given a limit of 90 days for which they could make temporary appointments and in case exigency of work required they too make casual or temporary appointment either prior approval should be competent. The workman has further filed circular staff 183/84 which lays down that engagement of casual labour was required for work of casual nature only. It may be mentioned that work of a Messenger in a newly opened bank is not a work of casual nature but is a work of regular permanent nature. If according to the instruction of the head office, the workman was to be retained for temporary work for 90 days he should have been shown their number of days as casual labour and his services terminated much earlier before he completed 90 days. The management has failed to show for what work of casual nature the workman was employed for which the workman was paid daily wages as casual workman. The management witness Shri Naval Kishore MW 1 has admitted that the workman has been paid full wages for 89 days and he has neither given appointment letter nor termination letter. The reason being that he was doing work of casual nature. In his affidavit Shri Naval Kishore mentioned that after the services of workman were terminated on 15-1-81 and there was no requirement of calling back the workman before appointing other persons when the workman voluntarily accepted the termination was not available. When questioned in cross examination he has said that by that time the workman was not available and that the workman himself has accepted the termination and he was not required to be present later on any day nor was any notice sent to him to call him to work. In my opinion, the management has infringed the rule 78 of the ID Central Rules mentioned above by not calling him for the similar nature of work of messenger. Thus this termination of the workman and employing another person for the same or similar nature of work would be nothing but colourable exercise of powers which would be an unfair labour practice and has to be whitled down for none compliance of section 25H of the I.D. Act.

8. The result is that the termination being by way of unfair labour practice, the same is liable to be set aside and the workman may be deemed to be continued in service with full back wages.

9. I, therefore, taking into consideration, entire facts, circumstances and evidence of the case find that the action of the management State Bank of India Lucknow in relation to their Pariyawan Branch in not absorbing Shri Shiv Shanker sub staff in bank's service and terminating his service w.e.f. 14-1-1981 is not justified.

10. The result is that he may be reinstated in service with full back wages.

11. It is further made clear that regarding the absorption of the workman in the regular service of the bank, the management may consider the workman according to rules.

I, therefore, give my award accordingly.

12. I et six copies of this award be sent to the Government for its publication.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-12012|129|83-D.II(A)]

का. आ. 5481.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, रोहतक, के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चंडीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6-11-85 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 5481.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Central Bank of India, Rohtak and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th November, 1985.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH

Case No. I.D. 37 of 1984 (CHD)

PARTIES :

Employers in relation to the management of Central Bank of India.

AND

Their workman : Shri Chand Singh.

APPEARANCES :

For the Management : Shri Yogesh Jain

For the Workman : Shri Raj Kumar Sharma

ACTIVITY : Banking STATE : Haryana

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, per their Order No. L-12012|142|84-D. II(A) dated the 16th November, 1984 referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the management of Central Bank of India, Rohtak in awarding the punishment of discharging from service Shri Chand Singh. Substaff with effect from 28-5-82 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. The petitioner, Chand Singh, was working as a Peon-cum-Cyclostyle Operator at the Rohtak Branch of the Respondent Bank in the years 1979-80. It was alleged that in August 1979 he managed to remove and steal a cheque bearing No. 002613 worth Rs. 131.80 favouring M|s. Delhi Paper and Board Company, Rohtak which he succeeded in encashing and ultimately misappropriated the proceeds thereof. On dection of the incident he was placed under suspension w.e.f. 7-1-79 and proceeded departmentally on the basis of a charge sheet dated 20-5-80 on the ground that he had dishonestly stolen the aforesaid cheque and misappropriated its proceeds on 3-8-79. It was further alleged that he had also removed page No. 87 of the Token Book which contained the entry of the said cheque.

3. Shri P. N. Banerjee, the than Chief Officer, Regional Office Chandigarh was appointed as the Enquiry Officer; on joining the petitioner in the proceedings he recorded the evidence produced before him by both the parties and concluded his findings to the effct that even though the petitioner had dishonestly got the cheque encashed and misappropriated its proceeds yet there was no evidence of his tampering with the Bank records resulting in the loss of page No. 87 of the Token Book.

4. In due course of time the Regional Manager, who happened to the Disciplinary Authority in the instant case, considered the report, including the findings, of the Enquiry Officer and on accepting the same, issued a show cause notice to the petitioner as to why his services should not be terminated. But the petitioner's reply did not find favour with him and thus he directed his discharge from the Bank service w.e.f. 28-5-82.

5. Feeling aggrieved, the petitioner raised on industrial dispute through his Union because according to him he had a spotless service record ever since he joined the Bank in August, 1973 and that the charges against him were either fabricated or based on mere surmises and conjustures due to the personal Vendetta of the local officers. He also assailed the validity of the Enquiry proceedings and fairness of the orders passed by the Disciplinary Authority terminating his services.

6. Since the management was found unresponsive inspite of the intervention of the ALC(C) at the Conciliation stage, hence the reference.

7. In support of his case the petitioner examined his Union General Secretary Shri R. K. Sharma whereas the Management filed the affidavit of the concerned Disciplinary Authority Shri H. S. Dhingra.

8. In all fairness to him, the petitioner's representative did not question the propriety, regularly or validity of the Enquiry proceedings during the course of hearing before me. As a matter of fact the burden of his testimony as well as the submissions was confined to the quantum of sentence. In a manner of speaking he just sought the indulgence of the Tribunal on the point of punishment by virtue of Section 11A of the Act with the submission that the petitioner might have been swayed by some momentry aberration otherwise he was serving the Management for a number of years without any blemish and that there had never been any complaint against his work or conduct; that he belongs to the weaker section of the society (schedule caste) and was the sole bread winner of a large family consisting of 8 persons including aged parents; moreover, the incident took place in the year 1979 and ever since his suspension in the year 1980, he was running around without any assured source of income adding to the agonies of a long and protected trial. In the same sequence it was alleged that in yet another similar, but serious, incident, the Management had taken a lenient view in favour of one of their official holding a key post.

9. To be precise, the case of one B. B. Magoo was cited before me. The said Shri Magoo was posted as Assistant Cashier at the Karnal Branch of the Respondent Bank and in his position as such, was alleged to have stolen a cash amount of Rs. 1150 from the Bank on 7-1-82; he was proceeded departmentally and found guilty but let off with amount og Rs. 1150 from the Bank on 7-1-82; he was nently with cumulative effect."

10. It was thus urged that when a person, who in the very nature of things was required to be the guardian of the Bank Cash, was found guilty of an abhoring activity like theft and still retained in service there should be no reason to deny a little magnanimity towards the first lapse of a class IV employee belonging to the downtrodden strata of society, particularly when he was genuinely repentant of his fault.

11. Significantly enough, the sworn deposition the Union General Secretary, Shri Sharma, on the precedent of Shri Magoo, was allowed to go unchallenged despite an opportunity to the Management. Of course their indulgence in one particular case may not bind them to show the same generousity towards the dereliction of the petitioner also, but all the same in the totality of the circumstances I feel that the ends of justice would have sufficed even if any other punishment, short of disengagement, was imposed on him.

12. Accordingly on sustaining the Management's action in its pith and substance I quash the impunged order of punishment and substitute the same with the loss of his uptodate wages including graded increments permanently and cumulatively; but he would be reinstated in service with immediate effect and even though the intervening period will count towards his service for the purpose of terminal benefits as and when they fall due, yet he will not be entitled for any leave of encashable service benefits of any type whatsoever accruing during the meanwhile. To put it in simple words, he shall be fied at the stage where he was at the time of his suspension on 7-11-1979.

13. Award returned accordingly.

Chandigarh.

30-10-85.

I. P. VASISHTH, Presiding Officer

No. L-12012/142/84-D. II(A)

का. आ. 5482.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, केनरा बैंक, नई दिल्ली, के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5 नवम्बर, 1985 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 5482.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Canara Bank, New Delhi and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th November, 1985.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL KANPUR

Reference No. L-12012/157/82-D.II-A. dt. 27-4-83

Industrial Dispute No. 184 of 1983

In the matter of dispute

BETWEEN

Shri Bhagwan Singh C/o The Dy. General Secretary C/o Shri Basudeb Singh, Village Samiraka Taf P.O. Samuri Teh. Agra, Distt. Agra.

AND

The Deputy General Manager, Canara Bank Marshall House, Hanuman Road, Parliament Street, New Delhi.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its order no. L-12012/157/82-D.II(A) dated 4-5-1983 has referred the following dispute for adjudication:

Whether the action of the management of Canara Bank in relation to their Idgah Branch Agra in terminating the services of Shri Bhagwan Singh sub staff

with effect from 7-8-81 is justified or not to what relief is the workman entitled?

2. The workman filed statement of claim alleging that he was appointed as guard-cum-peon on 15-12-80 in permanent vacancy but without giving him any appointment letter. His services were utilised upto 5-6-81 and after giving a break his services were again utilised as temporary hand from 8-6-81 to 7-8-81 and ultimately his services were terminated on 7-8-81. That the termiantion being against the provision of para 522(4) of Sastri Award is illegal consequently he prayed that he be reinstated with full back wages.

3. The management contested the claim of the workman on the ground that no copy of the claim statement was given to the management hence the workman be directed to supply the copy of the claim statement to enable them to file its reply, hence the workman was directed to supply a copy of the claim statement to the management so that they may file proper reply of the same.

4. The workman thereafter never appeared despite notice. Ultimately on 10-5-85 it was ordered that no one is present to prosecute the case for the workman let it go as no dispute award. As the management has failed to enquire the case after 10-5-85 and did not furnish the copy of the claim statement to the management in order that the management be filed written statement and to proceed further. The reference is answered in negative for want of prosecution and I accordingly hold that the action of the management of Canara Bank in relation to their Idgah Branch Agra in terminating the services of Shri Bhagwan Singh sub staff with effect from 7-8-81 is justified.

5. The result is that the workman is not entitled to any relief as claimed in the statement of claim.

6. I, therefore, give my award accordingly.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

7. Let six copies of this award be sent to the government for publication.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-12012/157/82-D.II(A)]

का. आ. 5483 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एन्ड जयपुर के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-11-85 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 5483.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby pubilshes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of Bikaner and Jaipur and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th November, 1985.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, KANPUR

Industrial Dispute No. 234/1985

Reference No L-12012/21/4/84-D.II(A) dated 8-3-1985 In the matter of dispute

BETWEEN

Ieet Lal Pal C/o General Secretary, UP Bank Employees Union 165, Sobhatia Bagh, Allahabad.

AND

The Manager, State Bank of Bikaner and Jaipur Allahabad.

AWARD

1. The Central Government Miinstry of Labour vide its notification No. L-12012/214/84-D.II(A) dated 8-3-85 has referred the following dispute for adjudication :

Whether the action of the management of State Bank of Bikaner and Jaipur Allahabad, in terminating the services of Shri Jeetlal Pal, Peon Allahabad Branch with effect from 25-1-84 and not considering him for further employment under section 25H of the I.D. Act is justified? If not to what relief is the workman concerned entitled?

2. The above reference was received in this tribunal on 23-3-85 and the notices to the parties were sent fixing 8-4-85 for written statement and claim statement. On 8-4-85 none appeared from the side of workman and 30-4-85 was fixed again in the case. On the said date the workman again absented himself. From the perusal of the letter dated 27th March, 1985 addressed to this tribunal by the management it appears that the workman was appointed in the bank according to rules in a permanent capacity. If this is so the dispute between the parties automatically comes to an end.

4. Under the circumstances of the case, let no claim award be sent to the govt.

5. I, therefore, give my award accordingly.

Dated : 30-10-85

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

Let six copies of this award be sent to the government for publication.

Dated : 30-10-85

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-12012/214/84-D.II(A)]

का. आ. 5484 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, यूनाइटेड कामर्शियल बैंक के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-10-85 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 5484.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as is shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the United Commercial Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th November, 1985.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 28 of 1984

Reference No. L-12012/229/83-DII(A) dated 12th March, 84 In the matter of dispute

BETWEEN

Shri Brij Bhushan R/o Janak Nagar Opposite Gandhi Memorial School Saharanpur

AND

The Assistant General Manager, United Commercial Bank 23 Vidhan Sabha Marg, Lucknow.

APPEARANCE :

Shri Amrik Singh.—for the management.

Shri O. P. Mathur.—for the workman.

AWARD

1. The Central Government Government. Ministry of Labour vide its notification No. L-12012(229)|83-DII (A) dated 12-3-84 has referred the following dispute for adjudication.

> Whether the action of the management of United Commercial Bank Lucknow in relation to their Ambehta Branch in terminating the services of Shri Brij Bhushan Peon Cum Watchman with effect from 20-7-73 is justified ? If not to what relief is the workman concerned entitled ?

It is common ground that the workman was employed under the management at Ambehta Branch Shahranpur during the period 19-5-69 to 20-7-73 as peon cum watchman. That out of said 548 days the workman had completed 241 days service in the year commencing from 1-5-72 to 30-4-73. The workman asserts that he worked against vacancies of permanent nature of job and acquired status of a temporary employee. According to the management the workman was employed in leave vacancy of purely temporary nature and after expiry of leave vacancy the temporary employment of the workman used to come to an end automatically and it would be wrong to say that the workman was employed in clear or permanent vacancy. The management has denied the workman's contention that services of the workman was terminated on 20-7-73 without assigning any reason and asserted that there was no question of terminating the services of the workman without any reason As his employment was against temporary vacancy which automatically came to end after expiry of period of temporary employment and as such there was no question of reinstatement of the workman with full back wages.

3. The management has admitted all the working days which is amply established by certificate issued by the management Bank It is further admitted that in two speels the workman worked for 99 days in Ambehta Branch i.e. from 2-4-73 to 9-6-73 for 69 days and again from 21-6-73 to 20-7-73 for 30 days.

4. From the management documents dated 2-4-73 filed alongwith affidavit of R. S. Chanana and the other document ment ext. M-1 dated 20th July, 1973 that the workmen was appointed on the basis of application given by him. As per terms of appointment his services were terminated after 20 days w.e.f. 20-7-73 vide Ext. M-1 The management has filed these documents per list dated 14-9-84 which shows that on two occasion the workman was employed on leave vacancy and on another occasion he was given temporary assignments for 16 days and on the appointment letter dated 19-5-69 he was given temporary appointment for eight days.

5. From these documents it is established that the workman was given work either on his own application or otherwise in leave vacancy or for short duration. The management has filed a penal of sub staff formed on 25-6-73 at Hairat Ganj Branch at Lucknow. In this list (penal) there is name of one Ram Kishore who appointed on probation at Ambehta Branch on 22-1-74. There was no penal for the period 69 to 73 when the workman is said to have worked on temporary basis and acquired a right to be appointed as sub-staff Counting bach from 20-7-73 to 20-7-72, the workman had worked in all for more than 240 days in temporary capacity for which no notice or retrenchment compensation was paid to the workman.

6. In cross examination, the management witness has deposed that it would be wrong to say that the penal of sub staff filed by him related only to Hairatganj branch rather it related to whole of uttar pradesh as posting have been made in different branches of U.P.

7. The workman having completed 240 days in one span was entitled to retrenchment compensation which was admittedly not given to the workman on the date of termination i.e. 20-7-73 as such in view of the law laid down in Santosh Gupta Vs State Bank of India 1980 II LLJ page 72, the termination would be void abinitio.

8. The result is that the workman will have to be reinstated in service with full back wages

9. Moreover, future vacancies have not been denied by the management. If vacancy occurred after termination of the workmen he should have been given appointment which was not done by the management. Thus there is infringment of provision of section 25 G and H also and the termination will be illegal on that count also.

10. I, therefore, taking into consideration entire facts, circumstances and evidence of the case hold that the action of the management of United Commercial Bank in relation to their Ambehta Branch in terminating the services of Shri Brij Bhushan concerned workman w.e.f. 20-7-73 is not justified

11. The result is that the workman will be reinstated in service with full back wages.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

Let six copies of this award be sent to the Govt. for its publication.

Dated 30-10-85

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-12012|229|83-D II(A)]

का. आ. 5485.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-11-85 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 5485.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India, Allahabad and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th November, 1985.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL KANPUR

Industrial Dispute No. 42 of 1984

In the matter of dispute

BETWEEN

Shri Laxmi Nath Mehrotra C|o Shri N. C. Pandey C-323 Guruteg Bahadur Nagar Kareli Allahabad.

AND

The Regional Manager, Region III, State Bank of India, The Mall Kanpur.

APPEARANCE

Shri S. C. Uprati.—for workman

Shri A. S. Saxena—for the Management.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification no. L-12012|283|83-D. II (A) dt 3rd March, 1984 has referred the following dispute for adjudication.

Whether the action of the management of State Bank of India Region III in relation to their Naini Branch Allahabad in discharging from service Shri Lakshmi nath Mehrotra, clerk w. e. f. 12.9.83 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?

2. It is common ground that the workman was a clerk in the clearing department at relevant time at Naini Branch Allahabad. He wrongly creditted two cheques one of Rs. 35000 and the other was of Rs. 8295 to wrong beneficieries. The workman was given a memo dated 14-10-82 requiring him to receipt the same. The workmen gave reply which was considered by the disciplinary authority and as the disciplinary authority was not satisfied with the reply, he passed discharge order being discharge simplicitor under para 522 (1) of the Sastri Award on the ground that no confidence could be reposed in the workman. The Regional Manager who was the competent authority terminated the services of the workman.

3. On the other hand the case of the workman is that he did the work in a bonafide manner and as a matter of fact the voucher had been changed by one Shri Rahul Malaviya while he had left his counter shortwhile and had gone to the urinal. Rahul Malaviya changed the voucher meanwhile which resulted wrong entry in the name of wrong beneficieries. Rahul Malviya has admitted his guilt and sought time to recompensonate the bank and subsequently he compensated the bank as result of which the bank suffered no loss.

4. Para 522(i) of the Sastri Award deals with the procedure for termination of employment in cases not involving disciplinary action for mistake and subject to clause (6) below the employment of a permanent employee may be terminated by three months notice or on payments of three months pay and allowances in lieu of notice. Bank in the termination order dated 12-9-83 has mentioned nothing as to why the services of the workman are being terminated. The workman was given memo for wrong credit of the two cheques on 14th October, 1982 regarding which he gave reply on 4-2-83 admitting that the pay order was duly entered in clearing register and that the party concerned has changed the voucher attached to the cheques which he has admitted and compensated the bank. This wrong doing has been detected by passing officer. The management not feeling satisfy with the reply of the workman passed the termination order under para 522 (i) of the Sastri Award though not clearly mentioning in words that the termination was for loss of confidence. There having been no enquiry, there having been no other grounds except the ground of wrong credit of two cheques to wrong beneficiaries, the management lost confidence in the workman and consequently terminated his services. Even this act if not amounting to making forgery himself amounted to coming up to expected standard of conduct giving rise to situation involving loss of confidence and involving disciplinary action for misconduct as enumerated in para 521 of the Sastri Award. The management not having done it. The termination under para 522 (i) would not be legal as his case involved disciplinary action for mistake. I am supported in my view with law laid down in Chandu Lal Versus The management of M|s. Pan Americal World Airways 1985 Lab I.C.SC. page 1225 wherein it was observed thus;

> Want of confidence in an employee does point out to an adverse facet in his charactor as true meaning of allegation is that the employee has failed to be have up to expected standard of conduct which has given rise to a situation involving loss of confidence. In such circumstances termination would not amount to retrenchment and disciplinary proceeding were necessary as condition precedent to infliction of termination as measure of punishment.

The result is that the termination being illegal the workman is entitled to be reinstated with full back wages.

I accordingly hold that the action of the management State Bank of India Region III in relation to their Naini Branch Allahabad in discharging from service Shri Lakshmi Nath Mehrotra, clerk w.e.f. 12-9-83 is not justified. The result is that the workman will be reinstated with full back wages. in service

I, therefore, give my award accordingly

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

Let six copies of this award be sent to the Government for publication.
Dt.—30-10-85.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer
[No. L-12012/283/83-D.II(A)]

का. आ. 5486.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और इनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-11-85 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 5486.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India, Lucknow and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th November, 1985.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL KANPUR

Reference No. L-12012|322|83-D.II(A) dt. 11-7-1984

Industrial Dispute No. 61 of 1984

In the matter of dispute between;

Shri Rakesh Kumar Tewari C|o Shri R. K. Pande, authorised representative 67|99 Lalkuwan, Lucknow.

AND

The Regional Manager, Region III, State Bank of India, Hazarat Ganj, Lucknow.

APPEARANCES :

Shri Mahesh Chandra representative—for the Management.

Shri O. P. Nigam, representative—for the workman.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-12012|322|83. D-II(A), dated 11th July, 1984 has referred the following dispute for adjudication;

> Whether the action of the management of State Bank of India, Region-III, Lucknow, in relation to their Gonda Main Branch, Gonda in terminating the services of Shri Rakesh Kumar Tewari, Subordinate staff, with effect from 6-10-82 and not considering him for further employment under section 25-H of the I.D. Act is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?

2. It is common ground that the workman Shri R. K. Tewari, worked as sub staff temporarily (Massenger) w.e.f 2-7-82 to 5-10-82. It is further not disputed that the workman worked for 87 working days with intervening 8 Sundays and Holidays and he was paid for 87 days, for the remaining 8 days workman moved an application for computation u|s 33-C-2 which was allowed. The bank management accepted the claim of the workman and the wages for 8 days

were duly paid by cheque and the case was disposed of by full and final settlement of workman's claim. Under the Shop and Commercial Establishment Act Sundays and Holidays are paid days for commercial establishments in Uttar Pradesh and hence it would be deemed that the workman worked for 8 days and in this way the total number of working days comes to 95 days. As per annexure III filed by the management alongwith affidavit the management too has admitted that the workman had worked for a total period of 87 days and the workman was paid at the rate of Rs. 550.06 per month. The workman moved an application that after his termination Pavan Kumar, Ramakant Tewari and 9 or 10 persons were appointed temporarily. The management failed to keep the required information whereafter, the workman in his affidavit evidence specifically named 8 persons who were either employed after his termination or who being juniors were continued after his termination.

3. In cross examination, the management witness Shri M. P. Joshi M. W.1 admitted that Shri Pavan Kumar and Ramakant Tewari worked some times as temporary workman thus the affidavit averments of the workman stands corroborated that Pavan Kumar and Ramakant did work. I see no reason to disbelieve the sole testimony of workman specially in the absence of any rebutting documentary evidence and in view of the admission of management own witness that Pavan Kumar and Ramakant worked in the bank that Pavan Kumar worked in the bank between August 82 to December 82 and Ramakant was appointed from 7-1-83 to 5-4-83. This itself specifically show that at the time of service of workman were terminated Pavan Kumar was working who was appointed later in August 82 while workman's appointment continued from 2-7-82. In my opinion, if at all there was necessity to terminate the temporary services of workman, Pavan Kumar junior to Rakesh should have been dispensed with and workmen. Further after having been terminated the workman on 6-10-82 if there was any necessity at all to employ fresh hand in place of workman Ramakant, workman whose services were terminated earlier on 6-10-82 should have been intimated and called. In this way there had been a clear violation of the provisions (i) firstly of section 25-G when Pavan Kumar should have been terminated and secondly infringement of provision of section 25-H of the ID Act when Ramakant was appointed without giving opportunity to workman whose services were terminated earlier than even Pawan Kumar who was terminated in December, 82.

4. It appears that the management had been adopting this practice of employing workman temporarily for a period of 90 days in view of their internal circular one of which is circular no. 69|81 filed by management itself. Similarly there are other circulars that temporary employees should not be employed for a period more than 90 days. Not only this in one of the circular no. 168|76 it was clearly mentioned that in cases irregular temporary employment are made the branch manager and departmental head shall be held responsible for irregularities. Management's witness Shri Joshi had admitted that the workman was employed for job of purely temporary nature and no appointment letter was issued to the workman and he was not told on what date and when his appointment shall stand terminated and that the work for which he was employed was temporary nature of job and was not appointed in increase of permanent nature of job nor was appointed in any leave vacancy of a permanent vacancy. Thus in view of definition of temporary workman given in para 20.7 of bipartite settlement, the status of the workman would not be casual but a temporary workman. For such temporary employees as required by para of the agreement arrived between the State Bank and their workman there should have been a register maintained by bank of the temporary employees, management should have issued appointments and termination letters. In view of other provisions of the agreement a service book should have been maintained and ultimately there should have been a 14 days notice and a termination letter. Admittedly none of the above provisions were complied with by the manangement in the instant case.

5. Under section 25-G of the I.D. Act, the retrenched workman should ordinarily be the person who was the last appointed in that category and similarly at the time of employing any other person in that category, the retrenched workman should have been offered re-employment first, for such re-employment procedure is laid down under rule 78 of the I.D. Central Rules. None of which were complied by the management bank. Retrenchment being termination for any reason what so ever these were the mandatory provisions to have been complied by the management. Non compliance of which will render termination illegal and in operative and employment of fresh hands after 89 or 90 days by terminating temporary employee for any reason or without any reason would be an unfair labour practice. This is high time for the management to note that the social justice to workmen is insured by legislature of the ID Act and their infringement by circumventing them can not be allowed. I accordingly hold that the termination of the workman brought about on 6-10-82 is illegal and in operative.

6. The result is that the workman is entitled to be reinstated with full back wages.

7. I, therefore, hold that the action of the management bank against the workman as specified in schedule, is not justified and the workman is entitled for reinstatement with full back wages.

8. I, therefore, give my award accordingly.

9. Let requisite numbers of copies be sent to the Government for its publication.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

Dt. 30-10-1985.

[No. L-12012|322|83-DII(A)]

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1985

का.आ. 5487—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, देना बैंक के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-11-85 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 21st November, 1985

S.O. 5487.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Dena Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th November, 1985.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, KANPUR

Industrial dispute No. 222|1984

Reference No. L-12012|111|84-D.II(A) dated 22nd November, 1984.

In the matter of dispute between :

Gyandha Kumar C|o The State Vice President, U.P. Bank Employees Congress Vijai Hotel, Railway Road, Aligarh.

AND

The Regional Manager, Dena Bank Gedore House, Nehru Place, New Delhi.

APPEARANCE :

Shri P. C. Jain—for the workman.

Shri Ramesh Pathak—for management.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-12012/111/D. II(A) dated 22nd November, 1984, has referred the following dispute for adjudication :

> Whether the action of the management of Dena Bank in relation to their Aligarh Branch in terminating the services of Shri Rajender Kumar, Temporary Sepoy w.e.f. 9-7-82 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?

2. It is common ground that the workman Rajendra Kumar was engaged as temporary sepoy on 1-6-81 and was terminated on 9-7-82; that the management was persuing unfair labour policy of engaging temporary hands and terminating them after some time though taking work of permanent nature from them and in persuance of this labour practice the management terminated the services of the workman. It is further not disputed that he was on daily rated basis and that his total span of work was about one year two months. The management reiterates that during 12 consequitive months, the workman did not complete 240 days of work, though in the total span of temporary service, the workman worked for one year one month and 9 days i.e. 246 days from time to time. The management has reiterated that the workman was not entitle to the retrenchment compensation as he has not worked for 240 days, the workman in his statement of claim has averred that after terminating his service the management recruited another temporary sepoy. The workman has further ascerted that within 12 months of proceeding of his termination he had completed 281 days of work and was entitle to retrenchment compensation and further he was entitle to be reappointed when fresh hands were recruited in the said permanent vacancy. The workman has consequently prayed to be reinstated with full back wages and that he should be absorbed permanently in the banks services.

3. On behalf of the management Shri M. K. Jain Manager, Dena Bank Dariyaganj Branch, New Delhi gave his affidavit and was subject to cross examination he has stated that between 1-6-81 to 9-7-82, the workman actually worked for 246 days. He has further admitted that during span of 12 months the workman had actually worked only for 228 days. In cross examination he stated that since the workman was temporary his service book was not maintained and no adverse remark was given to the workman and no service certificate was issued to him. He further stated that the workman has paid on weekly off i.e. for sundays and holidays on his representation and was engaged when ever required.

4. On behalf of the workman one Shri Kripal Singh has given his affidavit. In cross examination he has admitted that after termination of workman one Rajvir Singh was appointed. He further stated that he had no knowledge if any other temporary employee was recruited after termination of Rajendra Kumar. He has further stated that after the termination of the workman two or three persons were appointed and one of them Ram Prasad who was terminated.

5. Even according to own showing of the management as per chart filed by them the workman worked for 228 days in a span of one year between 31-7-81 to 9-7-82. As observed earlier in cross examination management witness Shri M. K. Jain admitted having paid wages for Sundays and holidays and according to the chart filed 63 days full wages were paid to the workman on account of Sundays and holidays adding 63 days to 228 days the admitted actual number of days total comes to 281. According to section 25(B) (2) of the I. D. Act, that period has to be included on which cessation of work was not due to any fault on the part of the workman. Though on sundays and holidays no work was taken from the workman but he was paid full wages for 63 days and he will be deemed to be on duty and hence the period would include in actual working days. The management paid 63 days as under the Shop Act section 10, 11 and 14 full wages are to be paid for weekly off and holidays.

6. My attention was drawn to the law laid down in D B R Mills Limited Versus Appellate Authority Under Payment of Gratuity Act 1985 1 LLJ page 181 wherein it was observed.

> As part of the management of an establishment the employer himself either in compliance with the standing orders or a statutory duty imposed upon him, in relation to the establishment in which the employee concerned is rendering service has to observe certain number of days as public holidays and sundays. The establishment itself can not work or even if it works the same employees can not be employed on those days. In such cases the holidays are staggered and other employees are employed to do the work. For what ever the reason it may be the cessation of work by the individual can not be termed as are due to any fault of the employee. Hence cessation of work of the responders employees on sundays and other public holidays during a year satisfied the inclusive definition of continuous service. Though the service is interrupted, it is not an interruption caused due to any fault of the employee. If that be the position, then as per explanation he would be deemed to be in continuous service if he has been actually employed by an employer during the 12 months immediately preceding the year for not less than 240 days in an establishment as the appellant company.

7. The management has drawn my attention to the case V. Ramaswami and Ratnawel 1979, Lab IC NOC 136 Madras H R 1979 2 Mad 264, wherein it was held :

> The words "actually worked" would not include even holidays much less saturdays and sundays, for which full wages are paid. The words days worked itself would normally mean days actually worked. The legislature as if to give emphasis, has also added the word actually. There could therefore, be no scope for argument that paid holidays are to be included in this actually worked. The explanation to S. 25B has included in this actually worked days certain deemed actual working days. Only these days which are provided in the explanation could be included in calculating 240 days in addition to the actual working days. The meaning of words actually worked can not be enlarged beyond what is contained in the explanation.

8. Agreeing to the reasonings of law laid down in latest pronouncement of Andhra Pradesh High Court I hold that having completed 240 days of work in one continuous year in temporary capacity he was entitled to retrenchment compensation which was not admittedly done amounting to violation of provision of section 25F and the termination having being brought about without paying retrenchment compensation being illegal, the termination will be void abinitio and the workman will be entitled to be reinstated in service with full back wages.

9. Under the circumstances I hold that the action of the management of Dena Bank in relation to their Aligarh branch in terminating the services of workman w.e.f 9-7-82 was not justified being illegal.

10. The result is that the workman will be entitled to be reinstated in service with full back wages.

11. , therefore, give my award accordingly.

Let six copies of this award be sent to the Government for publication.

Dt 30-10-85

R. B SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-12012(111)/84-D. II(A)]

का.आ. 5488 —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, सन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, लखनऊ, के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 5-11-85 को प्राप्त हुआ था

S.O. 5488.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the awrad of the Central Government Industrial Tribunal Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Central Bank of India, Lucknow and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th November, 1985.

PRESENT SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Reference No. L-12012/22/81(D)(II)(A) dated 12-8-81

Industrial Dispute No. 116/1981

In the mater of dispute

BETWEEN

Shri Ram Chandra C|o. The President UP Bank Employees Federation, 26/104 Birhana Road, Kanpur.

AND

The Chief Manager, Central Bank of India, Regional Office, Vidhan Sabha Marg, Lucknow.

APPEARANCE :

For the Workman—Shri O. P. Nigam & Shri V. N. Sekhari.

For the Management—Shri S. Trivedi.

AWARD

. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification no. L-12012/22/81-D.II(A) dated 12-8-81, has referred the following dispute for adjudication :

> Whether the action of the management of Central Bank of India, Lucknow in paying daily wages and to terminating the services of Shri Ram Chander Sub Staff from 11-6-79 (A.N.) is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?

2. The case of the workman has been spouced by UP Bank Employees Federation who was admitedly appointed in the bank. According to the union, the workman was appointed as peon cum water man on 14-5-68 and continued to work upto 11-6-79. In the after noon on 11-6-79 his services were illegally terminated after working of so long years. That despite such long stand in service he was not paid regular wages but was paid daily rated workman. That no notice pay or retrenchment compensation was paid to the workman. The mandatory provision of section 25F, G and H of the I.D. Act has also been violated, hence the termination of the workman was void abinitio. Thus the workman is entitled to scale rate wages and reinstatement with full back wages w.e.f. 12-6-79.

3. The management has denied in its written statement that the workman Ram Chandra was a workman within the meaning of the industrial dispute act. It is further admitted that Ram Chandra worked as casual daily rated worker at Aminabad Branch of the management bank in Lucknow and the quantum of wages paid to him was depended upon the duties performed by him from time to time and that he was solely employee for serving water or lying water to the upper storey of the branch and was called for work as and when necessary and it was in these circumstances that he was not issued any appointment letter nor he ever signed the muster roll and neither he completed 240 days in one calender year and that he could not claim employment as a matter of right and hence was not entitled to any notice or retrenchment compensation, and also was not entitled to any claim made.

4. The management filed a chart showing the number of working days and amount paid by the management during span January, 1974 to 31st December, 1979. According to this chart the workman worked for number of days specified in the chart at the rate of Rs. 5 mostly except for some times when he was paid Rs. 7, 4, 3 or Rs. 2. According to the chart supplied by the management the workman had not completed 240 days in any span of one year.

5. The parties filed joint inspection report marked Ext. W-1. According to this joint inspection report also the workman has not completed 240 days in any calender year.

6. In support of its contention the management examined one Shri P. K. De Chief Officer (Personnel) who was looking to the personnel matters of the staff members. He has reiterated the stand taken by the management in its written statement. In cross examinaion he has deposed that there was no water man in Aminabad branch as there was no post of water man and that the appointment of the workman was not in temporary vacancy but he was casual labour. He went to depose that that casual work of waterman is done by usual peon and when there are too much absentees of the peon, casual labour is appointed on daily wages and he was not appointed on any leave vacancy or temporary vacancy. He was not appointed temporarily for increase in permanent nature of work and he was also not appointed for limited period but at daily wages as casual labour. He admits that no appointment letter or termination letter was issued to him and he was not allowed to sign attendance register and he was not entitle to any weekly rest as he had not done seven days continuous work in a week. He further stated that Ram Chandra was not working for whole time and that though in vouchers things are not given but the very amount paid. One can desifer that he worked for less hours and not full day. He has admitted that there was no penal for temporary employees or casual employees and no service records are maintained for such casual employees.

7. On the other hand the workman in his affidavit reiterated that he worked as temporary member of sub staff in Aminabad branch of the management bank from 14-5-68 to 11-6-68 with artificial break, that though he was working full time but he was paid only at the rate of Rs. 5 per day and on few dates Rs. 7. When he was doing some other job from and above, serving water to the staff members of the branch. He has further averred in the affidavit beside serving water he was also doing other job of the peon which is carrying papers and registers from one seat to another and also outside duties trusted to him. That few candidates who had some relations in the mangement or influence in the branch were given regular work and were taken in permanent employment but the deponent was not given any chance and when he requested for his regular absorption the branch manager stopped taking work from him abruptly and asked him not to come in the bank.

8. In cross examination he had deposed that in Aminabad he worked as water man and also worked as peon for carrying account book etc. and going to post office and whenever he worked extra he was paid Rs. 2 for that work.

9. Para 169 of the Sastri Award shows that water man also come within the category of sub staff. Para 20.7 of the Bipartite settlement gives the definition of temporary employees as follows:

> Temporary employee will mean a workman who has been appointed for limited period of work which is of a essentially temporary in nature or who is employed temporarily as a additional workman in connection of a temporary increase of work of a permanent nature and includes a workman other than permanent employee who is appointed in a temporary vacancy caused by the absence of a particular permanent workman.

10. Now it has to be seen whether the workman whom the management calls a casual workman was really casual or temporary workman. It is common ground that the workman Ram Chandra was not appointed in any temporary vacancy caused by temporarily absence of permanent workman Ram Chandra was not appointed in any temporary is not a work which is essentially of temporary nature which may come off and on days a work of regular nature for which in the banks water boy or water man are appointed in the category of sub staff. The management witness himself has admitted that mostly work of water man is done usually by peons. He further admitted that workman was appointed as casual labour as water man but not in place of any person. No appointment letter was issued to the

workman, so it can not be said that his period of apapointment was limited. No doubt in the case of a casual workman it can be said that his services commences when he starts work and comes to an end to the end of days work or after the stipulated time. But from the joint inspecion report it has been established that in the year 1979 he has worked almost continuously with breaks of holidays and other days. The work of water boy being a work of permanent nature the workman was given employment as the need arose which can be said that it must have been a temporary increase in the work of permanent nature of water supply and thus the services of the workman would be temporary and not casual Even if this work of temporary employee was taking by appointing some one on daily wages that would amount to unfair labour practice and it can be very easily said that the appointment of a workman for about 200 days in a year would be nothing but temporary. Had the workman completed 240 days in a year he would have been entitled to retrenchment compensation, but even from the joint inspection report it itself shows that the workman had not completed 240 days of work continuously in one calendar year There is nothing on record to show that other hands were appointed after his termination as water boy and his claim was not considered. The workman being the temporary workman as observed above he was atleast entitle to 14 days notice in view of provision of para 522(4) of the Shastri Award. As the workman was doing work of permanent nature and has been held to be a temporary employee and not casual he was entitled to minimum scale rate wages for the period he worked and also 14 days notice or pay in lieu of termination of his temporary employment.

11. In 1968 II LLJ page 646 Jammu & Kashmir Central Bank of India versus State of J & K at Page 654 it was thus:

> The discharge of the respondent also appears towards to be illegal as admittedly no written order signed by manager of the bank as contemplated by para 522 (4) of Sastri Award or served upon respondent.. dismissed with cost.

12. I, therefore, taking into consideration entire facts, circumstances and evidence of the case, hold that the action of the management bank, Central Bank of India, Lucknow in paying daily wage to and terminating the services of Shri Ram Chander Sub staff from 11-6-79 is not justified.

13. The result is that the workman is entitled to be reinstated with full back wages.

14. I, therefore, give my award accordingly.

Let six copies of this award be sent to the govt. for publication.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

Dated : 31-10-1985

[No. L-12012/22/81-D.II(A)]

का.आ. 5489 —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक, हैदराबाद के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-11-85 को प्राप्त हुआ था।

S.O 5489.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India, Hyderabad and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th November, 1985.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD.

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 17 OF 1981.

BETWEEN

The Workmen of State Bank of India, Hyderabad.

AND

The Management of State Bank of India, Hyderabad.

APPEARANCES :

Sarvashri K. Narasimham and D.S.R Varma, Advocates for the Workmen.

Sri K. Srinivasa Murthy and Miss G. Sudha, Advocates. for the Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-12011/41/80-D. II. A dated 30th July, 1981 referred the following dispute under Section 7A and 10 (1) (d) of the Industrial Disputes Act 1947 between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen to this Tribunal for adjudication.

> "Whether the action of the management of State Bank of India in relation to its Hyderabad Circle in designating Shri M. S. Rama Rao and Shri K. Satyanarayana as Sweeper and Sweeper-cum-Messenger respectively while appointing them as full time employees with effect from 1-9-78 is justified? If not, to what relief are the workmen concerned entitled?"

This reference was registered as Industrial Dispute No. 17 of 1981 and notices were issued to the parties.

2. It is mentioned in the claims statement of the workmen that Shri M. S. Rama Rao initially was recruited as full time Messenger at Marteru Branch of the State Bank of India and worked for a period of nine months from 5-7-1972 to 31-3-1973 having been employed through the employment Exchange. It is his case that he worked continuously for more than 240 days within a period of 12 months prior to 31-3-1973 but his services were terminated without complying with the conditions laid down under the Industrial Disputes Act. He mentioned that he was reappointed as a part time employee only with effect from 18-3-1974 that too as sweeper-cum-water boy; and that he being scheduled caste candidate had to accept the same as he was in dire circumstances. It is also his case that he was making representation that he should be taken as full time employee and that he should be regularised.

(a) He mentioned that in the case of Shri K. Satyanarayana of Patamata Branch of the State Bank of India who was appointed as temporary Messenger by an order dated 1-7-1971 when he put in around 255 days of service, his services were terminated by an order dated 13-3-1972. On the vary same day by another order he was appointed as temporary part time Sweeper-cum-Messenger which designation was subsequently altered by an order dated 11-8-1974 as part time sweeper. According to him the services as Messengers of both the workmen were illegally terminated and the said terminations are violative of Section 25F of the I.D. Act. He further mentioned that subsequent absorption of both of them on part time basis as sweeper-cum-water boy and Sweeper-cum-Messenger instead of reinstating them in their original post is also violative of Section 9A of the I.D. Act. According to them the matter was taken up by the Union. The Management appointed M. S. Rama Rao and K. Satyanarayana as full time employees with effect from 1-9-1978 as Sweeper and Sweeper-cum-Messenger respectively and that the same is in violation of section 9A of I. D. Act. It is mentioned that they are entitled to be reinstated for wages as Messenger from the dates of their illegal termination and therefore they are entitled to be taken back as messengers and not as Sweeper and Sweeper-cum-Messengers with effect from 31-3-1973 and 13-3-1972 respectively.

3. In the counter of the Management, it is mentioned that the claims statement has no relation whatsoever to the reference made under Section 10 of the I.D. Act. It is contended that it is open to the Petitioners to seek any other relief

other than what flows from the reference. According to them the so called rights of the concerned workmen for the period prior to 1-9-1978 is beyond the scope of the reference. According to them even if the allegations made are correct, they are not entitled to question their appointments made in 1972 and 1973 in the year 1982 as those matters are treated as closed, and further when they accepted full time posts which were subsequently regularised with retrospective effect. It is contended that the petitioners are put to strict proof of all the material allegations which are not admitted.

(a) It is mentioned that in the case of M.S. Rama Rao his first appointment was purely temporary and casual in nature and the allegation that he was making representation to appoint him as full time employee are not correct. It is asserted that he did not object to his appointment as temporary sweeper-cum-water boy nor raised any protest thereafter.

(b) Referring to K. Satyanarayana's service it is said that he was terminated when there was no necessity and that he did not raise any objection for his later appointment as Sweeper-cum-Messenger/Sweeper. So it is contended that there is no violation in appointing petitioner as Sweeper-cum-Water boy with effect from 1-9-1978. It is further mentioned that there is no necessity to appoint these petitioners as Messengers at the Branches where there were working. It is finally pointed out there was no reduction in status and no violation of Section 9A of the I.D. Act was involved and their appointments as Sweeper-cum-Water boy are legal, valid and proper from 1-9-1978 and it is mentioned that they are not entitled to the benefits of full time Messengers with effect from 31-3-1973 and 13-3-1972 respectively.

4. The workers examined two witnesses W.W. 1 and W.W. 2 and marked Exs. W1 to W20. On the other hand the Management examined one witness M.W. 1 and marked Exs. M1 only.

5. W.W. 1 is M. S. Rama Rao. He mentioned that he is a Scheduled Caste and he was appointed as Messenger in State Bank of India on 5-7-1972, after being selected through Employment Exchange for a permanent vacancy. According to him it is mentioned in the Order as if he was appointed temporary and marked Exs. W1, Exs. W2 to W10 are similar orders of appointments given to him. According to him between 5-7-72 and 31-3-1973 he worked for 259 days as Messenger and for 11 days for which he was subjected to breaks in between in giving postings are excluded. He mentioned that he got more than 240 days within a period of 12 months and without any notice of termination he was removed from service on 1-4-1973 and that he made representation as per Ex. W11 and the Management took him back on his representation into service from 18-3-1974 and thereafterwards he was taken as half-time part time employee i.e. from 31-3-1973 though he was Messenger. It is his case that he was taken back from 18-3-1974 as Sweeper-cum-Water boy and this amounted to reversion. Finally from 1-9-1978 he was made full-time as Sweeper-cum-Water boy as per Ex. W12. It is his case that he should get full time wages from 31-3-1973 instead of 1-9-1978. He also mentioned that Ex. W12 Order his designation as Messenger was not restored to him and Messenger is a subordinate designation while the Sweeper is a menial designation He pointed out that Ex. W12 it was mentioned that his services could be utilised as subordinate also. So he made representation seeking for attendant benefit as full time Messenger from 31-3-1973.

6. W.W. 2 is K. Satyanarayana who worked as Messenger from 1-7-1971 at Pattamata Branch as per Ex. W14. It is his case that he is appointed in permanent vacancy through Employment Exchange and that he worked as Messenger till 30-3-1972 When his services were terminated under Ex. W15. He pointed out that he was again appointed as Sweeper-cum-Messenger under Ex. W16 on 3/4th wages and Ex. 16 was part-time appointment while his original appointment was full time. According to him on 1-8-1974 another order was issued redesignating him as part time Sweeper only and Ex. W17 is the copy of that order. The categories of Sweeper and Messenger are different. Combining the higher category of Messenger with lower category of Sweeper was never in practice. Finally he meantioned under Ex. W17 dated 11-1-1979 he was appointed as full time Sweeper-cum-Water boy with effect from 1-9-1978. He marked the same as Ex. W18. It is his case that his earlier status of Messenger was not restored to him and therefore he made dispute under Ex. W19 and Ex. W20 service particulars issued to him by the Bank. He mentioned that he worked over 240 days from 1-7-1971 to 13-3-1972 and that he should be reinstated in the same post. According to him Ex. M1 order dated 11-1-1979 is replica of Ex. W18.

7 M.W.1 Shri P. S. Sarma is Officer working in the State Bank of India in the Personnel Department. He admitted that he know both M. S. Rama Rao and K. Satyanarayana (W.W. 1 and W.W. 2), who were appointed as Sweeper and Sweeper-cum-Messenger respectively. According to him Rama Rao was appointed in July, 1972 as temporary Messenger and K. Satyanarayana was appointed on 1-7-1971 as temporary Messenger and they were purely temporary. According to him the Union raised an objection about these appointments not being made permaanent and in 1974 K. Satyanarayana was appointed as Part time Sweeper and finally both were made as full time employee from 1-9-1978 and both were designated as Sweeper-cum-Water boy and Sweeper. They denied the suggestion that the Management has changed their designation as Sweeper from Messenger to Water boy. He admitted that all these Messengers or Water boys-cum-Sweeper are award employees and they are only subordinate staff. It is his case that Sundermani's judgement of the Supreme Court was not applicable to these workmen and therefore there is no question of viloation of Sections 9A and 25F of the I.D. Act. He also mentioned that they are not entitled to receive back wages from the original dates of appointment in the full time scale as Messengers. He conceded that from the date of appointment to the date of termination in both these cases of both employees completed 240 days continuous service and they were not given notice before they were terminated. According to him they were made full time employees from 1-9-1978. He denied the suggestion that Sweeper-cum-Water boy is lower designantion when compared to that of a Messenger.

8. The reference is very clear whether the Management of State Bank of India when they designated M. S. Rama Rao and K. Satyanarayana as Sweeper and Sweeper-cum-Messenger respectively while appointing them as full time employees with effect from 1-9-1978 is justified. The admitted facts which are not in dispute are as follows :—

(a) M. S. Rama Rao who was appointed for the first time on 5-7-1972 as Messenger continued to work as full time Messenger for more than 240 days till 31-3-1973 as could be seen from Ext. W1 to W 10. Similarly K. Stayanarayana who worked as Messenger from 1-7-1971 to 13-3-1972 for more than 240 days as could be seen form Ex. W 14 to W 16. It is admitted that they were terminated without notice by M. W1 on the ground that they are purely temporary or casual workers. Under Section 25F of the I. D. Act when they have put in more than 240 days in a continuous period of 12 months in a calender year both these workmen are entitled for the benefits provided under Section 25F of the I.D. Act. So the termination of these two workers without giving any notice when they worked for more than 240 days in 12 months of a calender year respectively without complying with the conditions precedent as laid down under Section 25F of the I. D. Act is beyond dispute. In MOHAN LAL v. BHARAT ELECTRONICS LIMITED [1981 (II) LLJ page 70] the Supreme Court following the Sundermani's case in 1976 (I) LLJ, page 478 STATE BANK OF INDIA v. SUNDARAMONI wherein it was held the termination in contravention of Section 25F when the said conditions are not fulfilled as abinitio void. It is further laid down in this judgement that a declaration that the employee continued to be in service with all consequential benefits will also follow. The judgement in AIR 1974 S.C., page 1166(Management W.B. India Ltd, v. Jagannath) and AIR 1966 S.C. page 1974 (Himmatrao v. Jaikishandas) would show that Section 25-F of the I. D. Act did not distinguish or discriminate between permanent and temporary workmen. The definition of workman under Section 2(s) of the I. D Act includes temporary employees as well. The awards also treat the temporary employees as workman, in fact those

judgements laid down if the service of the workman were terminated even though they are temporary employees they were entitled to retrenchment compensation and also entitled to the benefits of the provisions relating to the retrenchment. The argument of the Management that these terminations which are purely temporary and casual did not come under Section 25-F of the I.D. Act will not hold good.

9. It is contended by the Management counsel that what is being demanded out of the scope of the reference as such the Industrial Tribunal has no jurisdiction to adjudicate upon the same. It is true that the jurisdiction of the Industrial Tribunal speaks from the reference and it will not enlarge the same on a matter which is not the subject matter of the reference as laid down in 1972 Andhra Weekly Report page 165 (Singareni Collieries Company Limited v. Saleem Merchant). The Management relied upon the judgement of Supreme Court and contended the jurisdiction of the Tribunal to adjudicate upon the Industrial Dispute springs from the reference made to it and it would not be open to the workers and management to confer jurisdiction upon the Tribunal on the question not covered by the reference. In the instant case when they are redesignated. When they have put in qualifying service of more than 240 days in 12 months of calender year as Messenger and when they are redesignated on representation with another menial designation with different service conditions of menials and finally when they are shown full time sweeper or full time sweeper-cum-messenger from 1-9-1978 it means that the reference is very clear to look into these facts and the Tribunal is not going beyond the reference while appreciating the facts.

10. As pointed out in the reference the Managements actions in designating these two employees as Sweeper and Sweeper-cum-Messenger respectively as full time employees with effect from 1-9-1978, is the subject matter in issue. The preceding situation in which M. S. Rama Rao and K. Satyanarayana worked before they were designated as Sweeper and Sweeper-cum-Messenger respectively is a matter that is being questioned. It is the case of these workers that they were working as Messenger continuously for a period of 240 days as admitted by the Management in the fulltime Messengers posts and that they were terminated without notice and that they were agitating for the same and that they were reappointed in the case of M. S. Rama Rao, he was taken into service from 18-3-1974 as Sweeper-cum-Waterman as could be seen from Exs. W-1 and W-12 and that his original designation as Messenger was not restored to him and finally he was made full time Sweeper from 1-9-1978. So the action of the Management in designating M. S. Rama Rao as Sweeper has got the historical facts which relate to his service conditions for which he was agitating either individually or through his Union. Similarly in the case of K. Satyanarayana also though he was originally appointed as Messenger under Ex. W-15 would show that he was terminated on 13-3-1972 by which time he has put in more than 240 days in less than 12 calender months and that on the very next day he was appointed as Sweeper-cum-Messenger under Ex. W-16 and finally he made representation about categories of Sweeper and Messengers and the duties and timings being different and that from 1-9-1978 he is appointed as Sweeper-cum-Messenger. So the argument of the Management that the reference is stale and it is not open to the Government to refer the issue as stale and belated are unknown to industrial law. The question of belated representation or employing the principles of limitation when representations are pending and being decided after prolonged consultancy procedure and when employees are being terminated without notice in violation of mandatory provisions of the I.D. Act and when they were re-designated and appointed in a lower category to say that the reference is not valid and that the same is belated and stale seems to be absurd and the Management should not have taken such a ground at all. The citation of the Management in relying upon the decision reported in 1964 (II) LLJ page 644, has no reference at all to Vazir Sultan Company. It is with reference to Talang and Others v. Shaw Wallace and it is with reference to age of superannuation. The learned counsel for the Management relied upon the judgement said to be given in Writ Petition No. 101/83 (P. Ramalingeswar Rao v. State Bank of India Dated 27-3-1985) to show that it is belated application. In that case the person made an application after he was terminated in 1976 by the Bank more than five years later and sought for a direction for a writ of mandamus to reinstate him as watchman and during that time he made good use of the period for prospecting his studies and thus he wanted to make out a case on the basis that in some cases the Bank in similar circumstances was making reinstatement some of the temporary employees. It is mentioned therein in the judgement that many of the points raised by the Counsel were not put in the affidavit of the Petitioner and that the Court cannot ignore all practicalities and difficulties in the way of accepting his argument for reinstatement after lapse of so many years But this is not a case like that. These two persons who were terminated made representations immediately and they were given posting in a lesser category post and their cases were taken up by the union and they were also representing throughout and finally the Management after conciliation proceedings fixed them as full time Sweeper (M. S. Rama Rao) and Sweeper-cum-Messenger (K. Satyanarayana) from 1-9-1978. So the said judgement of our High Court had no comparison or identical facts and these principles which are laid down in Sundermani's case of the Supreme Court as well as the principles laid down in AIR 1974 S.C., page 1166 (Management W. B. India Ltd. v. Jagannath) and AIR 1966 S.C. Page 1975 (Himmatrao v. Jalkisan Da.) and 1981 (II) LLJ, page 70 S.C. (Mohanlal v. Bharat Electronics Co. Ltd.) will apply to these facts and the management is not justified to raise such contention and it is absurd to say that the reference cannot be adjudicated upon. The matter is properly referred and this Tribunal is competent to adjudicate upon the matter also on the available facts.

11. The second contention that the demand relates to appointment and how a person should be appointed is a matter of managerial function and therefore it cannot be a matter of an industrial dispute can be at best a good proposition of it is a fresh appointment. The Managerial function must be wisely and cleverly and deligently applied while making a first appointment. But you cannot say that it is the managerial function to reduce a mans ranking position or alteration of service conditions or designations detrimental to his interest having applied the said managerial function ones. It is not a case of a claim of appointment as a matter of right or it is not a case that individual should be appointed or not appointed. It is also not correct to say that the industrial disputes relates to question of not appointing to a particular grade or post if it is a fresh appointment, 1965 (II) LLJ, page 402 (Indian Hume Pipe Co. v. Bhimarao Bahiram Gajbhiya) was relied upon by the Management to show that one has no right to insist that he should be appointed in a particular post. But in this case it had no application. The Management as per the evidence of MW-1 would show that both M. S. Rama Rao and K. Satyanarayana who were working from 1972 or 1971 as the case may be for a continuous period of 240 days in 12 calender months were terminated without notice and again in 1974 K. Satyanarayana was appointed as part time Sweeper and that M. S. Rama Rao was also appointed as part time Sweeper-cum-Water boy. He conceded that the post of two Messenger for which they were appointed originally and in which they worked for more than 240 days continuous has no nexus with the post of Sweeper-cum-Water boy for which they were subsequently appointed on their representations and he also mentioned when the Union represented similar cases they mentioned before the Labour Commissioner that similar placed employees will be appointed as full time basis to accommodate them from 1-9-1978. So when they were appointed 1-9-1978 as admitted they were shown designation as Sweeper and Sweeper-cum-Messenger while they were only messengers when they were appointed. Finally he conceded that these Messengers and Water-boys and Sweeper-cum-Messengers are award employees. It is strange to say that Sundermani's judgement will not apply to subordinate staff when they are admittedly the subordinate staff as conceded by MW-1. The other point is that from 1-9-1978 till now that Rama Rao and K. Satyanarayana did not protest to receive their salaries and they were acquicised and established. In Pallayan Transport Corporation (METRO) Madras v. Presiding Officer (Vol. 51 I. F. and L. R. September 15th, Part 6) Page 297 the question of estoppel or acquicence is essentially held to be a question of fact and waiver is an intentional relinquishing of known right. It is also pointed out that there can be no waiver unless the person against waiver is claimed at full knowledge of his right and all facts enabling him to take all effectively action for the endorsement of such rights. So there is no much thing done by the worker. Therefore there is no question of acquicence or estoppel when facts indicate that there is unfair labour practice adopted by the Management and in the light of Sundermanj's judgement workmen should be put back where they were let of and their new salary would

be what he would draw where he had been appointed in the same post today demovo. So these two persons who were terminated originally and who were subsequently shown in different ranks designations which had different timings and different designations which are lower and menial should be set aside and they should be restored to their original appointments. The said posting or designations given to them as Sweeper and Sweeper-cum-Messenger respectively for M. S. Rama Rao and K. Satyanarayana are inoperative and illegal and they are lible to be set side. Moreover the plea of estoppel is out of place in an industrial dispute. The argument of the Management that they have appointed these two persons as Sweeper and Sweeper-cum-Messenger respectively from 1-9-1978 is an illegal one to circumvent the erroneous reinstatement in a wrong designations which is unfairly menial post and not to a sub-staff post as can be seen from the evidence of WW-1 and WW-2 and MW-1. In the cases these two workmen who worked as full time messengers for more than 240 days are entitled to be put back in the same designations (posts) in lieu of 1976(I) LLJ, page 478 judgement but the Bank acted mala fides and put them in lower designation. The designation of Sweeper-cum-Water boy and Sweeper-cum-Messengers which is in the cadre of nemial staff when the Messenger is a sub-staff category, it must be held that the said change of designation is illegal and void even prior to 1-9-1976. Therefore in other words Section 9A of the I. D. Act is violative when Section 25-F is violated that is from 31-1-1973 in the case of M. S. Rama Rao and 13-3-1972 in the case of K. Satyanarayana. It cannot be said that the duties of Sweeper and Messenger are one and the same by any process of imagination. Sweepers duties are mean and have more onerous work load they indicate a relatively lower status in relation to the designation of a messenger both hours of work and duties. Therefore it cannot be said that there is no change of designation and reduction in status. The argument that the matters which were of 1972 and 1973 when they were appointed as Messenger become closed when they were subsequently appointed as Sweeper-cum-Water boy and the same cannot be responed is not a correct proposition. As there cannot be any technical plea of estoppal in an industrial dispute like this refer in Sonukumar Chatterjee and Others v. District Signal Telecommunication Engineering and others (1970 (II) LLJ, page 179, at page 191 and 192 in paras 20 and 21). Thus the other argument of the Management Counsel is that Section 9A had no application to all these two cases is also not correct. Infact the very termination of their appointments without notice under Section 25-F of the I. D. Act when they were acting as full time Messengers is bad and abinitio void. If the retrenchment is abinitio void a declaration should be given that the employees continuous to be in service with all consequential benefits will follow as could be seen from 1981 (II) LLJ page 70. The attack of the Management for temporary appointment under Section 9A is not applicable as Section 9A contemplates the service condition which take the fact with that the date of appointment and that it had no relevance for previous jobs temporarily in the Bank in leave vacancies seems to be not good proposition. Infact MW-1 mentioned that in the year 1978 the union started raising the issue of appointment of these workmen who were appointed in the year 1971 and 1972 and at that time Sundermani's Judgement of Supreme Court is not applicable to these workers. Now Sundermani's judgement came in 1976 and to say that these workers are not attracted by Section 9A and 25-F of the I. D. Act seems to be illogical and incorrect. In Sundermani's case the Supreme Court upheld the law as per Sections 2(oo) and 25-F of the I. D. Act. The law as per Section 2(oo) and Section 25-F and Section 9A is made effective from the day the enactment is made by the Parliament even in 1980 (II) LLJ, S.C., page 72 (Santosh Guptas case) the same principle was upheld. When they have appointed them with effect from 1-9-1978 as Sweeper and Sweeper-cum-Messenger respectively they were only continuing the illegality or injustice following from the violation of Section 25-F of the I. D. Act on the part of the Bank. Therefore on a careful consideration of the entire evidence I hold that the Management erred in designating M. S. Rama Rao as Sweeper and K. Satyanarayana as Sweeper-cum-Messenger respectively while appointing them as full time employees with effect from 1-9-1978 instead of declaring them as full time Messengers with effect from 31-3-1973 and 13-3-1972 respectively with all attendant benefits. Therefore the present order of designating them as full time Sweeper and Sweeper-cum-Messenger from 1-9-1978 is held as illegal and improper and I hold that they are entitled to declare as full time Messenger with effect from 31-3-1973 (M. S. Rama Rao) and 13-3-1972 (K. Satyanarayana) respectively with full attendant benefits in the scale of Messengers only.

Award is passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him, corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 1st day of October, 1985.

Sd/-

INDUSTRIAL TRIBUNAL

Witnesses Examined

For the Workmen :

WW-1—M. S. Rama Rao.

WW-2—K. Satyanarayana.

Witnesses Examined

For the Management :

MW-1—P. S. Sarma.

Documents marked for the Workmen :

Ex. W-1—Appointment Order dated 5-7-1972, issued by Agent v. Solomon Raj State Bank of India, Marteru, to Mathe Sree Ramarao for a period of one month.

Ex. W-2—Appointment Order dated 5-8-1972, issued by Agent v. Solomon Raj State Bank of India, Marteru, to Mathe Sree Rama Rao, for a period of 15 days.

Ex. W-3—Appointment Order dated 18-8-1972 issued by Agent v. Solomon Raj State Bank of India, Marteru, to Mathe Sree Rama Rao for a period of 15 days.

Ex. W-4—Appointment Order dated 2-9-1972 issued by Branch Manager v. Solomon Raj State Bank of India, Marteru to Mathe Sree Rama Rao for a period of 25 days.

Ex. W-5—Appointment Order dated 1-10-72 issued by Branch Manager v. Solomon Raj, State Bank of India, Marteru to Mathe Sree Rama Rao, for a period of one month.

Ex. W-6—Appointment Order dated 1-11-1972 issued by Branch Manager v. Solomon Raj, State Bank of India, Marteru to Mathe Sree Rama Rao, for a period of one month.

Ex. W-7—Appointment Order dated 6-12-1972 issued by Branch Manager State Bank of India, Marteru to Mathe Sree Rama Rao, for a period of one month.

Ex. W-8—Appointment Order dated 12-1-1973 issued by Branch Manager, State Bank of India Marteru, to Mathe Sree Rama Rao for a period of one month.

Ex. W-9—Appointment Order dated 22-2-1973 issued by Branch Manager State Bank of India, Marteru to Mathe Sree Rama Rao, upto the end of February, 1973.

Ex. W-10—Appointment Order dated 23-3-1973 issued by Branch Manager State Bank of India Marteru, to Mathe Sree Rama Rao for the period from 5-3-1973 to 31-3-73 after break of 4 days from 1-3-73 to 4-3-73.

Ex. W-11—Representation dated 26-4-73 made by Mathe Sree Rama Rao, to the Regional Manager, State Bank of India Region II, Hyderabad, Local Head Office, Hyderabad with regard to continue in temporary service

Ex. W-12—Letter F. No. 26 dated 29-9-78 addressed by Branch Manager State Bank of India, Marteru, West Godavari District to M. S. Rama Rao with regard to appointment of regular part-time employees as full-time employees.

Ex. W-13—Acceptance Letter dated 30-9-78 addressed by M. S. Rama Rao to the Branch Manager, State Bank of India, Marteru

Ex. W-14—True copy of the Memorandum dated 1-7-71 from State Bank of India, patamata to K. Satyanarayana, Sitanagram-Tadepalli, Guntur District with regard to appointment of temporary Messenger.

Ex. W-15—True copy of the termination order dated 13-3-72 issued by State Bank of India, Patamata to K. Satyanarayana, Temp. Messenger.

Ex. W-16—True copy of the Memorandum No. S-4, dated 13-3-72 issued by State Bank of India, Patamata, to K. Satyanarayana, Temporary Messenger with regard to appointment rules.

Ex. W-17—True copy of the Memorandum dated 1-8-74 addressed by State Bank of India, Patamata to K. Satyanarayana, Part-time Sweeper-cum-Messenger, State Bank of India, Patamata with regard to redesignated him as part-time Sweeper.

Ex. W-18—True copy of the letter No. P. 26, dated 11-1-79 addressed by the Branch Manager, State Bank of India, to K. Satyanarayana, Temporary Part-time Sweeper, State Bank of India, Patamata, with regard to appointed him as a full-time Sweeper-cum-Water boy on a temporary basis.

Ex. W-19—True copy of the acceptance letter dated 15-1-79 addressed by K. Satyanarayana to the Branch Manager, State Bank of India, Patamata.

Ex. W-20—True copy of the Service particulars along with wages paid to K. Satyanarayana, Part-time Sweeper.

Documents marked for the Management :

Ex. M-1—Appointment Order No. P. 26 dated 11-1-79 issued by State Bank of India, Patamata to K. Satyanarayana.

Dated : 18-10-1985.

J. VENUGOPALA RAO, Industrial Tribunal

[No. L-12011/41/80-D.II (A)]

का.आ. 5490—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-11-85 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 5490.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annex. in the industrial dispute between the employers in relation to the Central Bank of India, Kanpur and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th November, 1985.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, KANPUR

Industrial Dispute No. 189 of 1981

Reference No. L-12012/262/80-D.II(A) dated 2-12-81

In the matter of dispute between :

Shri J. N. Tiwari s/o Shri G. N. Tewari Central Bank of India, Gumti No. 5 Kanpur.

AND

The Chief Manager, Central Bank of India, Karanchi Khana, Kanpur.

APPEARANCES

For Management—Shri S. Trivedi.

For Workman—Shri V. N. Sekhari

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-12012/262/80-D. II(A) dated 2nd December, 1981. has referred the following dispute for adjudication :

Whether the action of the management of the Central Bank of India, Kanpur in not providing employment to Shri J. N. Tewari clerk after 23rd March, 1972 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?

2. It is common ground that the workman worked in the management bank branch at Karanchikhana from 27th February, 1970 till July, 1970, but according to the workman he worked total number 49 days with artificial breaks whereas according to the management he worked only for 44 days only, Sundays and holidays being included. It is further admitted that during the period 15th June, 1971 to 8th September, 1971, the workman worked for 82 days with two breaks. It is further admitted that in third spell between 24th January, 1972 to 23rd March, 1972 the workman worked in Nayaganj Branch for sixty days when his services were brought to an end. Thus according to the workman the total working days were 291 days where as according to the management the workman worked for 286 days only on temporary basis during the periods February, 1970 to 23rd March, 1972. It is averred by the workman in his claim statement that having worked for more than 90 days at a stretch he was entitled for permanent absorption in view of para 20.7 and 20.8 of the Bipartite Settlement. In the end the workman has prayed that his termination after 23rd March, 1972 be set aside as unjust and illegal and may be ordered to be absorbed with full back wages.

3. The management in its written statement alleged that the applicant was not a workman within the meaning of the Industrial Dispute Act as he worked only on leave vacancy and never completed 240 days during any calender year. As para 20.7 of the Bipartite Settlement is not attracted as it refers to a case of a person who is eventually under continuation of his temporary service is taken up as probation. Thus the statement of claim of the workman be rejected.

4. In the rejoinder the workman has averred that those who have been thrown out of employment also come within the definition of the workman under section 2-A of the I. D. Act. He has further clarified that the break from 27th March, 1970 to 29th March, 1970 was a artificial break as 27th March, 1970 was a holiday on account of Good Friday. 29th March, 1970 was Sunday and again on 30th April, 1970 was an artifical break. Moreover there was an artifical break from 1st June, 1970 to 5th June, 1970. Taking these artifical break into account it would apparent that the workman worked more than three months at a stretch, and hence para 20.8 of the Bipartite Settlement could be applicable to him. It is further averred that provision of section 25G and H of the I.D. Act could be attracted in the instant case even though the workman had worked for less than 240 days. The workman named S/Shri Raj Kumar, Kishan Ji Baipai, Prem Shankar and Santosh Kumar as persons who comparatively have been put lessor number of working days and better position have been worked as pass book writer and failed in the test conducted by the management were given preference continued in service and ultimately absorbed in permanent service. That the workmen had worked against the permanent vacancy

5. In support of its contention, the management bank filed affidavit of Shri P. K. Dev Chief Personnel Officer and reiterated during course of cross-examination the averments of the written statement and verified the documents filed on his behalf. In cross examination he has deposed that he could not say any thing about persons mentioned in paragraph 3 of the rejoinder for want of further details. According to the witness the workman worked in leave vacancy at Karanchi Khana at Nayaganj, Kanpur. He has further admitted that fresh hands were employed after the termination of the workman on 23rd March, 1972. He has however admitted that no register and no service book of the temporary employees is maintained by the bank management and no notice was given to the workman at the time of his termination.

6. The workman in his affidavit averred the averments made in the claim statement and ascerted that during the period he worked at Karanchi Khana he worked as despatcher clerk beside his clerical duty and the job of despatcher and other duties including on over drafts ledger were of permanent nature and was not appointed on any leave vacancy or any other vacancy. Moreover, at Nayaganj, Kanpur, he worked as ledger keeper which was a work of permanent nature and was always managed by regular work. That many junior persons appointed after him were allowed to continue as his services were discontinued. They are namely Raj Kumar, Kishan Ji, Prem Shanker and Santosh Kumar who were all appointed temporarily in 1971 and were made permanent in 1972, after termination of his service. After his termination fresh hands were appointed. He has further averred that his termination was against the mandatory provision of the bipartite settlement and I.D. Act and against article 14, 16 and 21 of the Indian Constitution. The management's circular has been filed by the workman, which is dated 25th October, 1976 whereby temporary hands were not be employed beyond 60 days.

7. In cross examination he admitted that he appeared in bank's recruitment test but did not get its result and that he appeared in the test before entering in the bank's service. He has further admitted that he got service in the bank in the reserved category as his father was in the management bank's service. He has reiterated that he was not appointed in the vacancy of any one but has admitted that his father used to get information on phone from the Divisional Office to send him for joining temporarily. In the end he has said that he has no independent income.

8. From the evidence discussed above, it is evident that the workman worked in temporary capacity and in reserved category. Appointments temporary or permanent on reserved category being violative of article 14 of the Indian Constitution were dispensed with. The preliminary objection of the management bank that the workman being out of employment is not a workman and entitled to adjudication of dispute is repelled as in the definition of workman given under sec. 25-s of the I.D. Act includes any person who being employed earlier has been discharged from services. It is argued on behalf of the management that the temporary appointments will not give any right to the workman as he has not completed 240 days of work and that there was no discripency if a group of pass book writers were recruited temporarily.

9. The work of clerical nature in the bank are mostly of permanent nature unless proved that a particular work was essentially of temporary nature. The management's contention is that the workman was appointed for certain fixed period in leave vacancy. The workman has filed several such appointment letters showing that his appointment was for fixed period. Thus in any view whether he was in leave vacancy or employed in temporary basis in increase of work of permanent nature his appointment was all the time temporary. Para 20.8 of the Bipartite Settlement laid down that a temporary workman may be appointed to fill permanent vacancy provided that such temporary appointment shall not exceed for a period of three months during which the bank shall make a permanent arrangement for filling up permanent vacancies. If a temporary workman works on such a post for a period exceeding three months that shall not epso facto make him permanent on that post. It is only if such a temporary workman is eventually selected for filling up the vacancies the period of such temporary employment will be taken into account as part of his probationary period. This further shows that the temporary workman who was working on permanent post for 60 days or above shall have to undergo all the procedure for selection of a person for filling a permanent post and if he succeeds in such test and interview his previous temporary employment will be taken as part of his probationary period. Thus working on a permanent post for three months at all will not give the workman right to be treated as permanent.

10. The ruling cited by the workman of Jaswant Sugar Mills Vs. Badri Prasad 1961 I LLJ Lab. IC page 267 will not apply to the facts of the present case. The workman has claimed benefits u/s 25G & H of the ID Act. The management witness has admitted that fresh hands were appointed after termination of the workman i.e. on 23rd March, 1972 on which date the workman was terminated. Sec. 25G & H applies to the retrenched workman and retrenchment has been defined under section 2(00) of the I.D. Act as termination by employer of the service of the workman for any reason whatsoever otherwise than as punishment or other grounds mentioned therein. The termination of the workman was probably brought about by efflux of time or services no more required which termination is covered under the definition of the retrenchment.

11. The management should have maintained a list of temporary employees and terminated the juniors on 23rd March, 1972 if at all was necessary. There was no record as to who was the junior most man on that day for want of any such list. Re-employment having been admitted by management witness there was a clear violation of section 25H as the workman was not offered any opportunity to come and work as temporary hand after 23rd March, 1972. Before employing any person the management should have given notice to the workman as provided under rule 78 of the ID Rules (Central), moreover, management contravened the rules 77 laid down in I.D. Rules Central by not maintaining seniority list of the temporary workman. I am supported in my view by law laid down in Kanpur Tannery Limited, Kanpur Vs. Guhan and others, 1961 II LLJ page 110 S.C., Muller and Philips India Limited 1966 I LLJ page 254, Delhi High Court and British India Corporation Vs. Labour Court 1978 LIC page 523 Allahabad High Court wherein non-compliance of section 25H was held that retrenchment was not competent and was illegal and the workman was entitled to reinstatement.

13. Thus in view of the discussion made above, the termination of the workman on 23rd March, 1972 and employing fresh hands thereafter being illegal, the workman was entitled to be reinstated in service with full back wages.

14. I accordingly hold that the action of the management of the Central Bank of India, Kanpur, in not providing employment to Shri J. N. Tewari clerk after 23rd March, 1972 is not justified.

15. The result is that the workman be reinstated in service with full back wages.

16. I, therefore, give my award, accordingly.

17. Let six copies of this award be sent to the Central Government for its publication.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer
[No. L-12012/262/80-D.II(A)]

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1985

का.आ. 5491.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद, के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-11-85 को प्राप्त हुआ था

New Delhi, the 22nd November, 1985

S.O. 5491.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal Kanpur as shown in the Annexures in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India, Allahabad and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th November, 1985.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, KANPUR

Reference No. L-12012/104/83-D.II(A) dated 14th December, 1983

Industrial Dispute No. 249 of 1983

In the matter of dispute between:

Shri Brijendra Kumar C/o Shri N. C. Pande, C-323 Guru Teg Bahadur Nagar, Kareli, Allahabad.

AND

The Branch Manager, Naini, State Bank of India, Naini Allahabad.

APPEARANCE

Shri V. V. Mangalvadhekar—for the workman.

Shri A. S. Saxena—for the management.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-12012/104/83-D.II(A) dated 14th December, 1983, has referred the following dispute for adjudication:

> Whether the action of the management of State Bank of India in relation to their Naini Branch, Allahabad in not absorbing Shri Brijendra Kumar Temporary Cashier in Bank's Services and terminating his services with effect from 6th December, 1971 is justified? If not to what relief is the workman concerned entitled?

2. The case of the workman is that he was employed in the management bank Naini Branch Allahabad w.e.f. 23rd September, 1970 and worked upto there 6th December, 1971 and was not allowed to work there thereafter. That the workman made several representation verbally as well as in writing to the management who assured him to take in service and thus the employment of the workman was totally considerable after 6th December, 1971 when the workman was ceased to work and not given appointment subsequently several persons were appointed by the management bank but the workman was not called for work. That as a result of non-employment and giving employment to other persons, the workman raised industrial dispute in 83 which ended in failure. The workman having started work on 23rd September, 1970 as cashier worked for more than a year and thus became a permanent employee of the bank. That even if he treated temporary neither any register of temporary hands was maintained for purposes of retrenchment nor preference was given to the workman in the matter of employment and thus the provision of section 25G, H and F of the I.D. Act 1947 and para 493 of the Sastri Award and para 20.12 of the first Bipartite settlement were infringed. That the termination of the workman by way of giving artificial break and not following the provision given under section 25F of the I.D. Act is illegal and amounts unfair labour practice. No appointment letter and no termination letter was given to the workman as required under para 522(4) of the Sastri Award. The workman has consequently prayed treating the termination as illegal and unfair labour practice he be reinstated with full back wages.

2. The management has contested the case of the workman on the ground that no demand was made by the workman before raising the industrial dispute. It is not disputed that the workman worked for 29th September, 1970 to 6th December, 1971 on which date his services were finally terminated as no longer required. That the claim of the workman is highly belated. It is further averred that the appointment/employment of the workman as temporary hand was against casual or adhoc requirement and not against any vacancy of regular nature. The management has denied that the workman continued his services for one year or more and that the termination did not amount to retrenchment and hence the provision of section 25G, H and F are not attracted. The requirement of the written termination order is not condition precedent. In the lack of such order will not revadidate the termination. The applicant was not entitled to any relief.

3. In the amended written statement the management raised a plea that it was not the case of section 2A of the I.D. Act as the workman was never discharged, terminated or retrenched.

4. According to the management own showing the workman worked for 203 days counting from 23rd September, 1970 to 6th December, 1971 but on going back 12 months from 6th December, 1971 to 15th January, 1971, the number of working days comes to 194 days which is apparently less than 240 days.

5. In the rejoinder the workman gave a list of six persons namely Ishwar Chandra, V. K. Shula, R. P. Jaiwal, O. P. Srivastava, A. N. Mishra and A. V. Singh, as persons who were appointed subsequent to termination of the workman.

6. The workman in his cross examination has stated that he was not appointed on any leave vacancy or that he was working at Allahabad on ad hoc basis.

7. The management witness Shri B. N. Banwalekar stated that he has no knowledge that if any appointment letter from 25th January, 1971 and termination or extension letter was issued to the workman or not. He further stated that he was not sure if after the termination of workman on 6th December, 1971 the management appointed as many as six persons in March, 1972. In the end he admitted that to his knowledge no termination was issued to the workman.

8. On the point of preliminary objection namely demand and case being raised under section 2-A of the I.D. Act it may be mentioned that raising of industrial dispute on its first date i.e. stage before the A. L. C. Central amounts to demand. If the management was inclined to investigate and considered if the claim was just and proper they would have come out with its case and reconcile the dispute if possible. Thus raising of the dispute before A. L. C. amounted to raising a demand if no demand notice was made to the management prior to the dispute.

9. Second point that the dispute could have been raised u/s 2-A of the I.D. Act the same is incorrect in the very definition of the workman even those continued to be the workman who have been dismissed discharged or retrenched. Thus the applicant was a workman and having been discharged was entitled to raise dispute under sec. 2-A.

10. From the admitted case of the parties it emerges that it is not the case of the workman having worked for 240 days in one span of a year hence there is no question of infringement of section 25F of the I.D. Act. Utmost it could be said that it is the infringement of section 25G, but there is nothing on the record to show that there were other persons junior to the workman working on the date of his termination on 6th December, 1971.

11. As regards infringement of section 25H the workman has specifically stated in his rejoinder that six persons named therein were appointed after his termination. If the management was inclined to employ temporary hands thereafter he should have been given workman, a retrench employee, an opportunity to have come and join unless there was any thing derogatory against him. The management has failed to keep any register of temporary employees or retrenched temporary employees as provided under para 493 of the Sastri Award. The management has failed to disprove the averments of the workman made in his rejoinder and in the workman's affidavit by giving documentary evidence that the averments of the workman was wrong to that effect. The workman was also not given any termination letter as required under para 492 of the Sastri Award and termination notice as required under para 522(4) of the Sastri Award.

12. In Cawnpore Tannery Limited Versus Guha 1961 II LLJ page 110 Supreme Court it was held thus:

> Even before 25H was added to the act industrial adjudication generally recognises the plea that if an employer retrench the service of any employee on the ground that the employee in question had become surplus it was necessary that wherever employer had occasion to employee another hand the retrenched workman should be given an opportunity to join services. The plea was recorded as a general principle in industrial adjudication on the ground that it was based on consideration of fair play and justice.

13. In Muller Philips India Limited Versus Union 1961 page 254 Delhi High Court it was held that section 25 is mandatory in as much as retrenched workmen has to be given an opportunity to offer himself for reemployment and thus the preference shall be given.........it is enough to say that the management failed in their duty. The failure to re-employee is more than serious mistake than mistake of retrenchment.

14. The result is that the termination for violating provision of section 25H would be render illegal, the result being that the workman will be entitled to be reinstated with full back wages.

15. In view of the law laid down above and discussion I hold that the action of the bank management in not absorbing the workman and terminating him w.e.f. 6th December, 1971 is not justified. The result is that the retrenchment being illegal the workman will be entitled to be reinstated in service with full back wages.

16. I, therefore, give my award accordingly.

17. Let six copies of this award be sent to the Government for publication.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer
[No. L-12012/104/83-D.II(A)]
N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1985

का.आ. 5492.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार वेस्टर्न कोलफील्ड्स के बुरहार ग्रुप आफ माइन्स के प्रबन्ध तंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 11 नवम्बर, 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 21st November, 1985

S.O. 5492.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Burhar Group of Mines of Western Coal Field Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th November, 1985.

BEFORE SHRI V. S. YADAV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT|LC(R) (19)|1985.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Burhar Group of Mines of Western Coalfields Limited and their workman Shri Samnoo, Safety-cum-Production Assistant, represented through the General Secretary, M.P. Koyla Mazdoor Sabha (HMS) P.O. Dhanpuri, Colliery Distt. Shahdol (M.P.)

APPEARANCES :

For Workan Shri D. L. Agarwal General Secretary.
For Management Shri B. K. Anand, Senior Personnel Officer.

INDUSTRY : Coal Mining DISTRICT Shahdol(M.P.)

AWARD

Dated, November 1, 1985.

The Central Government in exercise of the powers conferred under Section 10 (1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947, has referred the following dispute, for adjudication, vide notification No. L-22012(4)|84-D.V. dated 15th March, 1985 :—

"Whether the action of the management of Burhar Group of Mines of WCL P.O. Dhanpuri Distt. Shahdol in dismissing the services of Shri Samnoo, Safety-cum-Production Assistant with effect from 25-2-1983 is justifified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The parties raising the dispute was directed to file a statement of claims complete with relevant documents, list of reliance and witnesses as required under Rule 10B of the Industrial Disputes (Central) Rule, 1957. Parties appeared today and filed a settlement arrived at between the management and the workman concerned, Shri Samnoo, terms of which are incorporated therein.

3. I have recorded the statements of the representatives of the parties and I am satisfied that the compromise is mutual and without any undue influence. I, therefore, accept the same. The reference is accordingly answered in terms of compromise as under :—

1. Shri Samnoo, Ex-Safety-cum-Production Asstt. Burhar Group of Mines shall be reinstated with immediate effect with continuity of service for the purpose of payment of Gratuity.
2. The period from the date of his dismissal till the date of his reinstatement shall be treated as "Dies Non".
3. Shri Samnoo will not be entitled for any wages for the period of his dismissal till date of his reinstatement.
4. Shri Samnoo will be paid suspension allowance as per rules if not already paid.
5. The settlement shall be registered under Rule 58 of the I.D. Act.

4. In view of the settlement the management has agreed to review the case of dismissal and allow Shri Samnoo to resume his duties on the above terms. In the circumstances question of justification and relief need not be considered. No order as to costs.

1-11-1985.

V. S. YADAV, Presiding Officer
[No. L-22012 (4)|84-D. V]

का.आ. 5493 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम, बम्बई के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

S.O. 5493.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Cental Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India, Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I AT BOMBAY

Reference No. CGIT-22 of 1984

PARTIES :

Employers in relation to Food Corporation of India, Bombay.

AND

Their workmen.

APPEARANCES:

For the Employer—Mr. Masurkar, Advocate and Mr. P. P. Khambatta, Advocate.

For the Workmen—Mr. Namjoshi, Advocate.

INDUSTRY: Food Corporation. STATE: Maharashtra.

Bombay, the 16th day of September, 1985

AWARD

This reference under Section 10(1)(d) as originally made on 16th November, 1984 was in these terms:—

"Whether the action of the management of Food Corporation of India, Bombay in not paying the overtime wages to its staff for first hour beyond their nomal working hours is justified? If not, to what relief the said workmen are entitled?"

2. The reference came to be amended on 20th March, 1985 and for the words "for first hour", appearing in the above reference, the word 'working' was substituted. In short the reference is whether the Food Corporation could deny to its workmen overtime wages for working beyond their normal working hours.

3. Most of the facts giving rise to this reference are admitted and accepted between the parties. In that position of the matter, they did not lead any oral or documentary evidence and argued their respective contentions. It was admitted that the Food Corporation has fixed hours of duty of its concerned employees work 39 hours per week as per schedule. The employees concerned are in class-III and class-IV and their daily working hours are 6-1|2 hours. However, according to the corporation, they are required to do duty between 8 A.M. to 12 Noon and 1 P.M. to 5 P.M. The grievance therefore is that the employees are required to do 1-1|2 hours of extra work every day in excess of normal working hours for which they say no payment is at all made. In other words, though the normal working hours per week for the class of employees is 39 hours, the work which is extracted from these employees is for 48 hours and not 39. For all these extra 9 hours in a week it is contended nothing is paid.

4. The Food Corporation admits in its para 2 of the written statement that the normal working hours of class-III and Class-IV staff at the godowns, docks, etc. is 6-1|2 hours a day. But it says that "departmental labourers working in the Godowns and Docks are required to work for 8 hours a day." The Corporation therefore admits that though their normal hours of work are 39 hours per week, they have to work "for 48 hours a week and sometimes, for more than 48 hours a week."

5. Accordng to it, the payment for this work over and above 39 hours is governed by "Rules of Government of India which are applicable and adopted by the Employer as per the instructions and which are in force." According to these instructions, it says that "first one hour's work per day in excess of the normal working hours, that is to say, six hours' work in a week beyond 39 hours' normal weekly working hours is to be considered as free hours and the employees are not entitled for any overtime allowance." Beyond that, i.e. over and above one hour, a single rate overtime is paid. Wherever they work for more than 48 hours in a week, they are paid double the rate of normal working hours as overtime allowance in accordance with S. 33 of the Bombay Shops and Establsihments Act. It will thus be seen that the Food Corporation of India takes shelter and seeks to justify, non-payment of overtime wages to these employees on the basis of certain orders and rules which were made by the Government of India and which are in force in the Food Corporation which adopted them.

6. At the hearing of the arguments in this reference, Mr. Khambatta, learned counsel for the Corporation submitted that these Rules have been prevailing in the Corporation for long and for historical reasons continued. He pointed out that it's activity was initially part of the Government activity and of Government Department of Food, which was engaged in procurement and distribution of food grains. Subsequently, this activity was entrusted to a public Corporation which is brought into existence in accordance with the parliamentary act, called the Food Corporation Act. As it was originally a Government Department, all those orders which were prevailing and applicable to Government employees and doing Government work were adopted and made applicable to the employees of the Food Corporation. The rules and directions which were therefore prevailing originally in the Government Department, which was handling procurement of food and its distribution, after its entrustment to it, the Food Corporation, continued to follow the same procedure. Those rules were produced, as also the directions in that behalf at Annexure-A and B to the written statement.

7. Annexure-C will go to show what are the duty hours of the particular staff employed at port operations and godowns. The prescribed working hours are from 8.00 a.m. to 5 p.m. with lunch break of one hour from 12 noon to 1 p.m. at Port and from 8.30 a.m. to 5.30 p.m. with a lunch break of 1 hour from 12 noon to 1 p.m. at Godowns. However, the same order says that "duty period of the staff will be reckoned 6-1|2 hours net per day. The extra hours put in to complete the prescribed shift hours will be compensated by way of overtime to be paid for according to the rules in force."

8. The rules are to be found at Annexure-A and they are containd in para 3. (i), (ii) and (iii) of O.N. No. 15011|2|E.-II(B)76 dated 11-8-76 from Ministry of Finance, New Delhi. In para 3(i), thereof, it says that whenever duty is performed beyond the full prescribed hours of work, namely 6-1-|2 hours, overtime allowance has to be paid, but "after deducting from the total the normal one hour of free work." In other words, over and above the working hours, the Food Corporation expects and extracts one hour free work from these employees. The plea put forward by the learned counsel was that this is being done from a number of years and that a large number of other staff of the Food Corporation is being paid and get the same rate of pay and wages in accordance with the circulars. He seems to suggest that one hour's free work is extracted by the Corporation from several other categories of workmen also. Therefore, these concerned workmen in the present reference have no justification or reason to grumble. It was even faintly argued that that was the wage pattern for a large number of workmen in the industry in the region and therefore it can not be tinkered with.

9. In the first instance, such a contention does not appear in the written statement. Secondly, there is no evidence to show that industrial employees in the Bombay region or employees in commercial establishments in this region which are an industry similar to the Food Corporation a practice is prevalent and the wages paid to the workmen are, in a majority of industries, for normal working hours plus one hour of free work.

10. The contention to my mind is preposterous. It is particularly so when we find that a public corporation which was at one time a part of the Government and which should be wedded to gradually bringing into operation and more towards the directive principles in the Constitution should flagrantly practice bonded labour and seek to justify its contention on historical grounds. Apart from the legal provisions to which I shall presently make a reference it seems to me that there could never be any justification found, much less pleaded by a public undertaking to take work from its employees without paying them anything even for a fraction of a day and thus flout the national objective.

11. Mr. Khambatta contended that the employees of the Food Corporation are like Government employees. He did not go to the length of saying that they were civil servants. But according to him, the employees in Government services have to work beyond their normal working hours and it is not known that they can lay any claim on their part for overtime, nor can any overtime wages demand entertained. The argument is inapplicable, since even in Government employment, civil employment and industrial employment has to be distinguished. Though it is true that civil servants of the Government may not be entitled to claim overtime, its industrial categories of employees would be entitled to and are entitled to be paid overtime wages. It is not possible to think that a Government which requires

private industries and establishments requiring its workmen employees to be paid overtime for working beyond the normal working hours, should|or can deny to its own workmen overtime wages for working beyond their normal working hours. Where the category of workmen is similar, namely, industrial governed by the various benevolent provisions of law relating to labour, requiring overtime to be paid for work beyond normal working hours, the liability to do so cannot be got away or skipped by saying that the employer in the case is the biggest employer, being either the Government itself or a public corporation brought into existence by a parliamentary charter, or other semi-Government body.

12. A number of decisions were sought to be relied upon in this behalf on behalf of the employees, such as AIR 1969, 1973 II LLJ-P. 258, 1972-II-LLJ p. 359 and 1969 II LLJ p. 648. A reference was also made to a judgement in Special Civil Application No. 1870 of 1973, decided on 27-4-1979. It was pointed out in that case that it was surprising that normal wages should not be paid for work beyond the normal working hours, but even something less. In the present case, which is still more obnoxious nothing is being paid at all for first hour's work. It is unusual and does not stand to reason that though the employee should be paid wages for normal working hours per hour or by the day, as the case may be, for a part of that day and for an hour, he should be paid nothing. There is, therefore, not even a semblance of justification. Indeed in the case of a private employer, he would have rendered himself liable to prosecution under the Minimum Wages Act or under the Shops and Establishments Act. While that is what should be and would be, it is difficult to think and consider that the Food Corporation of India should seek to justify its action by what would amount to a criminal offence.

13. It is significant in this connection that it is not the case of the Food Corporation that the wages fixed in this case and paid to the workman are on a 48 hour work week basis. When they are asked to do the extra 1-1|2 hour work beyond normal duty hours is already paid for fixing normal working hours of 39 per week as a matter of fact, it is not said, is really a bounty or bonus to the workmen. Such a plea could not have been taken and has no basis in fact for the simple reason that the corporation would not have in that case claimed to be entitled to extract one hour of "free work" and pay overtime wages for half an hour.

14. The minimum Wages Act provides for fixation, no doubt for scheduled employments, the number of hours of work for a normal working day. It also provides for payment of overtime for work in excess of the normal working hours for every hour or part thereof at a rate fixed under the Act. Ordinarily, that would be double the rate of normal rate over normal working hours. The present employment in the Food Corporation, undoubtedly, is not a scheduled employment. That does not however, make the non-payment any more justified. Under the Shops and Establishments Act, under S. 63 thereof, an employee required to work in excess of the limit of hours of work is entitled for the overtime work "wages at the rate of twice his ordinary rate of wages." In the present case, the normal working hours which is the "limit of hours", has been prescribed at 39. It was said that the Bombay Shops and Establishments Act does not apply, as the Food Corporation of India has been exempted from the operation of that Act in the state of Maharashtra. Though that may be so, the principle underlying the Act would still be applicable and the Food Corporation of India, which is a public Corporation should not instead of being an example to others, adopt a practice condemnable which is an offence, if practised by another and makes him an undesirable retrograde employer. It must therefore, be held that the Food Corporation's non-payment of overtime wages for its staff working beyond their normal working hours is not justified.

15. The next question is with regard to the relief to which the workmen are entitled. It must be noticed in that case that the reference does not say to what relief the said workmen are entitled and from what date. In other words, if it is found that the action was not justified, the workmen would be entitled to relief, but such relief can only be prospective and from the date of the reference. For the workmen, it was contended that it should be at least from the date of the demand. I am afraid, the terms of reference do not permit me to direct any retrospective relief, before the date of reference. The relief has, therefore, to be from the date of reference.

16. For the employer it was contended that 48 hours of work per week are as per Annexure-C prescribed working hours, while the duty per week is only for 39 hours. The Corporation, even at present, according to the rules, is paying double the rate of normal wages for work beyond 48 hours of work in a week. For the daily half an hour of extra work, which is done (8—6-1|4), i.e. prescribed working hours minus duty hours, is being paid after deducting the so-called free hour of work, at normal rate for half an hour per day. It was therefore said that upto 48 hours, the overtime which was paid and is being paid was at the normal rate. There is no demand for revision of that rate which can be raised by way of an independent demand and adjudicated. Such a reference has not been made and the terms of reference do not permit the Tribunal to go into the question whether the payment of normal rate of wage for that half an hour every day is justified or no. It was pointed out in this context that the workmen's contention that one and half hour every day is not paid at all is not correct.

17. This position was not disputed and it was conceded that half an hour's work every day is paid for at the normal rate of wages. In this view of the matter and since there is no demand nor any reference to consider the question whether the payment of overtime at normal rate of wages for overtime work beyond duty hours upto 48 which at present is paid for every half-an-hour a day, is or is not justified, there is no reason to depart from whatsoever is being done and what is being paid for the other hour of work, to which the workmen would become entitled, in accordance with this award. I would, therefore, direct that the workmen are entitled to the relief for being paid wages at the normal rate upto 48 hours per week over and above 39 hours of work in a week. In other words, they would be entitled to 1-1|2 hours overtime at normal rate per day, if required to work beyond 6-1|2 hours work per day.

18. Award accordingly.

R. D. TULPULE, Presiding Officer

[No. L-42011(8)|83-D.IV(B)|D.V]

R. K. GUPTA, Desk Officer

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110064, 1985